



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रामाण्य से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42]  
No. 42]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 15, 1994/ अश्विन 23, 1916  
NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 15, 1994/ASVINA 23, 1916

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)  
PART II—Section 3—Sub-section (II)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं  
Mandatory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government  
of India (other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आयकर महानिदेशक (छूट) का कार्यालय

कलकत्ता, 2 मार्च, 1994

आयकर

का. आ. 2702—सर्वगाथाकरण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन त्रिहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" संवर्ग के अधीन अनुसूचित किया गया है:—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा;

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली—110016 को भेजेगा; और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्च किया गया सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय विवरण को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

हस्तीमल संघर्षी शोध फाउंडेशन  
16, शिवाजी नगर, पुणे—411005

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1993 से 31-3-1995 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी :—1 उपर्युक्त जर्न (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2 संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुसंधान की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के

माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियां में आवेदन करें, अनुमोदन की प्रार्थना बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या 1041/एफ.सं. म. नि./आ. क. (छूट)/एम  
92/35 (1)(ii) (90)]  
राजेंद्र सिंह, उप निदेशक

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

Calcutta, the 2nd March, 1994

### INCOME TAX

S.O. 2702.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

### NAME OF THE ORGANISATION

Hastimal Sancheti Research Foundation,  
16, Shivajinagar, Pune-411005.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1995.

Notes.—(1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1041/E. No. DG/IT(E)/M-92/35(1)(ii)90]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 2 मार्च, 1994

### आयकर

का. प्रा. 2702 :—सर्वसाधारण को पत्रद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्रायश्चारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा;
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा; और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिमार्क किया गया सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिमाय को प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

गुजरात विकास संस्थान,  
मुख्य—गांधीनगर, हाइवे रा. गोदावर रास्ता,  
गोटा—382481, ग्रहमदाबाद

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1993 से 31-3-1994 तक की प्रार्थना के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी :—1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की प्रार्थना बढ़ाने के लिए, आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियां में आवेदन करें, अनुमोदन की प्रार्थना बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या 1042/एफ.सं. म. नि./आ. क. (छूट) जी-16/  
35 (1)(iii) (89)]

राजेंद्र सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 2nd March, 1994

### INCOME TAX

S.O. 2703.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan' New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

#### NAME OF THE ORGANISATION

Gujarat Institute of Development  
Research,  
Sarkhej-Gandhinagar Highway,  
Nr. Gota Char Rasta,  
Gota-382431, Ahmedabad.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1994.

Notes.—(1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1042/F. No. DG/IT(E)/G-16/35(1)(iii)/89]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 3 मार्च, 1994

#### प्रायश्चित्त

क्र. आ. 2704 :—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "विश्वविद्यालय" वर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहिया रखेगा।

- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली—110036 को भेजेगा, और

- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दो गई रिमार्क कार्यों में

सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

थापर इंजिनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान,

पटियाला—147001

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1992 से 31-3-1993 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी :—1. उपर्युक्त शर्त (1) "सघ" जैसा वर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने, के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करनी है।

[संख्या : 1043 (एफ. सं. म. नि./आ. क. (छूट) पी-4/35.

(1) (89)]

राजेश्वर सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 3rd March, 1994

#### INCOME TAX

S.O. 2704.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "University" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;

- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

#### NAME OF THE ORGANISATION

Thapar Institute of Engineering  
and Technology, Patiala-147001.

This Notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-1993.

Notes.—(1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions) Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1043/F No. DG/IT(E)/P-4/35(1)/89]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 3 मार्च, 1994

आयकर

का. आ. 2705.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

- (1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा;
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा; और
- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्यों से सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

माइनिंग जिओसाइजिकल एण्ड मेटालर्जिकल संस्थान भारत  
29, चौरंगी रोड, कलकत्ता-700016

। यह अधिसूचना दिनांक 13-12-1993 से 31-3-1995 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी :—1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें

अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग का प्रस्तुत करनी हैं।

[संख्या : 1044/एफ. नं. म. नि. /आ. क. (छूट) पब.—49  
35 (1) (ii)/92]

राजेन्द्र सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 3rd March, 1994

## INCOME TAX

S.O. 2705.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions —

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

## NAME OF THE ORGANISATION

The Mining, Geological and Metallurgical  
Institute of India,  
29, Chowringhee Road,  
Calcutta-700016.

This Notification is effective for the period from 13-12-1993 to 31-3-1995.

Notes.—(1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1044/F. No. DG/IT(E)/WB-49/35(1)(ii)92]

R. SINGH, Dy. Director



कलकत्ता, 3 मार्च, 1994

Calcutta, the 3rd March, 1994

## आयकर

## INCOME TAX

का.आ. 2706.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "विश्वविद्यालय" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा ;
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा ; और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्च कार्यों सम्बन्धी (छूट) के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा ।

## संगठन का नाम

सिल्क एंड आर्ट सिल्क मिल शोध संघ,  
समीरा, समीरा मार्ग बरली,  
बम्बई—400025

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1993 से 31-3-1994 के लिए प्रभावी है ।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा प्रवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है ।

[संख्या : 1045 / एफ. स. नि / आ. क. (छूट) एम-129/  
35 (1) (ii) 90]

राजेन्द्र सिंह, उपनिदेशक

S.O. 2706.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6, of the Income-tax Rules for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax, Director of Income tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

## NAME OF THE ORGANISATION

The Silk and Art Silk Mills' Research  
Association, Seemira, Sasmira Marg,  
Worli, Bombay-400025.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1994.

Notes.—(1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1045/F. No. DG/IT(E)/M-129/35(1)(ii)90]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 3 मार्च, 1994

## आयकर

का.आ. 2707 :—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा-बहियां रखेगा ;
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक

अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा; और

- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्यों सम्बंधी (छूट) के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

#### संगठन का नाम

नेशनल सोसाइटी फार दि प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस  
डा. राजेन्द्र प्रसाद सेक्टर फार प्रापेयिस्मिक साइन्सेज  
ए आई आई एम एस, अन्सारी नगर,  
नई दिल्ली-110029

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-95 से 31-3-93 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 10 46 / एफ. सं. म. नि./आ. क. (छूट) न.दि.—42/  
35 (1) (ii)]

राजेन्द्र सिंह, उपनिदेशक

Calcutta, the 3rd March, 1994

#### INCOME TAX

S.O. 2707.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6, of the Income tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and
- It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of

Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/ Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

#### NAME OF THE ORGANISATION

National Society for the Prevention  
of Blindness  
Dr. Rajendra Prasad Centre for  
Ophthalmic Sciences, AIIMS Ansari  
Nagar, New Delhi-110029.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1996.

Notes.—(1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1046/F. No. DG/IT(E)/ND-42/35(1)(ii)]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 3 मार्च 1994

आयकर

का.सं. 2708—यहांसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन बिहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग प्रौद्योगिकी भवन न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्च कार्यों सम्बंधी छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

हेरमान रिमर्च फाउन्डेशन ए-8 बंगलुरा एस्कनव. को-14,  
बल्लपुरा, नई दिल्ली।

यह अधिसूचना दिनांक 19-3-93 से 31-3-94 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

प्रायकर

कलकत्ता, 4 मार्च, 1994

टिप्पणी : 1 उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता की तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदनपत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1047 (एफ.सं० मं०/आ०क० (छूट) यदि 111/35(1) (ii) 93]

राजेश मिश्र, उप निदेशक

### INCOME TAX

Calcutta, the 3rd March, 1994

S.O. 2708.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

### NAME OF THE ORGANISATION

Hormone Research Foundation,  
A-8, Vasundhara Enclave,  
B-14, Near Bellupura,  
New Delhi.

This Notification is effective for the period from 19-3-1993 to 31-3-1994.

Notes.—(1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1047/F. No. DG/IT(E)/ND-111/35(1)(ii)93]

R. SINGH, Dy Director

कां०आ० 2709—गठमाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) क खण्ड (iii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है।—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहिया रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "तौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिचर्च किया गया सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब की भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

कृष्णमूर्ति फाउन्डेशन इंडिया, 64, श्रीनवेत्र रोड, मद्रास-600028

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-93 से 31-3-95 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदनपत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1048 (एफ.सं० मं०/आ०क० (छूट) टी.एन-7/35(1)(iii) 89]

राजेश मिश्र, उप निदेशक

### INCOME TAX

Calcutta, the 4th March, 1994

S.O. 2709.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

(i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;

(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology

Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

#### NAME OF THE ORGANISATION

Krishnamurti Foundation India,  
64, Greenways Road,  
Madras-600028.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1995.

Notes.—(1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.  
[No. 1048/F. No. DG/IT(F)/TN-7/35(1)(ii)|89]

[No. 1048/F. No. DG/IT(E)/TN-7/35(1)(iii)|89]  
R. SINGH, Dy. Director

आयकर

कलकत्ता, 4 मार्च, 1994

कांशा० 2710—सर्वसाधारण को एन्टर्प्राइज सूचित किया जाता है कि निम्न-उल्लिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहिया रखेगा।  
(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रोद्यो गिकी भवन" न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और  
(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (फूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (फूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिमच कार्यों सम्बन्धित फूट में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिमाव को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

फ्रेड्रिक पादप संरक्षण एवं टॉक्सिकोलॉजी पाडापाई-601301 चिंगलपुट, तमिलनाडु

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1992 से 31-3-1995 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संस्था" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदित की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (फूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है को माध्यम से आयकर महानिदेशक (फूट), कलकत्ता को मौन प्रतियाँ भेजें और, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संघर्ष में लिए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियाँ सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संस्था : 1049 (एफ.नं० डी.जी.आई/आ०क० (फूट) टीएन-43/35(1)(ii)/90]

राजेश्वर सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 4th March, 1994

#### INCOME TAX

S.O. 2710.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6, of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;  
(ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and  
(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

#### NAME OF THE ORGANISATION

Fredrick Institute of Plant  
Protection and Txicology,  
Padappai-601301,  
Chingleput,  
Dist., Tamil Nadu.

This Notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-1995.

Notes.—(1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1049/F. No. DG/IT(E)/TN-43/35(1)(ii)|90]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 7 मार्च, 1994

Calcutta, the 7th March, 1994

## आयकर

## INCOME TAX

का.आ. 2711.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न-उल्लिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा ;
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा ; और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्यों में सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा ।

## संगठन का नाम

इंदोर कैंसर फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, रातिलक साकेत, इंदौर-452001

यह अधिसूचना दिनांक 16-2-94 से 31-3-96 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है ।

[संख्या . 1050 (एफ०सं० म०नि०/आ०क० (छूट) एमपा-8/35(1)(ii)/93]

राजेश्वर सिंह, उप निदेशक

S.O. 2711.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6, of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year ; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

## NAME OF THE ORGANISATION

Indore Cancer Foundation  
Charitable Trust,  
Raftilak Saket,  
Indore-452002.

This Notification is effective for the period from 16-2-1994 to 31-3-1996.

Notes.—(1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1050/F. No. DG/IT(E)/MP-8/35(1)(ii)93]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 7 मार्च, 1994

## आयकर

का.आ. 2712.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा ;
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव,

वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग,  
“प्रौद्योगिकी भवन”, न्यू मेहरोली रोड, नई  
दिल्ली-110016 को भेजेगा; और

- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्यों से सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

#### संगठन का नाम

एनर फाउंडेशन रिसर्च सेंटर नेशनल हाइवे नं० 8 ग्राम धारगिरि  
पो-कबीरपुर, ता०-नवसारी-396424 गुजरात

यह अधिसूचना दिनांक 4-11-92 से 31-3-94 तक की  
अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (1) “संघ” जैसा संवर्ग के  
लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे  
अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर  
आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्रा-  
धिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से  
आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को  
तान प्रतियां में आवेदन करें, अनुमोदन की  
अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र  
को 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक  
अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना हैं।

[संख्या: 1051/एफ.सं० स.वि०/सा०क० (छूट) जी-61/35(1)(ii)/92]

राजेन्द्र सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 7th March, 1994

#### INCOME TAX

S.O. 2712.—It is hereby notified for general information  
that the organisation mentioned below has been approved by  
the Prescribed Authority under Rule 6, of the Income-tax  
Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of  
Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category  
“Institution” subject to the following conditions :—

- The organisation will maintain separate books of  
accounts for its research activities ;
- It will furnish the Annual Return of its scientific  
research activities to the Secretary, Department of  
Scientific and Industrial Research, “Techno-  
Bhawan”, New Mehrauli Road, New Delhi-110016  
for every financial year by 31st May of each year ;  
and
- It will submit to the (a) Director General of Income-  
tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of  
Scientific and Industrial Research, and (c) Com-  
missioner of Income-tax/Director of Income tax

(Exemptions), having jurisdiction over the organi-  
sation, by the 31st October each year, a copy of  
its audited Annual Accounts and also a copy of  
audited Income and Expenditure Account in respect  
of its research activities for which exemption was  
granted under sub-section (1) of Section 35 of  
Income-tax Act, 1961.

#### NAME OF THE ORGANISATION

Enar Foundation Research Centre,  
National Highway No. 8,  
Village Dharagiri, Post Kabilpore,  
Tal. Navsari-396424, Gujarat.

This Notification is effective for the period from 4-11-1992  
to 31-3-1994.

Notes.—(1) Condition (i) above will not apply to organisations  
categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicate  
and well in advance for further extension of the  
approval, to the Director General of Income-tax  
(Exemptions), Calcutta through the Commissioner  
of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions)  
having jurisdiction over the organisation. Six copies of  
the application for extension of approval should be sent  
directly to the Secretary, Department of Scientific and  
Industrial Research.

[No. 1051/F. No. DG/IT(E)/G-61/35(1)(ii)/92]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 7 मार्च, 1994

#### आयकर

का.भा. 2713.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित  
किया जाता है कि निम्न-उल्लिखित संगठन को, आयकर  
अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के  
खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन  
विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “संस्था”  
संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा-  
बहियां रखेगा ;
- यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों  
का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के  
लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव,  
वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग,  
“प्रौद्योगिकी भवन”, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-  
110016 को भेजेगा; और
- यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-  
परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर  
महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा  
औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर  
आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके  
क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर  
अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई  
रिसर्च कार्यों से सम्बन्धित (छूट) के बारे में लेखा-  
परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत  
करेगा।

## संगठन का नाम

हरिणकर सिंघानिया इलास्टोमर एंड टायर रिसर्च संस्थान पो-  
टायर फैक्टरी, कंकरोली त्रि-राजसामंड, राजस्थान-313 342

यह अधिसूचना दिनांक 15-6-93 से 31-3-94 तक की  
प्रवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के  
लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे  
अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर  
आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके  
क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम  
से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को  
तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की  
अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र  
की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक  
अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[मन्त्रा: 1052 (एफ०स० म०नि०/आ०क० (छूट) आर-13/35(1)  
ii/94]

र.० सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 7th March, 1994

## INCOME TAX

S.O. 2713.—It is hereby notified for general information  
that the organisation mentioned below has been approved by  
the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax  
Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of  
Section 13 of the Income Tax Act, 1961 under the category  
"Institution" subject to the following conditions :—

- (i) The organisation will maintain separate books of  
accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific  
research activities to the Secretary, Department of  
Scientific and Industrial Research, 'Technology  
Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016  
for every financial year by 31st May of each year, and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-  
tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of  
Scientific and Industrial Research, and (c) Com-  
missioner of Income-tax/Director of Income-tax  
(Exemptions), having jurisdiction over the organi-  
sation, by the 31st October each year, a copy of  
its audited Annual Accounts and also a copy of  
audited Income and Expenditure Account in respect  
of its research activities for which exemption was  
granted under sub-section (1) of Section 35 of  
Income-tax Act, 1961.

## NAME OF THE ORGANISATION

Hari Shankar Singhania Elastomer and Tyre Research  
Institute, P.O. Tyre Factory, Kankroli,  
Dist. Rajasamand, Rajasthan-313342.

This Notification is effective for the period from 15-6-1993  
to 31-3-1994.

Notes.—(1) Condition (i) above will not apply to organisations  
categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicate  
and well in advance for further extension of the  
approval, to the Director General of Income-tax

(Exemptions), Calcutta through the Commissioner  
of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions)  
having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of  
approval should be sent directly to the Secretary,  
Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1052/F. No. DG/IT(E)/R-13/35(1)(ii)94]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 8 मार्च, 1994

## आयकर

का.आ. 2714.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित  
किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर  
अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के  
खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन  
विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था"  
संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा  
बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों  
का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के  
लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव,  
वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग,  
"प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरोली रोड, नई  
दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-  
परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर  
महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा  
औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर  
आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके  
क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आय-  
कर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में  
दी गई रिसर्च कार्यों सम्बन्धित (छूट) के बारे  
में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी  
प्रस्तुत करेगा।

## संगठन का नाम

सेन्टर फॉर सोशल स्टडीज, दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय  
कैंपस, उधाना-मगडाला रोड, सूरत (गुजरात)-395007

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1992 से 31-3-1995 तक  
की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पण : 1. उपर्युक्त शर्त (1) 'संघ' जैसा संवर्ग के लिए  
लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की  
अवधि बढ़ाने के लिए आयुक्त आयुक्त/आयकर  
निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता  
है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता  
को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि

बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

कलकत्ता, 9 मार्च, 1994

आयकर

[सं. 1053/एफ सं. म. नि./आ. क. (छूट) जी-47/35-  
(1)(ii)/90-91]

राजेन्द्र सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 8th March, 1994

### INCOME-TAX

S.O. 2714.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

### NAME OF THE ORGANISATION

Centre for Social Studies, South Gujarat University Campus, Udhna-Magdalla Road, Surat (Gujarat)-395007.

This Notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-1995.

NOTES: 1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1053/F. No. DG/IT(E)/G-47/35(1)(ii)/90-91]

R. SINGH, Director

का.आ. 2715 सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा को प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख), सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्यों सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिमाव को भी प्रस्तुत करेगा।

### संगठन का नाम

मद्रास विकास अध्ययन संस्थान,  
7911 मुख्य रोड, गांधी नगर  
मद्रास-600020

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1992 से 31-3-1995 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1 उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

- (2) संगठन को सूचित किया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में दिए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या 1054/एफ.सं. म. नि./आ. क. (छूट)/टीएन-27/  
35(1)(iii)/90-91]

राजेन्द्र सिंह, उप निदेशक



Calcutta, the 9th March, 1994

## INCOME-TAX

S.O. 2715.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

## NAME OF THE ORGANISATION

Madras Institute of Development Studies,  
79 II Main Road, Gandhi Nagar,  
Madras-600020.

This Notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-1995.

NOTES: 1. Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2. The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1054/F. No. DG/IT(E)/TN-27/35(1)(iii)/90-91]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 10 मार्च, 1994

## आयकर

का.आ. 2716:—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा;
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, 'प्रौद्योगिकी भवन', न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा; और

- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख), सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्यों सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

टी. ए. पाई मैनेजमेंट संस्थान,  
मनीपाल-576119, कर्नाटक

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1993 से 31-3-1995 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: (1) उपर्युक्त शर्तें (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

- (2) संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए गए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

संख्या: 1055/एफ. सं. म. नि./आ. क. (छूट) कंटी-43  
35(i) (iii)/93]

राजेन्द्र सिंह, उपनिदेशक

Calcutta, the 10th March, 1994

## INCOME-TAX

S.O. 2716.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

T. A. Pai Management Institute,  
Manipal-576119, Karnataka.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1995.

NOTES: (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1055/F. No. DG/IT(E)/KT-43/35(1)(ii)/93]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 10 मार्च, 1994

आयकर

का.आ. 2717:—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियाँ रखेगा;
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, 'प्रौद्योगिकी भवन, न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016' को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्यों सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

संधाता मेडिकल रिसर्च सोसायटी,  
एक्सटेंशन एरिया, मिराज-416410  
महाराष्ट्र स्टेट

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1993 से 31-3-1995 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

(2) संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर के महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करे, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या 1056/ए.सं.म.नि./आ.क. (छूट) एम-44/  
35(1)(ii)/89]

राजेन्द्र सिंह, उपनिदेशक

Calcutta, the 10th March, 1994

INCOME-TAX

S.O. 2717.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

NAME OF THE ORGANISATION

Sandhata Medical Research Society,  
Extension Area, Miraj-416410,  
Maharashtra State.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1995.

NOTES:

- (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1056/F. No. DG/IT(E)/M-44/35(1)(ii)/89]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 10 मार्च, 1994

Calcutta, the 10th March, 1994

## आयकर

का.आ. 2718.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा-बहियां रखेगा;
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग 'प्रौद्योगिकी भवन', न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा; और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (फूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (फूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्यों सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

## संगठन का नाम

मराठे रिसर्च फाउंडेशन,  
नन्दन एनक्लेव,  
श्री गोविन्दरागी मराठे रोड,  
मोरा जिला-सांगली,  
(महाराष्ट्र राज्य) पिन-416410

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1993 से 31-3-1995 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

(2) संगठन को सुभाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए, आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (फूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (फूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या 1057 /एफ ग. म. नि./आ. क. (फूट)/  
35(1) (ii) 90]

राजेंद्र सिंह, उपनिदेशक

## INCOME-TAX

S.O. 2718.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

## NAME OF THE ORGANISATION

Marathe Research Foundation,  
Nandan Enclave, Shri Govindragi,  
Marathe Road, Mira, Distt. Sangli,  
(Maharashtra State), Pin-416410.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1995.

## NOTES:

- (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1057/F. No. DG/IT(E)/M-81/35(1)(ii)/90]

R. SINGH, Dy. Director.

कलकत्ता, 10 मार्च, 1993

## आयकर

का. आ. 2719.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा-बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए,

प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दो गई रिसर्च कार्यों सम्बन्धी छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

#### संगठन का नाम

एफ आई इ रिसर्च संस्थान,  
गंगानगर पो.—इचालकरजी-416001  
(महाराष्ट्र)

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1994 से 31-3-1995 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी:—1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या: 1058/एफ.सं. म.नि./आ.क. (छूट)एम-74/  
35(1)(ii)(89)]

राजेन्द्र सिंह, उपनिदेशक

Calcutta, the 10th March, 1994

#### INCOME-TAX

S.O. 2719.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary Department of Scientific & Industrial Research, 'Technological Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

- (iii) It will submit to the (a) Director General of income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

#### NAME OF THE ORGANISATION

FIE Research Institute,  
Ganganagar P.O.,  
Ichalkaranji-416001,  
(Maharashtra).

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1995.

#### NOTES:

- (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.
- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1058/E, No. DG/IT(E)/M-74/35(1)(ii)/89]

R. SINGH, Dy. Director.

कलकत्ता 15 मार्च, 1994

#### आयकर

का. घा. 2720.—सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहिया रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दो गई रिसर्च कार्यों संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

## संगठन का नाम

इंडियन रजिस्टर आफ शिपिंग  
72, मेकर टावर्स "एफ"  
(आठवीं मंजिल) कुफे परेड,  
बम्बई-400005

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1993 से 31-3-1995 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संघों के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता की तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन का अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, 'ज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान' विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या: 1059/एफ सं. म. नि. आ. क. (छूट)एम-2  
35(i)(ii)/89]

राजेंद्र सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 15th March, 1994

## INCOME-TAX

S.O. 2720.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:

- The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research 'Technology Bhawan' New Mehrauli Road, New Delhi-110 016 for every financial year by 31st May of each year; and
- It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its Research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act 1961.

## NAME OF THE ORGANISATION :

Indian Register of Shipping,  
72 Maker Towers 'F' (7th Floor),  
Cuffe Parade, Bombay-400 005.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1995.

NOTES (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

2241 GI/94—3.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1059/F. No. DG/IT(E)/M-2/35(1)(ii)/89]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 18 मार्च, 1994

## आयकर

का. आ. 2721 :—सर्वसाधारण को एनड्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर प्रवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

- (1) संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त धन के लिए एक अलग लेखा रखेगा;
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्य-कलापों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा; और
- (3) यह प्रत्येक वर्ष को 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसच क्रियाकलाप सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

## संगठन का नाम

नेशनल अकादमी आफ मेडिकल सर्विसेज (इंडियन)  
अन्सारी नगर, महात्मा गांधी मार्ग,  
नई दिल्ली-110029

यह अधिसूचना दिनांक 22-10-91 से 31-3-94 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी :—1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा प्रवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि व अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 1060/फा.सं. डी.जी./आ. कर (छूट) एनडी-114/  
कल./35/(1)(ii)/93]

राजेंद्र सिंह, उपनिदेशक

Calcutta, the 18th March, 1994

### INCOME-TAX

S.O. 2721.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research "Technology Bhawan" New Mehrauli Road, New Delhi-110 016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of its audited Income and Expenditure Account in respect of its Research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act 1961.

### NAME OF THE ORGANISATION :

National Academy of Medical Sciences (India),  
Ansari Nagar, Mahatma Gandhi Marg,  
New Delhi-110 029.

This Notification is effective for the period from 28-10-1991 to 31-3-1994.

NOTES (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1060/F. No. DG/IT(E)/ND-114/35(I)(ii)/93]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 18 मार्च, 1994

आयकर

का.भा. 2722:—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के गण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" शर्तों के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

- (1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए, अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा; और
- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग; और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है, और आयकर अधिनियम, 1944 की धारा 35(1) में दी गई रिक्त स्थानों को सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय विवरण के साथ प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

आर्य इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन सोमराटी फॉर प्रोमोशन ऑफ मेडिकल रिसर्च, हाजी अमीरी पार्क महालक्ष्मी, बम्बई-400034.

यह आधिसूचना दिनांक 1-4-1993 से 31-3-1994 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्तें (1) "सब" शर्तों के लिए लागू नहीं होंगी।

- 2 संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संस्था 19661/फा.सं. सचि/आ. कर (छूट) एन-134/35(i)(ii)/90]

राजेंद्र सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 18th March, 1994

### INCOME-TAX

S.O. 2722.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research "Technology Bhawan" New Mehrauli Road, New Delhi-110 016 for every financial year by 31st May of each year; and

(iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its Research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act 1961.

#### NAME OF THE ORGANISATION :

All India Institute of Physical Medicine,  
and Rehabilitation Society for Promotion,  
of Medical Research, Haji Ali Park,  
Mahalaxmi, Bombay-400 034.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1994.

NOTES (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1061/F. No. DG/IT(E)/M-134/35(1)(ii)/90]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 18 मार्च, 1994

आयकर

का.भा. 723:—संबंधाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए, अनिवार्य लेखा बहियाँ रखेगा;
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा; और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दो गई रिमर्क क्रियाकलाप सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

इंडियन कौंसिल फॉर रिसर्च ऑफ इंटरनेशनल इकात्मिक रिलेशन  
40, लोदी एस्टेट, नयी दिल्ली-110008

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1993 से 31-3-1994 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्तें (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होंगी।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन के अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता का तीन प्रतियाँ भेजें। प्रत्येक प्रतियाँ में अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए गए प्रवेदन-पत्र का 6 प्रतियाँ सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या 1062/एफ.सं. म नि/आ क (छूट)/एन डी-23 35 (1)(iii)/89]

राजेन्द्र सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 18th March, 1994

#### INCOME-TAX

S.O. 2723.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research 'Technology Bhawan' New Mehrauli Road, New Delhi-110 016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its Research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act 1961.

#### NAME OF THE ORGANISATION :

Income-tax Act, 1961.  
International Economic Relations.  
40, Lodi Estate, New Delhi-110003.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1994.

NOTES: (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1062/F. No. DG/IT(E)/ND-23/35(1)(iii)/89]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 22 मार्च, 1994

## आयकर

का.आ. 2724:—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा;
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा; और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च ब्याकलाप सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय विवरण को भी प्रस्तुत करेगा।

## संगठन का नाम

नैशनल सेंटर फार सॉफ्टवेयर टेक्नालॉजी, गुलमोहर ज़ास रोड, संख्या-9, जुहू, बम्बई-400049

यह अधिपूचना दिनांक 1-4-1992 से 31-3-1995 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में भेजें और, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या 1063/एफ सं मनि/आ क (छूट)/एम-22/35 1(ii)/89]

राजेंद्र सिंह, उप निदेशक

Calcutta, the 22nd March, 1994

## INCOME-TAX

S.O. 2724.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 5 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research "Technology Bhawan", New Mehrauli Road, New Delhi-110 016 for every financial year by 31st May of each year; and

- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific and Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act 1961.

## NAME OF THE ORGANISATION :

National Centre for Software Technology,  
Gulmohar Cross Road No. 9, Juhu,  
Bombay-400 049.

This Notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-1995.

NOTES: (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1063/F. No. DG/IT(E)/M-22/35(1)(ii)/89]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता 22 मार्च 1994

## आयकर

का.आ. 2725:—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

- (1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा; और
- (3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्च ब्याकलाप सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय विवरण को भी प्रस्तुत करेगा।

## संगठन का नाम

मैटैरिअल्स रिसर्च सोसाइटी आफ इंडिया (एम आर एस आई),  
के./भा-डिफेन्स मसालाजुल रिसर्च लैबोरेटरी, पो. कंचनबाव  
हैदराबाद-500258



यह अधिसूचना दिनांक 30-9-1991 से 31-3-1993 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

कलकत्ता, 22 मार्च, 1994

आयकर

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

- संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या 1064/एफ सं.मं.नि./आ.क. (छूट) एपी-15/35 (1) (ii)/91]

राजेंद्र सिंह, उपनिदेशक

Calcutta, the 22nd March, 1994

### INCOME-TAX

S.O. 2725.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110 016 for every financial year by 31st May of each year; and
- It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

### NAME OF THE ORGANISATION :

Materials Research Society of India (MRSI),  
C/o. Defence Metallurgical Research Laboratory,  
P. O. Kanchanbagh, Hyderabad-500 258.

This Notification is effective for the period from 30-9-1991 to 31-3-1993.

NOTES (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

- The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1064/F. No. DG/IT(E)/AP-15/35(1)(ii)/91]

R. SINGH, Dy. Director.

का.आ. 2726:—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न-उल्लिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा;
- यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा; और
- यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षण वार्षिक लेखाकी प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्च किया-कलाप सम्बन्धित (छूट) के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

### संगठन का नाम

मैटीरिअल्स रिसर्च सोसाइटी आफ इंडिया (एमआरएसआई)  
के./आ.-डिफेंस मेटालर्जिकल रिसर्च लैबोरेटरी पो.-कंचनबाग  
हैदराबाद-500258

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-93 से 31-3-96 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

- संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1065/एफ सं. म.नि./आ.क. (छूट)/  
एपी-15/35 (1) (ii)/91]

राजेंद्र सिंह, उपनिदेशक

Calcutta, the 22nd March, 1994

## INCOME-TAX

S.O. 2726.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110 016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, and (c) commissioner of Income-tax [Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation], by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

## NAME OF THE ORGANISATION :

Materials Research Society of India (MRSI),  
C/o. Defence Metallurgical Research Laboratory,  
P. O. Kanchanbagh, Hyderabad-500 258.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1996.

NOTES (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax [Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1065/F. No. DG/IT(E)/AP-15/35(1)(ii)/91]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 22 मार्च, 1994

आयकर

का०आ० 2727.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न-उल्लिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए शलग लेखा बहियां रखेगा;
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग,

"प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा; और

- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्तूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दो गई रिमर्च क्रिया-कलापों सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

## संगठन का नाम

आयबैजिज रिसर्च सेंटर फाउंडेशन, 4, मेन रोड, रोयापुरम,  
मद्रास-600013

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-94 से 31-3-95 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (i) "संव" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट), जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है, के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र को 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[सं. 1066/फा.सं.म.नि./आ.क. (छूट)/टीएन-18/35(1)  
(ii)/89]

राजेंद्र सिंह, उपनिदेशक

Calcutta, the 22nd March, 1994

## INCOME-TAX

S.O. 2727.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110016 for every financial year by 31st May of each year; and

- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act 1961.

#### NAME OF THE ORGANISATION :

Diabetes Research Centre Foundation,  
4, Main Road, Royapuram,  
Madras-600 013.

This Notification is effective for the period from 1-4-1994 to 31-3-1995.

NOTES: (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1066/F. No. DG/IT(E)/TN-18/35(1)(II)/89]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 22 मार्च, 1994

आयकर

का.आ. 2728.—सर्वसाधारण को एवद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन लिखित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" शब्दों के अधीन प्रत्येक वर्ष प्रमाणित किया गया है:—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अपना लेखा-परीक्षण वार्षिक

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षण वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई छूट काव्यों संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षण मास-मास विवरण को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, पोस्ट बॉक्स नं.-8313, सायन-ट्राम्बे रोड, देवनार, बम्बई-400088।

यह अधिसूचना 1-4-93 से 31-3-96 तक प्रभावी रहेगी।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्तें (i) "संव" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होंगी।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुसंधान की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महा-निदेशक (छूट), भारत सरकार के वित्त विभाग में आवेदन एवं अनुमोदन की प्रवृत्ति बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या 1067/एफ.सं.म. नि./आ.क. (छूट)एम. 96/35(1) (iii) 90]  
रा० सिंह, उपनिदेशक

Calcutta, the 22nd March, 1994

INCOME-TAX

S.O. 2728.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110 016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act 1961.

#### NAME OF THE ORGANISATION :

Tata Institute of Social Sciences,  
Post, Box No. 8313, Sion-Trombay Road,  
Deonar, Bombay-400 088.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1996.

NOTES: (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax|Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1067/F. No. DG/IT(E)/M-96/35(1)(iii)/90]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 23 मार्च, 1994

Calcutta, the 23rd March, 1994

## आयकर

का. आ. 2729.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “संस्था” संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा ।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, “प्रौद्योगिकी भवन” न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्यों सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिमाब को भी प्रस्तुत करेगा ।

## संगठन का नाम

विवेकानन्द मेडिकल रिसर्च सोसाइटी, विद्यानगर, लातूर-413531 (महाराष्ट्र)

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-93 से 31-3-95 तक की अवधि के लिए प्रभावी है ।

टिप्पणी:—

1. उपर्युक्त शर्त (1) “संघ” जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा ।
2. संगठन को सूत्राव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है ।

[संख्या : 1068/एफ. सं. म. नि./आ. क. (छूट)  
एम-15/35(1) (ii) 89]

रा. सिंह, उपनिदेशक

## INCOME-TAX

S.O. 2729.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority, under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category “Association” subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research “Technology Bhawan”, New Mehrauli Road, New Delhi-110 016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

## NAME OF THE ORGANISATION :

Vivekanand Medical Research Society,  
Vidya Nagar Latour-413 531,  
(Maharashtra).

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1995.

NOTES: (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval to the Director General of Income-tax (Exemptions) Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1068/F. No. DG/IT(E)/M-15/35(1)(ii)89]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 23 मार्च, 1994

## आयकर

का. आ. 2730—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “संघ” संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा ;

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन” न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा ; और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट) (ख), सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार के उक्त संगठन पड़ता है। और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्च क्रिया-क्लाप सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

किम्बकर कृषि शोध संस्थान पो. बाक्स 44,  
फालनाभ पिन-415523 (महाराष्ट्र)

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1993 से 31 मार्च 1994 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी:— 1 उपयुक्त शर्त (i) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या 1069 /एफ सं. म. नि./आ.क. छूट एम-16  
35 (i) (ii)/89]

राजन्द्र सिंह, उपनिदेशक

Calcutta, the 23rd March, 1994

#### INCOME-TAX

S.O. 2730.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act 1961 under the category "Association" subject to the following conditions:

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110 016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act 1961.

#### NAME OF THE ORGANISATION :

Niwbkar Agricultural Research Institute,  
P. O. Box 44, Phaltan,  
Pin. 415 523 (Maharashtra).

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1994.

NOTES (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

- (2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions) Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1069/F. No. DG/IT(E)/M-16/35(i)(ii)/89]  
R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता 23 मार्च, 1994

आयकर

का. आ. 2731—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहिया रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग प्रौद्योगिकी भवन न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली 110016 को भेजेगा और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है, और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च क्रिया क्लाप सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

श्री जयदेव इन्स्टिट्यूट आफ कार्डियोलॉजी रिकवरी हास्पिटल कम्प्लेक्स बंगलौर 560002

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1993 से 31-3-1995 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी:—1. उपयुक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2 संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वह अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता की तीन प्रतियों में आवेदन करे, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या 1070 /एफ. सं. म. नि. /आ. क.  
केटी-32/35 (i) (ii) / 90]

राजेन्द्र सिंह, उपनिदेशक

Calcutta, the 23rd March, 1994

### INCOME-TAX

S.O. 2731.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110 016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

### NAME OF THE ORGANISATION :

Sri Jayadeva Institute of Cardiology, Victoria Hospital Complex Bangalore-560 002.

This Notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-1995.

NOTES : (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1070/F. No. DG/IT(F)/KT/32/35(1)(ii)90]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 21 मार्च, 1994

आयकर

का.आ. 2732:—सर्वसाधारण की सूचना सूचित किया जाता है कि निम्न-उल्लिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड ( ) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संघ" संवर्ग के अधीन अनुमोदन किया गया है :—

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए खर्च लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) वह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महा-निदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिमर्च कार्यों सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिमात्र को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

शायबेटिक एशोसिएशन आफ इंडिया मानकेजीवाडिया बिल.,

फास्ट फ्लोर

127, एम.सी. रोड, फोर्ट,

बम्बई-400001

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1995 से 31-3-1997 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता की तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1071 /एफ. सं. म. नि. /आ. क. (छूट)

एम-56/35 (1) (ii)/89]

राजेन्द्र सिंह, उपनिदेशक

Calcutta, the 24th March, 1994

## INCOME-TAX

S.O. 2732. It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Association" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110 016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

## NAME OF THE ORGANISATION :

Diabetic Association of India, Maneckji Wadja Bldg., 1st Floor, 127, M.G. Road, Fort, Bombay-400 001.

This Notification is effective for the period from 1-4-1995 to 31-3-1997.

NOTES : (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1071/F. No. DG/IT(F)/M-56/35(1)(ii)/89]

R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 24 मार्च, 1994

आयकर.

का.आ. 2733:— सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न-उल्लिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संव" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया :—

- (1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।

- (i) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिक भवन"

न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

- (ii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्च कार्यों सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिस्सा को भी प्रस्तुत करेगा।

## संगठन का नाम

नोकमाम्य तिलक हॉस्पिटल सिलवर जुबली रिसर्च फाउंडेशन,

एल.टी.एम.जी. हॉस्पिटल मायन,

बम्बई-400022

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1992 से 31-3-1995 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संव" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1072 /एफ सं. म.नि./आ.क. (छूट)/एम-104/35(1) (ii)/90]

राजेन्द्र सिंह, उपनिदेशक

Calcutta, the 24th March, 1994

## INCOME-TAX

S.O. 2733.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;

- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110 016 for every financial year by 31st May of each year; and

- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

#### NAME OF THE ORGANISATION :

Lokmanya Tilak Hospital Silver Jubilee Research Foundation, L.T.M.G. Hospital Sion, Bombay-400 022.

This Notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-1995.

NOTES: (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1072/F. No. DG/IT(E)/M-104/35(1)(ii)/90]  
R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 25 मार्च, 1994

आयकर

का.आ.2734:- सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न उल्लिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :-

- (1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखाबहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, 'प्रौद्योगिकी भवन' न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्च कार्यों सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

स्पैसिफिक सोसाइटी आफ इंडिया,  
अपर कोलाबा रोड,  
अपो. अफगान चर्च, कोलाबा, बम्बई-400005

यह अधिमूचना दिनांक 1-4-1993 से 31-3-1996 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संघ" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

- 2 संगठन का सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1073 /एफ सं. म.नि./आ.क. (छूट)  
एम-52/35 (1) (ii)/89]

राजेंद्र सिंह, उपनिदेशक

Calcutta, the 25th March, 1994

#### INCOME-TAX

S.O. 2734.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110 016 for every financial year by 31st May of each year ; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

#### NAME OF THE ORGANISATION :

The Spectice Society of India, Upper Colaba Road, Opp. Afghan Church, Colaba, Bombay-400 005.

This Notification is effective for the period from 1-4-1993 to 31-3-1996.

NOTES: (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.



(2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.

[No. 1073/F. No. DG/IT(E)/M-52/35(1)(ii)/89]  
R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 28 मार्च, 1994

आयकर

का.आ. 2735:—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न उल्लिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर “संघ” संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया :-

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, “प्रौद्योगिकी भवन” न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्च कार्यों सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

संगठन का नाम

सेरम इंस्टिट्यूट आफ इंडियन,  
रिसर्च फाउन्डेशन (एस आई आई आर एफ) सरोश भवन  
16 बी/1, डॉ आम्बेकर रोड  
पूना-411001।

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1994 से 31-3-1995 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: 1 उपर्युक्त शर्त (i) “संघ” जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार

में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1074/एफ सं. म.नि./आ.क. (छूट)  
एम-41/35 (1) (ii)/89]

राजेन्द्र सिंह, उपनिदेशक

Calcutta, the 28th March, 1994

#### INCOME-TAX

S.O. 2735.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category “Association” subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, “Technology Bhawan”, New Mehrauli Road, New Delhi-110 016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exception was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

#### NAME OF THE ORGANISATION :

Serum Institute of India Research Foundation (SIIRF),  
Sarosh Bhavan, 16B/1, Dr. Ambedkar Road, Pune-411 001.

This Notification is effective for the period from 1-4-1994 to 31-3-1995.

Notes : (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1074/F. No. DG/IT(E)/M-41/35(1)(ii)/89]  
R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 29 मार्च, 1994

आयकर

का.आ. 2736:— सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (iii) के

लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :-

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च फ्रिक्वाक्लाप सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

#### संगठन का नाम

इंदिरा गांधी नैशनल सेंटर फार द आर्ट्स,  
सी.वी. मस, जनपथ,  
नयी दिल्ली-110001

यह अधिनूचना दिनांक 1-4-1994 से 31-3-1995 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी: 1 उपर्युक्त शर्त (i) "संव" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

- 2 संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियां में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1075 /एफ सं. म.नि./आ.क. (छूट)  
एन डी-22 /35/(1) (iii)/89]

राजेन्द्र सिंह, उपनिदेशक

Calcutta, the 29th March, 1994

#### INCOME-TAX

S.O. 2736.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35

of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110 016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

#### NAME OF THE ORGANISATION :

Indira Gandhi National Centre for the Arts, C. V. Mess,  
Janpath, New Delhi-110 001.

This Notification is effective for the period from 1-4-1994 to 31-3-1995.

Notes : (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1075/F. No. DG/IT(E)/ND-22/35(1)(iii)/89]  
R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 29 मार्च, 1994

आयकर

का.आ. 2737:- सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न उल्लिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के लिए आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :-

- (i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।
- (ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली 110016 को भेजेगा, और
- (iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानि-

निदेशक (छूट), (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (1) में दी गई रिसर्च कार्यकलाप सम्बन्धित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

#### संगठन का नाम

कैरेंट साइंस एसोसियेशन,  
पी. बी. 80001, सी.वी. रमन एवेन्यू,  
सदाशिवनगर,  
बंगलूर-560080

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1992 से 31-3-1995 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1 उपर्युक्त शर्त (1) "संव" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2 संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनु-मोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है के माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियों में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध के लिए आवेदन-पत्र को 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1076/एफ. सं. म. नि./प्रा. क. (छूट)  
के. टी.-27/35 (1)(ii)/90]

राजेंद्र सिंह, उपनिदेशक

Calcutta, the 29th March, 1994

#### INCOME-TAX

S.O. 2737.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110 016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of

its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

#### NAME OF THE ORGANISATION

Current Science Association, P.B. 80001, C. V. Raman Avenue, Sadashivanagar, Bangalore-560 080.

This Notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-1995.

NOTES: (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1076/F. No. DG IT(E)/KT-27/35(1)(ii)/90]  
R. SINGH, Dy. Director

कलकत्ता, 29 मार्च, 1994

#### आयकर

का.प्रा. 2738.—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्न उल्लिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संस्था" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है:—

(1) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए अलग लेखा बहियां रखेगा।

(2) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरौली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(3) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट) (ख) सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्यकलाप संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

#### संगठन का नाम

भारतीय मनोविज्ञान संस्थान  
'एवरश्रीत प्लाजा' (सेकेंड टु फिफथ फ्लोर)  
117, बी. टी. रोड, कलकत्ता-700035

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1992 से 31-3-1995 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संव" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

कलकत्ता, 29 मार्च, 1994

आयकर

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है कि माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियां में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1077 /एफ. सं. म. नि./आ.क. (छूट) प.बं-7/35(1) (iii) 89]

राजेंद्र सिंह, उपनिदेशक

Calcutta, the 29th March, 1994

#### INCOME-TAX

S.O. 2738.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110 016 for every financial year by 31st May of each year; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

#### NAME OF THE ORGANISATION

Indian Institute of Psychometry 'Evergreen Plaza' (2nd to 5th Floors), 117, B. T. Road, Calcutta-700 035.

This Notification is effective for the period from 1-4-1992 to 31-3-1995.

Notes : (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1077/F. No. DG/IT(E)/WB-7/35(1)(iii)/89]

R. SINGH, Dy. Director

का.आ. 2739 .—सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित संगठन को, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (i) के खंड (iii) के लिए, आयकर नियम के नियम 6 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर "संगठन" संवर्ग के अधीन अनुमोदित किया गया है :—

(i) संगठन अनुसंधान कार्यों के लिए प्रलग लेखा बहियां रखेगा।

(ii) यह अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों का एक वार्षिक विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के 31 मई तक सचिव, वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान विभाग, "प्रौद्योगिकी भवन" न्यू मेहरोली रोड, नई दिल्ली-110016 को भेजेगा, और

(iii) यह प्रत्येक वर्ष के 31 अक्टूबर तक लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखा की प्रति (क) आयकर महानिदेशक (छूट), (ख) सचिव वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग और (ग) आयकर आयुक्त/आयकर महानिदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त संगठन पड़ता है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35(1) में दी गई रिसर्च कार्य-कलाप संबंधित छूट के बारे में लेखा-परीक्षित आय-व्यय हिसाब को भी प्रस्तुत करेगा।

#### संगठन का नाम

भारतीय साइकोमेट्री संस्थान

'एवरग्रीन प्लाजा' (मेकेंडू फ्लोर)

117, बी.टी.रोड

कलकत्ता-700035

यह अधिसूचना दिनांक 1-4-1995 से 31-3-1996 तक की अवधि के लिए प्रभावी है।

टिप्पणी : 1. उपर्युक्त शर्त (1) "संव" जैसा संवर्ग के लिए लागू नहीं होगा।

2. संगठन को सुझाव दिया जाता है कि वे अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के लिए आयकर आयुक्त/आयकर निदेशक (छूट) जिनके क्षेत्राधिकार में संगठन पड़ता है कि माध्यम से आयकर महानिदेशक (छूट), कलकत्ता को तीन प्रतियां में आवेदन करें, अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के संबंध में किए आवेदन-पत्र की 6 प्रतियां सचिव वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को प्रस्तुत करना है।

[संख्या : 1078 /एफ. सं. म. नि./आ.क. (छूट) प.बं-7/35(1) (iii)/89]

राजेंद्र सिंह, उपनिदेशक

Calcutta, the 29th March, 1994

## INCOME-TAX

S.O. 2739.—It is hereby notified for general information that the organisation mentioned below has been approved by the Prescribed Authority under Rule 6 of the Income-tax Rules, for the purposes of clause (iii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income Tax Act, 1961 under the category "Institution" subject to the following conditions :

- (i) The organisation will maintain separate books of accounts for its research activities ;
- (ii) It will furnish the Annual Return of its scientific research activities to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research, 'Technology Bhawan', New Mehrauli Road, New Delhi-110 016 for every financial year by 31st May of each year ; and
- (iii) It will submit to the (a) Director General of Income-tax (Exemptions), (b) Secretary, Department of Scientific & Industrial Research and (c) Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions), having jurisdiction over the organisation, by the 31st October each year, a copy of its audited Annual Accounts and also a copy of audited Income and Expenditure Account in respect of its research activities for which exemption was granted under sub-section (1) of Section 35 of Income-tax Act, 1961.

## NAME OF THE ORGANISATION :

Indian Institute of Psychometry 'Evergreen Plaza' (2nd to 5th Floors), 117, B. T. Road, Calcutta-700 035.

This Notification is effective for the period from 1-4-1995 to 31-3-1996.

NOTES : (1) Condition (i) above will not apply to organisations categorised as associations.

(2) The organisation is advised to apply in triplicate and well in advance for further extension of the approval, to the Director General of Income-tax (Exemptions), Calcutta through the Commissioner of Income-tax/Director of Income-tax (Exemptions) having jurisdiction over the organisation. Six copies of the application for extension of approval should be sent directly to the Secretary, Department of Scientific & Industrial Research.

[No. 1078/F. No. DG/IT(E)/WB-7/35(1)(iii)/89]

R. SINGH, Dy. Director

(अधिकार्य विभाग)

(बीमा खंड)

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1994

का.आ. 2740.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम 1985 के नियम 13 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्धारित करती है कि वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों में से प्रत्येक को 1 अप्रैल, 1993 को आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए बोनस के बदले में संदाय, उक्त उपनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसके संबलम के 15 प्रतिशत की दर पर किया जाएगा।

[फा. सं. 2(7)/बीमा-3/94]

तरलोक चन्द नन्दा, अव्वर सचिव

(Department of Economic Affairs)  
INSURANCE DIVISION

New Delhi, the 27th September, 1994

S.O. 2740.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 13 of the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985, the Central Government hereby determine that, subject to the other provisions of the said sub-rule, the payment in lieu of bonus for the period commencing on the 1st day of April, 1993 and ending with 31st day of March, 1994 to every Class III and Class IV employee shall be at the rate of 15 per cent of his salary.

[F. No. 2(7)/Ins. III/94]

T. C. NANDA, Under Secy.

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1994

का.आ. 2741.—बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंध इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 31 मार्च, 1996 तक जयपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. जयपुर (राजस्थान) पर लागू नहीं होंगे।

[एफ. सं. 1/1/94-ए.सी.]

एम. एल. कुक्रेजा, अव्वर सचिव

(Banking Division)

New Delhi, the 27th September, 1994

S.O. 2741.—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) the Central Government on the recommendations of the Reserve Bank of India declares that the provisions of sub-section 1 of Section 11 of the said Act shall not apply to the Jaipur Central Co-operative Bank Ltd., Jaipur (Rajasthan) from the date of publication of this notification in the official Gazette to 31 March 1996.

[F. No. 1-1/94-AC]

M. L. KUKREJA, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1994

का.आ. 2742.—बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबंध केनरा बैंक बंगलौर पर 10 नवंबर, 1996 तक की अवधि के लिए उस सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहां तक उनका संबंध गिहवीदार के रूप में मैमर्स रुबी रखर ववर्स लि. (परिसमापनाधीन) की 30% से अधिक की चुकता शेयर पूंजी की उसकी धारिता से है।

[सं. 15/3/88-बी.ओ.-iii]

वी. एल. सचदेव, अव्वर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 28th September, 1994

S.O. 2742.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (2) of Section 19 of the said Act shall not apply to Canara Bank, Bangalore for a period upto 10th November, 1996 in so far as they relate to its holding of the shares in M/s. Ruby Rubber Works Ltd. (in liquidation) in excess of 30% of the paid up share capital of the company as pledgee.

[No. 15/3/88-B.O.II]

B. L. SACHDEVA, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1994

का.आ. 2743.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 3 के साथ पठित, निर्यात

(क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर चुके हुए, केन्द्रीय सरकार अधिसूचना सं. 3(i)/26/93-ई.आई.एंड.ई.पी. तारीख 19 अगस्त, 1993 में रूपांतर करते हुए श्री आर. चन्द्रशेखर संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय को श्री जे. के. बागची, के स्थान पर निर्यात निरीक्षण परिषद का एतद्वारा चुनित अध्यक्ष नियुक्त करती है।

[फाइल संख्या-3(i) 48/94-ई.आई.एंड.ई.पी.]

कुमारी सुमा सुब्बाना, निदेशक

## MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 28th September, 1994

S.O. 2743.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), read with Rule 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, the Central Government, in modification of Notification No. 3(i)/26/93-EI&EP dated 19-8-1993 hereby appoints Shri R. Chandrashekhar, Joint Secretary, Ministry of Commerce, as Chairman of the Export Inspection Council with immediate effect, vice Shri J. K. Bagchi.

[File No. 3(i)/48/94-EI&amp;EP]

KUM. SUNA SUBBANNA, Director

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

भारतीय मानक ब्यूरो

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1994

का.आ. 2744.—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम 1988 के विनियम 5 के उपविनियम (6) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि निम्न विवरण वाले लाइसेंस/लाइसेंसों को उनके आगे दर्शायी गई तारीख से रद्द कर दिया गया है।

लाइसेंस सं.	लाइसेंस धारी का नाम और पता	लाइसेंस में बिग गे प्रक्रम/वस्तु सम्बद्ध भारतीय मानक सहित	रद्द किए जाने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1. 0628955	श्री ईसबहार अलवाय स्टील्स इन्दौर	आईएस: 2062-1992	आईएस: 226-1975 के अतिक्रमण होने के कारण 1993-05-01 से रद्द
2. 0657962	फेरोस इंजीनियर राजकोट	आईएस: 10001: 1981	कर्म की रूचि न होने के कारण 1993-04-01 से रद्द।
3. 0731948	रायपुर आईस्टील एंड वायस बेल्ट इंडस्ट्रीज रायपुर	आईएस 2062-1992	आईएस: 226-1975 के अतिक्रमण होने के कारण 1993-05-01 रद्द।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. 0772457	हरयाणा मेटल एण्ड रि-रोलिंग मिल्स लि०, बम्बई	आईएस : 226-1975	आईएस : 2062 के आईएस : 223 के अतिक्रमण होने के कारण 1993-05-01 से रद्द।	
5. 0875467	सेव्हीटीट्यूब्स लि०, सेंक्टर 26, रोहतक रोड भिवानी	आईएस 1239(भाग 1) 1990	फर्म से अनुरोध पर लाइसेंस 1990-05-16 से रद्द	
6. 0955566	कयना इंडस्ट्री राजकोट	आईएस : 10001-1981	फर्म की रुचि न होने के कारण 1993-04-01 से रद्द।	
7. 0979075	जयी पीवीसी पाइपस प्रा० लि०, जलगांव	आईएम 4985-1988	प्रसामकों के बदलने के कारण 1993-04-01 से रद्द।	
8. 1058339	अडवानी ओरलिकोन लि. मद्रास	आईएस : 814-1991	मानक के विलय के कारण 1993-03-31 से रद्द।	
9. 1099757	मुरका इंटरप्राइस कोटर	आईएस : 398 (भाग 2)- 1976	फर्म की रुचि न होने के कारण 1993-04-19 से रद्द।	
10. 1123839	एसोसिएटेड एरोमिशन लि. उज्जैन	आईएस : 4956-1977	फर्म की रुचि न होने के कारण 1993-04-01 से रद्द।	
11. 1123930	जेय फूड प्राडक्ट बंगलौर।	आईएम : 1011-1992	फर्म का लाइसेंस त्याग के कारण 1993-06-02 से रद्द।	
12. 1251131	मोदी आर्क इलेक्ट्रोड्स कं०, मोदी नगर	आईएस : 814 (भाग 2)-	फर्म की रुचि न होने के कारण 1992-02-28 से रद्द।	
13. 1264645	जे.के. जूट मिल्स कं. लि., कालपी रोड, कानपुर	आईएस : 258-1967	फर्म के अनुरोध पर 1993-04-01 से रद्द।	
14. 1322936	नोदर्न मिनरल्स लि. गुडगांव, (हरियाणा)।	आईएस : 1308-1984	भारत सरकार के अनुरोध पर पिपत्र के द्वारा एल्यूमीनियम का प्रयोग भारत में धीरे-धीरे समाप्त करने के कारण 1993-04-01 से रद्द	
15. 1395054	प्राइमर इलेक्ट्रोड्स प्रा. लि. नासिक	आईएस : 814(भाग 2) 1994	मानक के पुनरीक्षित होने और आईएस : 814-1994 में विलय होने के कारण 1991-11-01 से रद्द।	
16. 1422940	गुरु नानक इंजी. वर्क्स, कैथल रोड, पेहोवा।	आईएस : 9020-1979	लाइसेंसधारी की इच्छा पर 1993-04-01 से रद्द।	
17. 1457959	मोतीलाल पदमापत उद्योग लि., गुटाइया, कानपुर।	आईएस : 10633-1986	1993-03-06 से रद्द।	
18. 1688574	वोएनसी इलेक्ट्रोड्स मद्रास	आईएस : 814-1991	मानक में सम्मिलित होने के कारण 1993-05-15 से रद्द।	
19. 1698274	नॉदर्न स्टील एण्ड जनरल मिल्स, नई दिल्ली।	आईएस : 2062-1992	आईएस : 226-1975 के अतिक्रमण के कारण 1993-05-01 से रद्द।	
20. 1710642	साल्वो कंडक्टर्स प्रा. लि., सिलवाना-396230	आईएस : 398 (भाग 2)- 1976	फर्म की रुचि न होने के कारण 1993-04-01 से रद्द।	
21. 1721849	राहुल कंटेनर्स प्रा. लि., धार	आईएस : 10325-1989	फर्म की रुचि न होने के कारण 1993-04-01 से रद्द।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22. 1722851	ओरिएंटल कलर एंड पेंट्स इंडस्ट्रीज नई दिल्ली।	आईएस : 133-1975	फर्म के अनुरोध पर 1993-05-1 से रद्द।	
23. 1750755	यूनिक रोलिंग मिल्स प्रा० लि० रायपुर	आईएस : 226- 1975	आईएस : 226-1975 का अतिक्रमण के कारण 1993-05-01 से रद्द।	
24. 1805855	मोतीलाल पदमापुर उद्योग लि० कानपुर	आईएस : 11352- 1985	यूनिट के बंद होने के कारण 1993-05-05 रद्द।	
25. 1829768	स्टेयू इक्विपमेंट प्रा० लि०, 66, इंड एरिया, फेस-1 पंचकुला	आईएस : 398 (भाग 1) 1976	फर्म के अनुरोध पर 1993-05-16 लाइसेंस रद्द।	
26. 1855062	बालाजी बेजीटेल प्राइवेट प्रा० लि० पी०बी० नं० 43; सीतापुर	आई एस : 398 (भाग 1) 1976	जमुना निरीक्षण के अनुसार मही न होने और लगातार असफल होने के कारण 1993-06-16 रद्द से रद्द।	
27. 1949677	जे के जूट मिल्स कं लि०, कालपी रोड, कानपुर।	आईएस : 12154-1987	फर्म के अनुरोध पर 1993-04-01 से रद्द।	
28. 1958173	इंडिया आयरन फाउंड्री मुलतान गंज से रद्द। (आगरा)।	आईएस : 5455-1969	फर्म के अनुरोध पर 1993-07-14 से रद्द	
29. 2022222	बंगलौर पेस्टीसाइड्स लि०,	आईएस : 7121-1973	फर्म के अनुरोध पर 1993-06-14 से रद्द।	
30. 2056744	एसब इंडिया लि०, ठाणे	आईएस : 81 (भाग 1)-1974	मानक पुनरीक्षित एवं आईएस 814-1991 में शामिल कारण 1992-11-01 से रद्द।	
31. 2140834	महाराष्ट्र बेल्डेड लि , नागपुर	आईएस : 814 (भाग 2)- 1974	मानक के पुनरीक्षित एवं आईएस 814-1994 में शामिल होने के कारण 1992-11-01 को रद्द।	
32. 2160537	कंसोलिडेटेड स्टील्स अल्याय ग्वालियर।	आईएस : 2026-1975	आईएस : 226-1975 के अतिक्रमण के कारण 1993-05-01 से रद्द	
33. 2176855	इंडियन प्लास्टर मैके, बंगलौर।	आईएस : 303-1989	फर्म के अनुरोध पर निरस्तीकरण करने के कारण 1993-06-04 से रद्द।	
34. 2282349	बबले इंजी इंडिया, कोयम्बतूर	आईएस : 12225-1987	फर्म के लाइसेंस रद्द करने की इच्छा पर 1993-06-03 से रद्द।	
35. 2299770	बंजरंग अल्याय लि०, रायपुर	आईएस : 2062-1992	आईएस : 226-1975 के अतिक्रमण के कारण 1993-05-01 से रद्द।	
36. 2336346	नासिक बेल्डिंग प्राइवेट नासिक।	आईएस : 814 (भाग 2)- 1974	मानक के पुनरीक्षित होने एवं आईएस : 814-1991 में शामिल करने के कारण 1992-05-01 से रद्द	
37. 2351645	अग्रवाल एंड कं, नासिक	आईएस : 814 (भाग 1)- 1974	मानक के पुनरीक्षित होने एवं आईएस : 814-1991 में शामिल हो जाने के कारण 1992-11-01 से रद्द।	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
38. 2372752	पर्दा स्टील (प्रा.) लि०, जिला धार	आईएस : 226-1975	आईएस : 2062-1992 के अतिक्रमण के कारण 1993-05-01 से रद्द।	
39. 2375154	शाह स्टील इंडस्ट्रीज, कन्नौज	आईएस : 226-1975	आईएस : 2062-1992 के आईएस 226-1975 को अतिक्रमण के कारण 1993-05-01 से रद्द।	
40. 2376257	त्रिशूल आयरन एंड स्टील इंडिया, जलगांव	आईएस : 10325-1989	लाइसेंस स्वीकृत पर न्यूनतम मुहरांकन शुल्क न देने के कारण 1992-06-16 से रद्द।	
41. 2394057	बेल्डिंग स्पेशलिस्ट (आई) प्रा० लि० नासिक।	आईएस : 814(भाग 2)-1974	मानक के पुनरीक्षित होने एवं आईएस : 814-1991 में शामिल हो जाने के कारण 1992-11-01 से रद्द।	
42. 2412235	नोरमा स्टील एल्वस लि०, दिल्ली	आईएस : 1786-198	फर्म की रुचि न होने के कारण 1993-03-16 से रद्द।	
43. 8006961	बन्दना सीमेंट लि०, इन्दौर।	आईएस : 455-1989	फर्म की रुचि न होने के कारण 1993-01-16 से रद्द।	
44. 9012557	शिवालिक एग्रो केमिकल्स बी-59-60 फेस 3, मास नगर, जिला रोपड़ (पंजाब)।	आईएस : 13493-19	अग्रिम मुहरांकन शुल्क और वार्षिक लाइसेंस शुल्क न प्राप्त करने के कारण 1993-04-01 से रद्द।	

[के प्र वि/13 : 13]  
पी०एस० वास, अवर महानिदेशक

# MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES CONSUMER AFFAIRS & PUBLIC DISTRIBUTION

## BUREAU OF INDIAN STANDARDS

New Delhi, the 20th September, 1994

S.O. 2744 : —In pursuance of sub-regulation(6) of regulation 5 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulation 1988 the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the licence(s) particulars of which are given below have been Cancelled with effect from the date indicated against each :

### SCHEDULE

S. No.	Licence No. (CM/L—)	Name and Address of the licensee	Relevant Indian Standard covered by the licence cancelled	Date of Cancellation
1	2	3	4	5
1.	0628955	Shree Isbar Alloy Steels Indore,	IS : 2062—1992	Cancelled with effect from 1993-05-01 due to superseding of IS : 226 1975
2.	0657962	Ferrous Engineer Rajkot.	IS : 10001— 1981	Cancelled with effect from 1993-04-01 as the firm is not interested
3.	0731948	Raipur Bright Steel & Wire Weld Industries Raipur.	IS : 2062— 1992	Cancelled with effect from 1993-05-01 due to supersession of IS : 226—1975
4.	0772457	Haryana Metal & Re-rolling Mills Ltd., Bombay.	IS : 226—1975	Cancelled with effect from 1993-05-01 due to superseding of IS : 226 by IS : 2062—1992

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	0875467	Century Tubes Ltd., Sec. 26, Rohtak Road, Bhiwani.	IS : 1239 Part I—1990	Cancelled with effect from 1993-05-16 as the firm requested to cancelled the licence.
6.	0955566	CYMA Industry, Rajkot.	IS : 10001—1981	Cancelled with effect from 1993-04-01 as the firm is not interested.
7.	0979075	JAYEE PVC Pipes Pvt., Ltd., Jalgaon	IS : 4985—1988	Cancelled with effect from 1993-04-01 due to change of management
8.	1058339	Advani Oerlikon Ltd., Madras.	IS : 814—1991	Cancelled with effect from 1993-03-31 due to merger of the standards.
9.	1099757	Murarka Enterprise, Kota.	IS : 398(Part 2)—1976	Cancelled with effect from 1993-04-19 as the firm is not interested.
10.	1123839	Associated Acromatics Ltd., Ujjain.	IS : 4956—1977	Cancelled with effect from 1993-04-01 as the firm is not interested.
11.	1123930	Joy Food Products, Bangalore.	IS : 1011—1992	Cancelled with effect from 1993-06-02 as the firm surrendered the licence.
12.	1251131	Modi Are Electrodes Co., Modi Nagar.	IS : 814(Part 2)—1974	Cancelled with effect from 1993-02-28 as the the firm is not interested.
13.	1264645	J.K. Jute Mills Co. Ltd., Kalpi Road, Kanpur.	IS : 258—1967	Cancelled with effect from 1993-04-01 as requested by the firms.
14.	1322936	Northern Minerals Ltd., Gurgaon (Haryana).	IS : 1308—1984	Cancelled with effect from 1993-04-01 as required by Govt. vide their circular that use of aldrin has been faced out in India.
15.	1395054	Premier Electrodes Pvt. Ltd., Nasik.	IS : 814(Part II)—1974	Cancelled with effect from 1992-11-01 as the standard has been revised & merged as IS : 814—1991
16.	1422940	Guru Nank Engg. Works., Kaithal Road, Pehowa.	IS : 9020—1979	Cancelled with effect from 1993-04-01 as desired by the party
17.	1457959	Motilal Padmapat Udyog Ltd., Gutaiya, Kanpur	IS : 10633—1986	Cancelled with effect from 1993-03-06
18.	1688574	VNC Electrodes, Madras.	IS : 814—1991	Cancelled with effect from 1993-05-15 due to merger of the standards.
19.	1698274	Northern Steel and General Mills New Delhi	IS : 2062—1992	Cancelled with effect from 1993-05-01 due to supersession of IS : 226—1975
20.	1710642	Salbo Conductors Pvt. Ltd., Silvana-396230	IS : 398(Part II)—1976	Cancelled with effect from 1993-04-01 as the firm is not interested.
21.	1721849	Rahul Containers Pvt. Ltd., Dhar	IS : 10325—1989	Cancelled with effect from 1993-04-01 as the firm is not interested.
22.	1722851	Oriental Colour & Paints Industries, New Delhi.	IS : 133—1975	Cancelled with effect from 1993-06-16 as requested by the firm.
23.	1750755	Unique Rolling Mills Pvt. Ltd., Raipur.	IS : 226—1975	Cancelled with effect from 1993-05-01 due to supersession of IS : 226—1975
24.	1805855	Motilal Padampat Udyog Ltd., Kanpur.	IS : 11352—1985	Cancelled with effect from 1993-03-05 as unit closed.
25.	1829768	Stegue Equipments(P) Ltd., 66, Indl., Area, Phase-I, Punchkula.	IS : 398(Part I)—1976	Cancelled with effect from 1993-05-16 as the firm requested to cancellation of the licence.
26.	1855062	Balaji Vegetable Products (P) Ltd., P.B. No. 43, Sitapur.	IS : 11382—1986	Cancelled with effect from 1993-06-16 consecutive failure of samples, lot for pre Insp. not offered

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27.	1949677	J.K. Jute Mills Co. Ltd., Kalpi Road, Kanpur.	IS : 12154—1987	Cancelled with effect from 1993-04-01 as requested by the firm
28.	1958173	India Iron Foundry Sultanganj (Agra).	IS : 5455—1969	Cancelled with effect from 1993-07-14 on firm's request
29.	2022222	Bangalore Pesticides Ltd.,	IS : 7121—1973	Cancelled with effect from 1993-06-14 as the firm requested for cancellation
30.	2056744	ESAB India Ltd., Thane.	IS : 814(Part I)—1974	Cancelled with effect from 1992-11-01 as the standard has been revised merged in IS : 814—1991
31.	2140834	Maharashtra Weldaids Ltd., Nagpur.	IS : 814(Part II)—1974	Cancelled with effect 1992-11-01 as the standard has been revised & merged in IS : 814—1991
32.	2160537	Consolidated Steels Alloys, Gwalior.	IS : 2026—1975	Cancelled with effect from 1993-05-01 due to supersession of IS : 226—1975
33.	2176855	Indian Plywood Mfg. Co., Bangalore.	IS : 303—1989	Cancelled with effect from 1993-06-14 as the firm requested for cancellation .
34.	2282349	Bubbly Engg. Inds., Coimbatore.	IS : 12225—1987	Cancelled with effect from 1993-06-03 as the firm desired to cancel the licence.
35.	2299770	Bajrang Alloys Ltd., Raipur.	IS : 2062—1992	Cancelled with effect from 1993-05-01 due to supersession of IS : 226—1975
36.	2336346	Nasik Welding Products, Nasik.	IS : 814(Part II)—1974	Cancelled with effect from 1992-11-01 as the standard has been revised & merged in IS : 814—1991
37.	2351645	Agarwal & Co., Nasik	IS : 814(Part I)—1974	Cancelled with effect from 1992-11-01 as the standard has been revised & merged as IS : 814—1991
38.	2372754	Parda Steel (P) Ltd., Ghatbelfoo, Distt. Dhar	IS : 226—1975	Cancelled with effect from 1993-06-07 due to supersession of IS : 226—1975
39.	2375154	Shah Steel Industries, Kalol	IS : 226—1975	Cancelled with effect from 1993-05-01 due to superseeding of IS : 226 by IS : 2062—1992
40.	2376257	Trishul Iron & Steel Indus., Jalgaon.	IS : 10325—1989	Cancelled with effect from 1992-06-16 as the firm not paid, minimum marking fee on grant of licence.
41.	2394057	Welding Specialities (I) Pvt. Ltd., Nasik.	IS : 814(Part II)—1974	Cancelled with effect from 1992-11-01 as the standard has been revised & merged in IS : 814—1991
42.	2412235	Norma Steel & Alloys Ltd., Delhi.	IS : 1786—1985	Cancelled with effect from 1993-03-16 as the firm is not interested.
43.	8006961	Vadana Cement Ltd., Indore.	IS : 455—1989	Cancelled with effect from 1993-01-16 as the firm is not interested.
44.	9012557	Shivalik Agro Chemicals, B-59—60 Phase-III, SAS Nagar, Distt. Ropar (Punjab).	IS : 13493—1992	Cancelled with effect from 1993-04-01 as the advance marking fee and annual licence fee not received.

[No. CMD /13 : 13]

P.S. DAS, Additional Director General.

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1994

कां.आ.० 2745.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड “ख” के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे दिये गए मानक (कों) में संशोधन किया गया है/किये गये हैं।

## अनुसूची

क्रम संख्या	संशोधित भारतीय मानक की संख्या और वर्ष	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन लागू होने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आईएस 7539-1975	संशोधन सं० 3, मई 1994	1994-05-31
2.	आईएस : 7943:1976	संशोधन सं० 1, मई 1994	1994-05-31
3.	आईएस : 7944 : 1976	संशोधन सं० 1, मई 1994	1994-05-31
4.	आईएस : 7948 : 1987	संशोधन सं० 3, मई 1994	1994-05-31
5.	आईएस : 8026:1987	संशोधन सं० 1, मई 1994	1994-05-31
6.	आईएस : 8027 : 1976	संशोधन सं० 1, मई 1994	1994-05-31
7.	आईएस : 8028:1987	संशोधन सं० 1, मई 1994	1994-05-31
8.	आईएस: 8029 : 1985	संशोधन सं० 2, मई 1994	1994-05-31
9.	आईएस: 8259-1976	संशोधन सं० 2, मई 1994	1994-05-31
10.	आईएस 8286:1976	संशोधन सं० 1, मई 1994	1994-05-31
11.	आईएस : 8448:1989	संशोधन सं० 1, मई 1994	1994-05-31
12.	आईएस: 8487:1977	संशोधन सं० 3, मई 1994	1994-05-31
13.	आईएस 8703:1978	संशोधन सं० 2, मई 1994	1994-05-31
14.	आईएस : 8708:1978	संशोधन सं० 2, मई 1994	1994-05-31
15.	आईएस: 8888 (भाग 1):1993	संशोधन सं० 1, मई 1994	1994-05-31
16.	आईएस: 8959:1978	संशोधन सं० 2, मई 1994	1994-05-31
17.	आईएस: 8960:1978	संशोधन सं० 2, मई 1994	1994-05-31
18.	आईएस: 9356:1980	संशोधन सं० 3, मई 1994	1994-05-31
19.	आईएस: 9358: 1980	संशोधन सं० 2, मई 1994	1994-05-31
20.	आईएस: 9360 : 1980	संशोधन सं० 3, मई 1994	1994-05-31
21.	आईएस 9361: 1980	संशोधन सं० 2, मई 1994	1994-05-31
22.	आईएस: 9364:1980	संशोधन सं० 2, मई 1994	1994-05-31
23.	आईएस: 9365:1980	संशोधन सं० 2, मई 1994	1994-05-31
24.	आईएस: 9366:1987	संशोधन सं० 1, मई 1994	1994-05-31
25.	आईएस: 9367:1980	संशोधन सं० 3, मई 1994	1994-05-31
26.	आईएस: 9368: 1980	संशोधन सं० 2, मई 1994	1994-05-31
27.	आईएस: 9665:1981	संशोधन सं० 3, मई 1994	1994-05-31
28.	आईएस: 10523:1983	संशोधन सं० 3, मई 1994	1994-05-31
29.	आईएस: 9611:1983	संशोधन सं० 1, अप्रैल 1994	1994-04-30
30.	आईएस: 0962:1984	संशोधन सं० 2, मई 1994	1994-05-31
31.	आईएस 11303: 1985	संशोधन सं० 2, मई 1994	1994-05-31
32.	आईएस: 11346:1985	संशोधन सं० 4, अप्रैल 1994	1994-04-30
33.	आईएस: 11479:1985	संशोधन सं० 2, मई 1994	1994-05-31
34.	आईएस: 11652:1992	संशोधन सं० 1, मई 1994	1994-05-31
35.	आईएस : 12076 : 1986	संशोधन सं० 2, अप्रैल 1994	1994-04-31
36.	आईएस: 12562:1988	संशोधन सं० 1, मई 1994	1994-05-31

(1)	(2)	(3)	(4)
37. आईएस: 12873:1990		संशोधन सं० 3, मई 1994	1994-05-31
38. आईएस: 13200:1993		संशोधन सं० 1, मई 1994	1994-05-31
39. आईएस: 13292:1994		संशोधन सं० 1, अप्रैल, 1994	1994-04-30
40. आईएस: 13457:1992		संशोधन सं० 1, मई 1994	1994-05-31
41. आईएस: 13872:1993		संशोधन सं० 1, मई 1994	1994-05-31
42. आईएस: 13923:1993		संशोधन सं० 1, अप्रैल 1994	1994-04-30
43. आईएस: 13947(भाग 2): 1993		संशोधन सं० 1, मई 1994	1994-05-31

इन संशोधनों की प्रतियां भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 और क्षेत्रीय कार्यालयों बम्बई, कलकता, चण्डीगढ़ तथा मद्रास और शाखा कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलूर, भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना और त्रिवेन्द्रम, गाजियाबाद तथा फरीदाबाद में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[सं० के प्र वि/13 : 5]

पी०एस० दास, अपर महानिदेशक

New Delhi, the 21st September, 1994

S.O. 2745.—In pursuance of clause (b) of Sub-rule (1) or Rule 7 of Bureau of Indian Standards Rules, 1981, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendment(s) to the Indian Standard(s) given in the schedule hereto annexed has/have been issued.

#### THE SCHEDULE

Sl. No. and year of the Indian Standard amended	No. and date of the amendment	Date from which the amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)
(1)	(2)	(4)
1. IS 7539 : 1975	Amendment No. 3 May 1994	94-05-31
2. IS 7943 : 1976	Amendment No. 1 May 1994	94-05-31
3. IS 7944 : 1976	Amendment No. 1 May 1994	94-05-31
4. IS 7948 : 1987	Amendment No. 3 May 1994	94-05-31
5. IS 8026 : 1987	Amendment No. 1 May 1994	94-05-31
6. IS 8027 : 1976	Amendment No. 1 May 1994	94-05-31
7. IS 8028 : 1987	Amendment No. 1 May 1994	94-05-31
8. IS 8029 : 1985	Amendment No. 2 May 1994	94-05-31
9. IS 8259 : 1976	Amendment No. 2 May 1994	94-05-31
10. IS 8286 : 1976	Amendment No. 1 May 1994	94-05-31
11. IS 8448 : 1989	Amendment No. 1 May 1994	94-05-31

(1)	(2)	(3)	(4)
12. IS 8487 : 1977		Amendment No. 3 May 1994	94-05-31
13. IS 8703 : 1978		Amendment No. 2 May 1994	94-05-31
14. IS 8708 : 1978		Amendment No. 2 May 1994	94-05-31
15. IS 8888 (Part 1) : 1993		Amendment No. 1 May 1994	94-05-31
16. IS 8959 : 1978		Amendment No. 2 May 1994	94-05-31
17. IS 8960 : 1978		Amendment No. 2 May 1994	94-05-31
18. IS 9356 : 1980		Amendment No. 3 May 1994	94-05-31
19. IS 9358 : 1980		Amendment No. 2 May 1994	94-05-31
20. IS 9360 : 1980		Amendment No. 3 May 1994	94-05-31
21. IS 9361 : 1980		Amendment No. 2 May 1994	94-05-31
22. IS 9364 : 1980		Amendment No. 2 May 1994	94-05-31
23. IS 9365 : 1980		Amendment No. 2 May 1994	94-05-31
24. IS 9366 : 1987		Amendment No. 1 May 1994	94-05-31
25. IS 9367 : 1980		Amendment No. 3 May 1994	94-05-31
26. IS 9368 : 1980		Amendment No. 2 May 1994	94-05-31
27. IS 9665 : 1981		Amendment No. 3 May 1994	94-05-31
28. IS 10523 : 1983		Amendment No. 3 May 1994	94-05-31
29. IS 10611 : 1983		Amendment No. 1 April 1994	94-04-30
30. IS 10962 : 1984		Amendment No. 2 May 1994	94-05-31
31. IS 11303 : 1985		Amendment No. 2 May 1994	94-05-31
32. IS 11346 : 1985		Amendment No. 4 April 1994	94-04-30
33. IS 11479 : 1985		Amendment No. 2 May 1994	94-05-31
34. IS 11652 : 1992		Amendment No. 1 May 1994	94-05-31
35. IS 12076 : 1986		Amendment No. 2 April 1994	94-04-30
36. IS 12562 : 1988		Amendment No. 1 May 1994	94-05-31

(1)	(2)	(3)	(4)
37. IS 12873 : 199		Amendment No. 3 May 1994	94-05-31
38. IS 13200 : 1993		Amendment No. 1 May 1994	94-04-31
39. IS 13292 : 1994		Amendment No. 1 April 1994	94-04-30
40. IS 13457 : 1992		Amendment No. 1 May 1994	94-05-31
41. IS 13872 : 1993		Amendment No. 1 May 1994	94-05-31
42. IS 13923 : 1993		Amendment No. 1 April 1994	94- 4-30
43. IS 13947 (Part 2) : 1993		Amendment No. 1 May 1994	94-05-31

Copies of these amendments are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002 and Regional Offices : New Delhi, Calcutta, Chandigarh, Madras, Bombay and also Branch Offices : Ahmadabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Faridabad, Ghaziabad, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Lucknow, Patna, Thiruvananthapuram.

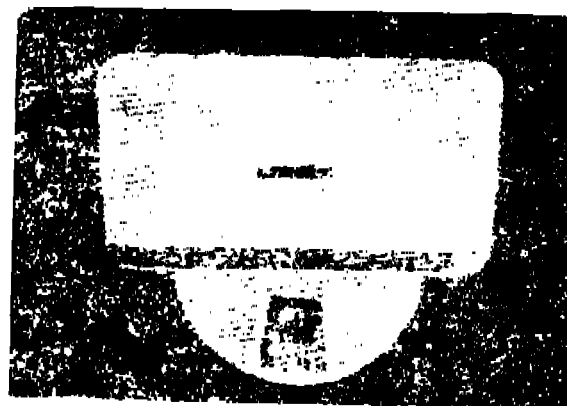
[No. CMD/13 : 5]  
P.S. DAS, Addl. Director General

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1994

का. आ. 2746—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित प्रतिमान, वाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा वाट और माप मानक (प्रतिमान का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुस्यू है और यह संभावना है कि उक्त प्रतिमान लम्बी अवधि तक अविरल उपयोग के संबंध में ठीक बना रहेगा और परिवर्तित दशाओं में सही सेवा देगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए, मैसर्स डाक्टर बैलीगम मस्य (एम. एफ. जी.) 3/17, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 द्वारा विनिर्मित "कृष्ण" ब्रांड नाम वाले स्वतः संचालित अल्ट्रासोनिक तौलन उपकरण के प्रतिमान का (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रतिमान कहा गया है) और जिसे अनुमोदन विज्ञापन आई एन डी/

09/94/23 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है :



(आकृति)

प्रतिमान (आकृति देखिए) एक साधारण शुद्धता वर्ग (शुद्धता वर्ग III) वाला तौलन उपकरण है। इसकी

अधिकतम क्षमता 25 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 1 किलोग्राम है। सत्यापन मापमान अंतर (ई) 100 ग्राम है। इसमें एक सेटिंग युक्ति की व्यवस्था की गई है। इसका आधार, शीर्ष आवरण और सरकने वाला पलड़ा इस्पात का बना है। पलड़े को तोलन तुला से मशीन के शीर्ष पर दो सुराखों में पलड़े के नीचे लगे दो ब्रेकटों को दबाकर लगाया जा सकता है। सरकने वाले पलड़े का आकार 483 मिलीमीटर × 254 मिलीमीटर 64 × मिलीमीटर है।

[फा. सं. डब्ल्यू. एम. 21 (39) 193]

राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 29th September, 1994

S.O. 2746.—Whereas the Central Government after considering the report submitted to it by the prescribed authority is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of self-indicating non-automatic weighing instrument with brand name 'KRUPS' (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Doctor Beli Ram & Sons (MFG), 3/17, Asaf Ali Road, New Delhi-110 002, and which is assigned the approval mark IND/09/94/23.



(Figure)

The Model (see figure) is a weighing instrument of ordinary accuracy (Accuracy class III). It has a maximum capa-

city of 25 kilogram and a minimum capacity of 1 kilogram. The verification scale interval (e) is 100 gram. It is prepared with a zero setting device. The base, its top cover and the sliding pan are made up of steel. The pan can be fixed to the weighing scale by pushing the two brackets fixed underneath the pan into the two slots on the top of the machine. The sliding pan is of size 483 millimeter × 254 millimetre × 64 millimetre.

[F. No. WM-21(39)/93.]

RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 29 सितम्बर 1994

फा. ग्रा. 2747.—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित प्रतिमान, वाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा वाट और माप मानक (प्रतिमान का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और यह संभावना है कि उक्त प्रतिमान लम्बी अवधि तक अविरत उपयोग के संबंध में टोक बना रहेगा और परिवर्तित दशाओं में सही सेवा देगा।

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैथिली शिवा इलेक्ट्रॉनिक्स, 30 दिव्य बंधुधरा कम्प्युनिटी हाऊस, मिर्जापुर, अहमदाबाद-380001 द्वारा विनिर्मित "एस" सिरोज के टाइप संख्यांक-एस 1001 और "शिवा ब्रॉड" नाम वाले स्वतः सूचक, अस्वचालित तोलन उपकरण के प्रतिमान का (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रतिमान कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी /09/94/17 समनुदेशित किया गया है अनुमोदन प्रमाण पत्र प्रकाशित करती है।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि प्रतिमान के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी मिश्रित के अनुसार और उन्हीं सामग्री से, जिनसे अनुमोदित प्रतिमान का

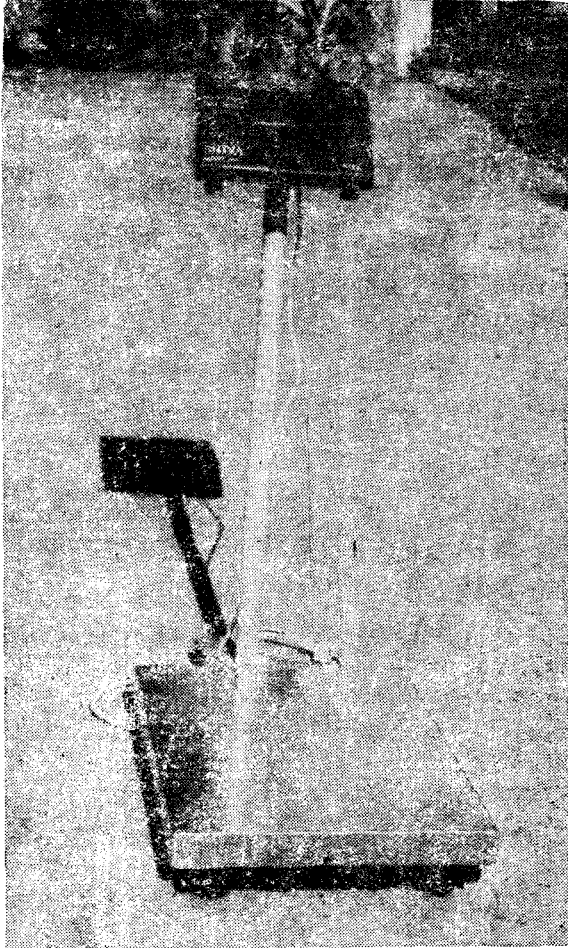


विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित 50 किलोग्राम, 150 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 300 किलोग्राम, 500 किलोग्राम, 1 टन और 2 टन की अधिकतम क्षमता वाले उसी सिरीज के समरूप मॉडल, शुद्धता और कार्यकरण वाले तोलन उपकरण भी आएंगे।

New Delhi, the 29th September, 1994

S.O. 2747.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards or Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Model) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self indicating non-automatic weighing instrument of type number S-1001 belonging to 'S' series and with brand name 'SHIVA' (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Shiva Electronics, 30 Diyya Vasundhara Comm. House, Mirzapur, Ahmedabad-380 001, and which is assigned the approval Mark IND/09/94/17.

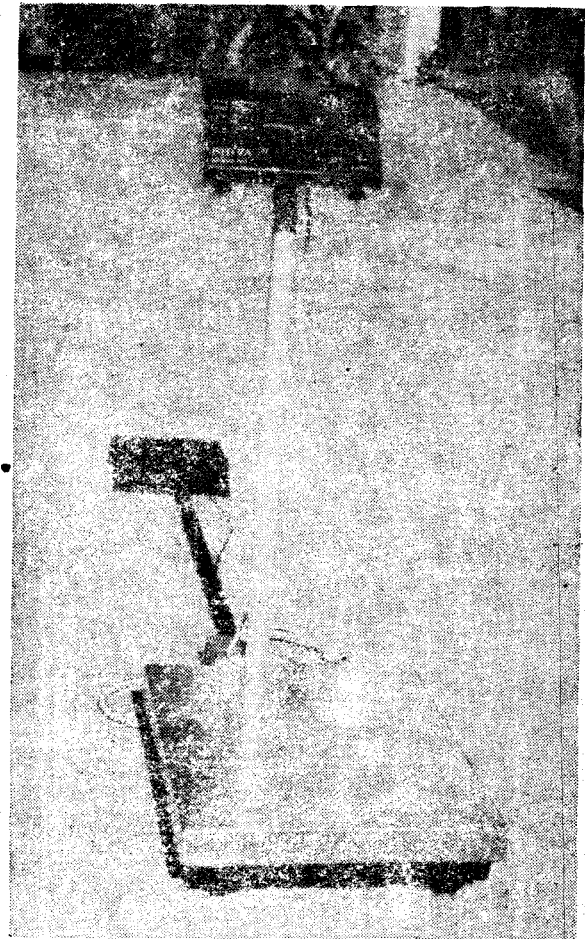


(आकृति)

प्रतिमान (आकृति देखिए) एक मध्यम शुद्धता (शुद्धता वर्ग 3) वाला तोलन उपकरण है, जिसकी अधिकतम क्षमता 100 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 400 ग्राम है सत्यापन अंतर (ई) 20 ग्राम है। इसमें एक ऐसी टेरे यूनिट है, जिसका व्यकलानात्मक प्रतिधरित टेरे प्रभाव, शत-प्रतिशत है इसका आधार ढलवा स्टेनलेस स्टील से बना है और भार अभिग्राहक मृदु इस्पात का है। भार अभिग्राहक की आकृति आयताकार है, जिसका आकार 600 मिलीमीटर × 550 मिलीमीटर है। द्रव क्रिस्टल प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्टज के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर चलाया जाता है।

[फा. सं. डब्ल्यू. एम. 21 (28) 92]

राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव



(Figure)

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series and with maximum capacity of 50 kilogram, 150 kilogram, 200 kilogram, 300 kilogram, 500 kilogram, 1 tonne and 2 tonne manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

The Model (see figure) is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 100 kilogram and a minimum capacity of 400 gram. The verification interval (e) is 20 gram. It has a tare device with

a 100 per cent subtractive retained tare effect. The base is made up of stainless steel and the load receptor is of mild steel. The load receptor is rectangular in shape with dimension 600 millimetre x 550 millimetre. The liquide crystal display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts, 50 hertz alternate current power supply.

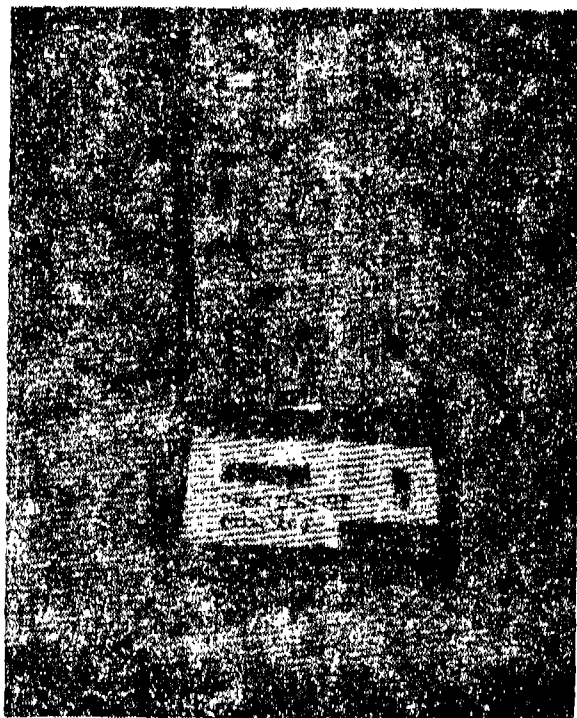
[F. No. WM-21(28)/93]

RAJIV SRIVASTAVA, H. Secy.

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1994

का. आ. 2748.—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिका-  
कारी द्वारा उस प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के  
पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित  
प्रतिमान, बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976  
का 60) तथा बाट और माप मानक (प्रतिमान का अनुमोदन)  
नियम, 1987 के उपबंधों के अनुसार है और यह संभावना  
है कि उक्त प्रतिमान लंबी अवधि तक अविरत उपयोग के  
संबंध में ठीक बना रहेगा और परिवर्तित दशाओं में सही  
सेवा देगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा  
36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते  
हुए, मैसर्स जस्मिन इंडस्ट्रीज, अखंडानंद, सी टी एस, अमराई-  
वाड़ी, अहमदाबाद-380026 द्वारा विनिर्मित जे आई मिरीज  
के टाइप संख्यांक जे आई-1006 और जस्मिन बाट नाम वाले  
स्वतः सूचक, अस्वचालित तोलन उपकरण के प्रतिमान का (जिसे  
इसमें इसके पश्चात् प्रतिमान कहा गया है) और जिसे अनुमोदित  
चिह्न आई.एन.डी. /09194/21 समनुदेशित किया गया है,  
अनुमोदन प्रमाण-पत्र प्रकाशित करती है;



इसके अनिवार्य केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा को उपधारा  
(12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा  
करती है कि प्रतिमान के अनुमोदन के इस प्रमाण-पत्र के  
अंतर्गत उगी विनिर्माता द्वारा उगी सिद्धांत के अनुसार, और  
उन्ही सामग्री से, जिनसे अनुमोदन प्रतिमान का विनिर्माण किया  
गया है विनिर्मित उमी सीरीज के और 200 ग्राम, 500 ग्राम,  
1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 10 किलोग्राम,  
20 किलोग्राम और 30 किलोग्राम की अधिकतम क्षमता के  
समरूप भेक, शुद्धता और कार्यकरण वाले तोलन उपकरण भी  
आएंगे।

प्रतिमान (आकृति देखिए) एक मध्यम शुद्धता (शुद्धता  
वर्ग 3) वाला तोलन उपकरण है, जिसकी अधिकतम क्षमता 5  
किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 20 ग्राम है। सत्यापन अंतर  
(ई) 1 ग्राम है इसमें एक ऐसी टैरे सुविधा है जिसका व्यव-  
कलातात्मक प्रतिधारित टैरे प्रभाव शून्य-प्रतिशत है। आधार  
फाइबर कांच का और भार अभिस्राहक स्टेनलेस स्टील का है।  
भार अभिस्राहक वर्गीकार आकृति का है और पार्श्व लंबाई  
250 मिलीमीटर है। द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन तोलन परिणाम  
उपदिशित करता है। उपकरण को 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज  
के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत पर चलाया जाता है।

[फा सं. डब्ल्यूएम-21(40)/93]

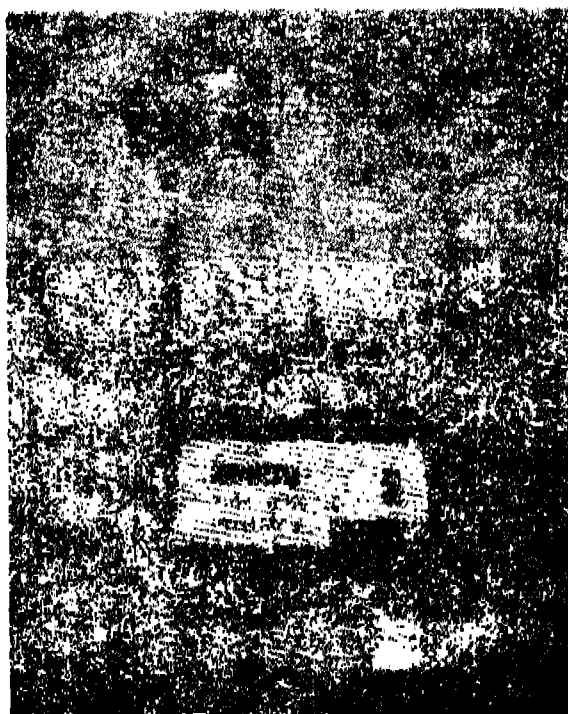
राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 29th September, 1994

S.O. 2748.—Whereas the Central Government, after con-  
sidering the report submitted to it by the prescribed authority,  
is satisfied that the Model described in the said report is in  
conformity with the provisions of the Standards of Weights  
and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of  
Weights and Measures (Approval of Model) Rules, 1987 and  
the said Model is likely to maintain accuracy over periods  
of sustained use and to render accurate service under varied  
conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by  
sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central  
Government hereby publishes the certificate of approval of  
the Model of the self indicating non-automatic weighing  
instrument of type No. JI-1006 belonging to 'JI' series and  
with brand name 'JASMIN' (hereinafter referred to as the  
Model) manufactured by M/s. Jasmin Industries, Akhand-

band, C FM, Amraiwadi, Ahmedabad-380026, and which is assigned the approval mark IND/09/94/21;



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make accuracy and performance of same series and with maximum capacity of 500 gram, 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram, 10 kilogram, 20 kilogram and 30 kilogram manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

The Model (see figure) is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 5 kilogram and a minimum capacity of 20 gram. The verification interval (e) is 1 gram. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The base is of fibre glass and the load receptor is of stainless steel. The load receptor is square in shape with side length of 250 millimeter. The liquid crystal display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts, 50 hertz alternate current power supply.

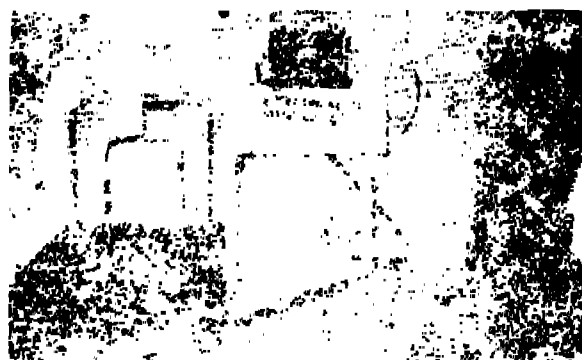
[F. No. WM-21(40)]93]  
RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 29 सितंबर, 1994

का. आ. 2749.—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित प्रतिमान, बाट और माप मानक अधिनियम 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (प्रतिमान का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और यह संभावना है कि उक्त प्रतिमान लंबी अवधि तक अधिस्त उपयोग के संबंध में ठीक चला रहेगा और परिवर्तित दशाओं में गंभी सेवा देगा;

अतः, अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सैमर्स जॉस्मिन इंडस्ट्रीज, अखंडानंद, सी टी एम, अमराई-

वाड़ी, अहमदाबाद-380026 द्वारा विनिर्मित जे आई सीरीज के टाइप संस्थांक जे आई-2002 और जॉस्मिन ब्रांड नाम वाले स्वतःशुल्क, अस्वचालित तौलन उपकरण के प्रतिमान का (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रतिमान कहा गया है) और जिसे अनुमोदित चिह्न आई.एन.डी/09/94/21 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है;



इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि प्रतिमान के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी विद्यान के अनुसार और उन्हीं मापसी में, जिनमें अनुमोदित प्रतिमान का विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी सीरीज के और 50 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, 150 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 400 किलोग्राम, 500 किलोग्राम, 1 टन और 2 टन की अधिकतम क्षमता के समस्त भेज, शुद्धता और कार्यकरण वाले तौलन उपकरण भी आगें।

प्रतिमान (आकृति देखिए) (एक मध्यम शुद्धता वर्ग 3) वाला तौलन उपकरण है, जिसकी अधिकतम क्षमता 100 किलोग्राम और न्यूनतम 400 ग्राम है। मत्यापन अंतर (ई) 20 ग्राम है। इसमें एक ऐसी टैरे युक्ति है जिसका व्यव-कलनात्मक प्रतिधारित टैरे प्रभाव शून्य-प्रतिशत है। आधार क्लवा लोहे और भार ग्राहक मृदु इस्पात का है। भार ग्रहि-ग्राहक वर्गीकार आकृति का है और पार्श्व लंबाई 500 मिली-मीटर है। द्रव क्रिस्टल प्रदर्श तौलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण को 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत् प्रदाय पर चलाया जाता है।

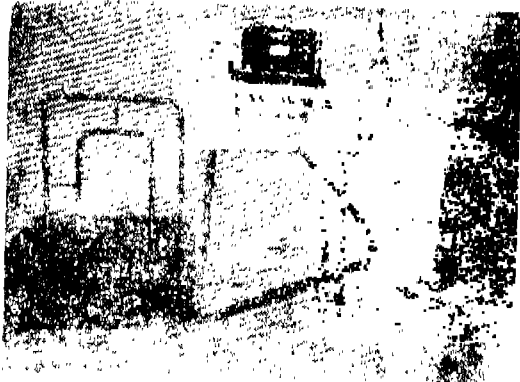
[फा. सं. डब्ल्यू.एम.-21(40)/93]  
राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 29th September, 1994

S.O. 2749.—Whereas the Central Government after considering the report submitted to it by the prescribed authority is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Model) Rules, 1987

and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self indicating non-automatic weighing instrument of type No. JI-2002 belonging to 'JI' series and with brand name 'JASMIN' (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Jasmin Industries, Akhandnand, CFM, Amraiwadi, Ahmedabad-380026, and which is assigned the approval mark IND[09/94]22.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series and with maximum capacity of 50 kilogram, 120 kilogram, 200 kilogram, 400 kilogram, 500 kilogram, 1 tonne and 2 tonne manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

The Model (see figure) is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 100 kilogram and a minimum capacity of 400 gram. The verification interval (e) is 20 gram. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The base is of cast iron and the load receptor is of mild steel. The load receptor is square in shape with side length of 500 millimeter. The liquid crystal display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts, 50 hertz alternate current power supply.

[F. No. WM-21(40)93]  
RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 29 सितंबर, 1994

का.आ. 2750.—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित प्रतिमान, बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (प्रतिमान का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और यह संभावना है कि उक्त प्रतिमान लंबी अवधि तक अविरत उपयोग के संबंध में ठीक बना रहेगा और परिवर्तित दशाओं में सही सेवा देगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स दिग्ग इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, 38 इलेक्ट्रॉनिक्स एस्टेट लिमिटेड, पुणे—सतारा रोड, पुणे 411009 द्वारा विनिर्मित “आटो फेयर” ब्रांड नाम वाले टैक्सी मीटर के प्रतिमान का (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रतिमान कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई.एन. डी 10/94/12 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।



प्रतिमान (आकृति देखिए) एक बाक्स में बंद टैक्सी मीटर है जिसका संपूर्ण आकार 190 मिलीमीटर × 165 मिलीमीटर 118 मिलीमीटर है, पृष्ठभाग में नियंत्रण स्विच की पृथक्-पृथक् तीन स्थितियाँ अर्थात् “स्टॉप” मीटर “आफ” है प्रकाश उत्सर्जक डायड प्रदर्श किराया उपदर्शित करता है। किराया सूचक में अधिकतम किराया 999 रु. 99 पैसे तक दर्शित करने की व्यवस्था है। प्रदर्श के ऊपर प्रकाश उत्सर्जक डायड सूचक टैक्सी मीटर का प्रचालन दृग उपदर्शित करता है।

[फा. सं. डब्ल्यू.एम.-21(17)92]  
राजीव श्रीवास्तव, सयुक्त सचिव,

New Delhi, the 29th September, 1994

S.O. 2750.—Whereas the Central Government after considering the report submitted to it by the prescribed authority is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the 'Taxi Meter with brand name 'AUTOFARE' (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Dighe Electronics Limited, 38, Electronic Co-op Estate Limited, Pune-Satara Road, Pune-411009, and which is assigned the approval Mark IND/10/94/12.



(Figure)

The Model (See figure) is a Taxi meter housed in a box with overall dimension 190 millimetre×160 millimetre×118 millimetre. The control switch at the back has three different positions namely 'STOP', 'METER' and 'OFF'. The Light emitting diode display indicates the fare. The fare indication has a provision to show a maximum fare of Rs. 999.99 P. The Light Emitting Diode indicator above the display indicates the operation mode of Taxi Meter.

[F. No. WM-21(17)/92]

RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1994

का.आ. 2751.—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित प्रतिमान, वाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा वाट और माप मानक (प्रतिमान का अनुमोदन) नियम 1987 के उपबन्धों के अनुरूप है और यह संभावना है कि उक्त प्रतिमान सम्बन्धी अवधि तक अविरत उपयोग के संबंध में ठीक चला रहेगा और परिवर्तित दशाओं में सही सेवा देगा।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम, की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स लिक्विड कंट्रोल (इंडिया) प्रा. लि., डी-102, सिद्धार्थ पटेल स्वरायर, पो.वा.सं. 4028, ओल्ड पट्टा रोड, बडोदा-390005 द्वारा विनिर्मित टाइप संख्या एमएम-30 और एम. 30 सीरीज के जल से शून्य) द्रव के लिये मीटर के प्रतिमान का जिसे हमें इसके पश्चात् प्रतिमान 2241 GI '94-7.

कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई.एन.डी. 09/94/13 समनुमोदित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण पत्र प्रकाशित करती है।



(आकृति)

इसके अनुरिक्त, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि प्रतिमान के अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अन्तर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उनी सिद्धान्त के अनुसार और उन्ही सामग्री से, जिनसे अनुमोदित प्रतिमान का विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित एम-25, एम-40, एम-60, एम-75, एम-80, और एम-120 सीरीज के समरूप मीटर, शुद्धता और कार्यकरण वाले मीटर भी आनेंगे।

प्रतिमान (आकृति देखिए) टाइप सं. एम.एम. 30 और एम. 30 सीरीज से संबंधित (जल से शून्य) द्रवों के लिये मीटर है। यह प्रति मिनट 1325 लीटर की अधिकतम प्रवाह दर और 132 लीटर की न्यूनतम प्रवाह दर के घनात्मक विस्थापन प्रकार का मीटर है। रजिस्टर अधिकतम 99999 लीटर तक संप्रदर्शित कर सकता है और यह पुनर्नियोज्य है। इसको 0.1 लीटर का न्यूनतम गणना है। सर्वयोजित 99999999 लीटर तक रजिस्टर चार सकता है और यह पुनर्नियोज्य नहीं है।

[फा. सं. डी.एम. 21(54)/93]

राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 29th September, 1994

S.O. 2751.—Whereas the Central Government after considering the report submitted to it by the prescribed authority is satisfied that the Model described in the said report is

in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Model) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the Meter for liquids (Other than water) of type No. MS-30 and belonging to M-30 series (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Liquid Controls (India) Pvt. Ltd., T-102, Sidharth Patel Square, P. Box No. 4028, Old Padra Road, Baroda-390005, and which is assigned the approval mark IND/09/94/13.



(Figure)

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the meters of similar make, accuracy and performance of M-25, M-40, M-60, M-75, M-80 and M-120 series manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle and with the same materials with which the approved Model has been manufactured.

The Model (see figure) is a Meter for liquids (Other than water) of type No. MS-30 and belonging to M-30 series. It is a positive displacement type meter with a maximum flow rate of 1325 litre per minute and a minimum flow rate of 132 litre. The register can display to a maximum of 99999 litre and is resettable. It has a least count of 0.1 litre. The totaliser can register upto 99999999 litre and is non-resettable.

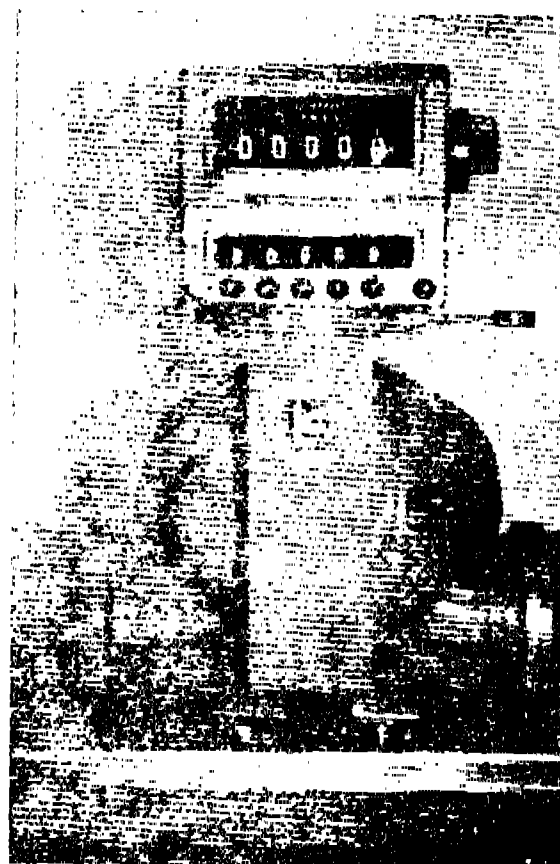
[F. No. WM-21(54)/93]  
RAJIV SRIVASTAVA, H. Secy.

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1994

का.आ. 2752.—केन्द्रीय सरकार, का विज्ञित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित प्रतिमान,

वाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा वाट और माप मानक (प्रतिमान का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबन्धों के अनुरूप है और वह संभावना है कि उक्त प्रतिमान लम्बी अवधि तक अविरत उपयोग के संबंध में ठीक बना रहेगा और परिवर्तित दशाओं में सही सेवा देगा।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम, की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सैमर्स लिक्विड कंट्रोल्स (इंडिया) प्रा. लि., टी-102, सिद्धार्थ पटेल स्क्वायर, पो. बा. सं. 4028, ओल्ड पट्टा रोड, बड़ौदा-390005 द्वारा विनिर्मित टाइप संस्था "एम. एस. ए. 15" और एम.एस. 15 मीरीज के (जल से अन्य) द्रवों के लिये मीटर के प्रतिमान का जिसे इसमें हमके पश्चात् प्रतिमान कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई. एन. डी./09/94/14 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है;



आकृति

हमके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि प्रतिमान के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अन्तर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धान्त के अनुसार और उन्हीं सामग्री से, जिनसे अनुमोदित प्रतिमान का विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित एम-4, एम-5 और एम-7 मीरीज के समरूप मीटर, शुद्धता और कार्यकरण वाले मीटर भी आधेगे;



प्रतिमान (आकृति देखिए) टाइप सं. एम.एस.ए. 15 और एम. 15 मीरीज से संबंधित (जल से अन्य) द्रवों के लिये मीटर है। यह प्रति मिनट 757 लीटर की अधिकतम प्रवाह दर और 75 लीटर की न्यूनतम प्रवाह दर के घनात्मक विस्थापन प्रकार का मीटर है। रजिस्टर अधिकतम 99999 लीटर तक संपर्कित कर सकता है और यह पुनर्नियोज्य है। इसकी 0.1 लीटर की न्यूनतम गणना है। सर्वयोग्य 99999999 लीटर तक रजिस्टर कर सकता है और यह पुनर्नियोज्य नहीं है।

[फा.सं. डब्ल्यू.एम. 21(54)/93]

राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 29th September, 1994

S.O. 2752.—Whereas the Central Government after considering the report submitted to it by the prescribed authority is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Model) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the Meter for liquids (Other than water) of type No. MSA-15 and belonging to 'M-15' series (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Liquid Controls (India) Pvt. Ltd., T-102, Siddharth Patel Square, P. Box No. 4028, Old Padra Road, Baroda-390005, and which is assigned the approval mark IND/09/94/14.



(Figure)

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall

also cover the meters of similar make, accuracy and performance of M-1, M-5 and M-7 series manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

The Model (see figure) is a Meter for liquids (Other than water) of type No. MSA-15 and belonging to 'M-15' series. It is a positive displacement type meter with a maximum flow rate of 757 litre per minute and a minimum flow rate of 75 litres. The register can display to a maximum of 99999 litres and is resettable. It has a least count of 0.1 litre. The totaliser can register upto 99999999 litres and is non-resettable.

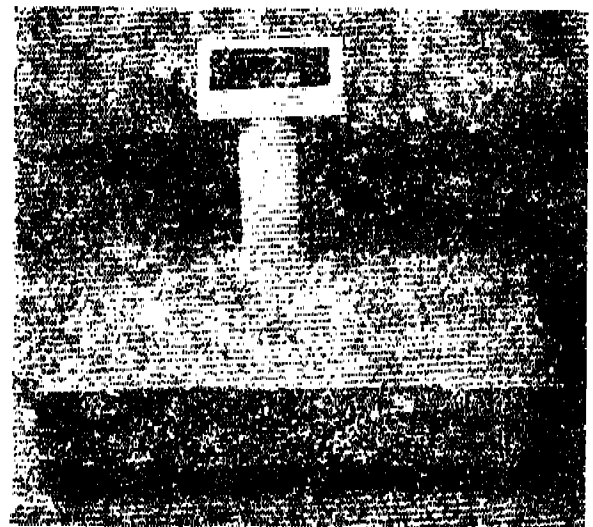
[F. No. WM-21(54)/93]

RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1994

का.प्रा. 2753.—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित प्रतिमान, बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (प्रतिमान का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबन्धों के अनुरूप है और यह संभावना है कि उक्त प्रतिमान लम्बी अवधि तक अविरत उपयोग के संबंध में ठीक बना रहेगा और परिवर्तित दशाओं में सही सेवा देगा;

अतः, प्रब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स इन्डोवेग इन्डियन मेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, 109 के.पी. पी. जॉयिंग सेंटर केनेलीबाव, बड़ीदा-3900018 द्वारा विनिर्मित "आई. डब्ल्यू. पी." मीरीज के और "इन्डोवेग" ब्रांड नाम वाले सार्वभूतक अस्तित्वान्वित, तोलन उपकरण के प्रतिमान का (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रतिमान कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई.एम.डी./09/94/18 सम्बन्धित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है;



आकृति

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि प्रतिमान के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अन्तर्गत उर्पा विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत के अनुसार

और उन्हीं सामग्री से जिनसे अनुमोदित प्रतिमान विनिर्माण किया गया है। विनिर्मित 60 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 250 किलोग्राम, 300 किलोग्राम, 500 किलोग्राम, 600 किलोग्राम, 800 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम, 1200 किलोग्राम, 1500 किलोग्राम और 2000 किलोग्राम की अधिकतम क्षमता वाले उसी निरीज के समरूप मैक, शुद्धता और कार्यकरण वाले तोलन उपकरण भी आएंगे।

प्रतिमान (आकृति देखिए) एक मध्यम शुद्धता (शुद्धता वर्ग 3) वाला तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 100 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 400 ग्राम है। सत्यापन अंतर (ई) 20 ग्राम है। एक प्रतिशत प्रतिधारित टैरे प्रभाव सहित एक टैरे युक्ति है। ढांचा और भार अभिग्राहक क्रमशः मृदु इस्पात और स्टेनलेस स्टील का लेना है। भार अभिग्राहक की आकृति आयताकार है जिसका आकार 600 मिलीमीटर × 450 मिलीमीटर है। प्रकाश उत्सर्जक डायड प्रदर्श तोल परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती द्वारा बिजुत प्रदाय पर चलाया जाता है।

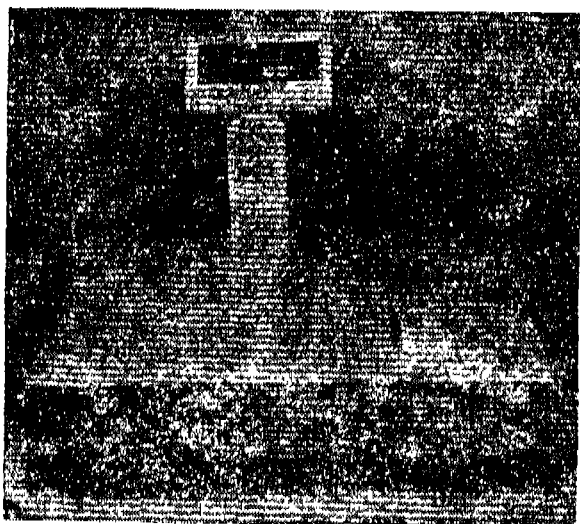
[फा.सं. डब्ल्यू.एम 21(51)/92]

राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 29th September, 1994

S.O. 2753.—Whereas the Central Government after considering the report submitted to it by the prescribed authority is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Model) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes, the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic weighing instrument of 'IWP' series with brand name "INNO WEIGH" (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M.S. Inno Weigh Equipments Private Limited, 109, K. P. Shopping Centre, Kareli Bag, Baroda-3900018 and which is assigned the approval Mark (IND/09/94/18).



(Figure)

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of the same series with a maximum capacity of 60 kilogram, 200 kilogram, 250 kilogram, 300 kilogram, 500 kilogram, 600 kilogram, 800 kilogram, 1000 kilogram, 1200 kilogram, 1500 kilogram and 2000 kilogram manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

The Model (see figure) is a medium accuracy (Accuracy Class-III) weighing instrument with a maximum capacity of 100 kilogram and a minimum capacity of 400 gram. The verification interval (e) is 20 gram. It has a tare device with a 100 per cent retained tare effect. The housing and the load receptor are made up of mild steel and stainless steel respectively. The load receptor is of rectangular shape with dimension 600 millimetre × 450 millimetre. The Light Emitting Diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts, 50 hertz alternate current power supply.

[F. No. WM-21(51)/92]

RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1994

का.आ. 2754.—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित प्रतिमान, बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (प्रतिमान का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और यह संभावना है कि उक्त प्रतिमान लम्बी अवधि तक अविरत प्रयोग के संबंध में ठीक बना रहेगा और परिवर्तित दशाओं में सही सेवा देगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेसर्स इन्नो वेग इक्विपमेंट्स प्रा. लि., 109 के.पी. शापिंग सेंटर करेली बाग, बड़ौदा-3900018 द्वारा विनिर्मित "आई डब्ल्यू.टी." निरीज के और "इन्नोवेग" ब्रांड नाम वाले स्वतः सूचक, अस्वचालित तोलन उपकरण के प्रतिमान का (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रतिमान कहा गया है) और जिसे



अनुमोदन चिन्ह आई.एन.डी./09/94/19 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।



इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार, उपर धारा की उप-धारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि प्रतिमान के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अन्तर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी शिखों के अनुसार और उन्हीं सामग्री से, जिनमें अनुमोदित प्रतिमान का विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 25 किलोग्राम, 30 किलोग्राम और 50 किलोग्राम की अधिकतम क्षमता वाले उसी शिरीज के समरूप मैक, शुद्धता और कार्यकरण वाले तोलन उपकरण भी आएगा।

प्रतिमान (आकृति देखिए) एक मध्यम शुद्धता (शुद्धता वर्ग 3) वाला तोलन उपकरण जिसकी अधिकतम क्षमता 20 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 100 ग्राम है। स्थापन अंतर (ई.) 5 ग्राम है इसमें एक प्रतिशत प्रतिधारित टैरे मुद्रित है। डाँचा और भार अभिग्राहक मृदु इस्थान का बना है। भार कृभिग्राहक की आकृति आयताकार है जिसका आकार 100 मिलीमीटर × 150 मिलीमीटर है। प्रकाश उत्सर्जक डायड प्रदर्श तोल परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्टज के प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत प्रवाय पर चलाया जाता है।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-21(51)/92]

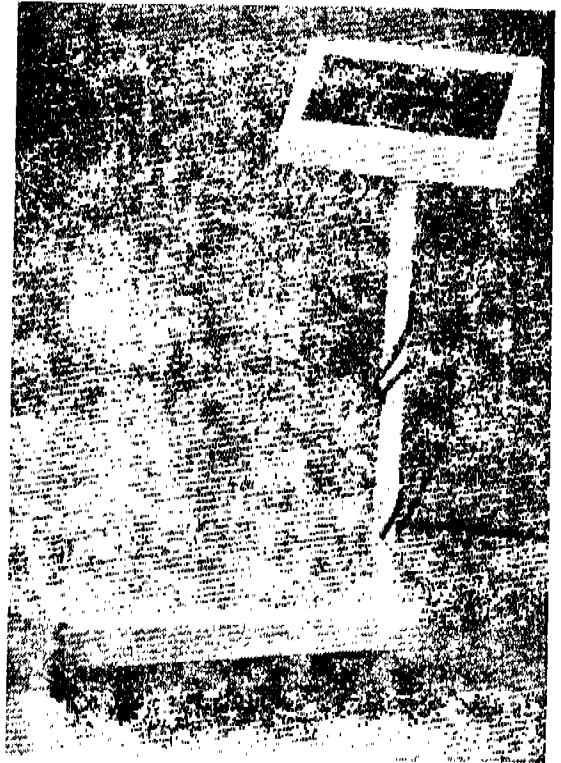
राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 29th September, 1994

S.O. 2754.—Whereas the Central Government after considering the report submitted to it by the prescribed authority is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights

and Measures Act, 1976 (60 of 1976), and the Standards of Weights and Measures (Approval of Model) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes, the certificate of approval of the Model of the self indicating, non-automatic weighing instrument of 'IWT' series with brand name 'INNO WEIGH' (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M.S. Inno Weigh Equipments Private Limited, 109, K. P. Shopping Centre, Kareli Bauge, Baroda-390018 and which is assigned the approval Mark IND/09/94/19.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of the same series with a maximum capacity of 500 gram, 1 kilogram, 5 kilogram, 10 kilogram, 15 kilogram, 25 kilogram, 50 kilogram and 50 kilogram manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

The Model (see figure) is a medium accuracy (Accuracy Class-III) weighing instrument with a maximum capacity of 20 kilogram and a minimum capacity of 100 gram. The verification interval (e) is 5 gram. It has a tare device with a 100 per cent retained tare effect. The housing and the load receptor are made up of mild steel. The load receptor is of rectangular shape with dimension 100 millimetre × 150 millimetre. The Light Emitting Diode display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts, 50 hertz alternate current power supply.

[F. No. WM-21(51)/92]

RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1994

का.ग्रा. 2755.—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित प्रतिमान, बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60)

तथा बाट और माप मानक (प्रतिमान का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और यह संभावना ( कि उक्त प्रतिमान लम्बी अवधि तक अपरिणत उपयोग के सबंध में ठीक बना रहेगा और परिवर्तित दशाओं में भी सेवा देगा,

अतः अत्र, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स शारित्रदान इंटरप्राइजेज, कैलाश भवन, मं. घू. शाह कॉलेज के पीछे ब्रायम रोड, अहमदाबाद-380014 द्वारा विनिर्मित टाइप संख्या एम.पी.पी. 100 के और प्राद नाम वाले एम. पी.पी. मिरीज के स्वतः सूचक, अस्वचालित तोलन उपकरण के प्रतिमान का (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रतिमान कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/94/11 समनु-देशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

क्षमता 100 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 400 ग्राम है। स्थापन अंतर (ई) 20 ग्राम है। इसमें एक ऐसी टैर्युक्ति है, जिसका व्यक्तनात्मक प्रतिधारित टैर प्रभाव अतः प्रतिशत है। आधार और प्लेटफार्म मृदु इस्पात का बना है। आयताकार प्लेटफार्म 400 मिलीमीटर 530 मिलीमीटर आकार का है। 12 मिलीमीटर संप्रतीक आकार का प्रदीपितशील नियत प्रदीपितशील प्रदर्श तोल परिणाम उपदर्शित करता है। यह उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्स के प्रत्यावर्तनधारा विद्युत प्रदाय पर चलाया जाता है।

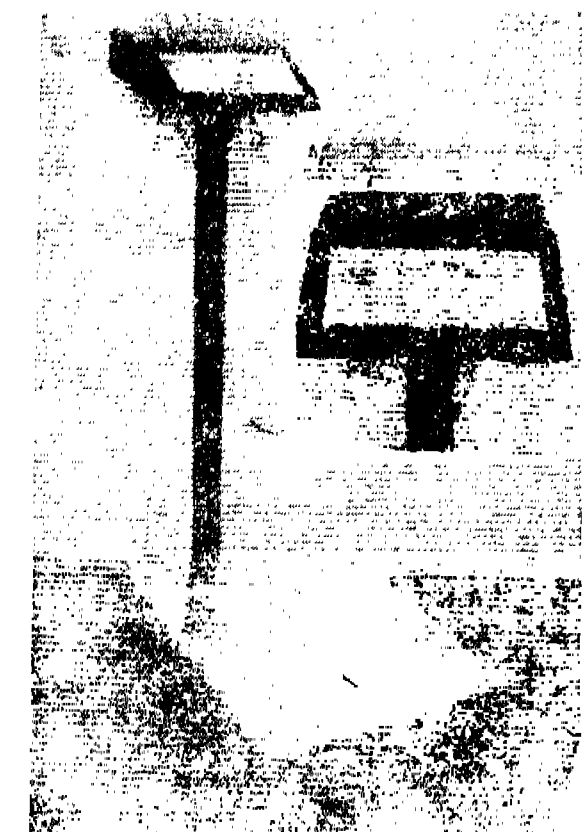
[फा.सं. डब्ल्यूएम 21(24)/92]

प्रदीप बैजल, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 29th September, 1994

S.O. 2755.—Whereas the Central Government after considering the report submitted to it by the prescribed authority is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of Model of self-indicating, non-automatic weighing instrument of type number SPP-100 and belonging to 'SPP' series with brand name 'PROMPT' (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Orbitron Enterprises, Kailash Bhavan, Behind C. U. Shah College, Ashram Road, Ahmedabad-380014, and which is assigned the approval mark IND/02/91/11;



इसके अनुरिक्त केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा के अधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि प्रतिमान के अनुमोदन के इन प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी मिहान के अनु-सार और उन्हीं मागगी से, जिनमें अनुमोदित प्रतिमान का विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित 30 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 150 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 500 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम और 1500 किलोग्राम की अधिकतम क्षमता वाले उन्हीं मिरीजों के सम्पूर्ण मेक, शुद्धता और कार्यकरण वाले तोलन उपकरण भी जायेंगे।

प्रतिमान (आकृति देखिए) एक मध्यम शुद्धता (शुद्धता वर्ग 3) वाला तोलन उपकरण है, जिसकी अधिकतम



Further, in exercise of powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of the same series with a maximum capacity of 30 kilogram, 50 kilogram, 150 kilogram, 200 kilogram, 500 kilogram, 1000 kilogram and 1500 kilogram manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle and with the same material with which the approved Model has been manufactured.

The Model (see figure) is a medium accuracy (Accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 100 kilogram and a minimum capacity of 400 gram. The verification scale interval (e) is 20 gram. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The base and the platform are made up of mild steel. The rectangular platform is of size 400 millimetre × 530 millimetre. The vacuum fluorescent display of character size 12 millimetre indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volt, 50 hertz alternate current power supply.

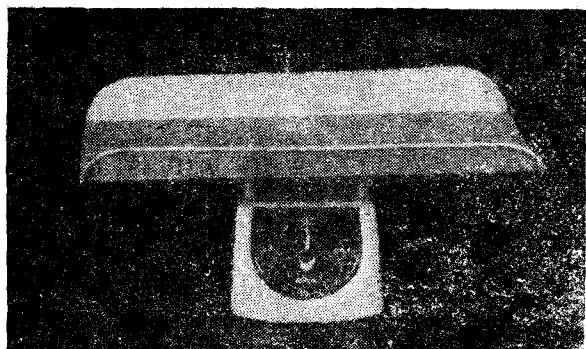
[F. No. WM-21(24)/92]

PRADIP BAIJAL, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1994

का.आ. 2756.—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करी के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में, वर्णित प्रतिमान, बाट और माप मानक अधिनियम 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (प्रतिमान का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और यह संभावना है कि उक्त प्रतिमान लम्बी अवधि तक अविरत उपयोग के संबंध में ठीक बना रहेगा और परिवर्तित दशाओं में सही सेवा देगा ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स डॉकवेल इंडस्ट्रीज, 3/17, आसफअली रोड, नई दिल्ली 110002 द्वारा विनिर्मित "ब्रॉन" नाम वाले स्वतः सूचक, अस्वचलित तोलन उपकरण के प्रतिमान का (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रतिमान कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई.एन.डी./09/94/10 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है,



आकृति

प्रतिमान (आकृति देखिए) एक साधारण शुद्धता (शुद्धता वर्ग 3 वाला तोल उपकरण है, जिसकी अधिकतम क्षमता 10 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 1 किलोग्राम है। सत्यापन अन्तर (ई.) 50 ग्राम है इस शून्य समायोजन युक्ति है। आधार और तुलाई के पलड़े इस्पात के बने हैं। तुलाई पलड़े का आकार 483 मिली मीटर × 280 मिली मीटर × 70 मिलीमीटर है।

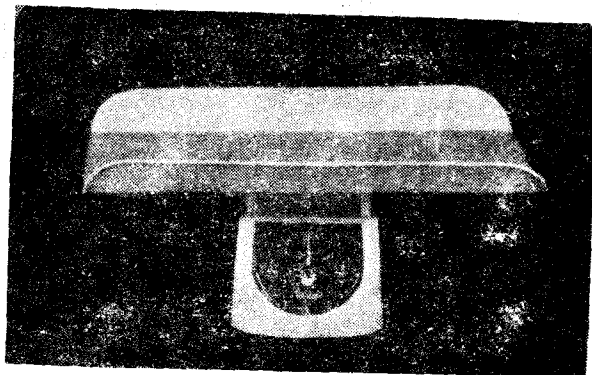
[फा.सं. डब्ल्यू.एम.-21(47)93]

राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 30th September, 1994

S.O. 2756.—Whereas the Central Government after considering the report submitted to it by the prescribed authority is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976, (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of Model of self-indicating non-automatic weighing instrument with brand name 'BRAUN' (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Docbel Industries, 3/17, Asaf Ali Road, New Delhi-110 002, and which is assigned the approval mark IND/02/94/10.



(Figure)

The Model (see figure) is an ordinary accuracy (Accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 10 kilogram and a minimum capacity of 1 kilogram. The verification scale interval (e) is 50 gram. It has a zero adjustment device. The base and the weighing pan are made up of steel. The weighing pan is of dimension 483 millimetre × 280 millimetre × 70 millimetre.

[F. No. WM-21 (47)/93]

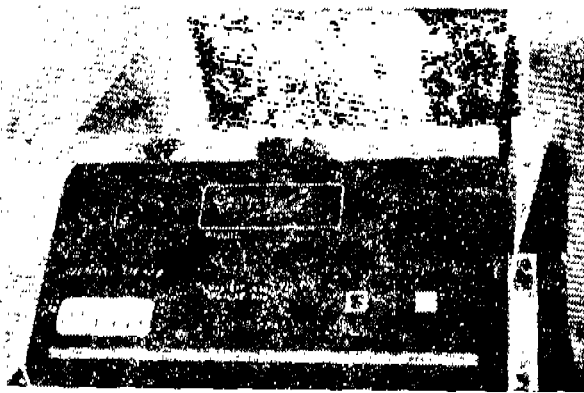
RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1994

का.आ. 2757.—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित प्रतिमान, बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (प्रतिमान का अनुमोदन) नियम, 1987 उपबंधों के अनुरूप है और यह संभावना है कि उक्त प्रति-

मान लम्बी अवधि तक अविरत उपयोग के संबंध में ठीक बना रहेगा और परिवर्तित दशाओं में सही सेवा देगा ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स सीकेल मिस्टम्स एंड सर्विसेज, 3 हराल कुटीर लिंकिंग रोड, बीर शेवे हाउसिंग कोऑपरेटिव, सोसायटी लिमिटेड चिंचोली बंदर रोड, मलाड वेस्ट मुम्बई-400064 द्वारा विनिर्मित "टी.टी.एस." मिरोज के और "केल" ब्रांड नाम वाले स्वतःसूचक, अस्वचालित तौलन उपकरण के प्रतिमान का (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रतिमान कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई.एन.डी./09/94/20 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकशित करती है।



आकृति

इसके अनिवार्य केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि प्रतिमान के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी मिश्रांत के अनुसार और उन्हीं सामग्री से जिनसे अनुमोदित प्रतिमान का विनिर्माण किया गया है। विनिर्माण 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलो ग्राम 10 किलोग्राम 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, और 30 किलोग्राम की अधिकतम क्षमता वाले उसी मिरोज के समरूप सेक, बूझना और कार्यकरण वाले तौलन उपकरण भी आएंगे ;

प्रतिमान (आकृति देखिए) एक मध्यम श्रेणी (शुद्धता वर्ग 3) वाला तौलन उपकरण है, जिसकी अधिकतम क्षमता 5 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 20 ग्राम है। सन्वयन अंतर (ई) 20 ग्राम है। इसके एक ऐसी टेरे युक्ति है जिसका प्रतिप्रति टेरे प्रभाव का प्रतिशत है, ढांचा और भार अभिग्राहक क्रमशः गुरु हस्तान और स्टेनलेस स्टील का बना है, भार अभिग्राहक की आकृति आयताकार है जिसका आकार 230 मिलीमीटर × 290 मिलीमीटर है। उपकरण 230 वोल्ट 50 हर्टज के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर चलाया जाता है।

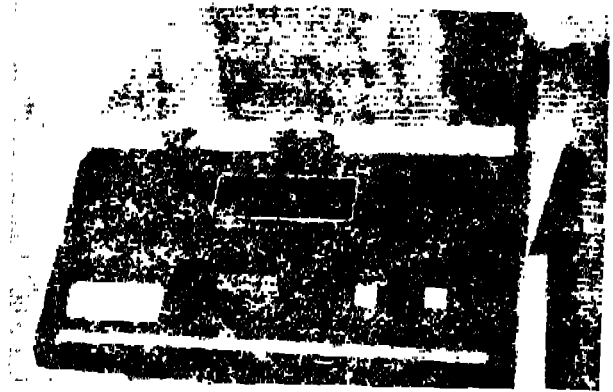
[फा.सं. उन्वय.एम. 21(41)93]

संजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 30th September, 1994

S.O. 2757.—Whereas the Central Government after considering the report submitted to it by the prescribed authority is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976, (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self indicating non-automatic weighing instrument of 'TTM' series and with brand name 'MECHEL' (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Mechel systems and services, 3, Haral kutir linking Road, Veer Shevo Housing Co-op. Society Ltd., Chincholi Bunder Road, Malad West, Bombay-400 064 and which is assigned the approval Mark IND/09/94/20.



(Figure)

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series and with maximum capacity of 500 gram, 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram, 10 kilogram, 15 kilogram, 20 kilogram and 30 kilogram manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle and with the same materials with which the approved Model has been manufactured

The Model (see figure) is a medium accuracy (accuracy class II) weighing instrument with a maximum capacity of 5 kilogram and a minimum capacity of 20 grams. The verification interval (e) is 1 gram. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The housing and the load receptor are made up of mild steel and stainless steel respectively. The load receptor is of rectangular shape with dimension 230 millimetre × 290 millimetre. The instrument operates on 230 volts, 50 hertz alternate current power supply.

[F. No. WM-21 (4)/93]

RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 30. सितम्बर, 1994

फा.सं. 2758.—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित प्रतिमान, बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976

का 60) तथा बाट और माप मानक (प्रतिमान का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और यह संभावना है कि उक्त प्रतिमान लम्बी अवधि तक अविरत उपयोग के संबंध में ठीक बना रहेगा और परिवर्तित दशाओं में सही सेवा देगा;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सैमस सैन्यों मीटर एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट सं. बी. 51, परि-रमण गमदी, जी.आई.डी.सी., बड़ौदा गुजरात-391243 द्वारा विनिर्दिष्ट "सैन्यों" ब्रांड नाम वाले टैक्सी मीटर के प्रतिमान का, जिसे अनुमोदन चिह्न आई.एन.डी./10/94/15 समनुदशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र प्रकाशित करती है।



and Measures Act, 1976, (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1989 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;



Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the Taxi Meter with brand name 'SANYO' (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s. Sanyo meter and Electronics Pvt. Ltd., Plot No. B. 51, Por-Raman Gandhi, GIDC, Baroda, Gujarat-391243 which is assigned the approval Mark IND/10/94/15.

The Model (see figure) is a Taxi meter of mechanical type. The maximum fare display is Rs. 99.90 p. The control mechanism at the back can be set in three different positions namely 'FOR HIRE', 'HIRED' and 'TO PAY'. In addition to the above, units counter, Trips counter, kilometer counter and paid kilometers counter may be allowed to be provided.

[F. No. WM-21(58)/93]  
RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1994

प्रतिमान (आकृति 1 देखिए) एक यांत्रिक प्रकार का टैक्सी मीटर है। अधिकतम किराया प्रदर्शन 99 रुपए, 90 पैसे हैं। पृष्ठ भाग में नियंत्रण यंत्रावली को तीन भिन्न-भिन्न स्थिति में, अर्थात्, "किराए के लिए" "किराए का" "भुगतान के लिए" व्यवस्थिति किया जा सकता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त यूनिट काउंटर, फेरा काउंटर, किलोमीटर काउंटर और संकुल किलोमीटर काउंटर की व्यवस्था करने की अनुज्ञा दी जा सकती है।

[फा. सं. डब्ल्यू.एम. 21(58)93]

राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

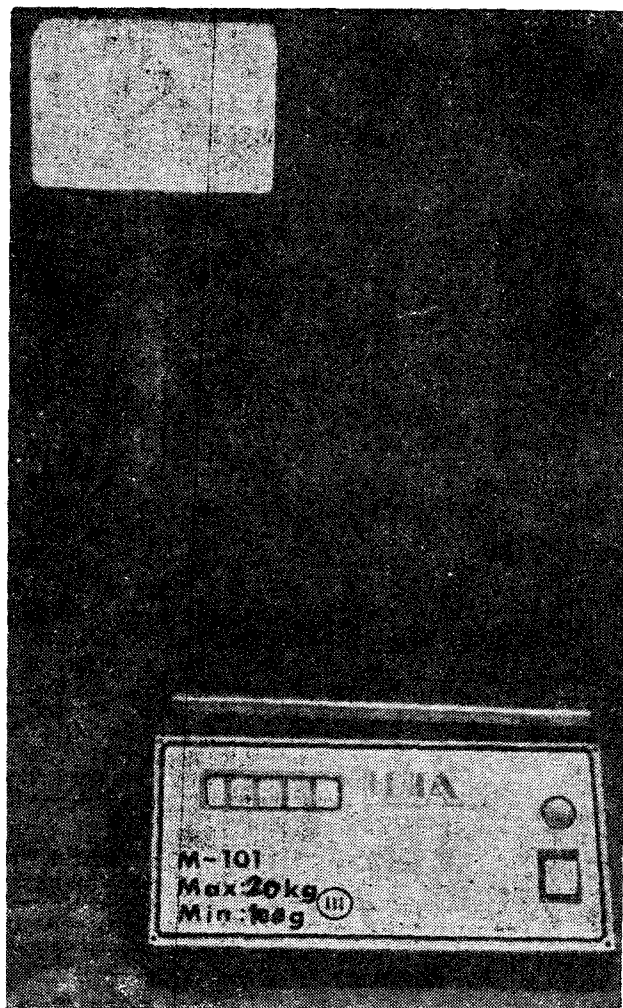
New Delhi, the 30th September, 1994

S.O. 2758.—Whereas the Central Government after considering the report submitted to it by the prescribed authority is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights

का.आ. 2759.—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करते के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित प्रतिमान, बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60 तथा बाट और माप मानक (प्रतिमान का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और यह संभावना है कि उक्त प्रतिमान लम्बी अवधि तक अविरत उपयोग के संबंध में ठीक बना रहेगा और परिवर्तित दशाओं में सही सेवा देगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सैमस तनशाइत इलेक्ट्रॉनिक्स 114, पहला तल, मंगलमूर्ति काम्पलेक्स, आशम रोड, अहमदाबाद-380009 द्वारा विनिर्दिष्ट टैक्सी संख्यांक "एम 101" और "सैन्यों" ब्रांड नाम वाले स्वतः भूतक, अस्वचलित, तालन उपकरण के प्रतिमान

का (जिसे इसके इसके पश्चात् प्रतिमान कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई.एन.डी./09/94/16 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाण-पत्र प्रकाशित करती है;



प्रतिमान (आकृति देखिए) (एक मध्यम शुद्धता (शुद्धता वर्ग 3) वाला तोलन उपकरण है, जिसकी अधिकतम क्षमता 20 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 100 ग्राम है। सत्यापन अंतर (ई.) 5 ग्राम है। इसमें एक ऐसी टेरे युक्ति है जिसका प्रतिधारित टेरे प्रभाव शत-प्रतिशत है। भार अभिग्राहक की जो वर्गीकार आकृति का है, पार्श्व लम्बाई 250 किलोमीटर है। सात खंडीय प्रकाश उत्सर्जक डायोड तोल परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर चलाया जाता है।

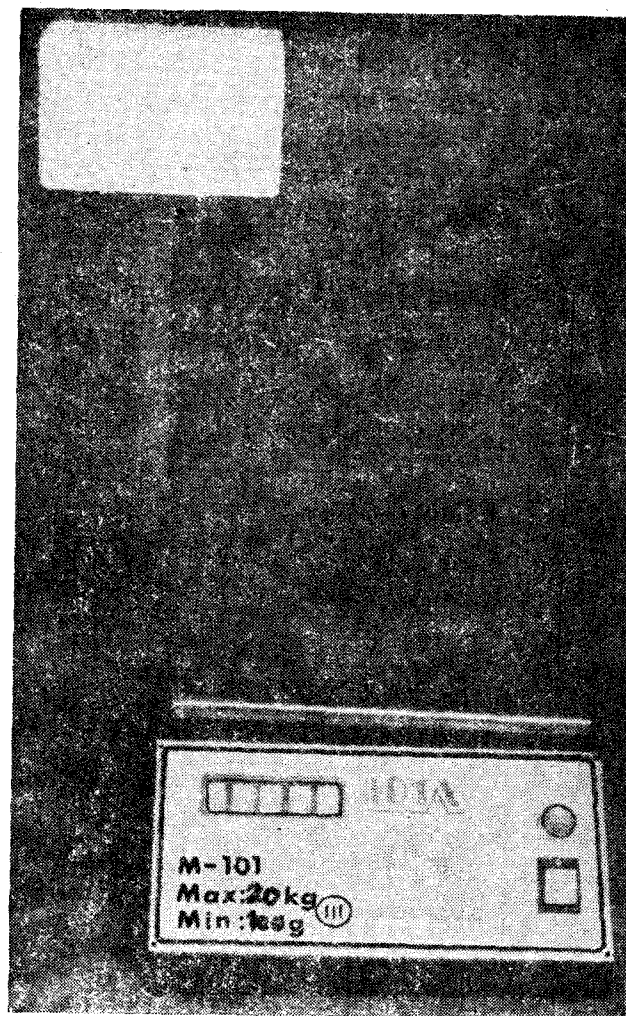
[फा. सं. डब्ल्यू.एम. 21/6/93]

राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 30th September, 1994

S.O. 2759.—Whereas the Central Government after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976, (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Model) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self indicating non-automatic weighing instrument of type number 'M-101' and with brand name 'IOTA' (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/S. Sunshine Electronics, 114, I Floor, Mangal-Murti Complex, Ashram Road, Ahmedabad-380 009, and which is assigned the approval mark IND/09/94/16.



Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series and with maximum capacity of 200 gram, 500 gram, 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram, 5 kilogram and 10 kilogram manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

The Model (see figure) is a medium accuracy (Accuracy class III), weighing instrument with a maximum capacity of 20 kilogram and a minimum capacity of 100 gram. The verification interval (e) is 5 gram. It has a tare device with a 100 per cent subtractive retained tare effect. The load receptor which is square in shape has the side length of 250 millimetre. The seven segment Light Emitting Diode indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts, 50 hertz alternate current power supply.

[F. No. WM-21 (6)/93]  
RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.



## पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

का.आ. 2760.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में विजयपुर से दादरी तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और यतः वह प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पावद्य अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1992 (1992 का 20) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

वर्णित कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय विद्यालय चौराहा, ए.बी. रोड, शिवपुरी (म.प्र.) को इस अधिसूचना की तारीख से इन दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसी आपत्ति करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह चाहता है कि इसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

## अनुसूची

विजयपुर-दादरी गैस पाइपलाइन परियोजना

जोड़

8.7808

ग्राम : राखेरा तहसील : जौरा जि. ला. मोरेना  
क्रमांक खसरा नं. सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें आर.ओ.यू. अध्यापित किया जाना है (हेक्टेयर में)

ग्राम बृजगढ़ी

ग्राम : राखेरा

01.	201	0.0690
02.	157	0.1410
03.	158	0.0030
04.	159	0.0347
05.	156	0.2713
06.	155	0.0850
07.	153	0.0090
08.	152	0.0660
09.	151	0.0405
10.	150	0.0025
11.	149	0.7220

01.	962	0.1200
02.	963	0.0600
03.	964	0.0345
04.	965	0.0480
05.	966	0.0390
06.	967	0.0420
07.	958	0.3960
08.	957	0.1690
09.	956	0.2460
10.	955	0.0248
11.	949	0.1980
12.	948	0.2100
13.	946	0.0240
14.	581	0.2010
15.	582	0.1593
16.	580	0.0012
17.	586	0.1234
18.	584	0.1347

1	2	3		
			05. 49	0. 2484
19. 585		0. 0156	06. 46	0. 2160
20. 587		0. 1555	07. 47	0. 0980
21. 609		0. 2351	08. 50	0. 0065
22. 608		0. 2310	09. 48	0. 0540
23. 606		0. 0578	10. 45	0. 0220
24. 605		0. 1360	11. 44	0. 0270
25. 603		0. 2700	12. 43	0. 4397
26. 602		0. 0008	13. 32	0. 2220
27. 601		0. 1066	14. 33	0. 0297
28. 633		0. 2601	15. 29	0. 0108
29. 635		0. 0900	16. 28	0. 0970
30. 638		8. 0300	17. 27	0. 0756
31. 643		0. 1050	18. 26	0. 0650
32. 639		0.2055		
33. 641		0. 0660	जोड़	3. 8635
34. 640		0.0300		
35. 274		0. 2443	ग्राम : मरा	
36. 272		0. 0172	01. 257	0. 0756
37. 276		0. 0112	02. 266	0. 3464
38. 275		0. 0033	03. 267	0. 1296
39. 271		0. 1312	04. 268	0. 2376
40. 268		0. 2000	05. 269	0. 0015
41. 267		0. 0270	06. 234	1. 0476
42. 265		0. 1350	07. 233	0. 2160
43. 263		0. 1785	08. 162	0. 5508
44. 262		0. 4090	09. 216	0. 2484
45. 261		0. 2725	10. 215	0. 0758
46. 260		0. 0710	11. 172	0. 0756
47. 694		0. 6538	12. 173	0. 2700
48. 695		0. 4450	13. 174	0. 1080
49. 693		0. 9447	14. 177	0. 3564
50. 692		0. 8595	15. 208	0. 2160
51. 700		0. 4104	16. 207	0. 0065
52. 701		0. 9301	17. 110	0. 0324
53. 711		0. 9955	18. 182	0. 0864
54. 710		0. 8475	19. 187	0. 3300
55. 709		0. 4725	20. 188	0. 0088
56. 714		0. 3765	21. 186	0. 0432
57. 706		1. 0800	22. 185	0. 1400
			23. 190	0. 0648
	जोड़	13. 9416	24. 191	0. 3132
			25. 13	0. 7884
ग्राम : हृगियापुरा			26. 10	1. 2204
01. 58		0. 9396	27. 9	0. 2700
02. 57		0. 9504	28. 7	0. 9400
03. 55		0. 3348		
04. 54		0. 0270	जोड़	8. 1994



ग्राम : भज्जे का पुरा, तहसील : जोरा, जिला-मोरेना			1	2	3
क्रमांक	खसरा नं.	सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें आर.ओ.यू. अध्यापित किया जाना है। (हेक्टेयर में)			
01.	69	1.7822	05.	156	0.2713
02.	29	1.2744	06.	155	0.0580
03.	31	1.0800	07.	153	0.0090
04.	32	1.0152	08.	152	0.0660
05.	23	1.0260	09.	151	0.0405
06.	22	1.4472	10.	150	0.0025
07.	13	2.3760	11.	149	0.7220
08.	12	0.9288	12.	107	0.2280
09.	11	0.0540	13.	132	0.1331
10.	10	1.2636	14.	131	0.0498
11.	1	2.9052	15.	113	0.2090
जोड़ :			16.	57	0.1221
			17.	109	0.2217
			18.	60	0.0680
			19.	61	0.1410
			20.	64	0.0938
			21.	63	0.0586
			22.	65	0.1320
			23.	66	0.1230
			24.	90	0.1530
			25.	89	0.1320
			26.	88	0.1260
			27.	87	0.2310
			28.	16	0.1965
			29.	15	0.2370
			30.	94	1.1175
			31.	104/1	0.3750
			32.	95/2	0.3690
			33.	95/3	0.2580
			34.	96/3	0.2820
			35.	91	0.0315
			36.	7	0.7050
			37.	1	1.5432
			Total		8.7808
			01.	962	0.1200
			02.	963	0.0600
			03.	964	0.0345
			04.	965	0.0480
			05.	966	0.0390
			06.	967	0.0420
			07.	958	0.3960
			08.	957	0.1690
			09.	956	0.2460
			10.	955	0.0248
			11.	949	0.1980
			12.	948	0.2100
			13.	946	0.0240
			14.	581	0.2010
			15.	582	0.1693
			16.	580	0.0012
			17.	586	0.1234
			18.	584	0.1347
			19.	685	0.0156
			20.	587	0.1555
			21.	609	0.2351
			22.	608	0.2310
			23.	606	0.0578
			24.	605	0.1360
			25.	603	0.2700
			26.	602	0.0008
			27.	601	0.1066
			28.	633	0.2601
			29.	635	0.0900

[सं. एल-14016/11/94-जी. पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 22nd September, 1994

S.O. 2760.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural gas from Vijaipur to Dadri in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the Land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Limited, Bhartiya Vidyalyaya Chauraha, A. B. Road, Shivpuri (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

[No. L-14016/11/94-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director.

## SCHEDULE

Vijaypur—Dadri Gas Pipeline project

Village Rakhera, Tehsil Jaura, Distt. Morena

Sl. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
01.	201	0.0690
02.	157	0.1410
03.	158	0.0030
04.	159	0.0347

1	2	3			
30.	638	0.0300	15.	208	0.2160
31.	641	0.1050	16.	207	0.0065
32.	639	0.2055	17.	110	0.0324
33.	641	0.0660	18.	182	0.0864
34.	640	0.0300	19.	187	0.3300
35.	274	0.2443	20.	188	0.0088
36.	272	0.0172	21.	186	0.0432
37.	276	0.0122	22.	185	0.1400
38.	275	0.0033	23.	190	0.0648
39.	271	0.1312	24.	191	0.3132
40.	268	0.2000	25.	13	0.7884
41.	267	0.0270	26.	10	1.2204
42.	265	0.1350	27.	9	0.2700
43.	263	0.1785	28.	7	0.9400
44.	262	0.4090			
45.	261	0.2725	Total		8.1994
46.	260	0.0710			
47.	694	0.6538	01.	69	1.7828
48.	695	0.4450	02.	29	1.2744
49.	693	0.9447	03.	31	1.0800
50.	692	0.8695	04.	32	1.0152
51.	700	0.5104	05.	23	1.0260
52.	701	0.9301	06.	22	1.4472
53.	711	0.9965	07.	13	2.3760
54.	710	0.8475	08.	12	0.9288
55.	709	0.5725	09.	11	0.0540
56.	714	0.3765	10.	10	1.2636
57.	706	1.0800	11.	1	2.9052
Total		13-9416	Total		15.1532
01.	68	0.9396			
02.	57	0.9504			
03.	55	0.3348			
04.	54	0.0270			
05.	49	0.2584			
06.	46	0.2160			
07.	47	0.9980			
08.	40	0.0065			
09.	48	0.0540			
10.	45	0.0220			
11.	44	0.0270			
12.	43	0.4497			
13.	32	0.2220			
14.	33	0.0278			
15.	29	0.0108			
16.	28	0.0970			
17.	27	0.0756			
18.	26	0.0650			
Total		3.8635			
01.	257	0.0756			
02.	266	0.3464			
03.	267	0.1296			
04.	268	0.2376			
05.	269	0.0015			
06.	234	1.0476			
07.	233	0.2160			
08.	162	0.5508			
09.	216	0.2484			
10.	215	0.0758			
11.	172	0.0756			
12.	173	0.2700			
13.	174	0.1080			
14.	177	0.3564			

[No. L-14016/11/94-G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

का.आ. 2761.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में बिजयपुर से दादरी तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पाइप-लाइन बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन), अधिनियम, 1962 (1962 का 20) की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

वर्तते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय विद्यालय चौराहा, ए.बी. रोड, गिबपूरी (म.प्र.) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

[No. L-14016/11/94-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

का.आ. 2761.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में विजयपुर से दादरी तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पाइप-लाइन बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन), अधिनियम, 1962 (1962 का 20) की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

वर्णित कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय विद्यालय चौराहा, ए.बी. रोड, शिवपुरी (म.प्र.) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसी आपत्ति करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप में हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।			1	2	3
अनुसूची					
विजयपुर दादरी गैस पाइपलाइन परियोजना					
ग्राम : एनबारा	तहसील : कोलारम	जिला : शिवपुरी			
क्रमांक	खमरा नं.	सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें ग्राम.ओ.यू. अध्यापित किया जाना है (हेक्टेयर में)			
1	2	3	जोड़		7.1689
01.	728	0.0600	ग्राम : कुलबारा		
02.	730	0.4425	01.	456	0.0385
03.	733	0.3030	02.	469	0.2803
04.	738	0.3240	03.	467	0.0040
05.	737	0.1410	04.	468	0.0468
06.	646	0.0450	05.	470	0.3463
07.	644	0.1000	06.	471	0.0240
08.	647	0.0077	07.	472	0.0250
09.	648	0.0549	08.	473	0.0385
10.	643	0.0272	09.	441	0.1679
11.	641	0.1704	10.	432	0.0600
12.	642	0.2430	11.	433	0.2790
13.	634	0.0469	12.	431	0.1590
14.	638	0.1931	13.	434	0.4650
15.	636	0.2580	14.	298	0.0600
16.	597	0.2797	15.	210	0.0600
17.	156	0.0024	16.	209	0.0975
18.	157	0.1095	17.	207	0.2295
19.	161	0.1988	18.	206	0.2415
20.	134	0.0707	19.	205	0.3420
21.	165	0.0245	20.	192	0.4050
22.	119	0.1335	21.	194	0.3918
23.	120	0.4524	22.	195	0.0192
24.	117	0.0245	जोड़		3 7808
25.	116	0.1987	[सं. 14016/11/94-जी.पी.]		
26.	76	0.0540	अध्वेन्दु सैन निदेशक		
27.	115	0.0152	New Delhi, the 22nd September, 1994		
28.	78	0.1566	S.O. 2761.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural gas from Vijaipur to Dadri in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.		
29.	77	0.0168	And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.		
30.	75	0.0252	Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.		
31.	70	0.0297			
32.	69	0.0768			
33.	68	0.1280			
34.	64	0.0266			
35.	67	0.5077			
36.	66	0.2842			
37.	30	0.0038			

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Limited, Bhartiya Vidyalya Chauraha, A. B. Road, Shivpuri (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

### SCHEDULE

Vijaypur-Dadri Gas Pipeline Project.

Village : Anwara, Tehsil : Kolaras, Distt: Shivpur.

Sr.No.	Survey No.	Ara to be acquired for R.O.U. in Hectare.
1	2	3
01.	728	0.0600
02.	730	0.4425
03.	733	0.3030
04.	738	0.3240
05.	737	0.1410
06.	646	0.0450
07.	644	0.1000
08.	647	0.0077
09.	648	0.0549
10.	643	0.0272
11.	641	0.1704
12.	642	0.2430
13.	634	0.0469
14.	638	0.1931
15.	636	0.2580
16.	597	0.2797
17.	156	0.0024
18.	157	0.1095
19.	161	0.1988
20.	134	0.0707
21.	165	0.0245
22.	119	0.1335
23.	120	0.4524
24.	117	0.0245
25.	116	0.1987
26.	76	0.0540
27.	115	0.0152
28.	78	0.1566
29.	77	0.0168
30.	75	0.0252
31.	70	0.0297
32.	69	0.0768
33.	68	0.1280
34.	64	0.0266
35.	67	0.5077
36.	66	0.2842
37.	30	0.0038
38.	32	0.2295
39.	33	0.2175
40.	34	0.1454
41.	22	0.0234
42.	21	0.4291
43.	18	0.1410
44.	17	0.1740
45.	16	0.3690
46.	07	0.2040
Total		7.1689

1	2	3
01.	456	0.0385
02.	469	0.2803
03.	467	0.0040
04.	468	0.0468
05.	470	0.3463
06.	471	0.0240
07.	472	0.0250
08.	473	0.0385
09.	441	0.1679
10.	432	0.0600
11.	433	0.2790
12.	431	0.1590
13.	434	0.4650
14.	298	0.0600
15.	210	0.0600
16.	209	0.0975
17.	207	0.2295
18.	206	0.2415
19.	205	0.3420
20.	192	0.4050
21.	194	0.3918
22.	194	0.0192
Total		3.7808

[No. L-14016/11/94-G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director.

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

का.आ. 2762.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में विजयपुर से दादरी तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्पावस्त्र अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अमरा आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्त कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आपत्ति मक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय विद्यालय चौराहा ए.बी. रोड, शिवपुरी (म.प्र.) को इस अधिसूचना की तारीख में दस दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसी आपत्ति करने वाला हर व्यक्ति निर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

## सूची

विजापुर-दादरी गैस पाइपलाइन परियोजना

ग्राम : सिगाखेड़ी तहसील : कोलारम जिला : शिवपुरी

क्रमिक क्रमांक. सर्वे का क्षेत्रफल जिसमें ग्राम, ओ. यू. अध्यापित किया जाना है। (हेक्टेयर में)

01.	334	0.0280
02.	335	0.5717
03.	332	0.2725
04.	339	0.4910
05.	352	0.9410
06.	353	0.2527
07.	355	0.0330
08.	356	0.1935
09.	358	0.0342
10.	357	0.2133
11.	367	0.2333
12.	528	0.0824
13.	527	0.2053
14.	525	0.3878
15.	376	0.0032
16.	524	0.3000
17.	523	0.0735
18.	377	0.0120
19.	427	0.1734
20.	430	0.2010
21.	429	0.2797
22.	421	0.1823
23.	419	0.1712
24.	420	0.0006
25.	448	0.3889
26.	449	0.1320
27.	450	0.3820
28.	451	0.5800
29.	452	0.2140
जोड़		7.0335

[सं. एन-14016/7/94-जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 22nd September, 1994

S.O. 2762.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural gas from Vijapur to Dadri in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited,

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum, and 2241 GI/94—9

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Limited, Bhartiya Vidyalaya Chauraha, A.B. Road, Shivpuri (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

Vijapur-Dadri Gas Pipeline Project.

Village : Singakheri, Tehsil : Kolaras, Dist. : Shivpuri

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare.
1	2	3
01.	334	0.0280
02.	335	0.5717
03.	332	0.2725
04.	339	0.4910
05.	352	0.9410
06.	353	0.2527
07.	355	0.0330
08.	356	0.1935
09.	358	0.0342
10.	357	0.2133
11.	367	0.2333
12.	528	0.0824
13.	527	0.2053
14.	525	0.3878
15.	376	0.0032
16.	524	0.3000
17.	523	0.0735
18.	377	0.0120
19.	427	0.1734
20.	430	0.2010
21.	429	0.2797
22.	421	0.1823
23.	419	0.1712
24.	420	0.0006
25.	448	0.3889
26.	449	0.1320
27.	450	0.3820
28.	451	0.5800
29.	452	0.2140
Total		7.0335

[No. L-14016/7/94-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director.

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

का.प्र. 2763—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में विजापुर से दादरी तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और यत्न यह प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1992 (1992 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय विद्यालय चौराहा, ए.बी. रोड, शिवपुरी (म.प्र.) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसी आपत्ति करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो, या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

#### अनुसूची

विजयपुर-दादरी गैस पाइपलाइन परियोजना

ग्राम : बकसपुर तहसील : कोलारस जिला : शिवपुरी

क्रमांक खसरा नं. सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें आर.ओ.यू. अध्यापित किया जाना है। (हेक्टेयर में)

1	2	3
01.	607	0.3095
02.	608	0.3415
03.	609	0.0012
04.	595	0.0661
05.	598	0.2783
06.	596	0.3115
07.	597	0.0930
08.	600	0.0090
09.	411	0.4712
10.	414	0.1031
11.	415	0.0240
12.	417	0.2326
13.	420	0.0078
14.	421	0.0066
15.	422	0.0440
16.	385	0.0505
17.	384	0.3190
18.	172	0.1710
19.	376	0.0210

1	2	3
20.	374	0.1710
21.	175	0.1875
22.	174	0.1545
23.	177	0.1335
24.	179	0.0270
25.	154	0.1275
26.	180	0.0054
27.	153	0.1275
28.	152	0.0210
29.	150	0.2654
30.	148	0.2338
31.	159	0.0902
32.	59	0.0208
33.	60	0.0280
34.	61	0.0825
35.	62	0.2066
36.	67	0.2025
37.	63	0.0945
38.	138	0.0576
39.	139	0.0044
40.	135	0.1539
41.	136	0.2028
42.	196	0.2672
43.	130	5.0633
44.	129	0.4253
45.	197	0.1874
46.	127	0.3182
47.	128	0.0068
48.	116	0.0036
49.	130	0.3214
50.	117	0.0650
51.	119	0.5960
कुल		7.7130

[सं. एल-14016/7/94-जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 22nd September, 1994

S.O. 2763.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural Gas from Vijaipur to Dadri in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Limited, Bhartiya Vidyalyaya Chauraha A.B. Road, Shivpuri (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

#### Vijaypur Dadri Gas Pipeline Project

Village : Bakaspar Tehsil : Kolaras Distt. Shivpuri

1	2	3
01.	607	0.3095
02.	608	0.3415
03.	609	0.0012
04.	595	0.0661
05.	598	0.2783
06.	596	0.3115
07.	597	0.0930
08.	600	0.0090
09.	411	0.4712
10.	414	0.1031
11.	415	0.0240
12.	417	0.2326
13.	420	0.0078
14.	421	0.0066
15.	422	0.0440
16.	385	0.0505
17.	384	0.3190
18.	172	0.1710
19.	376	0.0210
20.	374	0.1710
21.	175	0.1875
22.	174	0.1545
23.	177	0.1335
24.	179	0.0270
25.	154	0.1275
26.	180	0.0054
27.	153	0.1275
28.	152	0.0210
29.	150	0.2654
30.	148	0.2338
31.	159	0.0902
32.	59	0.0003
33.	60	0.0280
34.	61	0.0825
35.	62	0.2066
36.	67	0.2025
37.	63	0.0945
38.	138	0.0576
39.	139	0.0044
40.	135	0.1539
41.	136	0.2028
42.	196	0.2672
43.	130	0.0632
44.	129	0.4253
45.	197	0.1874
46.	127	0.3182
47.	128	0.0068
48.	116	0.0036
49.	120	0.3214
50.	117	0.0650
51.	119	0.5960
Total		7.7130

[No. L-14016/794-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director.

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

का.ग्रा. 2764.— यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में विजयपुर से दादरी तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गैस ग्रथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्भावद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हिजवद कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस ग्रथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय विद्यालय चौराहा, ए.बी. रोड, शिवपुरी (म.प्र.) को इस अधिभूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसी आपत्ति करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

ग्राम : सुमेला तहसील : कोलारस जिला : शिवपुरी

क्रमांक	खसरा नं.	सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें भार.ओ.यू. अध्यापित किया जाना है। (हेक्टेयर में)
1	2	3
01.	1181	0.0378
02.	1237	0.1459
03.	1236	0.1762
04.	1234	0.1937
05.	1235	0.0925
06.	1232	0.1851
07.	1240	0.0734
08.	1231	0.0408
09.	1216	0.0015
10.	1215	0.1835
11.	1213	0.1540

1	2	3
12.	1212	0.2364
13.	1211	0.0006
14.	1210	0.0014
15.	1208	0.1590
16.	1201	0.1650
17.	1197	0.1710
18.	1195	0.1020
19.	1194	0.1031
20.	1193	0.0049
21.	1169	0.5747
22.	1172	0.1590
23.	1174	0.1800
24.	1176	0.0195
25.	828	0.4860
26.	827	0.1530
27.	830	0.5190
28.	831	0.2700
29.	832	0.0270
30.	808	0.0270
31.	785	0.0283
32.	784	0.5520
33.	792	0.0075
34.	793	0.0180
35.	701	0.0266
36.	640	0.0918
37.	639	0.2661
38.	647	0.0948
39.	638	0.1552
40.	648	0.0627
41.	649	0.5100
42.	632	0.2250
43.	630	0.1720
44.	624	0.0600
45.	625	0.2102
46.	627	0.0826
47.	626	0.0202

कुल : 7.2220

[फा.सं. एल-14016/7/94-जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 22nd September, 1994

S.O. 2764.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural gas from Vijapur to Dadri in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Limited, Bhartiya Vidyalaya Chauraha A.B. Road, Shivpuri (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Vijaypur Dadri Gas Pipelin Project

Village : Kasur Tehsil : Kolaras, Distt. Shivpuri

Sr. Survey No.		Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
01.	1181	0.0378
02.	1237	0.1459
03.	1236	0.1762
04.	1234	0.1937
05.	1235	0.0925
06.	1232	0.1851
07.	1240	0.0734
08.	1231	0.0408
09.	1216	0.0015
10.	1215	0.1835
11.	1213	0.1500
12.	1212	0.2364
13.	1211	0.0006
14.	1210	0.0014
15.	1208	0.1590
16.	1201	0.1650
17.	1197	0.1710
18.	1195	0.1020
19.	1194	0.1031
20.	1193	0.0049
21.	1169	0.5747
22.	1172	0.1590
23.	1174	0.1800
24.	1176	0.0195
25.	828	0.4860
26.	827	0.1530
27.	830	0.5190
28.	831	0.2700
29.	832	0.0270
30.	803	0.0270
31.	785	0.0283
32.	784	0.5520
33.	792	0.0075
34.	793	0.0180
35.	701	0.0266
36.	640	0.0918
37.	639	0.2661
38.	647	0.0948
39.	638	0.1552
40.	648	0.0627
41.	649	0.5100
42.	632	0.2250
43.	630	0.1720
44.	624	0.0600
45.	625	0.2102
46.	627	0.0826
47.	626	0.0202

Total

7.2220

[No. L-14016/7/94-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director.



नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

का.प्र. 2765.— यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में विजयपुर से दादरा तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड, द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एनर्वाबल अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोनियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एनर्वाबल घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आपत्ति राक्षम प्राधिकारों गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड भारतीय विद्यालय चौराहा, ए.बी. रोड, शिवपुरी (म.प्र.) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसी आपत्ति करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी बताने करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप में हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

ग्राम : बदर वास, तहसील : कोलारम जिला : शिवपुरी

सर्वे का यह क्षेत्रफल  
जिसमें आर.ओ.यू.  
अध्यापित किया जाना  
है। (हेक्टेयर में)

1	2	3
ग्राम : बदर वास		
01.	1256	0.0892
02.	1208	0.0432
03.	1439	0.3819
04.	1438	0.0391
05.	1436	0.3445
06.	1256	0.1899
07.	1260	0.3135
08.	1262	0.3550
09.	1264	0.2640
10.	1265	0.3130

1	2	3
11.	1276	0.4225
12.	1277	0.3416
13.	1299	0.1750
14.	1302	0.1550
15.	1301	0.0934
16.	1208	0.0434
17.	934	0.1039
18.	933	0.0418
19.	935	0.2882
20.	932	0.1415
21.	936	0.4900
22.	937	0.2700
23.	938	0.3100
24.	939	0.1380
25.	849	0.0150
26.	838	0.2814
27.	837	0.4630
28.	836	0.2490
29.	811	0.3130
30.	830	0.0077
31.	812	0.1723
32.	813	0.2750
33.	805	0.5290

कुल 7.6530

[सं. एल-14016/7/94 जी.पी.०]

अधेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 22nd September, 1994

S.O. 2765.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural gas from Vijalpura to Dadri in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Limited, Bhartiya Vidyalaya Chauraha A.B. Road, Shivpuri (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Village : Badarwas Tehsil : Kolras. Dist. : Shivpuri

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
01.	1256	0.0892
02.	1208	0.0432
03.	1439	0.3819
04.	1438	0.0391
05.	1436	0.3445
06.	1259	0.1899
07.	1260	0.3135
08.	1262	0.3550
09.	1264	0.2640
10.	1265	0.3130
11.	1276	0.4225
12.	1277	0.3416
13.	1299	0.1750
14.	1302	0.1556
15.	1301	0.0934
16.	1208	0.0434
17.	934	0.1039
18.	933	0.0418
19.	935	0.2882
20.	932	0.1415
21.	936	0.4900
22.	937	0.2700
23.	938	0.3100
24.	939	0.1380
25.	849	0.0150
26.	838	0.2814
27.	837	0.4630
28.	836	0.2490
29.	811	0.3130
30.	810	0.0077
31.	812	0.1723
32.	813	0.2750
33.	805	0.5290
Total		7.6530

[No. L-14016/7/94-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

क्रा.प्र. 2766.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में बिजयपुर से बादरी तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, द्वारा पाइप लाइन विछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन विछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1992 का 50) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का प्रपन प्राण्य एतद्वारा घोषित किया है।

वर्णित कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन विछाने के लिए आपत्ति मक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय विद्यालय चीराहा, ए.बी. रोड, शिवपुरी (म.प्र.) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसी आपत्ति करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो, या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

तहसील : कोलारस

जिला : शिवपुरी

सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें आर.ओ.यू. अध्यापित किया जाना है (हेक्टेयर में)

1	2	3
ग्राम : तिलातिली		
01.	686	0.4340
02.	683	0.0126
03.	684	0.2064
04.	682	0.1040
05.	680	0.0435
06.	677	0.0915
07.	657	0.0270
08.	643/2	0.2377
09.	642/2	0.0453
10.	642/1	0.3389
11.	641	0.0046
12.	640	0.1365
13.	639	0.3385
14.	634/2	0.2295
15.	634/1	0.3280
16.	631	0.4205
17.	617	0.1509
18.	616	0.1300
19.	615	0.0600
20.	607	0.2565
21.	614	0.0082

1	2	3
22.	613	0.0090
23.	608	0.2580
24.	609	0.1290
25.	601	0.2970
26.	598	0.0660
27.	546	0.2880
28.	545	0.3337
29.	503	0.0700
30.	557	0.0160
31.	504	0.3595
32.	505	0.1515
33.	499/2	0.1037
34.	499/1	0.0100
35.	481	0.0770
36.	432	1.1460
37.	444	0.4610
38.	448	0.4855
39.	452	0.0455
40.	451	0.1382
41.	467	0.5663
42.	473	0.1043
43.	475	0.4346
44.	478	0.0350
कुल :		9.1889

[सं एल-14016/7/94 जी.पी.]

अर्जुन सेन, निदेशक

New Delhi, the 22nd September, 1994

S.O. 2766.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural gas from Vijapur to Dadri in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Limited, Bhartiva Vidyalaya Chauraha, A.B. Road, Shivpuri (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Vijapur-Dadri Gas Pipeline Project

Village: Tilatili, Pansil: Kolaria Distt.: Shivpuri

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
01.	686	0.4343
02.	683	0.0126
03.	684	0.2064
04.	682	0.1040
05.	680	0.0435
06.	677	0.0915
07.	657	0.0270
08.	643/3	0.2377
09.	642/2	0.0453
10.	642/1	0.3389
11.	641	0.0016
12.	640	0.1365
13.	639	0.3383
14.	634/2	0.2295
15.	634/1	0.3280
16.	631	0.4205
17.	617	0.1509
18.	616	0.1300
19.	615	0.0600
20.	607	0.2563
21.	614	0.0082
22.	613	0.0690
23.	608	0.2580
24.	609	0.1290
25.	601	0.2970
26.	598	0.0660
27.	546	0.2880
28.	545	0.3337
29.	503	0.0700
30.	557	0.0160
31.	504	0.3595
32.	505	0.1515
33.	499/2	0.1037
34.	499/1	0.0100
35.	481	0.0770
36.	432	1.1460
37.	444	0.4610
38.	448	0.4855
39.	452	0.0455
40.	451	0.1382
41.	467	0.5663
42.	473	0.1043
43.	475	0.4346
44.	478	0.0350
Total		9.1889

[No. L-14016/7/94-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director.

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

क्र.आ. 2767.—सतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में विजयपुर से दादरी तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गैस अधिनियम अफ इंडिया लिमिटेड, द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

अतः यत् प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्भावद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1992 (1992 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

अतः कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय विद्यालय चौराहा, ए.बी. रोड, शिवपुरी (म.प्र.) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसी आपत्ति करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

ग्राम : डिगोड तहसील : कोलारस जिला : शिवपुर

क्रमांक	खनरा नं.	सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें आर.ओ.यू. प्रख्यापित किया जाना है (हेक्टेयर में)
01.	1066	0.1366
02.	1040	0.3482
03.	1039	0.2180
04.	1038	0.2341
05.	1044	0.0338
06.	1037	0.0288
07.	1036	0.4255
कुल		1.4250

[सं. एन-14016/7/94-जी.पी.1]

अर्जेंदु सेन, निदेशक

New Delhi, the 22nd September, 1994

S.O. 2767.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural gas from Vijaipur to Dadri in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Limited, Bhartiya Vidyalaya Chauraha, A.B. Road, Shivpuri (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Village : Digodi, Tehsil : Kolaras, Distt. : Shivpuri

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
01.	1066	0.1366
02.	1040	0.3482
03.	1039	0.2180
04.	1038	0.2341
05.	1044	0.0338
06.	1037	0.0288
07.	1036	0.4255
Total		1.4250

[No. L-14016/7/94-G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

का.आ. 2768.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में विजयपुर से दादरी तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड, द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्भावद अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

अतः कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय विद्यालय चौराहा, ए.बी. रोड, शिवपुरी (म.प्र.) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसी आपत्ति करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

गांव : बिजा तहसील : कोलारम जिला : शिवपुरी

क्रमांक खसरा नं. सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें आर.ओ.यू. अध्यापित किया जाना है। (हेक्टर में)

01.	326	0.1860
02.	325	0.1650
03.	39	0.3540
04.	38	0.2030
05.	40	0.1122
06.	35	0.3105
07.	42	0.0439
08.	34	0.1950
09.	33	0.1650
10.	32	0.0299
11.	30	0.0761
12.	31	0.0780
13.	29	0.2430
14.	28	0.1654
15.	17	0.0110
16.	16	0.0410

कुल 2.3790

[सं. एल-14016/7/94 जी.पी.]  
अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 22nd September, 1994

S.O. 2768.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural gas from Vijaipur to Dadri in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Limited, Bhartiya Vidyalaya Chauraha, A.B. Road, Shivpuri (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

2241 GI/94—10.

Village : Chitara Tehsil : Kolaras Distt : Shivpuri

Sr. No. Survey No. Area to be acquired for R.O.U. in Hectare

1	2	3
01.	326	0.1860
02.	325	0.1650
03.	39	0.3540
04.	38	0.2030
05.	40	0.1122
06.	35	0.3105
07.	42	0.0439
08.	34	0.1950
09.	33	0.1650
10.	32	0.0299
11.	30	0.0761
12.	31	0.0780
13.	29	0.2430
14.	28	0.1654
15.	17	0.0110
16.	16	0.0410
Total		2.3790

[No. L-14016/7/94-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director.

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

का.आ. 2769.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में विजयपुर से दादरी तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, द्वारा पाइपलाइन बिछाई जाती चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय विशालय चौराहा ए.बी. रोड, शिवपुरी (म.प्र.) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसी आपत्ति करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

ग्राम : कुरुहाडी, तहसील : कोलारस, जिला : शिवपुरी

क्रमांक खमरा नं. सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें आर.ओ.यू. अध्यापित किया जाना है । (हेक्टेयर में)

01.	233	0.1935
02.	234	0.0210
03.	236	0.3515
04.	237	0.2160
05.	238	0.2385
06.	243	0.3515
07.	242	0.0405
08.	264	0.0525
09.	278	0.0720
10.	277	0.1170
11.	279	0.2100
12.	283	0.0758
13.	284	0.2640
14.	302	0.3570
15.	304	0.2040
16.	306	0.2041
17.	305	0.0111
18.	308	0.1980
19.	312	0.0180
20.	313	0.2850
21.	327	0.3260
22.	329	0.0504
23.	332	0.1686
24.	330	0.1643
25.	331	0.2137

कुल 4.4040

[सं. एल-14016/7/94 जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 22nd September, 1994

S.O. 2769.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural gas from Vijaipur to Dadri in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Limited, Bhartiya Vidyalyaya Chauraha, A.B. Road, Shivpuri (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner

Village : Kulhari Tehsil : Kolaras Distt. : Shivpuri

Sr. No. Survey No.		Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	4
01.	233	0.1935
02.	234	0.0210
03.	236	0.3515
04.	237	0.2160
05.	238	0.2385
06.	243	0.3515
07.	242	0.0450
08.	264	0.0525
09.	278	0.0720
10.	277	0.1170
11.	279	0.2100
12.	283	0.0758
13.	284	0.2640
14.	302	0.3570
15.	304	0.2040
16.	306	0.2041
17.	305	0.0111
18.	308	0.1980
19.	312	0.0180
20.	313	0.2850
21.	327	0.3260
22.	329	0.0504
23.	332	0.1686
24.	330	0.1643
25.	331	0.2137
Total		0.4040

[No. L-14016/7/94-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

का.आ. 2770.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में विजयपुर से दादरी तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पाइप-लाइन बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्-द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय विद्यालय चौराहा, ए.बी. रोड, शिवपुरी (म.प्र.) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसी आपत्ति करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

ग्राम : खरई तहसील : कोलारस जिला : शिवपुरी

क्रमांक	खसरा नं.	सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें आर.ओ.यू. अध्यापित किया जाना है) (हेक्टेयर में)
---------	----------	---

1	2	3
ग्राम : खरई		
01.	271	0.4568
02.	272	0.1314
03.	270	0.1446
04.	269	0.0174
05.	263	0.3990
06.	264	0.2400
07.	249	0.5190
08.	243	0.3900
09.	180	0.1800
10.	178	0.4050
11.	177	0.1620
12.	167	0.1730
13.	166	0.1505
14.	165	0.1610
15.	164	0.2935
16.	154	0.0300
17.	139	0.0012
18.	138	0.4268
19.	136	0.5224
20.	135	0.1615
21.	134	0.0752
22.	129	0.1115

1	2	3
23.	133	0.0128
24.	130	0.0128
25.	132	0.1100
26.	49	0.3110
27.	48	0.2803
28.	40	0.1033
कुल		5.9820

[सं. एल-14016/7/94 जी.पो.]

अधेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 22nd September, 1994

S.O. 2770.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural gas from Vijaipur to Dadri in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Limited, Bhartiya Vidyalaya Chauraha, A.B. Road, Shivpurī (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Village : Kharai		Tehsil : Kolaras,	Dist. : Shivpurī
Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R. O. U. in Hectare	
1	2	3	
01.	271	0.4568	
02.	272	0.1314	
03.	270	0.1446	
04.	269	0.0174	
05.	263	0.3990	
06.	264	0.2400	
07.	249	0.5190	
08.	243	0.3900	
09.	180	0.1800	
10.	178	0.4050	
11.	177	0.1620	
12.	167	0.1730	
13.	166	0.1505	
14.	165	0.161	

1	2	3
15.	164	0.2935
16.	154	0.0300
17.	139	0.0012
18.	138	0.4268
19.	136	0.5224
20.	135	0.1615
21.	134	0.0752
22.	129	0.1115
23.	133	0.0128
24.	130	0.0128
25.	132	0.1100
26.	49	0.3110
27.	48	0.2803
28.	40	0.1033
Total		5.9820

[No. L-14016/7/94-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director.

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

का.आ. 2771.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में विजयपुर से दादरी तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय विद्यालय चौराहा, ए.बी. रोड, शिवपुरी (म.प्र.) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसी आपत्ति करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

ग्राम : लुकवासा तहसील : कोलारस, जिला : शिवपुरी

क्रमांक खसरा नं. सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें आर.ओ.यू. अध्यापित किया जाना है। (हेक्टेयर में)

01.	349	0.3578
02.	281	0.0450
03.	282	0.1889
04.	283	0.0632
05.	289	0.0607
06.	288	0.0081
07.	290	0.3947
08.	291	0.2320
09.	292	0.0080
10.	301	0.2292
11.	300	0.4638
12.	201	0.0112
13.	231	0.4639
14.	230	0.2775
15.	229	0.3515
16.	207	0.3195
17.	206	0.2490
18.	166	0.0375
19.	162	0.1765
20.	38	0.3262
21.	37	0.0093
22.	41	0.0350
23.	40	0.5111
24.	42	0.1151
25.	45	0.1154
26.	44	0.7249

कुल : 5.7750

[सं. एल-14016/7/94 जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 22nd September, 1994

S.O. 2771. —Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural gas from Vijaipur to Dadri in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the



land Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Limited, Bhartiya Vidyalaya Chauraha, A.B. Road, Shivpuri (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Village : Lukwasa Tehsil : Kolaras Distt. : Shivpuri

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R. O. U. in Hectare
1	2	3
01.	349	0.3578
02.	281	0.0450
03.	282	0.1889
04.	283	0.0632
05.	289	0.0607
06.	288	0.0081
07.	290	0.3947
08.	281	0.2320
09.	292	0.0080
10.	301	0.2292
11.	300	0.4638
12.	201	0.0112
13.	231	0.4639
14.	230	0.2775
15.	229	0.3515
16.	207	0.3195
17.	206	0.2490
18.	166	0.0375
19.	162	0.1765
20.	38	0.3269
21.	37	0.0093
22.	41	0.0350
23.	40	0.5111
24.	42	0.1151
25.	45	0.1154
26.	44	0.7249
Total		5.7740

[No L-14016/7/94-G. P.]  
ARDHENDU SEN, Director.

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

का.आ. 2772.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में बिजयपुर से दादरी तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है :

वशत कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय विद्यालय चौराहा, ए.बी. रोड, शिवपुरी (म.प्र.) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसी आपत्ति करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

ग्राम : डोंडहाई तहसील : कोलारस, जिला : शिवपुरी

क्रमांक खसरा नं. सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें ग्राम.ओ.यू. अध्यापित किया जाना है। (हेक्टेयर में)

1	2	3
01.	366	0.3840
02.	365	0.0170
03.	367	0.3066
04.	368	0.1950
05.	333	0.3184
06.	330	0.0270
07.	329	0.0330
08.	325	0.0418
09.	335	0.2439
10.	336	0.2055
11.	337	0.5255
12.	339	0.0180
13.	151	0.4580
14.	152	0.4820
15.	158	0.4364
16.	157	0.0546
17.	111	0.0270
18.	105	0.1170
19.	104	0.0165
20.	103	0.0744
21.	102	0.0473
22.	99	0.2243
23.	78	0.2502

1	2	3
24.	77	0.0457
25.	74	0.3739
26.	70	0.0435
27.	68	0.0822
28.	67	0.0488
29.	69	0.0648
30.	66	0.0802
31.	10	0.2175
32.	9	0.0630
33.	8	0.4110
कुल :		5.9340

[सं. एल-14016/7/94 जो.पो.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 22nd September, 1994

S.O. 2772.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural gas from Vijapur to Dadri in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein:

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Limited, Bhartiya Vidyalaya Chauraha, A.B. Road, Shivpuri (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Village : Donrhahaj, Tehsil : Kolaras, Distt. : Shivpuri

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
01.	366	0.3840
02.	365	0.0170
03.	367	0.3066
04.	368	0.1950
05.	333	0.3184
06.	330	0.0270
07.	329	0.0330
08.	325	0.0418
09.	335	0.2439
10.	336	0.2055

1	2	3
11.	337	0.5255
12.	339	0.0180
13.	151	0.4580
14.	152	0.4820
15.	158	0.4364
16.	157	0.0546
17.	111	0.0270
18.	105	0.1170
19.	104	0.0165
20.	103	0.0744
21.	102	0.0473
22.	99	0.2243
23.	78	0.2502
24.	77	0.0457
25.	74	0.3739
26.	70	0.0435
27.	68	0.0822
28.	67	0.0488
29.	69	0.0648
30.	66	0.0802
31.	10	0.2175
32.	9	0.0630
33.	8	0.4110

Total : 5.9340

[F. No. I-14016/7/94 G.P.]

ARDHEDU SEN, Director

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

का.आ. 2773—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में बिजयपुर से बादरी तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय विद्यालय चौराहा, ए.बी. रोड, शिवपुरी (म.प्र.) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा;

और ऐसी आपत्ति करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

## ग्राम जूर तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी

क्रमांक खसरा नं० सर्वे का यह क्षेत्रफल  
जिसमें आर.ओ.यू.  
अध्यापित किया जाता है  
(हेक्टेयर में)

01.	207	0.4980
02.	208	0.2150
03.	215	0.1080
04.	506	0.0034
05.	505	0.4280
06.	209	0.0030
07.	504	0.3130
08.	503	0.2790
09.	499	0.0150
10.	216	0.3717
11.	219	0.2550
12.	220	0.3030
13.	227	0.0785
14.	226	0.2515
15.	231	0.0315
16.	235	0.1035
17.	240	0.3990
18.	242	0.0050
19.	241	0.3340
20.	247	0.2190
21.	249	0.0552
22.	248	0.0279
23.	262	0.1287
24.	261	0.2445
25.	263	0.0295
26.	289	0.2225
27.	288	0.3765
28.	293	0.0500
29.	294	0.5800

कुल : 5.9279

[सं. एल-14016/7/94 जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 22nd September, 1994

S.O. 2773.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural gas from Vijaipur to Dadri in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed here to the purpose

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Limited, Bhartiya Vidyalyaya Charaha, A.B. Road, Shivpuri (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Village : Jur, Tehsil : Kolaras, Distt. : Shivpuri

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
01.	207	0.4980
02.	208	0.2150
03.	215	0.1080
04.	506	0.0034
05.	505	0.4280
06.	209	0.0030
07.	504	0.3130
08.	503	0.2790
09.	499	0.0150
10.	216	0.3717
11.	219	0.2550
12.	220	0.3030
13.	227	0.0785
14.	226	0.2515
15.	231	0.0315
16.	235	0.1035
17.	240	0.3990
18.	242	0.0050
19.	241	0.3340
20.	247	0.2190
21.	249	0.0552
22.	248	0.0279
23.	262	0.1287
24.	261	0.2445
25.	263	0.0295
26.	289	0.2225
27.	288	0.3765
28.	293	0.0500
29.	294	0.5800
Total		5.9279

[F. No. L-14016/7/94 G.P.]  
Ardhendu Sen, Director

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

का.आ. 2774. —यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में विजयपुर से दादरी तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, द्वारा पाइप-लाइन बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय विद्यालय चौराहा, ए.बी., रोड, शिवपुरी (म.प्र.) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसी आपत्ति करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

ग्राम : उकावल

तहसील : कोलारस, जिला : शिवपुरी

क्रमांक खसरा न.

सर्वे का वह क्षेत्रफल  
जिसमें आर.ओ.यू.  
अव्यापित किया जाना है।  
(हेक्टेयर में)

01.	713	0.0831
02.	712	0.1130
03.	710	0.0354
04.	711	0.0216
05.	706	0.0364
06.	709	0.0972
07.	704	0.3570
08.	615	0.2856
09.	613	0.1187
10.	612	0.1080
11.	610	0.0966
12.	611	0.1212
13.	608	0.5371
14.	607	0.0180
15.	530	0.1300
16.	524	0.0200
17.	528	0.5499
18.	363	0.0400
19.	350	0.0730
20.	351	0.1445
21.	348	0.1040

22.	349	0.0594
23.	353	0.1235
24.	354	0.0200
25.	355	0.0210
26.	356	0.0640
27.	323	0.0108
28.	322	0.3635
29.	321	0.0462
30.	320	0.4579
31.	318	0.0771
32.	282	0.0102
33.	292	0.5585
34.	294	0.0805
35.	289	0.0150

कुल : 4.9970

[सं. एल-14016/7/94 जी.पी.]

अर्घेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 22nd September, 1994

S.O. 2774.--Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural gas from Vijaipur to Dadri in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Lands) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Limited, Bhartiya Vidyalaya Chauraha, A.B. Road, Shivpur (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Village : Ukawal, Tehsil : Kolaras, Distt. : Shivpur

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
01.	713	0.0831
02.	712	0.1130
03.	710	0.0354
04.	711	0.0216
05.	706	0.0364
06.	709	0.0972
07.	704	0.3570

1	2	3	और ऐसी आपत्ति करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट:
08.	615	0.2856	यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी
09.	613	0.1187	मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी
10.	612	0.1080	की मार्फत।
11.	610	0.0966	ग्राम : पनवारी तहसील : कोनारम, जिला : शिवपुरी
12.	611	0.1212	क्रमांक : स्वसरा नं. सर्वे का वह क्षेत्रफल
13.	608	0.5371	जिसमें आर.ओ.यू.
14.	607	0.0180	अव्यापित किया जाना
15.	530	0.1300	है। (हेक्टेयर में)
16.	524	0.0200	
17.	528	0.5490	01 486 0.1365
18.	363	0.0400	02. 485 0.2320
19.	350	0.0730	03. 488 0.0007
20.	351	0.1445	04. 489 0.1888
21.	348	0.1040	05. 514 0.2843
22.	349	0.0594	06. 513 0.0794
23.	353	0.1235	07. 495 0.3681
24.	354	0.0200	08. 467 0.0435
25.	355	0.0210	09. 497 0.0660
26.	356	0.0640	10. 352 0.3685
27.	323	0.0108	11. 350 0.0330
28.	322	0.3635	12. 351 0.0180
29.	321	0.0467	13. 347 0.0248
30.	320	0.4579	14. 333 0.1660
31.	318	0.0771	15. 332 0.3823
32.	282	0.0102	16. 335 0.0450
33.	292	0.5585	17. 337 0.2186
34.	294	0.0805	18. 331 0.0208
35.	289	0.0150	19. 338 0.1776
		4 9970	20. 339 0.0020
			21. 306 0.0315
			22. 200 0.3142
			23. 259 0.0878
			24. 204 0.0130
			25. 201 0.1320
			26. 202 0.3100
			27. 210 0.0347
			28. 211 0.1225
			29. 212 0.1500
			30. 191 0.2077
			31. 188 0.4928
			32. 187 0.0313
			33. 186 0.0536
			34. 185 0.0230
			कुल : 4.8600

[ No. I-14016/7/94 G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

का.आ. 2775 —यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में विजयपुर से दादरी तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड, द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

वर्णित कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय विद्यालय चौराहा, ए.बी., रोड, शिवपुरी (म.प्र.) को इस अधि-सूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

[सं. एत-14016/7/94 जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 22nd September, 1994

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

S.O. 2775.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural gas from Vijapur to Dadri in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Limited, Bhandari Vidyaleva Chauraha, A.B. Road, Shivpuri (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Vijaypur-Dadri Gas Pipeline Project  
Village : Panwari, Tehsil : Kolaras, Distt. : Shivpuri

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
01.	486	0.1365
02.	485	0.2320
03.	488	0.0007
04.	489	0.1888
05.	514	0.2843
06.	513	0.0794
07.	495	0.3681
08.	467	0.0435
09.	497	0.0660
10.	352	0.3685
11.	350	0.0330
12.	351	0.0170
13.	347	0.0248
14.	333	0.1660
15.	332	0.3823
16.	335	0.0450
17.	337	0.2186
18.	331	0.0208
19.	338	0.1776
20.	339	0.0020
21.	306	0.0315
22.	200	0.3142
23.	259	0.0878
24.	204	0.0130
25.	201	0.1320
26.	202	0.3100
27.	210	0.0347
28.	211	0.1225
29.	212	0.1500
30.	191	0.2077
31.	188	0.4978
32.	187	0.0313
33.	186	0.0536
34.	185	0.0730
Total		4.8600

[F. No. L-14016/7/94 G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director

का.आ. 2776—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में विजयपुर में दादरी तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गैस ग्रंथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाय अनुसूची में वर्णित भूमि उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस ग्रंथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय विद्यालय चौराहा, ए.बी. रोड, शिवपुरी (म.प्र.) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसी आपत्ति करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

ग्राम : गूदा तहसील : कोलारस, जिला : शिवपुरी

क्रमांक खसरा नं० भूखे का वह क्षेत्रफल जिसमें आर.ओ.यू. अध्यापित किया जाना है (हेक्टेयर में)

1	2	3
01.	381	0.2606
02.	383	0.2615
03.	378	0.0390
04.	329	0.2315
05.	336	0.0300
06.	337	0.3390
07.	385	0.0321
08.	339	0.3655
09.	341	0.0300
10.	344	0.3908
11.	343	0.0684
12.	346	0.0765
13.	134	0.4889

1	2	3
14.	108	0.2095
15.	133	0.2085
16.	109	0.0003
17.	132	0.1295
18.	127	0.2650
19.	130	0.2000
20.	126	0.0008
21.	128	0.3368
22.	129	0.0007
23.	42	0.0493
24.	144	0.0008
25.	43	0.4583
26.	40	0.0052
27.	44	0.2868
28.	46	0.0254
29.	45	0.0092
30.	7	0.1471
कुल:		4.9470

[सं. एन-14016/7/94 जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 22nd September, 1994

S.O. 2776.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural gas from Vijapur to Dadri in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Limited, Bhartiya Vidyalaya Chauraha, A.B. Road, Shivpuri (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Vijaypur-Dadri Gas Pipeline Project  
Village : Gura, Tehsil : Kolaras, Distr. : Shivpuri

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
01.	381	0.2600
02.	383	0.2615
03.	378	0.0390
04.	329	0.2315
05.	336	0.0300
06.	337	0.3390
07.	385	0.0321
08.	339	0.3655
09.	341	0.0300
10.	344	0.3908
11.	343	0.0684
12.	346	0.0765
13.	134	0.4889
14.	108	0.2095
15.	133	0.2085
16.	109	0.0003
17.	132	0.1295
18.	127	0.2650
19.	130	0.2000
20.	126	0.0008
21.	128	0.3368
22.	129	0.0007
23.	42	0.0493
24.	144	0.0008
25.	43	0.4583
26.	40	0.0052
27.	44	0.2868
28.	46	0.0254
29.	45	0.0092
30.	7	0.1471

Total 4.9470

[F. No. L-14016/7/94-GP]

Ardhendu Sen, Director

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

का.आ. 2777.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकार्हात में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में विजयपुर से दादरी तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एनदपावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (सि. के. उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपर्युक्त का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एनद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस आथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय विद्यालय चौराहा, ए. बी. रोड, शिवपुरी (म.प्र.) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

आर एसी आपत्ति करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टनः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

ग्राम : गुगवारा, तहसील : कोलारस, जिला : शिवपुरी

क्रमांक	खसरा नं.	सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें आर.ओ.यू. अध्यापित किया जाना है। (हेक्टेयर में)
01.	467	0.1990
02.	101	0.4910
03.	466	0.0336
04.	465	0.2200
05.	464	0.1641
06.	463	0.2380
07.	462	0.2745
08.	461	0.0078
09.	116	0.3367
10.	118	0.3235
11.	117	0.1745
12.	119	0.2990
13.	76	0.0007
14.	160	0.2301
15.	161	0.0201
16.	162	0.2179
17.	163	0.3930
18.	70	0.0004
19.	69	0.2512
20.	166	0.0048
21.	57/1	0.2580
22.	57/2	0.2760
23.	56	0.1680
24.	55	0.0420
25.	54	0.0780
26.	52	0.0165
27.	42	0.3515
28.	40	0.0330
29.	39	0.3650
30.	36	0.3387
31.	35	0.0708
32.	34	0.0800

कुल : 5.9574

[मं एल-14016/7/94. जी. पी.]  
अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 22nd September, 1994

S.O. 2777.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural gas from Vijaipur to Dadri in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Limited, Bhartiya Vidyulaya Chauraha, A.B. Road Shivpuri (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner

### SCHEDULE

Village : Gugawara, Tehsil : Kolaras, Dist. : Shivpuri

S.No.	Survey No.	Area to be acquired for for ROU in Hectare
1	2	3
01.	467	0.1990
02.	101	0.4910
03.	466	0.0336
04.	465	0.2200
05.	464	0.1641
06.	463	0.2380
07.	462	0.2745
08.	461	0.0078
09.	116	0.3367
10.	118	0.3235
11.	117	0.1745
12.	119	0.2990
13.	76	0.0007
14.	161	0.2301
15.	161	0.0201
16.	162	0.2179
17.	163	0.3930
18.	7	0.0004
19.	69	0.2512
20.	166	0.0048
21.	57(1	0.2580
22.	57/2	0.2760
23.	56	0.1680
24.	55	0.0420
25.	54	0.0780
26.	52	0.0165
27.	42	0.3515
28.	40	0.0330
29.	39	0.3650
30.	36	0.3387
31.	35	0.0708
32.	34	0.0800

Total

5.9574

[F. No. L-14016/7/94 G.F.]  
ARDHENDU SEN, Director



नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

का.आ.2778:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में विजयपुर से दादरी तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उक्त भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय विद्यालय चौराहा, ए.बी. रोड, शिवपुरी (म.प्र.) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसी आपत्ति करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

ग्राम : बोरमखेडी, तहसील : कोलारम, जिला : शिवपुरी

क्रमांक	खसरा नं.	सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें आर. ओ. यू. अध्यापित किया जाना है। (हेक्टेयर में)
1	2	3
01.	258	0.0360
02.	222	0.8348
03.	225	0.0270
04.	232	0.2164
05.	228	0.1102
06.	226	0.9122
07.	227	0.1483

1	2	3
08.	229	0.0309
09.	140	0.0300
10.	141	0.0330
11.	142	0.3535
12.	152	0.0420
13.	136	0.0240
14.	135	0.0310
15.	154	0.3040
16.	153	0.1078
17.	159	0.3431
18.	164	0.1976
19.	165	0.5590
20.	7	0.0051
21.	15	0.0444
22.	8	0.2255
23.	9	0.0073
24.	12	0.0462
25.	11	0.1769
26.	10	0.0045
कुल		3.9510

[सं. एन-14016/7/94-जी पी.]

अर्जुन सेन, निदेशक

New Delhi, the 22nd September, 1994

S.O. 2778.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural gas from Vijaipur to Dadri in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Limited, Bhartiya Vidyalaya Chauraha, A.B. Road, Shivpur (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

1	2	3
01.	258	0.0360
02.	222	0.8348
03.	225	0.0270
04.	232	0.2164
05.	228	0.1102
06.	226	0.0122
07.	227	0.1483
08.	229	0.0390
09.	140	0.0300
10.	141	0.0330
11.	142	0.3535
12.	152	0.0420
13.	136	0.0040
14.	135	0.0310
15.	154	0.3040
16.	153	0.1078
17.	159	0.3431
18.	164	0.1976
19.	165	0.5590
20.	7	0.0054
21.	15	0.0444
22.	8	0.2255
23.	9	0.0073
24.	12	0.0462
25.	11	0.1769
26.	10	0.0045
Total		3.9510

[F. No. L-14016/7/94 G.P.]

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

का.प्र. 2779:— यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में विजयपुर में दादरी तक प्राकृतिक गैस का परिवहन के लिए गैस प्रयॉरिटी ग्राफ इंडिया लिमिटेड, द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एनशासक अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एनश- द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में द्विवार्ष कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए प्राप्ति मक्षम प्राधिकारी गस प्रयॉरिटी ग्राफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय विद्यालय चीराहा ए. बी. रोड, शिवपुरी (म.प्र.) को इस अधिमूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसी प्राप्ति करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विशिष्ट व्यवसायी की मार्फत।

## अनुसूची

ग्राम : मोहरा, तहसील : कोलारम, जिला : शिवपुरी

क्रमांक खसरा नं. सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें आर.ओ.यू. अध्यापित किया जाता है। (हेक्टेयर में)

1	2	3
01.	1642	0.0092
02.	1638	0.1614
03.	1641	0.0027
04.	1639	0.0550
05.	1640	0.0070
06.	1636	0.1519
07.	1628	0.0703
08.	1629	0.0580
09.	1637	0.1267
10.	1625	0.0450
11.	1624	0.0953
12.	1211	0.1539
13.	1210	0.0368
14.	1148	0.0496
15.	1193	0.1214
16.	1215	0.2675
17.	1208	0.0766
18.	1195	0.1104
19.	1196	0.0765
20.	1197	0.4445
21.	1105	0.0758
22.	1059	0.0363
23.	1053	0.0420
24.	1052	0.0032

1	2	3	SCHEDULE	
25	1040	0.1960	Vijapur—Dadar Gas Pipeline Project	
26	1051	0.0394	Village : Mohara, Tehsil : Kolaras, Distt.: Shivpuri	
27	1042	0.1409	Sl. Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
28	1049	0.0061		
29	1043	0.3000		
30	1028	0.0420		
31	1029	0.1300	01. 1642	0.0092
32	1027	0.0670	02. 1638	0.1614
33	1018	0.0903	03. 1641	0.0027
34	1019	0.0306	04. 1639	0.0550
35	1015	0.0280	05. 1640	0.0070
36	1017	0.1144	06. 1636	0.1519
37	1016	0.0630	07. 1628	0.0703
38	1020	0.0075	08. 1629	0.0580
39	175	0.2325	09. 1637	0.1267
40	166	0.0112	10. 1625	0.0450
			11. 1624	0.0953
			12. 1211	0.1539
			13. 1210	0.0368
			14. 1148	0.0496
			15. 1193	0.1214
			16. 1215	0.2675
			17. 1208	0.0766
			18. 1195	0.1104
			19. 1196	0.0765
			20. 1197	0.4445
			21. 1105	0.0758
			22. 1059	0.0363
			23. 1053	0.0420
			24. 1052	0.0032
			25. 1040	0.1960
			26. 1051	0.0394
			27. 1042	0.1409
			28. 1049	0.0061
			29. 1043	0.3000
			30. 1028	0.0420
			31. 1029	0.1300
			32. 1027	0.0670
			33. 1018	0.0903
			34. 1019	0.0306
			35. 1015	0.0280
			36. 1017	0.1144
			37. 1016	0.0630
			38. 1020	0.0075
			39. 175	0.2325
			40. 176	0.0112
			Total	3.7759

कुल : 3.7759

[सं. एन-14016/7/94 जी. पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 22nd September, 1994

S.O. 2779.--Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural gas from Vijapur to Dadri in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Limited, Bhartiya Vidyalya Chauraha, A.B. Road Shivpuri (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

[F. No. L-14016/7/94 G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 22 सितम्बर 1994

का.आ. 2780:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में विजयपुर से दादरी तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपायधन अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः मंत्र पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

वर्तते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आपत्ति मक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय विद्यालय चौगहा, ए. बी. रोड, शिवपुरी (म.प्र.) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसी आपत्ति करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

#### अनुसूची

ग्राम : तिघरिया, तहसील : कोलारग, जिला : शिवपुरी

क्रमांक	खसरा नं.	सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें आर.ओ.य. अध्यापित किया जाना है (हेक्टेयर में)
1	2	3
01.	139	0.0270
02.	138	0.0491
03.	137	0.1073
04.	135	0.0465
05.	134	0.0480
06.	133	0.0930
07.	157	0.0330
08.	158	0.0285
09.	159	0.0450
10.	173	0.2240
11.	174	0.4230
12.	176	0.0180
13.	180	0.3538
14.	182	0.1972

1	2	3
15.	187	0.1201
16.	189	0.0102
17.	188	0.0668
18.	15	0.1625
19.	8	0.0550
20.	14	0.2273
21.	9	0.2800
22.	10	0.1005
23.	4	0.0045
24.	3	0.1549
25.	2	0.0820
26.	1	0.0663

कुल : 3.0235

[सं.एल 14016/7/94. जी. पी.]

अर्धेन्दु मेन, निदेशक

New Delhi, the 22nd September, 1994

S.O. 2780.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural gas from Vijapur to Dadri in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Limited, Bhartiya Vidyalaya Chauraha, A.B. Road, Shivpuri (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

#### SCHEDULE

Village: Tighariya, Tehsil: Kolaras, Dist.: Shivpuri

S.No.	Survey No.	Area to be acquired for ROU in Hectar
1	2	3
1.	139	0.0270
2.	138	0.0491
3.	137	0.1073
4.	135	0.0465
5.	134	0.0480
6.	133	0.0930
7.	157	0.0330
8.	158	0.0285
9.	159	0.0450
10.	173	0.2240

11.	174	0.4230
12.	176	0.0180
13.	180	0.3538
14.	182	0.1972
15.	187	0.1201
16.	189	0.0102
17.	188	0.0668
18.	15	0.1625
19.	8	0.0550
20.	14	0.2273
21.	9	0.2800
22.	10	0.1005
23.	4	0.0045
24.	3	0.1549
25.	2	0.0820
26.	1	0.0663
Total		3.0235

[F. No. I-14016/7/94 G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

का.आ. 2781 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में विजापुर से दादरी तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपारब्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में डिनयड कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आपत्ति सक्षम अधिकारी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय विद्यालय और हाहा, ए. बी. रोड, शिवपुरी (म.प्र.) को इस आग्रहपूर्वकता को तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसी आपत्ति करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चितः वह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

## अनुसूची

ग्राम : विपरोदा, तहसील : कोलारस, जिला : शिवपुरी

क्रमांक खसरा नं. सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें आर. बी. यू. अध्यापित किया जाना है। (हेक्टेयर में)

01.	52	0.7840
02.	65	0.3096
03.	45	0.2642
04.	66	0.0500
05.	44	0.2150
06.	43	0.1458
07.	37	0.1843
08.	31	0.0800
09.	38	0.0759
10.	30	0.1489
11.	29	0.3160
12.	25	0.1095
13.	26	0.0750
14.	12	0.0210
15.	8	0.1590
16.	9	0.1110
17.	5	0.0135
18.	14	0.0838
19.	17	0.0380
20.	4	0.0270
21.	3	0.0585

कुल : 3.2700

[सं. एल-14016/7/94—जी. पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 22nd September, 1994

S.O. 2781.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural gas from Vijaipur to Dadri in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Limited, Ehartiya Vidyalaya Chauraha, A.B. Road, Shivpur (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioners.

## SCHEDULE

## VIJAYPUR-DADRI GAS PIPELINE PROJECT

Village : Piproda, Tehsil : Kolaras, Distt.: Shivpuri

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
01.	52	0.7840
02.	65	0.3096
03.	45	0.2642
04.	66	0.0500
05.	44	0.2150
06.	43	0.1458
07.	37	0.1843
08.	31	0.0800
09.	38	0.0759
10.	30	0.1489
11.	29	0.3160
12.	25	0.1095
13.	26	0.0750
14.	12	0.0210
15.	8	0.1590
16.	9	0.1110
17.	5	0.0135
18.	14	0.0838
19.	17	0.0380
20.	4	0.0270
21.	3	0.0585
Total :		3.2700

[F. No. L-14016/7/94 G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

का.आ. 2782 :—यतः केन्द्रीय सरकार को वह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में विजयपुर से दादरी तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गैस थ्यारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपामुख अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा

श्वेत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्-द्वारा घोषित किया है।

अर्थात् कि उक्त भूमि में हितवन्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आपात सक्षम प्राधिकारी, गैस थ्यारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय विद्यालय चौराहा ए. बी. रोड, शिवपुरी (म.प्र.) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसी आपाति करने वाला हर व्यक्ति विनविष्टतः

यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

ग्राम : बगिरोद, तहसील : कोलारस, जिला : शिवपुरी

क्रमांक खबरानं.	मर्वे का वह क्षत्रफल जिसमें आर.ओ. यू. अध्यापित किया जाना है। (हेक्टेयर में)
-----------------	---

01.	341	0.1140
02.	340	0.0380
03.	342	0.2560
04.	343	0.1140
05.	337	0.0248
06.	336	0.0487
07.	335	0.1983
08.	333	0.1948
09.	334	0.0067
10.	321	0.3782
11.	324	0.0033
12.	322	0.0215
13.	323	0.1156
14.	310	0.0425
15.	306	0.2395
16.	305	0.1485
17.	307	0.0270
18.	294	0.0270
19.	248	0.1688
20.	247	0.0130
21.	246	0.0363
22.	237	0.1027
23.	239	0.0525
24.	240	0.0314
25.	241	0.2040
26.	242	0.3990
27.	167	0.1381

1	2	3
28.	168	0.0696
29.	151	0.6005
30.	152	0.0885
31.	150	0.0210
32.	149	0.2275
33.	147	0.0323
34.	148	0.0387
35.	1	0.0140
कुल:		4.2363

[सं. एल-14016/7/94 जी. पी.]  
अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 22nd September, 1994

S.O. 2782.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural gas from Vijapur to Dadri in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Limited, Bhartiya Vidyalaya Chauraha, A.B. Road, Shivpuri (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Village : Bagrod, Tehsil : Kolaras, Distt.: Shivpuri

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
01.	341	0.1140
02.	340	0.0380
03.	342	0.2560
04.	343	0.1140
05.	337	0.0248
06.	336	0.0487
07.	335	0.1983
08.	333	0.1948

1	2	3
09.	334	0.0067
10.	321	0.3782
11.	324	0.0033
12.	322	0.0215
13.	323	0.1156
14.	310	0.0425
15.	306	0.2395
16.	305	0.1485
17.	307	0.0270
18.	294	0.027
19.	248	0.1688
20.	247	0.0130
21.	246	0.0363
22.	237	0.1027
23.	239	0.0525
24.	240	0.0314
25.	241	0.2040
26.	242	0.3990
27.	167	0.1381
28.	168	0.0696
29.	151	0.6005
30.	152	0.0885
31.	150	0.0210
32.	149	0.2275
33.	147	0.0323
34.	148	0.0387
35.	1	0.0140

Total: 4.2363

[F. No. L-14016/7/94 G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

का.आ. 2783.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में विजयपुर से दादरी तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

वर्तते कि उक्त भूमि में हितवश कोई व्यक्ति, उस भूमिके नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आपत्ति सूक्ष्म प्राधिकारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय विद्यालय चौराहा, ए.बी. रोड, शिवपुरी (म.प्र.) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसी आपत्ति करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी खुदवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

ग्राम : नतवास, तहसील : कोलारस, जिला : शिवपुरी

क्रमांक खसरा नं. सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें ग्रार.ओ.यू. अध्यापित किया जाना है। (हेक्टेयर में)

01	810	0.0465
02	809	0.2580
03	808	0.0975
04	807	0.0004
05	770	0.2874
06	771	0.0016
07	775	0.2550
08	776	0.0009
09	774	0.3969
10	777	0.0108
11	778	0.0858
12	779	0.3100
13	733	0.0696
14	731	0.2466
15	730	0.0024
16	729	0.1619
17	728	0.0822
18	724	0.0175
19	725	0.0288
20	718	0.0180
21	714/823	0.3855
22	713	0.0330
23	710	0.0150
24	711	0.2900
25	708	0.0015
26	706	0.0472

कुल: 3.1500

[सं. एन-14016/7/94 जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 22nd September, 1994

S.O. 2783.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural gas from Vijapur to Dadri in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Limited, Bhartiya Vidyalaya Chauraha, A.B. Road, Shivpuri (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Village : Naitbas, Tehsil : Kolaras, Distt.: Shivpuri

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
01.	810	0.0465
02.	809	0.2580
03.	808	0.0975
04.	807	0.0004
05.	770	0.2874
06.	771	0.0016
07.	775	0.2550
08.	776	0.0009
09.	774	0.3969
10.	777	0.0108
11.	778	0.0858
12.	779	0.3100
13.	733	0.0696
14.	731	0.2466
15.	730	0.0024
16.	729	0.1619
17.	728	0.0822
18.	724	0.0175
19.	725	0.0288
20.	718	0.0180
21.	714/823	0.3855
22.	713	0.0330
23.	710	0.0150
24.	711	0.2900
25.	708	0.0015
26.	706	0.0472

Total: 3.1500

[F. No. L-14016/7/94 G.P.]

ARDHENDU SEN, Director



नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

का.आ. 2784.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में विजयपुर में दादरी तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

अतएव कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय विद्यालय चौराहा, ए.बी., रोड, शिवपुरी (म.प्र.) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसी आपत्ति करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

ग्राम: मदीखेड़ा, तहसील: कोलारस, जिला: शिवपुरी

कुल: 4.5549

[सं. एल-14016/1/94-जी.पी.]

अध्वेश्वर सेन, निदेशक

New Delhi, the 22nd September, 1994

क्रमांक खसरा नं. सर्वे का यह क्षेत्रफल जिसमें आर.ओ.यू. अध्यापित किया जाना है। (हेक्टेयर में)

1	2	3
01	671	0.1312
02	672	0.4388
03	673	0.4035
04	649	0.0135
05	642	0.1140
06	646	0.3497
07	644	0.0006
08	647	0.0036
09	645	0.0053
10	610	0.0384
11	624	0.0050
12	637	0.0023
13	635	0.3212

S.O. 2784.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural gas from Vijapur to Dadri in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (30 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Limited, Bhartiya Vidyalaya Chauraha, A. B. Road, Shivpuri (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

Village : Murikhera Tehsil : Kolaras Distt. :

Shivpuri

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
01.	671	0.1312
02.	672	0.4388
03.	673	0.4035
04.	649	0.0135
05.	642	0.1140
06.	646	0.3497
07.	644	0.0006
08.	647	0.0036
09.	645	0.0053
10.	610	0.0384
11.	624	0.0050
12.	637	0.0023
13.	635	0.3212
14.	633	0.2190
15.	632	0.2460
16.	614	0.1525
17.	618	0.0920
18.	617	0.0384
19.	495	0.0288
20.	493	0.1460
21.	492	0.0400
22.	476	0.0300
23.	441	0.5384
24.	449	0.0552
25.	444	0.0822
26.	448	0.0444
27.	447	0.0550
28.	446	0.2939
29.	456	0.2655
30.	457	0.1665
31.	445	0.0495
32.	163	0.0140
33.	162	0.1705
Total:		4.5549

[F. No. L-14016/7/94 G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

का.आ. 2735 —यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में विजयपुर से दादरी तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गैस ग्रैवॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाषण्ड अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आग्रह एतद्द्वारा घोषित किया है।

बतते कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस ग्रैवॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय विद्यालय चौराहा, ए.बी. रोड, शिवपुरी (म.प्र.) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसी आपत्ति करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्ट: यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी मुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

ग्राम : डहूरवारा, तहसील : कोलारस, जिला : शिवपुरी

क्रमांक	खसरा नं.	सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें आर.ओ.यू. अध्यापित किया जाना है। (हेक्टेयर में)
---------	----------	---

1	2	3
01	1811	0.2640
02	1812	0.3040
03	1614	0.2315
04	1619	0.1063
05	1610	0.4170
06	1612	0.0360
07	1609	0.1025
08	1608	0.0400
09	1607	0.1770
10	1606	0.0645
11	1603	0.0304
12	1604	0.1677
13	1605	0.0812
14	1600	0.1425
15	1598	0.0950
16	1599	0.0885
17	1565	0.3698
18	1566	0.1368
19	1564	0.0277
20	1567	0.1555
21	1563	0.1275
22	1161	0.0300
23	1561	0.1858
24	1560	0.0618
25	1559	0.0048
26	1558	0.0318
27	1557	0.4190

			Village : Daharwara, Tehsil : Kolaras, Distt : Shivpuri	
1	2	3	Sr. Survey No	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
28	1556	0.0450		
29	1555	0.3760		
30	1554	0.0225	01. 1811	0.2640
31	1444	0.3890	02. 1812	0.3040
32	1445	0.0270	03. 1614	0.2315
33	1409	0.1095	04. 1619	0.1063
34	1452	0.2203	05. 1610	0.4170
35	1454	0.0136	06. 1612	0.0360
36	1458	0.3184	07. 1609	0.1025
37	1434	0.0847	08. 1608	0.0400
38	1433	0.0960	09. 1607	0.1770
39	1414	0.0322	10. 1606	0.0645
40	1417	0.0297	11. 1603	0.0304
41	1416	0.0275	12. 1604	0.1677
42	1418	0.1020	13. 1605	0.0812
43	1419	0.2428	14. 1600	0.1425
44	1415	0.0525	15. 1598	0.0950
45	1413	0.0466	16. 1599	0.0885
46	1420	0.0050	17. 1565	0.3698
47	1407	0.0507	18. 1566	0.1368
48	1421	0.2905	19. 1564	0.0277
49	1398	0.2359	20. 1567	0.1555
50	1399	0.0165	21. 1563	0.1275
कुल 6.7325			22. 1161	0.0300
			23. 1561	0.1858
[सं. एल. 14016/7/94-जी. पी.] अर्धेन्दु सेन, निदेशक			24. 1560	0.0618
			25. 1559	0.0048
New Delhi, the 22nd September, 1994			26. 1558	0.0318
			27. 1557	0.4190
S.O. 2785.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural gas from Vijaipur to Dadri in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.			28. 1556	0.0450
			29. 1555	0.3760
And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire, the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.			30. 1554	0.0225
			31. 1444	0.3890
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.			32. 1445	0.0270
			33. 1409	0.1095
Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Limited, Bhartiya Vidyalaya Chauraha, A. B. Road, Shivpuri (M.P.).			34. 1452	0.2203
			35. 1454	0.0136
And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.			36. 1458	0.3184
			37. 1434	0.0847
			38. 1433	0.0960
			39. 1414	0.0322
			40. 1417	0.0297
			41. 1416	0.0275
			42. 1418	0.1020
			43. 1419	0.2428
			44. 1415	0.0525
			45. 1413	0.0466
			46. 1420	0.0050
			47. 1407	0.0507
			48. 1421	0.2905
			49. 1398	0.2359
			50. 1399	0.0165
Total:				6.7325

[No. L-14016/7/94-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

1

2

3

का.भा.स. 2786—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में विजयपुर से दावरी तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एन.व.पाव. अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

यसमें कि उक्त भूमि में हितवद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय विद्यालय चौराहा, ए.बी., रोड, शिवपुरी (म.प्र.) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसी आपत्ति करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

## अनुसूची

विजयपुर—रादराँ गैस पाइपलाइन परियोजना

ग्राम : सहसराम, नहसीन : विजयपुर, जिला : मोरेना

क्रमांक खसरा नं. सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें ग्राम.प्र.यू. अध्यापित किया जाना है। (हेक्टेयर में)

1	2	3
01.	3123	0.1230
02.	3122	0.1230
03.	3124	0.0696
04.	3125	0.0042
05.	3119	0.0302
06.	3120	0.6344
07.	3110	0.1047
08.	3096	0.1200
09.	3095	0.0365
10.	3092	0.0383

11.	3093	0.1843
12.	3090	0.0112
13.	3089	0.0168
14.	3068	0.2722
15.	3065	0.0105
16.	3060	0.2469
17.	3058	0.0863
18.	3044	0.0045
19.	3043	0.2080
20.	3040	0.1230
21.	3038	0.1230
22.	3036	0.1380
23.	3013	0.0594
24.	3028	0.1440
25.	3030	0.0048
26.	3031	0.0926
27.	3026	0.0072
28.	3032	0.0099
29.	3025	0.0765
30.	3024	0.0648
31.	3033	0.0100
32.	3023	0.0504
33.	3034	0.0010
34.	3022	0.0920
35.	3140/3336	0.0021
36.	2975	0.2160
37.	3151	1.2010
38.	2178	1.1130
39.	2177	0.3900
40.	2133	0.6270
41.	2134	0.2650
42.	2131	0.0005
43.	2135	0.1639
44.	2129	0.5775
45.	2136	0.1464
46.	2137	0.1174
47.	2138	0.0093
48.	1951	0.0342
49.	2287	0.0182
50.	2288	0.0234
51.	1947	0.2235
52.	1946	0.2100
53.	1943	0.3180
54.	1932	0.5335
55.	1933	0.1205
56.	1823	0.2730
57.	1820	0.1380

1	2	3	ग्राम : परारा : तहसील : विजयपुर, जिला : मोरेना		
58.	1818	0.1710	क्रमांक	खसरा नं.	सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें आर.ओ.यू. अध्यापित किया जाना है। (हेक्टेयर में)
59.	1814	0.1680			
60.	1815	0.0182			
61.	1812	0.0027			
62.	1806	0.4116			
63.	1807	0.0086			
64.	1726	0.3928	01.	909	0.990
65.	1808	0.1080	02.	893	0.0195
66.	1725	0.0390	03.	892	0.2847
67.	1711	0.0459	04.	890	0.0198
68.	1689	0.2841	05.	889	0.0770
69.	1690	0.0840	06.	888	0.1560
70.	1692	0.2370	07.	887	0.0233
71.	1685	0.0360			
72.	1628	0.0004			0.6793
73.	1627	0.2156	ग्राम : बुररा : तहसील : विजयपुर, जिला : मोरेना		
74.	1625	0.2245	क्रमांक	खसरा नं.	सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें आर.ओ.यू. अध्यापित किया जाना है। (हेक्टेयर में)
75.	1626	0.0035			
76.	1624	0.0832			
77.	1621	0.0104			
78.	1622	0.3096			
79.	1540	0.0465			
80.	1477	0.3390			
81.	1478	0.2820	1	2	3
82.	1470	0.0540	01.	1002	0.0090
83.	1454	0.2655	02.	2196	0.1440
84.	1453	0.2715	03.	2184	1.0030
85.	1458	0.0714	04.	2179	0.8430
86.	1441	0.4896	05.	2178	0.0884
87.	1440	0.1575	06.	2177	0.1940
88.	1417	0.2280	07.	2173	0.3990
89.	1394	0.1105	08.	2171	0.4485
90.	1393	0.1865	09.	1216	0.6000
91.	1389	0.0340	10.	1218	0.1380
92.	1390	0.3020	11.	1219	0.1665
93.	1388	0.3300	12.	1229	0.0780
94.	1386	0.0063	13.	1227	0.0425
95.	1399	0.0447	14.	1226	0.0075
96.	1166	0.1975	15.	2164	0.0160
97.	1167	0.0605	16.	1250	0.2175
98.	1160	0.1903	17.	1246	0.2055
99.	1181	0.0527	18.	1252	0.5793
100.	1159	0.0002	19.	1245	0.0498
101.	1158	0.0760	20.	1254	0.0220
102.	1182	0.1820	21.	1258	0.1172
कुल जोड़		16.8749	22.	1257	0.2010
			23.	1264	0.2690

1	2	3
24.	1280	0.2880
25.	1276	0.0924
26.	1277	0.0437
27.	1278/1	0.0020
28.	1274	0.0280
29.	1286	0.0056
30.	1273	0.0945
31.	1316	0.0165
32.	1302	0.0755
33.	1301	0.0063
34.	1303	0.1653
35.	1304	0.0321
36.	1306	0.0969
37.	1305	0.0247
38.	1296	0.0786
39.	1295	0.0705
40.	1294	0.0773
41.	1297	0.0735
42.	1293	0.0169
43.	1290	0.3335
44.	1289	0.2390
45.	2119	0.8670
46.	2120	0.3440
47.	2122	0.7500
48.	2123	1.3758
49.	2126	0.0360
50.	2124	0.0022
51.	2129	0.9814
52.	2128	0.1125
53.	2130	0.3480

जोड़ 12.5164

ग्राम : दुधरई, तहसील : विजयपुर, जिला : मोरेना

क्रमांक	खसरा नं.	सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें ग्रार.ओ.यू. अध्यापित किया जाना है। (हेक्टेयर में)
01.	17	0.8310
02.	13	0.2070
03.	12	0.8400
04.	11	0.4815
05.	5	1.1910
06.	10	0.0225
07.	9	0.0225
08.	8	0.2000
		3.7955

ग्राम : खुरजान, तहसील : विजयपुर, जिला : मोरेना

क्रमांक	खसरा नं.	सर्वे का वह क्षेत्रफल, जिसमें ग्रार.ओ.यू. अध्यापित किया जाना है। (हेक्टेयर में)
01.	717	0.1530
02.	716	0.4665
03.	699	0.2573
04.	694	0.5680
05.	684	0.1480
06.	685	0.5792
07.	675	0.0294
08.	674	0.1652
09.	676	0.0080
10.	673	0.0174
11.	671	0.1755
12.	661	0.0687
13.	670	0.1458
14.	668	0.0513
15.	669	0.0410
16.	666	0.1178
17.	651	0.5150
18.	637	0.2375
19.	638	0.2480
20.	640	0.0160
21.	641	0.0815
22.	504	0.1984
23.	503	0.0400
24.	528	0.0180
25.	506	0.1580
26.	508	0.1875
27.	507	0.0968
28.	606	0.1260
29.	605	0.0975
30.	604	0.1089
31.	603	0.0656
32.	528	0.0392
33.	555	0.0675
34.	556	0.2448
35.	558	0.0315
36.	559	0.1774
37.	560	0.0076
38.	566	0.1598
39.	565	0.0400
40.	564	0.0429

1	2	3
41.	572	0.0052
42.	592	0.0025
43.	573	0.3075
44.	574	0.0170
45.	575	0.1997
46.	582	0.0570
47.	576	0.0008
		6.5872

[सं. एल. 14016/7/94-जी.पी.]

अर्धेन्दु सेन, निदेशक

New Delhi, the 22nd September, 1994

S.O. 2786.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural gas from Vijapur to Dadri in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Limited, Bhartiya Vidyalaya Chauraha, A.B. Road, Shivpuri (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

## VIJAYPUR—DADRI GAS PIPELINE PROJECT

Village : Sahasram, Tehsil : Vijapur Distt: Morena

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
01.	3123	0.1230
02.	3122	0.1230
03.	3124	0.0696
04.	3125	0.0042
05.	3119	0.0302
06.	3120	0.6344
07.	3110	0.1047
08.	3096	0.1200
09.	3095	0.0365
10.	3092	0.0383
11.	3093	0.1843

1	2	3
12.	3090	0.0112
13.	3089	0.0168
14.	3068	0.2722
15.	3065	0.0105
16.	3060	0.2469
17.	3068	0.0863
18.	3044	0.0045
19.	3043	0.2080
20.	3040	0.1230
21.	3038	0.1230
22.	3036	0.1380
23.	3013	0.0594
24.	3028	0.1440
25.	3030	0.0048
26.	3031	0.0926
27.	3026	0.0072
28.	3032	0.0099
29.	3025	0.0765
30.	3024	0.0648
31.	3033	0.0100
32.	3023	0.0504
33.	3034	0.0010
34.	3022	0.0920
35.	3140/3336	0.0021
36.	2975	0.2160
37.	3151	1.2010
38.	2178	1.1130
39.	2177	0.3900
40.	2133	0.6270
41.	2134	0.2650
42.	2131	0.0005
43.	2135	0.1639
44.	2129	0.5775
45.	2136	0.1464
46.	2137	0.1174
47.	2138	0.0093
48.	1951	0.0342
49.	2287	0.0182
50.	2288	0.0234
51.	1947	0.2235
52.	1946	0.2100
53.	1943	0.3180
54.	1932	0.5335
55.	1933	0.1205
56.	1823	0.2730
57.	1820	0.1380
58.	1818	0.1710
59.	1814	0.1680
60.	1815	0.0182
61.	1812	0.0027
62.	1806	0.4116
63.	1807	0.0086
64.	1726	0.3928
65.	1808	0.1080
66.	1725	0.0390
67.	1711	0.0459

[illegible]



Village : Dudhai, Tehsil : Vijaypur, Distt : Morena

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
01.	17	0.8310
02.	13	0.2070
03.	12	0.8400
04.	11	0.4815
05.	5	1.1910
06.	10	0.0225
07.	9	0.0225
08.	8	0.2000
Total:		3.7955

1	2	3
34.	556	0.2448
35.	558	0.0315
36.	559	0.1774
37.	560	0.0076
38.	566	0.1598
39.	565	0.0400
40.	564	0.0429
41.	572	0.0052
42.	592	0.0025
43.	573	0.3075
44.	574	0.1170
45.	575	0.1997
46.	582	0.0570
47.	576	0.0008
Total		6.5872

Village : Khurjan, Tehsil : Vijaypur, Distt : Morena

Sl. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
---------	------------	---

01.	717	0.1530
02.	716	0.4665
03.	699	0.2573
04.	694	0.5680
05.	684	0.1480
06.	685	0.5792
07.	675	0.0294
08.	674	0.1652
09.	676	0.0080
10.	673	0.0174
11.	671	0.1755
12.	661	0.0687
13.	670	0.1458
14.	668	0.0513
15.	669	0.0410
16.	666	0.1178
17.	651	0.5150
18.	637	0.2375
19.	638	0.2480
20.	640	0.0160
21.	641	0.0815
22.	504	0.1984
23.	503	0.0400
24.	528	0.0180
25.	506	0.1580
26.	508	0.1875
27.	507	0.0968
28.	606	0.1260
29.	605	0.0975
30.	604	0.1089
31.	603	0.0656
32.	528	0.0392
33.	555	0.0675

[No. L-14016/7/94—G.P.]121

ARDHENDU SEN, Director

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

का. आ. 2787 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में विजयपुर से दादरी तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एनर्वाबल अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 को उन्मूलन (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्-द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय विद्यालय चौराहा, ए. बी. रोड, शिवपुरी (म. प्र.) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसी आपत्ति करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

ग्राम : टिडावली, तहसील : जोरा, जिला : मोरेना

क्रमांक खसरा नं. सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें आर. ओ. यू. अध्यापित किया जाना है। (हेक्टेयर में)

01.	430	0.1710
02.	424	0.0103
03.	423	0.0004
04.	422	0.0010
05.	405	0.0004
06.	42	0.0390
07.	21	0.1321
08.	22	0.0250
09.	19	0.4212
10.	18	0.0075
11.	12	0.2649
12.	20	0.0295
13.	11	0.0171

योग : 1.1194

ग्राम : भूरि, तहसील : जोरा, जिला : मोरेना

क्रमांक खसरा नं. सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें आर. ओ. यू. अध्यापित किया जाना है। (हेक्टेयर में)

01.	342	0.1020
02.	91	0.0120
03.	88	0.0729
04.	89	0.1285
05.	87	0.0216
06.	81	0.1241
07.	80	0.1620
08.	77	0.1909
09.	74	0.1040
10.	75	0.1519
11.	73	0.5031
12.	70	0.3105
13.	67	0.5560
14.	63	0.5955
15.	54	0.0032
16.	59	0.2720
17.	60	0.2387
18.	5	0.2414
19.	4	0.0828
20.	3	0.1485
21.	2	0.0450
22.	1	0.2310

योग : 4.2976

ग्राम : धौधा, तहसील : जोरा, जिला : मोरेना

क्रमांक खसरा नं. सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें आर. ओ. यू. अध्यापित किया जाना है। (हेक्टेयर में)

01.	20	0.0158
02.	31/2	0.0224
03.	10	0.0240
04.	5	0.3450
05.	6	0.0609
06.	7	0.3520
07.	8	0.3240
08.	9	0.2265
09.	38	0.7180
10.	56	0.0055
11.	57	0.1596
12.	92	0.7770
13.	81	0.1650
14.	84	0.0690
15.	126	0.1883
16.	125	0.0312
17.	132	0.0085
18.	129	0.0870
19.	130	0.0464
20.	131	0.0616
21.	144	0.1813
22.	142	1.1525
23.	267	0.4350

योग : 5.3664

ग्राम : बसबोहा, तहसील : जोरा, जिला : मोरेना

क्रमांक खसरा नं. सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें आर. ओ. यू. अध्यापित किया जाना है। (हेक्टेयर में)

01.	60	0.4650
02.	59	1.2360
03.	58	0.9720
04.	57	1.0636
05.	56	0.0915
06.	55	0.255
07.	54	0.4740

योग : 4.3276

ग्राम : जोगीपुरा तहसील : जोरा जिला : मोरेना			1	2	3
क्रमांक	खसरा नं.	सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें आर ओ यू अध्यापित किया जाता है (हेक्टेयर में)			
1	2	3			
01.	406	0.0570	42.	114	0.2490
02.	336	0.1100	43.	122	0.1670
03.	335	0.2038	44.	123	0.0100
04.	339	0.2685	45.	121/2	0.1855
05.	337	0.2339	46.	121/1	0.1205
06.	356	1.0501	47.	125	0.0540
07.	372	0.2577	48.	100/1	1.3050
08.	383	0.5759	49.	126/1	0.5138
09.	323	0.1805	50.	128	0.0245
10.	310	0.6195	51.	137	0.1734
11.	309	1.1850	52.	138	0.0758
12.	294	0.7553	53.	141	0.3049
13.	291	0.2160	54.	142	0.5578
14.	290	0.1830	55.	143	0.2312
15.	289	0.1950	56.	144	0.1110
16.	288	0.1050	57.	145	0.0600
17.	287	0.1020	जोड़		14.2522
18.	286	0.0660	ग्राम : कन्हार तहसील : जोरा जिला : मोरेना		
19.	284	0.3365	क्रमांक खसरा नं. सर्वे का वह क्षेत्र जिसमें आर ओ यू अध्यापित किया जाता है। (हेक्टेयर में)		
20.	296	0.0795	01.	304	0.0264
21.	293	0.0120	02.	303	0.0475
22.	266	0.6174	03.	302	1.0200
23.	265	0.0936	04.	296	0.1140
24.	259	0.4390	जोड़		1.2079
25.	260	0.1753	ग्राम : आरेठी तहसील : जोरा जिला : मोरेना		
26.	254	0.0646	क्रमांक खसरा नं. सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें आर ओ यू अध्यापित किया जाता है। (हेक्टेयर में)		
27.	255	0.0645	1	2	3
28.	256	0.0207	01.	307	0.0720
29.	257	0.2100	02.	331	0.2624
30.	258	0.0561	03.	330	0.2708
31.	236	0.0658	04.	329	0.1650
32.	239	0.2846	05.	338	0.0225
33.	235	0.2070	06.	328	0.0150
34.	234	0.2550	07.	325	0.2964
35.	213	0.2675			
36.	211	0.0628			
37.	210	0.0040			
38.	79	0.0823			
39.	109	0.0224			
40.	110	0.1590			
41.	113	0.1650			

1	2	3	ग्राम : गोपालपुरा	तहसील : जीरा	जिला : मोरेना
08.	339	0. 0172	क्रमांक	खसरा नं.	सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें ग्राम ० प्रो ० यू ० अध्यापित किया जाना है। (हेक्टेयर में)
09.	340	0. 2004			
10.	324	0. 0170			
11.	341	0. 2238			
12.	322	0. 0532	1	2	3
13.	304	0. 2605	01.	413	0. 1728
14.	214	0. 1006	02.	516/4	0. 0455
15.	221	0. 1464	03.	414/2	0. 1225
16.	220	0. 0137	04.	414/1	0. 1125
17.	225	0. 1485	05.	417/1	0. 0152
18.	226	0. 1818	06.	417/2	0. 1227
19.	188	0. 0030	07.	417/4	0. 0658
20.	227	0. 1419	08.	415/2	0. 0015
21.	286	0. 0333	09.	419	0. 2163
22.	228	0. 0375	10.	422	0. 0936
23.	284	0. 0502	11.	516/14	0. 0234
24.	230	0. 1238	12.	423	0. 0390
25.	231	0. 0850	13.	424	0. 0480
26.	232	0. 0095	14.	425	0. 1470
27.	177	0. 1370	15.	400	0. 1439
28.	176	0. 0248	16.	401	0. 0240
29.	174	0. 0109	17.	60	0. 0316
30.	170	0. 2445	18.	96	0. 0245
31.	163	0. 1080	19.	95	0. 1320
32.	173	0. 2506	20.	100	0. 1759
33.	162	0. 0905	21.	102	0. 0742
34.	161	0. 0795	22.	103	0. 1248
35.	160	0. 0780	23.	137	0. 1510
36.	157	0. 1684	24.	136	0. 0380
37.	156	0. 0095	25.	144	0. 1110
38.	106	0. 0510	26.	132	0. 0014
39.	108	0. 5227	27.	131	0. 0885
40.	109	0. 5000	28.	145	0. 1233
41.	111	0. 0369	29.	155	0. 1095
42.	120	0. 0495	30.	154	0. 0156
43.	114	0. 2160	31.	153/1	0. 0435
44.	115	0. 1140	32.	159	0. 2487
45.	116	0. 0677	33.	162	0. 0966
			34.	152	0. 0373
			35.	163	0. 1455
			36.	169	0. 1890
			37.	167	0. 1130
			38.	168	0. 0010
			39.	174	0. 0865
			40.	187	0. 0607
			41.	175	0. 1220
		57109			

1	2	3	ग्राम : धुरकुण्डा,	तहसील : जीरा,	जिला : मोरेना
42.	178	0.0878	क्रमिक खसरा नं. सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें आर.ओ.यू. अध्यापित किया जाना है (हेक्टेयर में)		
43.	179	0.1350			
44.	186	0.1275			
45.	185	0.1410			
46.	223	0.3900			
47.	232	0.0500			
48.	233	0.0620			
49.	234	0.0340			
50.	217	0.0418			
51.	236	0.1477			
52.	240	0.0340			
53.	237	0.0312			
54.	238	0.0025			
55.	239	0.1155			
56.	242	0.1020			
57.	243	0.0183			
58.	244	0.2000			
59.	1	0.3390	01.	952	0.1658
60.	516/1	6.7785	02.	953	0.0284
61.	409	0.1050	03.	954	0.1968
62.	516/19	0.2355	04.	955	0.1860
63.	516/9	0.4290	05.	956	0.0960
64.	516/5	0.3030	06.	921	0.1710
65.	516/8	0.0084	07.	919	0.0728
जोड़ 13.6574			08.	923	0.1095
ग्राम : टेलरी	तहसील : जीरा	जिला : मोरेना	09.	924	0.2005
क्रमिक खसरा नं.	सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें आर.ओ.यू. अध्यापित किया जाना है (हेक्टेयर में)		10.	917	0.0048
01.	79	0.2535	11.	512	0.0240
02.	78	0.6620	12.	550	0.2140
03.	69	0.0055	13.	549	0.1875
04.	70	0.3954	14.	542	0.1643
05.	74	0.2421	15.	506	0.0517
06.	47	0.5895	16.	541	0.0583
07.	45	0.1905	17.	507	0.0675
08.	46	0.0480	18.	508	0.0625
09.	44	0.0505	19.	509	0.1594
10.	43	0.1481	20.	523	0.0026
11.	42	0.0012	21.	522	0.2441
12.	40	0.0018	22.	496	0.0405
13.	38	0.2082	23.	519	0.0008
14.	37	0.1395	24.	518	0.0122
जोड़ 2.9358			25.	511	0.0363
			26.	513	0.1939
			27.	514	0.0048
			28.	516	0.1230
			29.	406	0.3282
			30.	405	0.1883
			31.	404	0.3839
			32.	403	0.0689
			33.	401	0.1398
			34.	399	0.1687
			35.	383	0.0113
			36.	400	0.0523
जोड़ 4.2204					

ग्राम : खेरली; तहसील : जौरा ; जिला : मोरेना

1 2 3

क्रमांक खसरा नं. सर्वे का वह क्षेत्रफल  
जिसमें ग्रार.ओ.यू.  
अध्यापित किया जाता  
है (हेक्टेयर में)

1 2 3

01.	745	0.0017
02.	746	0.4023
03.	744	0.3990
04.	736	0.2910
05.	735	0.4140
06.	734	0.1660
07.	750	0.0490
08.	730	0.0015
09.	752	0.2875
10.	729	0.2445
11.	570	0.0352
12.	574	0.0210
13.	572	0.2070
14.	573	0.1875
15.	577	0.1620
16.	584	0.1470
17.	583	0.2070
18.	587	0.1860
19.	588	0.1740
20.	554	0.0615
21.	591	0.0884
22.	589	0.2099
23.	545	0.2543
24.	543	0.2955
25.	209	0.0204
26.	272	0.1702
27.	542	0.0916
28.	274	0.0975
29.	273	0.0268
30.	275	0.0194
31.	265	0.2410
32.	271	0.0125
33.	268	0.0375
34.	269	0.2145
35.	257	0.0432
36.	267	0.1818
37.	266	0.0260
38.	258	0.1928
39.	261	0.0032
40.	259	0.1605

41.	253	0.1575
42.	139	0.1050
43.	140	0.1560
44.	141	0.1470
45.	144	0.1226
46.	145	0.0243
47.	142	0.3451
48.	115	0.2662
49.	114	0.0248
50.	116	0.0270
51.	120	0.1890
52.	121	0.1823
53.	122	0.3065
54.	46	0.2655
55.	123	0.0175
56.	44	0.1103
57.	43	0.0420
58.	727	0.1568

जोड़ 8.6771

ग्राम : जम्घाप, तहसील : जौरा, जिला : मोरेना

क्रमांक खसरा नं० सर्वे का वह क्षेत्रफल  
जिसमें ग्रार० ओ० यू०  
अध्यापित किया जाता  
है (हेक्टेयर में)

1	2	3
01.	465	0.4410
02.	473	0.1915
03.	472	0.2885
04.	466	0.1830
05.	457	0.1530
06.	456	0.1815
07.	455	0.1775
08.	453	0.0032
09.	452	0.2100
10.	436	0.0591
11.	437	0.0906
12.	440	0.0052
13.	438	0.3009
14.	428	0.1298
15.	419	0.2885

1	2	3	ग्राम : हुसैनपुर	तहसील : जौरा	जिला : मोरेना
16.	356	0.0360	क्रमांक	खसरा नं०	सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें आर०ओ०यू० अध्यापित किया जाना है। (हेक्टेयर में)
17.	368	0.0541			
18.	367	0.1964			
19.	366	0.1815			
20.	365	0.2810			
21.	364	0.1269	01.	348	0.0975
22.	363	2.1410	02.	346	0.3540
23.	362	0.1836	03.	341	0.1752
24.	361	0.0564	04.	340	0.0438
25.	198	0.0475	05.	339	0.4986
26.	197	0.1743	06.	331	0.0045
27.	180	0.4173	07.	332	0.0069
28.	178	0.1980	08.	334	0.1650
29.	179	0.0392	09.	328	0.0054
30.	175	0.0650	10.	325	0.4686
31.	174	0.3168	11.	327	0.0004
32.	173	0.0810	12.	319	0.1160
33.	140	0.2526	13.	318	0.0630
34.	141	0.0466	14.	314	0.4755
35.	143	0.4983			
36.	108	0.0222			योग : 2.4744
37.	107	0.2253			
38.	106	0.2034			[स० एन-14016/7/94-जीपी]
39.	109	0.0756			अर्धेन्दु सेन, निदेशक
40.	92	0.0552			
41.	91	0.3313			
42.	81	0.2465			New Delhi, the 22nd September, 1994
43.	80	0.2825			
44.	79	0.0690			S.O. 2787.—Whether it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural gas from Vijaipur to Dadri in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.
45.	78	0.0960			And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.
46.	77	0.1800			Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :
47.	76	0.1245			Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Limited, Bhartiya Vidyalaya Chauraha, A. B. Road, Shivpuri (M.P.).
48.	48	0.0960			
49.	49	0.0855			
50.	50	0.0315			
51.	52	0.0960			
52.	40	0.1065			
53.	27	0.1420			
54.	26	0.0260			
55.	23	0.1116			
56.	28	0.2639			
57.	21	0.4090			
58.	20	0.0385			

योग : 9.4148

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## VIJAYPUR—DADRI GAS PIPELINE PROJECT

Village : Tidawali, Tehsil : Jaura, Distt.: Morena

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. (in Hectare)
01.	430	0.1710
02.	424	0.0103
03.	423	0.0004
04.	422	0.0010
05.	405	0.0004
06.	42	0.0390
07.	21	0.1312
08.	22	0.0250
09.	19	0.4212
10.	18	0.0075
11.	12	0.2649
12.	20	0.0295
13.	11	0.0171
Total:		1.1194

Village : Dhondha, Tehsil : Jaura, Distt.: -Morena

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
01.	20	0.0158
02.	31/2	0.0224
03.	10	0.0240
04.	5	0.3450
05.	6	0.0609
06.	7	0.3520
07.	8	0.2340
08.	9	0.2265
09.	38	0.7180
10.	56	0.0055
11.	57	0.1595
12.	92	0.7770
13.	81	0.1650
14.	84	0.0690
15.	126	0.1883
16.	125	0.0312
17.	132	0.0085
18.	129	0.0870
19.	130	0.0464
20.	131	0.0616
21.	144	0.1813
22.	142	1.1525
23.	267	0.4350
Total:		5.3664

Village : Bhuri, Tehsil : Jaura, Distt. : Morena

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. (in Hectare)
01.	342	0.1020
02.	91	0.0120
03.	88	0.0729
04.	89	0.1285
05.	87	0.0216
06.	81	0.1241
07.	80	0.1620
08.	77	0.1909
09.	74	0.1040
10.	75	0.1519
11.	73	0.5031
12.	70	0.3105
13.	67	0.5560
14.	63	0.5955
15.	54	0.0032
16.	59	0.2720
17.	60	0.2387
18.	5	0.2414
19.	4	0.0828
20.	3	0.1485
21.	2	0.0450
22.	1	0.2310
Total:		4.2976

Village : Waskhoha, Tehsil : Jaura, Distt.: Morena

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. (in Hectare)
01.	60	0.4650
02.	59	1.2360
03.	58	0.9720
04.	57	1.0636
05.	56	0.0915
06.	55	0.0255
07.	54	0.4740
Total:		4.3276



Village : Jogipura, Tehsil : Jaura, Distt. : Morena

2

3

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
---------	------------	---

1	2	3
---	---	---

01.	406	0.0570
02.	336	0.1100
03.	335	0.2038
04.	339	0.2685
05.	337	0.2339
06.	356	1.0501
07.	372	0.2577
08.	383	0.5759
09.	323	0.1805
10.	310	0.6195
11.	309	1.1850
12.	204	0.7553
13.	291	0.2160
14.	290	0.1830
15.	289	0.1950
16.	288	0.1050
17.	287	0.1020
18.	286	0.0660
19.	284	0.3365
20.	296	0.0795
21.	295	0.0120
22.	266	0.6174
23.	265	0.0936
24.	259	0.4390
25.	260	0.1753
26.	254	0.0646
27.	255	0.0645
28.	256	0.0207
29.	257	0.2100
30.	258	0.0561
31.	236	0.0658
32.	239	0.2846
33.	235	0.2070
34.	234	0.2550
35.	213	0.2675
36.	211	0.0628
37.	210	0.0040
38.	79	0.0823
39.	109	0.0224
40.	110	0.1590
41.	113	0.1650
42.	114	0.2490
43.	122	0.1670
44.	123	0.0100
45.	121/2	0.1855
46.	121/1	0.1205
47.	125	0.0540
48.	100/1	1.3050
49.	126/1	0.5138
50.	128	0.0245

51.	137	0.1734
52.	138	0.0758
53.	141	0.3049
54.	142	0.5578
55.	143	0.2312
56.	144	0.1110
57.	146	0.0600

Total: 14.2522

Village: Kanhar, Tehsil: Jaura, Distt. : Morena

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
---------	------------	---

1	2	3
---	---	---

01.	304	0.0264
02.	303	0.0475
03.	302	1.0200
04.	296	0.1140

Total: 1.2079

Village: Aanento Tehsil : Jawa Distt. Morena

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
---------	------------	---

1	2	3
---	---	---

01.	307	0.0728
02.	331	0.2624
03.	330	0.2708
04.	329	0.1650
05.	338	0.0225
06.	328	0.0150
07.	325	0.2464
08.	339	0.0172
09.	340	0.2004
10.	324	0.0170
11.	341	0.2238
12.	322	0.0532
13.	304	0.2605
14.	214	0.1006
15.	221	0.1464
16.	220	0.0137
17.	225	0.1465
18.	226	0.1818
19.	188	0.0030
20.	227	0.1419
21.	286	0.0833
22.	228	0.0375
23.	284	0.0502
24.	230	0.1238
25.	231	0.0650
26.	232	0.0095
27.	177	0.1370
28.	176	0.0248
29.	174	0.0109
30.	170	0.2445

1	2	3
31.	163	0.1080
32.	173	0.2506
33.	162	0.0905
34.	161	0.0795
35.	160	0.0780
36.	157	0.1684
37.	156	0.0095
38.	106	0.0510
39.	108	0.5227
40.	109	0.5000
41.	111	0.0369
42.	120	0.0495
43.	114	0.2160
44.	115	0.1140
45.	116	0.0677
Total:		5.7109

Vijaypur-Dadri Gas Pipeline Project  
Village : Gopalpura, Tehsil : Jaura, Distt. : Morena

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
01.	413	0.1728
02.	516/4	0.0455
03.	414/2	0.1225
04.	414/1	0.1125
05.	417/1	0.0152
06.	417/2	0.1227
07.	417/4	0.0658
08.	415/2	0.0015
09.	419	0.2163
10.	422	0.0936
11.	516/14	0.0234
12.	423	0.0390
13.	424	0.0480
14.	425	0.1470
15.	400	0.1439
16.	401	0.0240
17.	60	0.0316
18.	96	0.0245
19.	95	0.1320
20.	100	0.1759
21.	102	0.0742
23.	103	0.1248
25.	137	0.1510
24.	136	0.0380
25.	144	0.1110
26.	132	0.0014
27.	131	0.0885
28.	145	0.1233
29.	155	0.1095
30.	154	0.0156
31.	153/1	0.0435
32.	159	0.2487
33.	162	0.0966
34.	152	0.0373
35.	163	0.1455
36.	169	0.1890
37.	167	0.1130
38.	168	0.0010

1	2	3
39.	174	0.0865
40.	187	0.0607
41.	175	0.1220
42.	178	0.0878
43.	179	0.1350
44.	186	0.1275
45.	185	0.1410
46.	223	0.3900
47.	232	0.0500
48.	233	0.0620
49.	234	0.0340
50.	217	0.0418
51.	236	0.1477
52.	240	0.0340
53.	237	0.0312
54.	238	0.0025
55.	239	0.1155
56.	242	0.1020
57.	243	0.0182
58.	244	0.2000
59.	1	0.3390
60.	516/1	0.7785
61.	409	0.1050
62.	516/19	0.2355
63.	516/9	0.4290
64.	516/5	0.3030
65.	516/8	0.0084
Total		13.6574

Vijaypur-Dadri Gas Pipeline Project  
Village : Telari Tehsil : Jaura, Distt. : Morena

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
01.	79	0.2535
02.	78	0.6620
03.	69	0.0055
04.	70	0.3954
05.	74	0.2421
06.	47	0.5895
07.	45	0.1905
08.	46	0.0480
09.	44	0.0505
10.	43	0.1481
11.	42	0.0012
12.	40	0.0018
13.	38	0.2082
14.	37	0.1395
Total		2.9358

Vijaypur-Dadri Gas Pipeline Project  
Village : Dhurkunda, Tehsil : Jaura, Distt. : Morena

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
01.	952	0.1658
02.	953	0.0284
03.	954	0.1968
04.	955	0.1860

1	2	3	1	2	3
05.	956	0.0960	23.	545	0.2543
06.	921	0.1710	24.	543	0.2955
07.	919	0.0728	25.	209	0.0204
08.	923	0.1095	26.	272	0.1702
09.	924	0.2005	27.	542	0.0916
10.	917	0.0048	28.	274	0.0975
11.	512	0.0240	29.	273	0.0268
12.	550	0.2140	30.	275	0.0194
13.	549	0.1875	31.	265	0.2410
14.	542	0.1643	32.	271	0.0125
15.	506	0.0517	33.	268	0.0375
16.	541	0.0583	34.	269	0.2145
17.	507	0.0675	35.	257	0.0432
18.	508	0.0625	36.	267	0.1818
19.	509	0.1594	37.	266	0.0260
20.	523	0.0026	38.	258	0.1928
21.	522	0.2441	39.	261	0.0032
22.	496	0.0405	40.	259	0.1605
23.	519	0.0008	41.	253	0.1575
24.	518	0.0122	42.	139	0.1050
25.	511	0.0363	43.	140	0.1560
26.	513	0.1939	44.	141	0.1470
27.	514	0.0048	45.	144	0.1226
28.	516	0.1230	46.	145	0.0243
29.	406	0.3282	47.	142	0.3451
30.	405	0.1883	48.	115	0.2662
31.	404	0.3839	49.	114	0.0248
32.	403	0.0689	50.	116	0.0270
33.	401	0.1398	51.	120	0.1890
34.	399	0.1687	52.	121	0.1823
35.	383	0.0113	53.	122	0.3065
36.	400	0.0523	54.	46	0.2655
Total		4.2204	55.	123	0.0175
			56.	44	0.1103
			57.	43	0.0420
			58.	727	0.1568

Village : Kherali, Tehsil : Jaura, Distt. : Morena

Total

9.6771

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
01.	745	0.0017
02.	746	0.4023
03.	744	0.3990
04.	736	0.2910
05.	735	0.4140
06.	734	0.1660
07.	750	0.0490
08.	730	0.0015
09.	752	0.2875
10.	729	0.2445
11.	570	0.0352
12.	574	0.0210
13.	572	0.2070
14.	573	0.1875
15.	577	0.1620
16.	584	0.1470
17.	583	0.2070
18.	587	0.1860
19.	588	0.1740
20.	554	0.0615
21.	591	0.0884
22.	589	0.2099

Village : Japthap, Tehsil : Jaura, Distt. : Morena

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
01.	465	0.4410
02.	473	0.1915
03.	472	0.2885
04.	466	0.1830
05.	457	0.1530
06.	456	0.1815
07.	455	0.1775
08.	453	0.0032
09.	452	0.2100
10.	436	0.0591
11.	437	0.0906
12.	440	0.0052
13.	438	0.3009
14.	428	0.1298
15.	419	0.2885
16.	356	0.0360
17.	368	0.0541
18.	367	0.1964
19.	366	0.1815

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

1	2	3
20.	365	0.2810
21.	364	0.1269
22.	363	0.1410
23.	362	0.1836
24.	361	0.0564
25.	198	0.0475
26.	197	0.1743
27.	180	0.4173
28.	178	0.1980
29.	179	0.0392
30.	175	0.0650
31.	174	0.3168
32.	173	0.0810
33.	140	0.2526
34.	141	0.0466
35.	143	0.4983
36.	108	0.0222
37.	107	0.2253
38.	106	0.2034
39.	109	0.0756
40.	92	0.0552
41.	91	0.3313
42.	81	0.2465
43.	80	0.2825
44.	79	0.0690
45.	78	0.0960
46.	77	0.1800
47.	76	0.1245
48.	48	0.0960
49.	49	0.0855
50.	50	0.0315
51.	52	0.0960
52.	50	0.1065
53.	27	0.1420
54.	26	0.0260
55.	23	0.1116
56.	28	0.2639
57.	21	0.4090
58.	20	0.0385

Total : 9.4148

Vill. : Husainpur	Teh. : Jaura	Disstt. : Morona
Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
01.	348	0.0975
02.	346	0.3540
03.	341	0.1752
04.	340	0.0438
05.	339	0.4986
06.	331	0.0045
07.	332	0.0069
08.	334	0.1650
09.	328	0.0054
10.	325	0.4686
11.	327	0.0004
12.	319	0.1160
13.	318	0.0630
14.	314	0.4755
Total :		2.4744

[No. I-14016/794-G.P.]  
ARDHENDU SEN, Director

कां० प्र० 2788.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि मध्य प्रदेश राज्य में विजयपुर से दादरी तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, द्वारा पाइप-लाइन बिछाई जानी चाहिए।

और अतः यह प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वाक्य अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आपत्ति सभ्य प्राधिकारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय विद्यालय चौराहा, ए० बी० रोड, शिवपुरी, (म० प्र०) को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसी आपत्ति करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

## अनुसूची

विजयपुर—दादरी गैस पाइपलाइन परियोजना

ग्राम : सगोरिया	तहसील : केलारस,	जिला : मोरेना
क्रमांक	खसरा न०	सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें आर०ओ०यू० अध्यापित किया जाना है। (हेक्टेयर में)
01.	211	0.0022
02.	210	0.1898
03.	207	0.0028
04.	208	0.3079
05.	196	0.2680
06.	205	0.2755
07.	198	0.0048
08.	199	0.1692
09.	200	0.0338
10.	201	0.1500
11.	202	0.2460

योग 1.6500

ग्राम : सिगाचौली, तहसील : केलारस, जिला : मोरेना

ग्राम : देवकच्छ, तहसील : केलारस जिला : मोरेना

क्रमांक	खसरा नं.	सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें ग्रार. ओ. यू. अध्यापित किया जाना है (हेक्टेयर में)
01.	524	0.1395
02.	523	0.0010
03.	520	0.1604
04.	521	0.0690
05.	516	0.0360
06.	508	0.1615
07.	509	0.0360
08.	460	0.0915
09.	461	0.1110
10.	462	0.1241
11.	466	0.0043
12.	463	0.0036
13.	468	0.0464
14.	469	0.0420
15.	453	0.0075
16.	470	0.0948
17.	472	0.0126
18.	571	0.1345
19.	348	0.2280
20.	346	0.2190
21.	345	0.2193
22.	343	0.0990
23.	314	0.0095
24.	313	0.0247
25.	303	0.4020
26.	302	0.1050
27.	301	0.0551
28.	298	0.1940
29.	296	0.0621
30.	299	0.0656
31.	283	0.1006
32.	283	0.0028
33.	281	0.1742
34.	280	0.0572
35.	279	0.1365
36.	271	0.0583
37.	273	0.0020
38.	270	0.1590
		3.6486

क्रमांक	खसरा नं.	सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें ग्रार. ओ. यू. अध्यापित किया जाना है। (हेक्टेयर में)
01.	224	0.0240
		0.0240

ग्राम : विलोघ्रा, तहसील : केलारस जिला : मोरेना

क्रमांक	खसरा नं.	सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें ग्रार. ओ. यू. अध्यापित किया जाना है (हेक्टेयर में)
1.	2	3
01.	328	0.0102
02.	326	0.1140
03.	325	0.1575
04.	318	0.0135
05.	315	0.1710
06.	313	0.1530
07.	311	0.1011
08.	84	0.0014
09.	297	0.0250
10.	108	0.1411
11.	109	0.1890
12.	117	0.0960
13.	116	0.2160
14.	115	0.1590
15.	122	0.1770
16.	140	0.0270
17.	139	0.0333
18.	133	0.3027
19.	132	0.0725
20.	134	0.0675
21.	131	0.4740
22.	158	0.0613
23.	129	0.0733
24.	160	0.0936
25.	159	0.1490
26.	29	0.1080

1	2	3
27.	30	0.1455
28.	32	0.0189
29.	21	0.0984
30.	22	0.0227
31.	16	0.3175
32.	15	0.0208
33.	14	0.1352
34.	12	0.0240
		3.9709

ग्राम भूरावली, तहसील:केलारस, जिला :मोरेना

क्रमांक	खसरा नं.	सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें भार.ओ.यू. अध्यापित किया जाना है (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
01.	69	0.4056
02.	70	0.0144
03.	64	0.1320
04.	63 ख	0.1260
05.	62	0.2520
06.	51	0.0300
07.	49	0.0125
08.	50	0.2365
09.	43	0.0572
10.	44	0.2120
11.	30/2	0.1717
12.	31	0.1163
13.	30/1	0.0330
14.	23	0.1530
15.	24	0.1760
16.	8	0.3186
17.	7	0.0354
18.	6	0.2057
19.	2	0.1890
20.	106	0.0300

2.9069

ग्राम : मूजरमा तहसील : केलारस जिला : मोरेना

क्रमांक	खसरा नं.	सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें भार. ओ. यू. अध्यापित किया जाना है (हेक्टेयर में)
1	2	3
01.	2028	0.2610
02.	2030	0.2490

1	2	3
03.	2033	0.2840
04.	1821	0.0054
05.	1822	0.0158
06.	1819	0.0030
07.	1818	0.3372
08.	1818	0.0378
09.	1815	0.4703
10.	1828	0.0127
11.	1584	0.2925
12.	1595	0.2610
13.	1596	0.0153
14.	1593	0.4780
15.	1588	0.0076
16.	1592	0.2044
17.	1591	0.1740
18.	1557/1	0.3690
19.	1557/2	0.0720
20.	1556	0.0300
21.	1555	0.2160
22.	1545	0.1068
23.	1653	0.0663
24.	1654	0.0750
25.	1655	0.1590
26.	1669	0.2506
27.	1670	0.0705
28.	1671	0.0918
29.	1677	0.1400
30.	1679	0.0040
31.	1678	0.2150
32.	1680	0.0050
33.	1684	0.1210
34.	1683	0.2160
35.	1682	0.0180
		5.3359

ग्राम : भीजसैया, तहसील:केलारस, जिला :मोरेना

क्रमांक	खसरा नं.	सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें भार. ओ. यू. अध्यापित किया जाना है (हेक्टेयर में)
1	2	3
01.	370	0.4290
02.	368	0.2610
03.	366	0.2610
04.	364	0.1890
05.	357	0.1980

1	2	3
06.	356	0.1545
07.	243	0.7340
08.	249	0.2185
09.	253	0.3060
10.	198	0.0975
11.	197	0.1080
12.	268	0.3300
13.	271	0.0552
14.	277	0.2808
15.	276	0.2655
16.	274	0.2460
17.	283	0.0270
18.	284	0.0075
19.	178	0.3030
20.	179	0.0088
21.	176	0.1035
22.	177	0.3600
23.	286	0.0390
		4.9828

ग्राम : बेरहमानगढ़, तहसील : केलारस, जिला : मोरेना

क्रमांक खसरा नं.

सर्वे का वह क्षेत्रफल  
जिसमें भार.ओ.यू.  
अध्यापित किया जाना है  
(हेक्टेयर में)

1	2	3
01.	243	0.1285
02.	244	0.0617
03.	245	0.1307
04.	246	0.2340
05.	237	0.3300
06.	232	0.1878
07.	231	0.0312
08.	227	0.1455
09.	228	0.1395
10.	222	0.2970
11.	217	0.0126
12.	218	0.3324
13.	215	0.0300
14.	214	0.1510
15.	211	0.0027
16.	210	0.0518
17.	296	0.0475
18.	209	0.0045
19.	197	0.1935

1	2	3
20.	201	0.2330
21.	200	0.1555
22.	122	0.0270
23.	124	0.0900
24.	121	0.2730
		3.2904

ग्राम : रिटोनिया, तहसील : केलारस, जिला : मोरेना

क्रमांक खसरा नं.

सर्वे का वह क्षेत्रफल  
जिसमें भार.ओ.यू.  
अध्यापित किया जाना  
है (हेक्टेयर में)।

1	2	3
01.	177	0.2433
02.	176	0.0440
03.	40	0.1280
04.	175	0.0060
05.	174	0.1448
06.	173	0.1762
07.	172	0.0850
08.	171	0.0505
09.	167	0.0080
10.	165	0.2695
11.	48	0.3858
12.	51	0.0546
13.	49	0.0206
14.	144	0.0495
15.	52	0.3776
16.	58	0.1050
17.	53	0.0036
18.	57	0.1254
19.	141	0.0300
20.	64	0.0650
21.	63	0.1485
22.	69	0.1604
23.	70	0.0121
24.	73	0.1530
25.	72	0.0003
26.	75	0.0300
27.	74	0.0480
28.	71	0.0754
29.	76	0.1103
30.	77	0.0247
31.	78	0.0900
32.	79	0.0540

1	2	3
33.	85	0.0420
34.	84	0.7058
35.	86	0.1018
36.	83	0.1671
37.	81	0.1770
		4.4228

ग्राम : नेवरी तहसील : केदारस जिला : मोरेना

सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें आर.ओ.यू. अध्यापित किया जाना है।  
(हेक्टेयर में)

1	2	3
01.	1055	0.0560
02.	1054	0.2390
03.	1053	0.1450
04.	1052	0.0034
05.	1051	0.0408
06.	1050	0.1576
07.	1048	0.1535
08.	1057	0.0702
09.	1030	0.0010
10.	1029	0.3026
11.	1028	0.0143
12.	1027	0.1796
13.	1012	0.2490
14.	460	0.1710
15.	1011	0.0225
16.	461	0.1578
17.	463	0.0465
18.	464	0.1516
19.	465	0.0012
20.	466	0.0675
21.	477	0.2472
22.	476	0.0850
23.	475	0.0288
24.	490	0.0360
25.	491	0.6435
26.	492	0.6632
27.	428/1	0.0126
28.	425	0.3423
29.	426	0.0392
30.	416	0.1408
31.	417	0.1517
32.	423	0.0190

1	2	3
33.	420	0.0367
34.	419	0.1731
35.	418/2	0.0519
36.	404	0.1840
37.	406	0.1755
38.	407	0.3495

5.6101

ग्राम : राजपुराजागीर तहसील : केदारस जिला : मोरेना

सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें आर.ओ.यू. अध्यापित किया जाना है। (हेक्टेयर में)

क्रमांक	खसरा नं.	सर्वे का वह क्षेत्रफल जिसमें आर.ओ.यू. अध्यापित किया जाना है। (हेक्टेयर में)
01.	50	0.8890
02.	51	0.1290
03.	44	0.0270
04.	19	0.4790
05.	20	0.1830
06.	21	0.1620
07.	26	0.2230
08.	27	0.4210
09.	29	0.0315

2.5445

ग्राम : पचेखा तहसील : केदारस जिला : मोरेना

सर्वे का यह क्षेत्रफल जिसमें आर.ओ.यू. अध्यापित किया जाना है। (हेक्टेयर में)

क्रमांक	खसरा नं.	सर्वे का यह क्षेत्रफल जिसमें आर.ओ.यू. अध्यापित किया जाना है। (हेक्टेयर में)
01.	313	0.3090
02.	312	0.1395
03.	311	0.1665
04.	310	0.1016
05.	309	0.0555
06.	308	0.1989
07.	300	0.1800
08.	304	0.2160

1.3670



ग्राम : हटीपुरा; तहसील : कैलारस; जिला : मोरेना

New Delhi, the 22nd September, 1994

क्रमांक खसरा नं. सर्वेका वह क्षेत्रफल  
जिसमें ग्रार. ओ. यू.  
अध्यापित किया जाना है  
(हेक्टर में)

01.	231	0.1305
02.	234	0.0895
03.	233	0.2460
04.	253	0.1668
05.	251	0.1247
06.	254	0.0493
07.	257	0.1905
08.	258	0.1635
09.	268	0.1600
10.	267	0.1590
11.	265	0.2147
12.	269	0.3360
13.	136	0.2794
14.	135	0.0052
15.	134	0.2565
16.	133	0.0300
17.	107	0.4425
18.	104	0.0025
19.	105	0.1491
20.	100	0.1573
21.	99	0.2535
22.	98	0.1350
23.	75	0.0120
24.	76	0.1740
25.	77	0.1930
26.	78	0.4138
27.	72	0.2589
28.	68	0.0888
29.	63	0.1475
30.	62	0.0055
31.	40	0.7295
32.	34	0.1863
33.	41	0.1410
34.	42	0.2100
35.	43	0.0357
		6.3375

[सं. एन-14016/7/94-जीपी]  
अर्धेन्दु सेन, निर्देशक

S.O. 2788.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of Natural gas from Vijapur to Dadri in Madhya Pradesh State pipeline should be laid by the Gas Authority of India Limited.

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Limited, Bhartiya Vidyalyaya Chauraha, A.E. Road, Shivpur (M.P.).

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

## SCHEDULE

## VIJAYPUR DADRI GAS PIPELINE PROJECT

Village : Sagoria, Tehsil : Kailaras, Distt. : Morena

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
01.	211	0.0022
02.	210	0.1898
03.	207	0.0028
04.	208	0.3079
05.	196	0.2680
06.	205	0.2875
07.	198	0.0048
08.	199	0.1692
09.	200	0.0338
10.	201	0.1500
11.	202	0.2460
Total		1.6500

Village : Singacholi, Tehsil : Koilaras, Distt. Morena

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
01.	524	0.1395
02.	523	0.0010
03.	520	0.1604
04.	521	0.0690
05.	516	0.0360
06.	508	0.1615
07.	509	0.0360
08.	460	0.0915
09.	461	0.1110
10.	462	0.1241
11.	466	0.0043
12.	463	0.0036
13.	468	0.0464
14.	469	0.0420
15.	453	0.0075

2	3	1	2	3
16. 470	0.0948	17. 139		0.0333
17. 472	0.0126	18. 133		0.3027
18. 471	0.1345	19. 132		0.0725
19. 348	0.2280	20. 134		0.0675
20. 346	0.2190	21. 131		0.4740
21. 345	0.2193	22. 158		0.0613
22. 343	0.0990	23. 129		0.0733
23. 314	0.0085	24. 160		0.0936
24. 313	0.0247	25. 159		0.1490
25. 303	0.4020	26. 29		0.1080
26. 302	0.1050	27. 30		0.1455
27. 301	0.0551	28. 32		0.0180
28. 298	0.1940	29. 21		0.0984
29. 296	0.0621	30. 22		0.0227
30. 299	0.0656	31. 16		0.3175
31. 283	0.1006	32. 15		0.0208
32. 282	0.0028	33. 14		0.1352
33. 281	0.1742	34. 12		0.0240
34. 280	0.0572			
35. 279	0.1365			
36. 271	0.0583			
37. 273	0.0020			
38. 270	0.1590			
Total :	3.6486	Total:		3.9709

Vijaypur-Dadri Gas Pipeline Project

Village : Deokacch, Tehsil : Kailaras, Distt. : Morena

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O. U. in Hectare
1	2	3
01.	224	0.0240
Total :		0.0240

Vijaypur-Dadri Gas Pipeline Project

Village : Bilauwa, Tehsil : Kailaras, Distt. : Morena

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O. U. in Hectare
1	2	3
01.	328	0.0120
02.	326	0.1140
03.	325	0.1575
04.	318	0.0135
05.	315	0.1710
06.	313	0.1530
07.	311	0.1011
08.	84	0.0014
09.	297	0.0250
10.	108	0.1411
11.	109	0.1890
12.	117	0.0960
13.	116	0.2160
14.	115	0.1590
15.	122	0.1770
16.	140	0.0270

Vijaypur-Dadri Gas Pipeline Project

Village : Bhurawali, Tehsil : Kailaras, Distt. : Morena

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O. U. in Hectare
1	2	3
01.	69	0.4056
02.	70	0.0144
03.	64	0.1320
04.	63 Kh	0.1260
05.	62	0.2520
06.	51	0.0300
07.	49	0.0125
08.	50	0.2365
09.	43	0.0572
10.	44	0.2120
11.	30/2	0.1717
12.	31	0.1163
13.	30/1	0.0330
14.	23	0.1530
15.	24	0.1760
16.	8	0.3186
17.	7	0.0354
18.	6	0.2057
19.	2	0.1890
20.	106	0.0300
Total :		2.9069

**Vijaypur-Dadri Gas Pipeline Project**  
**Village : Sujarama, Tehsil : Kailaras, Distt. : Morena**

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
01.	2028	0.2610
02.	2030	0.2490
03.	2033	0.2850
04.	1821	0.0054
05.	1822	0.0158
06.	1819	0.0030
07.	1816	0.3372
08.	1818	0.0378
09.	1815	0.4703
10.	1828	0.0127
11.	1584	0.2925
12.	1595	0.2610
13.	1596	0.0153
14.	1593	0.4780
15.	1588	0.0076
16.	1592	0.2044
17.	1591	0.1740
18.	1557/1	0.3690
19.	1557/2	0.0720
20.	1556	0.0300
21.	1555	0.2160
22.	1545	0.1068
23.	1653	0.0663
24.	1654	0.0750
25.	1655	0.1590
26.	1669	0.2505
27.	1670	0.0705
28.	1671	0.0918
29.	1677	0.1400
30.	1679	0.0040
31.	1678	0.2150
32.	1680	0.0050
33.	1684	0.1210
34.	1683	0.2150
35.	1682	0.0180
Total :		5.3359

**Vijaypur-Dadri Gas Pipeline Project**  
**Village : Bhilsaunyan, Tehsil : Kailaras, Distt. : Morena**

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
01.	370	0.4290
02.	368	0.2610
03.	366	0.2610
04.	364	0.1890
05.	357	0.1980
06.	356	0.1545
07.	243	0.7340
08.	347	0.2185
09.	253	0.3060
10.	198	0.0975
11.	197	0.1080
12.	268	0.3300
13.	271	0.0552
14.	177	0.2808
15.	276	0.2655

1	2	3
16.	274	0.2460
17.	283	0.0270
18.	284	0.0075
19.	178	0.3030
20.	179	0.0088
21.	176	0.1035
22.	177	0.3600
23.	286	0.0390
Total :		4.9828

**Vijaypur-Dadri Gas Pipeline Project**  
**Village : Baralmongarh, Tehsil : Kailaras, Distt. : Morena**

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
01.	243	0.1285
02.	244	0.0617
03.	245	0.1307
04.	246	0.2340
05.	237	0.3300
06.	232	0.1878
07.	231	0.0312
08.	227	0.1455
09.	228	0.1395
10.	222	0.2970
11.	217	0.0126
12.	218	0.0324
13.	215	0.0300
14.	214	0.1510
15.	211	0.0027
16.	210	0.0518
17.	296	0.0475
18.	209	0.0045
19.	197	0.1935
20.	201	0.2330
21.	200	0.1555
22.	122	0.0270
23.	124	0.0900
24.	121	0.2730
Total		3.2904

**Vijaypur-Dadri Gas Pipeline Project**  
**Village : Ritoaunyan, Tehsil : Kailaras, Distt. : Morena**

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
01.	177	0.2433
02.	176	0.0440
03.	40	0.1280
04.	175	0.0050
05.	174	0.1448
06.	173	0.1762
07.	172	0.0350
08.	171	0.0505
09.	167	0.0080
10.	165	0.2695
11.	48	0.3858

1	2	3
12.	51	0.0546
13.	49	0.0206
14.	144	0.0495
15.	52	0.3776
16.	58	0.1050
17.	53	0.0036
18.	57	0.1254
19.	141	0.0300
20.	64	0.0650
21.	63	0.1485
22.	69	0.1604
23.	70	0.0121
24.	73	0.1530
25.	72	0.0003
26.	75	0.0300
27.	74	0.0480
28.	71	0.0754
29.	76	0.1103
30.	77	0.0247
31.	78	0.0900
32.	79	0.0540
33.	85	0.0420
34.	84	0.7058
35.	86	0.1018
36.	83	0.1671
37.	81	0.1770
Total		4.4228

Vijaypur-Dadri Gas Pipeline Project  
Village : Nalpri, Tehsil : Kailaras, Distt. : Morena

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
01.	1055	0.0560
02.	1054	0.2390
03.	1053	0.1450
04.	1052	0.0034
05.	1051	0.0408
06.	1050	0.1576
07.	1048	0.1535
08.	1057	0.0702
09.	1030	0.0010
10.	1029	0.3026
11.	1028	0.0143
12.	1027	0.1796
13.	1012	0.2490
14.	460	0.1710
15.	1011	0.0225
16.	461	0.1578
17.	463	0.0465
18.	464	0.1516
19.	465	0.0012
20.	466	0.0675
21.	477	0.2472
22.	476	0.0850
23.	475	0.0288
24.	490	0.0360
25.	491	0.6435
26.	492	0.6623
27.	428/1	0.0126
28.	425	0.3432
29.	426	0.392

1	2	3
30.	416	0.1408
31.	417	0.1517
32.	423	0.0190
33.	420	0.0367
34.	419	0.1731
35.	418/2	0.0519
36.	404	0.1840
37.	406	0.1755
38.	407	0.3495
Total :		5.6101

Vijaypur-Dadri Gas Pipeline Project  
Village : Rajpura Jagir, Tehsil : Kailaras, Distt. : Morena

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
01.	50	0.8890
02.	51	0.1290
03.	44	0.0270
04.	19	0.4790
05.	20	0.1830
06.	21	0.1620
07.	26	0.2230
08.	27	0.4210
09.	29	0.0315

Total : 2.5445

Vijaypur-Dadri Gas Pipeline Project  
Village : Pachekha, Tehsil : Kailaras, Distt. : Morena

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
01.	313	0.3090
02.	312	0.1395
03.	311	0.1665
04.	310	0.1016
05.	309	0.0555
06.	308	0.1989
07.	300	0.1800
08.	304	0.2160

Total : 1.3670

Vijaypur-Dadri Gas Pipeline Project  
Village : Hatipura, Tehsil : Kailaras, Distt. : Morena

Sr. No.	Survey No.	Area to be acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
01.	231	0.1305
02.	234	0.0895
03.	233	0.2460
04.	253	0.1668
05.	251	0.1247
06.	254	0.0493
07.	257	0.1905
08.	258	0.1635
09.	268	0.1600

1	2	3	1	2	3
10.	267	0.1590			
11.	265	0.2147	26.	78	0.4130
12.	269	0.3360	27.	72	0.2589
13.	136	0.2794	28.	68	0.0888
14.	135	0.0052	29.	64	0.1475
15.	134	0.2526	30.	62	0.0055
16.	133	0.0300	31.	40	0.7295
17.	107	0.4425	32.	34	0.1863
18.	104	0.0025	33.	41	0.1410
19.	105	0.1491	34.	42	0.2100
20.	100	0.1573	35.	43	0.0357
21.	99	0.2535			
22.	98	0.1350	Total :		6.3375
23.	75	0.0120			
24.	76	0.1740			
25.	77	0.1930			

[No. L-14016/7/94-G.P.]

ARDHENDU SEN, Director.

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1994

का. आ. 2789—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. 1531 तारीख 14-7-93 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइन को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (ड) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे इस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेदन देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय असमगैस कं. लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की उस तारीख को निहित होगा।

## अनुसूची

कुछोत्रान से 8' (200 एम. एम.) अ. दो पाईप लाईन भारघोटा टि गैस ग्रीड के चाय बागानों के लिए पाईप लाईन बिछाना।

क्र.सं.	गांव	तालुक	पाटा नं.	दाग नं.	बि.	एरिया क.	मन्तव्य स.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	2 नं. बोरत्रील गांव	माकुम	सरकार	20	0	0	7
	प्रथम खण्ड		मियादी 10 नं.	22	0	3	17
			मियादी 28 नं.	24	0	2	8
			मियादी 62 नं.	26	0	4	6
			मियादी 139 नं.	27	0	2	11
			मियादी 123 नं.	36	0	1	13
			मियादी 70 नं.	37	1	0	14
			मियादी 48 नं.	38	0	1	13
			मियादी 90 नं.	39	2	1	18
			मियादी 109 नं.	57	0	1	17
			चाय मियादी 1 नं.	61	4	4	15
			कुल क्षेत्रफल		12	0	19

1	2	3	4	5	6	7	
2.	2 नं. बोरीबील गांव दूसरा खण्ड	माकुम	मियादी 35 नं. मियादी 69 नं. मियादी 36 नं. सरकार मियादी 150 नं. मियादी 37 नं. मियादी 8 नं. मियादी 115 नं. मियादी 49 नं. मियादी 72 नं. मियादी 110 नं. मियादी 30 नं. मियादी 106 नं. मियादी 132 नं. मियादी 85 नं. मियादी 43 नं. मियादी 85 नं. मियादी 43 नं. सरकार	120 121 122 144 407 123 408 126 127 128 129 130 131 132 133 139 136 137 230	0 0 1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2 2 0  1 3 2 0 4 2 4 2 3 3 1 4 0 0 0 0	8 6 3 7 19 8 17 7 19 13 2 11 3 15 17 19 12 3 11
कुल क्षेत्रफल				9	3	18	
3.	3 नं. बोरीबील गांव	माकुम	मियादी 58 नं. मियादी 59 नं. मियादी 4 नं. मियादी 10 नं.	253 254 481 489	0 0 0 0	2 1 0 1	0 2 7 2
कुल क्षेत्रफल				0	4	11	
4.	1 नं. बोरीबील गांव प्रथम खण्ड	माकुम	सरकार सरकार सरकार सरकार सरकार मियादी 7 नं. मियादी 77 नं. मियादी 108 नं. मियादी 13 नं. मियादी 148 नं. मियादी 54 नं. मियादी 83 नं. मियादी 3 नं. सरकार मियादी 52 नं. मियादी 52 नं. मियादी 52 नं.	1 5 72 73 71 74 74 76 77 69 80 66 82 84 86 93 92	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0	0 0 0 1 1 2 2 1 0 1 1 3 0 0 1 0 0	11 4 4 4 6 0 0 0 4 19 2 19 8 7 8 0 13

	4	5	6	7		
	सरकार	136	0	0	7	
	मियादी 87 नं.	94	0	4	6	
	मियादी 105 नं.	120	0	2	4	
	मियादी 149 नं.	118	0	1	17	
	मियादी 65 नं.	117	0	2	19	
	मियादी 39 नं.	112	0	3	15	
	मियादी 144 नं.	110	0	2	19	
	सरकार	98	0	0	7	
	मियादी 109 नं.	109	0	2	8	
	मियादी 130 नं.	105	0	3	2	
	मियादी 128 नं.	104	0	2	2	
	कुल क्षेत्रफल		9	4	4	
5. 1 नं. बोरीबोल गांव द्वितीय खण्ड	एकसना	505	0	2	13	
	मियादी 120 नं.	504	0	0	4	
	मियादी 50 नं.	443	0	4	1	
	मियादी 8 नं.	503	1	0	6	
	सरकार	502	0	0	6	
	मियादी 49 नं.	500	0	1	6	
	मियादी 62 नं.	444	0	1	6	
	मियादी 34 नं.	499	0	2	9	
	मियादी 71 नं.	524	0	0	6	
	मियादी 21 नं.	445	0	0	19	
	सरकार	434	0	0	6	
	मियादी 137 नं.	446	0	3	1	
	एकसना	448	0	2	19	
	एकसना	426	0	4	12	
	मियादी 122 नं.	425	0	4	3	
	सरकार	423	0	2	10	
	मियादी 85 नं.	422	1	0	12	
	मियादी 156 नं.	421	0	3	1	
	मियादी 136 नं.	420	0	3	6	
	मियादी 137 नं.	419	0	0	17	
	मियादी 137 नं.	406	0	0	17	
	मियादी 44 नं.	407	0	3	2	
	मियादी 138 नं.	409	0	0	18	
	मियादी 49 नं.	410	0	1	18	
	कुल क्षेत्रफल		11	0	18	
6. डिगबोई टाउन प्रथम खण्ड 5वां पृष्ठ	माकुम	एकसना 136	1521	0	0	15
		मियादी 159 नं.	1519	0	2	13
		मियादी 374 नं.	1517	1	0	18
		कुल क्षेत्रफल		1	4	6





New Delhi, the 27th September, 1994

S.O. 2789.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. 1532 dated 12-7-93 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests on this date of publication of this declaration in the Assam Gas Company Limited free from encumbrances.

## SCHEDULE

Laying of 8" (200 mm) O.D. underground natural gas pipe line from Kushijan to the tea gardens of Margherita Tea Gas Grid.

Sl. No.	Name of Village	Mouza	Patta No.	Dag	No.	Area	Remarks
					B	K	L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	2 No. Borbill Village Ist Part	Makum	Waste Land	20	0	0	7
			P.P. No. 10	22	0	3	17
			P.P. No. 28	24	0	2	8
			P.P. No. 62	26	0	4	6
			P.P. No. 139	27	0	2	11
			P.P. No. 123	36	0	1	13
			P.P. No. 70	37	1	0	14
			P.P. No. 48	38	0	1	13
			P.P. No. 90	39	2	1	18
			P.P. No. 109	57	0	1	17
			T.P. No. 1	61	4	4	15
			Total :				12
2.	2 No. Borbill Village 2nd Part	Makum	P.P. No. 35	120	0	2	8
			P.P. No. 69	121	0	2	6
			P.P. No. 36	122	1	0	3
			Waste Land	144	0	0	7
			P.P. No. 150	407	0	1	19
			P.P. No. 37	123	0	3	6
			P.P. No. 8	408	0	2	17
			P.P. No. 115	126	0	0	7
			P.P. No. 49	127	0	4	19
			P.P. No. 72	128	0	2	13
			P.P. No. 110	129	0	4	2
			P.P. No. 30	130	0	4	11
			P.P. No. 106	131	0	2	3
			P.P. No. 128	132	0	3	15
			P.P. No. 85	133	0	1	17
			P.P. No. 43	139	0	4	19
			P.P. No. 85	136	0	0	12
			P.P. No. 43	137	0	0	3
			Waste Land	230	0	0	11
Total :				9	3	18	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.	3 No. Borbill Village	Makum	P.P. No. 58	253	0	2	0	
			P.P. No. 59	254	0	1	2	
			P.P. No. 4	481	0	0	7	
			P.P. No. 10	489	0	1	2	
			Total :		0	4	11	
4.	1 No. Borbill Village 1st Part	Makum	Waste Land	1	0	0	11	
			Waste Land	5	0	0	4	
			Waste Land	72	0	0	4	
			Waste Land	73	0	1	4	
			Waste Land	71	0	1	6	
			P.P. No. 77	74	0	2	0	
			P.P. No. 108	76	0	1	9	
			P.P. No. 13	77	0	0	4	
			P.P. No. 148	69	0	1	19	
			P.P. No. 54	80	0	1	2	
			P.P. No. 83	66	0	1	19	
			P.P. No. 3	82	0	3	8	
			Waste Land	84	0	0	7	
			P.P. No. 52	86	1	0	8	
			P.P. No. 52	93	0	1	0	
			P.P. No. 52	92	0	0	13	
			Waste Land	136	0	0	7	
			P.P. No. 87	94	0	4	6	
			P.P. No. 105	120	0	2	4	
			P.P. No. 149	118	0	1	17	
			P.P. No. 65	117	0	2	19	
			P.P. No. 39	112	0	3	15	
			P.P. No. 144	110	0	2	19	
			Waste Land	98	0	0	7	
			P.P. No. 109	109	0	2	8	
			P.P. No. 130	105	0	3	2	
			P.P. No. 128	104	0	2	2	
			Total :		9	4	4	
5.	1 No. Borbill Village 2nd Part		Annual	505	0	2	13	
			P.P. No. 120	504	0	0	4	
			P.P. No. 50	443	0	4	1	
			P.P. No. 8	503	1	0	6	
			Waste Land	502	0	0	6	
			P.P. No. 49	500	0	1	6	
			P.P. No. 62	444	0	1	6	
			P.P. No. 34	499	0	2	9	
			P.P. No. 71	524	0	0	6	
			P.P. No. 21	445	0	0	19	
			Waste Land	434	0	0	6	
			P.P. No. 137	446	0	3	1	
			Annual	448	0	2	19	
			Annual	426	0	4	12	
			P.P. No. 122	425	0	4	3	
			Waste Land	423	0	2	10	
			P.P. No. 85	422	1	0	12	
			P.P. No. 156	421	0	3	1	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Waste Land	53	0	1	11	
			Annual	48	0	0	4	
			Annual	19	0	0	7	
			Annual	42	0	0	4	
			Waste Land	75	32	3	0	
			Total :		35	1	16	
10. Digboi Town Ist Part 10th Sheet	Makum		Waste Land	2958	0	4	14	
			Waste Land	2259	0	3	3	
			Total :		1	2	17	

[No. O-12016/81/93-ONG/D-4]

M. MARTIN, Desk Officer

भ्रम मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR

नई दिल्ली, 2 अगस्त 1994

New Delhi, the 2nd August, 1994

का.आ. 2790—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दक्षिण रेलवे मद्रास के प्रबन्धसूत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, मद्रास के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 1-8-94 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 2790.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Madras as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Southern Railway, Madras and their workmen, which was received by the Central Government on 1-8-1994.

[संख्या एस-41012/99/87-डी, II (बी) आईआरबी-I]  
वी.के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

[No. L-41012/99/87-D.II (B)/IR B-I]  
V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE  
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU  
MADRAS

Friday, the 15th day of April, 1994

Present :

THIRU K. SAMPATH KUMARAN, B.A.B.L.,  
INDUSTRIAL TRIBUNAL  
INDUSTRIAL DISPUTE No. 52/88

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10 (1)(d) of the Industrial Disputes Act 1947 between the workmen and the Management of Southern Railway, Madras).  
Between

1. Thiru J. Hayath Basha,
2. „ S. Sekhar.
3. „ G. Sekhar.
4. „ K.R. Pushpakaran.
5. „ K. Murlidharan
6. „ V. Daveedue
7. „ S. Subbarayudu

9. „ S. Vaypputhiran.
10. „ D. Vijayakumaran.
11. „ P. Ramasamy.
12. „ A. Chozhan.
13. „ P. Sekar.
14. „ M. Basheer.
15. „ K. Narayanan.
16. „ S. Subba
17. „ R. Ravi
18. „ K. Mohan
19. „ R. Ganesan.
20. „ J. Sundaramurthy.
21. „ E. Jeyapal
22. „ K. Babu
23. „ M. Prithivir.
24. „ I.K. Lezar
25. „ S. Devaraj
26. „ G. Krishnamurthy.
27. „ M. Mohan.
28. „ P.N. Khmar.
29. „ M. Henry Babu
30. „ K. Rajam.
31. „ L. Nanda Kumar.
32. „ S.A.K. Jeelami
33. „ D. Vivenkanandan.
34. „ J. Gopi
35. „ S. Chitti Babu

C/o. Shri T. Fenn Walter.  
Advocate, No. 161, Thambu Chetty Street,  
II nd Floor, Madras.

Nos. 14, 23 and 32 are corrected as per Corrigendum No. L.41012/99/87. D. II(B), Govt. of India, Ministry of Labour dt. 24-11-88.

This dispute after remand coming on for final hearing on Tuesday, the 13th day of July, 1993 upon perusing the reference Claim and Counter Statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Tvl. T. Fenn Walter, P. Vijayakumar and Fredric Castro, Authorised Representatives for the workmen and of Thiru R. Venugopalan, Advocate appearing for Management Nos. 1 to 3 and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following :

#### AWARD

This reference has been made for the adjudication of the following issue :

“Whether there exists employer-employee relationship between the piece rated workers (list enclosed) and the Management of Southern Railway Administration, Madras ? If yes, whether the termination of the said workers by the Management of General Manager, Controller of Stores, and Distt. Controller of Stores, GSD, Southern Railway Madras is justified ? If not, to what relief the workers concerned are entitled to ?”

2. The Workmen filed the following Claim Statement.—The petitioners entered service under the respondent as tailors on various dates as mentioned in the annexure (to the claim statement) and were working as piece rate tailors. They were working continuously and were drawing a sum of Rs. 800 p.m. These 35 workmen joined the Socialist Workers Union in January, 1986 and placed a charter of demands on 29-9-86. It has infuriated the respondent and the petitioner were issued orders of termination dated 20-12-86. It is unjust, improper and illegal. There is no necessity to terminate the services of the petitioners when there was plenty of work for them. The allegation that the contract period has expired on 20-12-86 is not correct. The termination is contrary to

Sections 25-F and 25-N of the Industrial Disputes Act, 1947. No retrenchment compensation was offered nor any notice was given. Therefore, the respondent may be directed to reinstate the petitioners to service with back wages, continuity of service, and other benefits.

3. The Respondent filed the following Counter Statement.—There is no relationship of employer and employee and the petitioners were independent contractors under an agreement with the respondent to stitch terricotton uniforms on piece rate basis. As per the orders of the Railway Board, two sets of terricotton uniforms are supplied to selected staff once in 2 years. The nature of work is seasonal. On 14-9-5: a notice was issued calling for tender for stitching terricotton uniforms on piece rate basis informing that the tailors will be selected after conducting a trade test and that they have to execute an agreement in the prescribed form. It is also informed that there is no recruitment for any railway service and that they will be paid only on the basis of quantum of work turned out. 36 tailors were found suitable and they entered into individual agreements for a period of 6 months renewable for a further period at the option of the railways. The administration reserved its right to terminate the engagement without notice or assigning any reason. The piece rate workers were also free to stay away after giving 3 days notice. They were engaged on different months and different years in 1984 and 1986. They were supplied with sewing machine, threads, needles and buttons and after completion of this work, the stitched uniforms will be taken back and the charges will be paid. The average income was between Rs. 200 to Rs. 600 p.m. The tailors come at any time and return the finished garments to the foreman. There is no roster for them and there is no attendance. They were not given any appointment order. They are not entitled to any of the privileged and they were not subscribers to the provident fund. There was no supervision of their work. If the stitched garment was not in accordance with the standard, loss will be recovered. They were not paid monthly salary.

There was no work of stitching and they were stopped from 20-12-86 as per para 14 of the agreement, and their Services were not terminated. They were stopped due to the expiry of the contract and are not entitled to any notice pay or retrenchment compensation. They are not entitled to be reinstated or back wages. Therefore, the petition may be dismissed.

4. The petitioners filed a reply statement reiterating their claims and also stating as follows.—The allegation that the petitioner-workmen are contractors has no basis. The agreement entered into by them will show that they are employees of the respondent. The petitioners were selected by the respondent after conducting a trade test. The administration cannot unilaterally terminate the services of the petitioners since it is contrary to the statue, principle of natural justice and opposed to public policy. The agreement is one sided and opposed to public policy and is not enforceable. The petitioners have worked continuously. The wages register will disclose the payments made to the petitioners. The finished garment will be handed over to the foreman and it should be to the entire satisfaction of the foreman of the Clothing Factory and other higher authorities. It is false to state that the workmen were retrenched from service for want of work. Even now the same work is being done by some others. Since the supply of uniforms to the railway staff is something permanent in nature, it has to be supplied to the staff every year, production cannot be stopped at any stage. Originally the contract was for 6 months and thereafter it was not extended. To state that the petitioners were stopped from service due to expiry of contract period is not true.

5. The petitioner filed the following additional claim Statement.—The retrenchment is an unfair labour practice and victimisation. The respondent had failed to obtain prior permission as contemplated under Section 25-N of the Industrial Disputes Act, 1947. The work that was being done by the petitioner is being done by some others till date. In O.A. 469/90, the contention of the respondent that they can terminate the services of the petitioner without notice was held to be invalid. A clear finding has been given that there is employer employee relationship between the respondent and the petitioner. The termination of the services of the petitioners is null and void. The respondent has not sought permission for retrenchment of the petitioners and hence it is a violation of Section 25-N of the Industrial Disputes Act, 1947.

6. The respondent filed the following Additional Counter—No charter of demands claiming benefits like permanency, higher scale of wages was received by the respondent. There was no unfair labour practice nor the act of victimisation. There was no violation of Sections 25-F and 25-N of the Industrial Disputes Act. The stitching of terricotton uniforms even now is not of a continuous nature. Whatever demands are received on every alternate years open tenders are floated in all leading dailies. The piece rate contractors have formed an organisation called PRC Garments and getting orders. The procedure for recruitment for Government service is different from that in Private Enterprises.

7. The petitioners filed the following additional reply Statement.—Two sets of uniforms are supplied to the existing staff, numbering about 1,50,000. Every year uniforms are supplied not only to Station Masters, Assistant Station Masters, Guards and Ticket examiners and also to Ticket Collectors, Parcel Clerks, Reservation Clerks, Points Man and Safai Walas. It is a perennial nature of the work which is being done throughout the year. Section 25-F and 25-N apply to all employees who are working in an industry and who have completed 240 days of service within a period of 12 months preceding the date of retrenchment, which conditions are present in this case. Even at present the work of stitching uniforms is given to contractors. Entrusting such perennial nature of work to contractors is an unfair labour practice. The respondent is aware of the charter of demands placed by the petitioners. The contention that the petitioners have formed an organisation called PRC and are getting orders is false. The only issues to be decided by this Tribunal are as to whether the petitioner have put in 240 days of service or not, within a period of 12 months; whether

there is victimisation; and whether there is no breach of contractor and unfair labour practice.

8. The petitioners herein were employed as piece rate

workers under the respondent for the purpose of stitching terricotton uniforms for the employees of the railway administration. Notice of intention to employ such tailors (Exhibited M-1) was published and in response to that the petitioners and others applied for employment as such piece rate workers. A trade test was also conducted by the respondent-railways and 35 workmen concerned in this reference were selected for employment as piece rate workers namely, tailors for stitching the terricotton uniforms. It is evident that they were employed during the course of the year 1984 and 1986. The respondent gave a termination order stating that the engagement of these workmen as piece rate tailors was terminated with effect from 20-12-86. One such termination order has been marked as Ex. M-5 dated 17-12-86 on the petitioner's side, and two other such orders have been marked on the side of the Management as Ex. M 6 dated 17-12-86 Ex. M-12 dated 17-12-86. The workmen questioned the termination and raised an Industrial Dispute which was referred to this Tribunal. This Tribunal after an enquiry, held by its award dated 3-11-89 that there is no relationship of employee and employer between the workmen and the Management of the respondent-railways, that they were paid piece rate wages, that the respondent-management had no control over these workmen and therefore, held that there was no violation of Sections 25-F and 25-N of the Industrial Disputes Act. Accordingly, this Tribunal held that the order of termination was justified. The workmen herein filed O.A. No. 469/90 on the file of the Central Administration Tribunal (Madras Bench) and the Central Administrative Tribunal held that there is employer and employee relationship between the respondent Management and the workmen, set aside the award of the Tribunal dated 3-11-89, and remitted back the matter to this Tribunal for disposal according to law observing that this Tribunal had not considered the question whether the respondent-Management had violated the provisions of Sections 25-F and 25-N of the Industrial Disputes Act, and directing this Tribunal to dispose off the case according to law. The workmen filed Miscellaneous Petition 58/92 on the file of the Central Administrative Tribunal seeking clarification as to whether they could raise the plea that there was victimisation, breach of contract and unfair application, and the Central Administrative Tribunal held that it is not necessary to issue any clarification in as much as this Tribunal has to dispose of the matter according to law, and in as much as it has not been stated in the order that the Industrial Tribunal is bound to consider only the points regarding violation of Sections 25-F and 25-N and not other points raised, and also observing that it is open to the petitioner to urge the same before the Industrial Tribunal. After the order of remand that the workmen filed the additional claim statement, the respondent filed the additional counter statement and the workmen the additional reply statement, which have been extracted above.

9. Therefore, the issues that arise for consideration in this Industrial Dispute now are :

1. Whether the workmen have been continuously working for more than 240 days in a year prior to the termination of their employment ?
2. Whether the termination of their employment is justified and legal ?
3. Whether the termination is the consequence of victimisation, and unfair labour practice and breach of contract on the part of the respondent-management ?
4. Whether the petitioner-workmen are entitled to the reliefs of reinstatement and attendant benefits ?

10. Issues 1 to 4.—The respondent contends that the workmen concerned in this dispute are only piece rate workers, that no wages were either fixed or paid to them per month, that they had no fixed hours of work, that they could come for work and go away as they pleased and that they were not given the benefits that were given to the employees of

the Railways. These very points were raised before remand by the respondent in support of the contention that there was no relationship of employer and employee between the respondent and workmen. As pointed out already, this contention was not accepted by the Central Administrative Tribunal. In spite of the fact that the workmen concerned in this dispute were piece rate workers it was held that there is relationship of employer and employee between them and the respondent-management. Even if they could come and go as they please, it is clear that there was supervision by a foreman who was also a railway employee, and who checked the garments and asked them to re-do it if there was any defect. So, it is evident that there was supervision and control over them. Simply because the status as that of the other railway employees was not given to them, it does not mean that they are employees of the railway. That is why the workmen raised a charter of demands and it is stated that because the workmen joined a Union and raised a charter of demands, their services were terminated. The copy of the Industrial Dispute raised by the petitioner-union regarding the charter of demands has been marked as Ex. W-4 and it mentions that the charter of demands was sent to the Management on 29-9-86 itself and no reply has been received. The Industrial Dispute raised by the Union is dated 11-11-86. Therefore, the fact these workmen were not given the benefits that were given to the other workmen of the respondent-railways need not mean that they are not employees of the railways. It is no more open to the respondent-railways to contend that there is no relationship of employer and employee between the respondent and the workmen after the order of the Central Administrative Tribunal.

11. Therefore, we have to consider the question whether the workmen have worked for 240 days in a year preceding the date of termination of their employment. WW-1 Hayath Basha, who is one of the employees concerned, has stated in his evidence that he joined the service of the respondent on 15-2-84, and that he was stopped from service on 20-12-86. He stated that though the agreement was only for 6 months, and that it was not renewed, even after the expiry of the agreement he worked for 3 years. He also stated that he continuously worked for 3 years. Though, a question was put to him as to whether 6 of the employees joined only in June, 1986, and were removed on 20-12-86, it was not suggested to him that either he or the worker other than those six persons had not worked continuously till 20-12-86 from the respective dates given against each of them in the annexure to the Claim Statement. The annexure to the Claim Statement mentions the names of the workmen, their respective date of joining and the date of termination. It shows that these workmen had joined on different dates and different months. Certain workmen have joined even in January, 1984. It was not suggested to WW-1 that either he or the others had not worked for 240 days continuously in a year preceding the date of termination. Even MWs-1 and 2 examined on the side of the management did not say that these workmen (other than six persons mentioned below) had not worked during the period mentioned by them continuously. They only stated that they are not employees of the respondent-management. MW-2 stated that no attendance register was maintained to show the number of days each of the workmen had worked. As pointed out already the annexure to claim statement gives the date of joining as well as date of termination. MW-2 did not even say that it is not correct. MW-1 admitted in his evidence that the Foreman was maintaining a register to show the supply of the cloth to the workmen and for the receipt of the same. Even that register was not produced. So, in the absence of any other evidence to the contra, we have to take it that the workmen concerned in this dispute except Sl. No. 21, Thiru E. Jeypal, Sl. No. 23, Thiru M. Prithiviraj, Sl. No. 24, Thiru I. K. Lazer, Sl. No. 26 Thiru G. Krishnamurthy, Sl. No. 27, Thiru M. Mohan, and Sl. No. 29 Thiru M. Henry Babu (who have worked only from June, 1986) have worked for more than 240 days in a year preceding the date of termination.

12. The respondent contended that these workmen were contract workmen that the contract itself fixed their term as six months and had given an option to the Railway to renew the contract for one year, that these workmen were sent out

on the expiry of the contract as there was no work. But, this contention cannot be accepted. Though, the contract gave an option to the respondent for a period of six months, the services of the workmen were not terminated exactly at the end of six months and many of them were allowed to work nearly for three years. As pointed out already the Annexure to the claim statement gives the dates of their joining, and termination of their services. As pointed out already, there is no evidence to show that they had worked continuously. The annexure shows that the workmen had joined the services of the respondent on various dates during January, 1984 to December 1984. As pointed out already the contract is only for six months, then their services ought to have been terminated at the end of the six months period. But, their services were terminated only in October, 1986. Of course, it is stated that the Railway had an option to renew their employment for the period of one year. There is no proof or written evidence to show that the contract was extended or renewed for the further period of one year. It is not proved on what dates the contract was extended, because different workers joined on different dates. Even if we take for the sake of argument that there is a renewal for one more year, it is evident that their services were not terminated even at the expiry of the alleged extended period of contract. All the workmen have been terminated from service of the same date i.e. 20-12-86, whereas they had joined on different dates. Therefore, the contention of the respondent that the period of contract expired and therefore their employment was put to an end cannot be accepted.

13. Another contention was put forward by the respondent is that there was no work after 1986, since no uniform was to be supplied during 1987, and therefore the employment of the workmen was put an end to. Even such a contention cannot be accepted is clear from the evidence of MW-2. MW-2 admitted in his evidence that once in two years two different uniforms are being supplied to 15,000 officers, that is, 30,000 pants and 30,000 shirts. Of course, it was suggested on behalf of the workmen that uniforms are being supplied to 40,000 officers which was denied by MW-2. But, he admitted that these uniforms are supplied for the whole of the Southern Railway. So, even if 30,000 pants and 30,000 shirts are stitched and supplied once in two years by employing 35 workers only, then there will be continuous work for these workmen. Further, it is not as if they were not supplying uniforms after 1986. Even on the admission of MW-2, subsequent to 1986 outside contractors are employed for the purpose of stitching uniforms twice or thrice in a year. Of course, no documents have been produced as to when such outside contractors are employed and for what period. But, the fact remains that outside contractors are employed for stitching uniforms. It shows that the work is not completed at the end of the contractual period as contended by the respondent. The fact that even according to MW-2, 30,000 pants and 30,000 shirts are stitched by 35 workers only is clear indication of the fact that the work of stitching these uniforms should be a continuous process. Because, even if single worker complete three items per day and works for 25 days in a month he will stitch only 75 items per month, and it comes to 900 items per year per worker. So, if 35 workers stitch at the rate of 900 items per year it comes to 31,500 items. Apart from stitching uniform, the workers have to submit them for being checked by the foreman and if there are defects they will have to re-do them. Therefore, it can be taken that they can complete per year 30,000 items, whereas they have to stitch 30,000 shirts and 30,000 pants. Therefore, I find that the stitching of uniforms must be a continuous process.

14. Another contention put forward by the respondent that the workmen were paid wages according to the items completed by them and were not paid monthly wages. But, this plea was raised even before the remand and was not accepted. In this connection, we have to see that the Railway Authorities, give the workers the place to work sewing machines, the cloth, thread and buttons. All that they do is only to stitch the garments. Therefore, the contention that they were piece rate workers will not affect the case of the workmen.

15. One important contention put forward by the Petitioner-workmen is that these workers who have been stitching the uniforms have been deprived of their job, but the

work they were doing still continues (as admitted in the evidence on the side of the management) and is being given to outside contractors. The learned counsel for the workmen contended that this is an unfair labour practice, Clause 6 of the Schedule IV to the Industrial Disputes Act, 1947 characterises the taking away of the work of a regular nature done by the workmen and giving it to contractors as unfair labour practice. Therefore, the termination of the services of the workmen (other than those who are named hereunder) is certainly unjustified and illegal. Admittedly, no notice before retrenchment was given to them and no compensation was paid either. Once, it is clear that these workers (other than those mentioned hereunder) had worked for more than 240 days in a year preceding date of their termination, their retrenchment without notice or compensation is illegal and these workmen (other than those mentioned hereunder) are entitled to be reinstated. But, I find that these workmen in the circumstances of the case will not be entitled to back wages.

16. As pointed out already, even in the annexure to the claim statement it is mentioned that Serial No. 21, E. Jeyapal, Serial No. 23, M. Prithiviraj, Serial No. 24, I. K. Lazar, Serial No. 26, G. Krishnamurthy, Serial No. 27, M. Mohan, and Serial No. 29, M. Henry Babu have joined the services of the respondent only in and their services were terminated in 1986 itself. Therefore, they are not entitled to the relief of reinstatement.

17. MW-1 stated in his evidence that the workmen by name Subbarayudu, Rajan and Chitti Babu (shown as Sl. No. 7, Serial No. 30 and Serial No. 35 in the reference) respectively have of their accord stopped from working. Though in cross-examination he was asked as to how he say so, and he gave the answer, it was not suggested to them that they did not stop coming for work of their own accord. WW-1 examined on the side of the workmen stated that he does not know that the Subbarayudu and Rajan have stopped coming for work. In spite of the fact that the workmen had an opportunity to let in evidence after the remand, these 3 workmen have not been examined to show that they were working till their services were terminated and that they had not stopped of their own accord. Therefore, I find that these three workmen Subbarayudu, Serial No. 7, Rajan Serial No. 30, and Chitti Babu Serial No. 35 are also not entitled to the relief of reinstatement.

18. In the result, an award is passed holding that there exists the relationship of employer and employee between the management and the workmen and the termination of the services of the workmen mentioned in the reference, other than Serial No. 7, Subbarayudu, Serial No. 30, K. Rajan and Serial No. 35 S. Chitti Babu, Serial No. 21 E. Jeyapal, Serial No. 23 M. Prithiviraj, Serial No. 24 I. K. Lazar, Serial No. 26, G. Krishnamurthy Serial No. 27 M. Mohan and Serial No. 29 M. Henry Babu, is not justified, and directing that they should be reinstated into the service of the respondent, but also directing that these workmen are not entitled to back wages. No costs.

Regional Commissioner of Labour (Conciliation)

Dated, this the 15th day of April, 1994.

K. SAMPATH KUMARAN, Industrial Tribunal

#### WITNESSES EXAMINED

Before Remand

For Workmen :

WW-1—J. Hayath Basha.

For Management :

MW-1—Thiru N. Rangasamy.

After Remand

For Workmen :

Nil.

For Management :

MW-2—S. Srinivasan.

#### DOCUMENTS MARKED

Before Remand

For Workmen :

W-1/18-1-84—Letter from General Stores Depot, Southern Railway, Madras-23 to Thiru S. Vayuputhiran (Xerox copy).

W-2/4-2-84—Letter from General Stores Depot, S. Railway, Perambur, to Thiru S. Vayuputhiran.

W-3/25-8-86—Letter from Socialist Workers' Union, Madras-1 to the General Manager, Southern Railway, Park Town, and another.

W-4/11-11-86—Letter regarding charter of demands raised by Socialist Workers Union, Madras to the Regional Commissioner of Labour (Conciliation) (Central) Madras-6.

W-5/17-12-86—Termination order issued to Thiru S. Vayuputhiran.

W-6/9-1-87—Advocate notice to the Management to reinstate the workmen.

W-7/27-1-87—Reply by Management to W-6.

W-8/25-9-87—High Court's order in W.P. No. 7965/87 (Certified copy).

W-9/16-6-88—Xerox copy of Order of Deputy Controller of Stores/II Southern Railway, Madras-23 to Society Dressing.

For Management :

Ex. M-1/14-9-88—Tender notice calling for piece rate tailors (copy).

M-2/Series—True copies of agreement executed by piece rate Tailors with Railway Administration dated 31-1-84, 1-2-84, 2-2-84, 7-2-84, 23-3-84 8-2-84 9-2-84, 13-2-84, 28-5-84, 31-1-84, 1-8-84, 14-2-84, 5-12-84, 24-5-84, 16-2-84, 2-2-84, 21-5-84, 3-5-84, 8-11-84, 26-10-84, 12-6-86, 18-6-86, 23-7-86, 12-6-84, 8-5-84, and 3-5-84.

M-3/1-3-84—True extract of Piece rates prescribed for stitching terricotton garments.

M-4/Series—Extracts of Payments made to Piece Rate tailors.

Ex. M-5/series—Xerox copies of Payment Register showing payments made to piece rate tailors with their acknowledgements.

Ex. M-6/17-12-86—Termination of engagement of piece rate tailors (copy).

After Remand

For Workmen :

Nil.

For Management :

Ex. M-7/14-9-83—Tender notice calling for piece rate tailors.

Ex. M-8/14-10-83—Application from Thiru J. Hayath Basha to the District Controller of Stores, Clothing Factory, Southern Railway, Madras-23 for the post of tailor. (copy).

Ex. M-9/20-1-84—Letter from Management to J. Hayath Basha requiring him to attend trade test for engagement as piece rate tailors (copy).

Ex. M-10/6-2-84—Order issued to Thiru J. Hayath Basha engaging him as piece rate tailor for a period of 6 months. (copy).

Ex. M-11/16-2-84—Agreement between Thiru J. Hayath Basha and the Management (copy).



- Ex. M-12/17-12-86—Termination order issued to Thiru J. Hayath Basha (copy).
- Ex. M-13 —Extract of Stitching Charges paid to the price rate Contractor Thiru J. Hayath Basha from the date of engagement to the date of stoppage of agreement.
- Ex. M-14 —Purchase Order given to M/s. PRC Garments, Thiruvottiyur, Madras-19 (Xerox copy).
- Ex. M-15/19-10-92—Letter from M/s. PRC Garments, Madras-82 to the Respondent (copy).

## ANNEXURE

Name of the Workmen	Date of termination
1. Shri J. Hayath Basha	20-12-86
2. Shri S. Sen	"
3. Shri G. Sekhar	"
4. Shri K. R. Pushapakaran	"
5. Shri K. Murlidharan	"
6. Shri V. Daveedue	"
7. Shri S. Subbarayadu	"
8. Shri P. Balasubramaniam	"
9. Shri S. Vayuputhiran	"
10. Shri D. Vijayakumaran	"
11. Shri P. Ramaswamy	"
12. Shri A. Chozhan	"
13. Shri P. Sekar	"
14. Shri M. Basheer	"
15. Shri K. Narayanan	"
16. Shri S. Subba	"
17. Shri R. Ravi	"
18. Shri K. Mohan	"
19. Shri R. Ganesan	"
20. Shri J. Sundaramurthy	"
21. Shri E. Jeyapal	"
22. Shri K. Babu	"
23. Shri M. Prithiviraj	"
24. Shri I. K. Lazer	"
25. Shri S. Devaraj	"
26. Shri G. Krishnamurthy	"
27. Shri M. Mohan	"
28. Shri P. N. Kumar	"
29. Shri M. Henry Babu	"
30. Shri K. Rajam	"
31. Shri L. Nanda Kumar	"
32. Shri S. A. K. Jeelami	"
33. Shri D. Vivekanadan	"
34. Shri J. Gopi	"
35. Shri S. Chittu Babu	"

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1994

का.आ. 2791 —औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अन्वय में, केन्द्रीय सरकार इन्ड्यु.सी.एल. के प्रबन्धन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, औद्योगिक अधिकरण, बम्बई के पंचवट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 8-9-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-22012/88/88 डी IV (बी.)]

राजालाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 15th September, 1994

S.O. 2791.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal Bombay, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of W.C. Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 8-9-94.

[No. L-22012/88/88 D-IV(B)]

RAJA LAL, Desk Officer

## ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT  
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, BOMBAY

PRESENT :

....

Shri Justice R. G. Sindhakar, Presiding Officer.

REFERENCE NO. CGIT-8 OF 1989

PARTIES :

Employers in relation to the management of M/s. Western Coalfields Ltd., Rajur Colliery.

And

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Management—Shri Shashi, Advocate.

For the Workmen—Shri Pendre.

INDUSTRY—Mining.

STATE—Maharashtra.

Bombay, the 26th day of August, 1994

## AWARD

Government of India, Ministry of Labour, New Delhi has by letter dated 6-1-1989, made under section 10(1)(d) read with sub-section 2K of the Industrial Disputes Act, 1947.

"Whether the action of the Management of Rajur Colliery Sub Area of M/s. Western Coalfields Ltd. (Wani Area), Distt. Yeotmal(MS) in dismissing from services of Smt. Basanti Suryabhan and Smt. Anjana Sitaram w.e.f. 1-12-1985 is justified ? If not, to what relief the workmen concerned are entitled ?"

2. By Corrigendum dated 9/13-2-1990, the words "In dismissing" have been substituted by "in terminating".

3. The Statement of claim has been filed by the two employees, Smt. Basanti Suryabhan and Smt. Anjana Sitaram is to the effect.

4. These two employees were working since July 1983, without any letter of appointment as casual labourers in the Rajur Colliery. They were attending duties daily and recording their attendance with the attendance clerk and were getting wages on the days when other employees were being paid wages, though it was much less than that paid to the other employees. They worked regularly between 1983 and 1985 December. With effect from 1-1-1986 without any written communication their services were terminated. In spite of their requests they were not provided work. They approached Shri Pendre, Secretary, Talzenda Coal Mines Mazdoor Union (C.I.T.U.) and authorised him to take up the matter. He discussed the matter with Nagpur W.C.L. office but did not get satisfactory reply. He thereafter on

11-1-1986 approached Shri Shrivastava and discussed with him the matter. It was found from the record of attendance that these two ladies worked for 121 days as shown below and mentioned these days.

1	Sht. Basanti Suryabhan	1983	1984	1985
		121	187	239
2.	Smt. Anchana Sitaram	1983	1984	1985
		155	207	239

A copy of the said statement was given to Shri Pendre by Shri N. K. Seth. He thereafter, approached the Asst. Labour Commissioner, Central Government Chandrapur and raised a dispute. However, failure report was made and thereafter this reference for adjudication is made by the Central Government to this Tribunal. It is mentioned in the statement that since 1983, these two ladies worked and the number of days attendance shows that those worked for 239 days between January, 1985 and November. They did not get sick leave or earned leave or any other leave. Because of this they are entitled to benefits of section 25G and 25C of the Industrial Disputes Act, because of the provisions of section 25B of the said Act. It is however, stated that there are about 50,000 lady workers in the Coal Industry of the Government of India. The management has infringed the provisions of section 25F and therefore, these ladies are entitled to reinstatement which may be directed by this Tribunal.

5. Management has filed written statement and stated there was no dispute raised which was a condition precedent for making reference and therefore, the reference is liable to be rejected. It is also stated that this Court does not have any jurisdiction to deal with the matter. It is contended that there was no dismissal and therefore, reference was not contemplated. It is also contended that the Central Government is not an 'appropriate Government' for making the reference in respect of persons employed in the Coal Mines. It is further stated that the management could not employ ladies in the mines and there was no vacant post therefore, they could not be absorbed. Besides it is stated that the management could adopt sympathetic attitude and was willing to provide employment to a male member of the family of these ladies, the union did not however, accept this offer. The management states that it is still willing to consider any such proposal if it emanates from the union. Management has taken up the matter with Government of India, Ministry of Labour for cancelling reference or for modifying it as it is without application of mind. It appears that because of the contentions raised the Government of India on 9-2-1990 substituted the words 'in dismissing' by the words 'in terminating'.

6. A rejoinder has been filed on behalf of the two ladies on 27-3-1989, the contentions of the management are denied. It is mentioned therein that the attendance have been checked and in respect of which documents will be produced and oral evidence led.

7. The dispute was raised that Shri Pendre, who is espousing the cause of these two ladies has resigned from the union that sponsored the dispute namely Lalzanda Coal Mines Mazdoor Union (hereafter referred to as CITU) and formed another union Lal Bavlā Coal Kamgar Union (hereafter referred to as LBKKU) Chandrapur and therefore, could not espouse that cause now. The next contention is that the two ladies were casual employees in the civil department in the construction of roads, buildings etc., and paid daily wages under the Minimum Wages Act as fixed by the Collector as and when work was available were provided with work. Further contention is that they had not completed 240 days of work and therefore, provisions of section 25-F were not attracted. Lastly, it is submitted that in any event they are not entitled to reinstatement.

8. I think that the decision in this reference could be given on the consideration of the main contention of the management that these two ladies who were working as casual employees were provided work as and when it was available and as and when they reported for work and had not put in 240 days of work within the meaning of Section 25B so as to attract provisions of Section 25F.

9. Section 25-F provides for conditions precedent to retrenchment. Admittedly the conditions had not been followed in as much as one month's notice contemplated by clause (a) is not given nor are they paid compensation. Management's contention is that Section 25F is not attracted because these ladies have not been in continuous service for not less than one year under the employer. Section 25B defines continuous service and it is the case of the workmen that provisions of sub-section 2 of Section 25B are attracted because these two ladies have during the period of 12 calendar months preceding the date of termination actually worked for not less than 240 days. In this connection, oral and documentary evidence is adduced. The management's witness Shri Anil Gundawar who has filed an affidavit stated they have not worked for 240 days. He has been cross-examined on behalf of the workmen by Shri Pendre. He has stated in the course of cross-examination that he would not be able to tell the number of days attendance of Basanti Suryabhan between October 1984 and September 1985. So far as Smt. Anchana Sitaram is concerned he has not been asked anything. Apart from that it has to be remembered that the two ladies when examined did not state in their evidence that they have worked for 240 days during the relevant period. The chart produced on behalf of the workmen is not duly proved and that the grievance of the management has been admitted by Shri Anil Gundawar. In fact, in the fitness of things it should have been shown to him. Apart from that Shri Pendre who happened to be a signatory to the document did not enter the witness box to give evidence to prove it. Even assuming it is held that it has been proved it did not show that they have put in 240 days during the relevant period. Some writing is made in the case of these two ladies but one does not know who has made it. The typed portion at any rate did not prove the contention that they have put in 240 days of actual work during the 12 months preceding their termination. The assertion by Shri Anil Gundawar that they had not put in 240 days of work in the facts and circumstances of the case and the evidence on record cannot be brushed aside lightly. In that event provisions of Section 25F cannot be invoked and in that event conditions not having been fulfilled the termination cannot be faulted. In my opinion, in that case these two ladies will not be entitled to the relief of either reinstatement or back wages.

10. It has to be remembered that the management has contended that they were casual employees employed on work as and when it was available. They could not be provided work in the mines and offer made was to nominate a male member in the family who could be employed but it was rejected by the union. In the circumstances, not much could be done for these two ladies. I also find that the management could not have in the circumstances helped them. There are recruitment rules set for the recruitment of regular employees Smt. Anjana Sitaram, one of the ladies has crossed more than 60 years. It is not possible to over-ride the rules and ignore the policy and straight away direct the regularisation of such employees. Decision of the Supreme Court in the case of State of Haryana Vs. Piara Singh, reported in AIR, 1992 Supreme Court, Page 2130 has been referred to and relied upon on behalf of the management which has given the guiding principle to be followed under directions for regularisation of services. Direction by High Court to regularise unconditionally all persons who have put in one year's service is found to be not sustainable because of the problems arising out of wholesome regularisation. It is also held that the direction for regularisation of service in respect of all ad-hoc/temporary employees was not proper. All that could be done is to make the efforts to regularise such employees as early as possible and subject to them being qualified and subject to availability of work. Another decision in the case between Mount Mettur Pharmaceuticals

Ltd., and Second Additional Labour Court, Madras and another reported in 1985 I.L.J Page 505 was referred to and relied upon in the course of arguments. In that case it is laid down that mere violation of Section 25-F cannot result in reinstatement with back wages and in such cases where retrenchment is bona fide and justified, compensation in lieu of reinstatement would be proper exercise of discretion. Here in this case, I have found that there is no infringement of Section 25F also.

11. There are other points raised on behalf of the management with regard to justification of the reference and the right of Shri Pendre, to represent workmen. I do not think it is necessary for me to deal with those contentions in view of the fact that my finding is not in favour of the workman on the point that the provisions of Section 25F of the Act were attracted, no relief could be given to the workmen and reference will have to be disposed off and award accordingly made.

R. G. SINDHAKAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1994

क्र.प्र. 2792.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, नाथे ईस्ट कोल फील्ड्स लि. के प्रबन्धन के संबंध में निम्नलिखित औद्योगिक विवाद उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, प्रमम के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-9-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-22012/219/88-डी IV (बी)आईआर-(सी-II)]

राजा लाल, हेड ऑफिसर

New Delhi, the 16th September, 1994

S.O. 2792.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal Assam as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of North Eastern Coal fields Ltd. and their workman, which was received by the Central Government on 14-9-1994.

[No. L-22012/219/88-D. IV (B) IR (C-II)]

RAJA LAL, Desk Officer

#### ANNEXURE

IN THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, GUWAHATI, ASSAM  
REFERENCE NO. 7 (C) OF 1989.

#### PRESENT :

Shri J. C. Kalita, Presiding Officer, Industrial Tribunal,  
Guwahati.

In the matter of an Industrial Dispute

#### BETWEEN :

The Management of Tipong Colliery North Eastern  
Coal Field. Coal India Ltd

#### AND

Their 35 workmen named in the Notification No I-  
22012 (219)/88-D. IV B/IR (C. II), dated 21-7-1989  
represented by the Assam Colliery Mazdoor Con-  
gress, Bargolai, Dibrugarh.

#### AWARD

This Reference arising out of the Central Government  
Notification No. I-22012 (219)/88/D. IV B/IR (C. II), dated  
21st July, 1989 relates to the dispute indicated in the Schedule  
below :

"Whether the action of the Management of Tipong Colliery, North Eastern Coalfields of Coal India Ltd., to employ the 35 workmen as casuals and to continue them as such for years, is entitled ? If not, to what relief the workman concerned are entitled ?"

On receipt of the notification notices were sent to the parties directing to appear before this Tribunal and to file their written statement. Both the parties appeared before this Tribunal and filed their written statements.

On 24-8-1994 both sides present. The Secretary of the Union has filed a petition praying to dispose of the reference by awarding a no dispute award as the matter is likely to be settled as per the Bilateral agreement reached between the Management and the National Mine Workers Federation.

Heard both sides. Prayer allowed and the reference is disposed of by a no dispute award.

I give this award on this 24th day of August, 1994 at Guwahati

J. C. KALITA, Presiding Officer

#### LIST OF THE WORKMEN :

1. Sri Lakhiram Soner
2. Sri D. Ananda Rao
3. Sri K. Erraiya
4. Sri Nandeswar Saikia
5. Sri Monohari Barman
6. Sri Abdul Mazid
7. Sri Taybe Ali
8. Sri Amir Hussain
9. Sri Gauranga Mallik
10. Sri Biman Dutta
11. Sri Basir Khan
12. Sri Rajnath Rai
13. Sri A. Apparao
14. Sri Anan Das
15. Sri Upen Bhuyan
16. Sri Narayan Sahu
17. Sri Mon. Bah. Chetry
18. Sri Mukhilai Rai
19. Sri Durga Bah. Chetry
20. Sri Nagen Borah
21. Sri G. Surnarayan
22. Sri Chandrakot Saha
23. Sri Jogendra Rai
24. Sri Ganga Bah. Pradhan
25. Sri P. Chasaiya
26. Sri T. Enkotrao
27. Sri Seo Sankar Ram.
28. Sri P. Apparao
29. Sri R. Rangarao
30. Sri L. Trinath
31. Sri S. Mohanrao
32. Sri K. Simachalam.
33. Sri Birjoo Keot
34. Sri D. Apparao
35. Sri S. Norsimloo

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1994

का.ग्रा. 2793.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के प्रसूचन में, फूड कारपोरेशन आफ इंडिया के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, असम के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-9-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एन-22012/162/एफ-आईआर (सी-II)]

राजालाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 16th September, 1994

S.O. 2793.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal Assam as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of F.C.I. and their workmen, which was received by the Central Government on the 14-9-1994.

[No. L-22012/162/F/92-IR (C. II)]

RATA LAL, Desk Officer.

#### ANNEXURE

IN THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, GUWAHATI, ASSAM  
REFERENCE NO. 12 (C) OF 1992.

#### PRESENT :

Shri J. C. Kalita, Presiding Officer, Industrial Tribunal,  
GUWAHATI.

In the matter of an Industrial Dispute.

#### BETWEEN :

The Management of Food Corporation of India,  
Guwahati.

#### AND

The workman Shri Ram Charan Bezbaruah.

#### APPEARANCES :

Shri Sishir Dutta, Advocate. : For the Management.

Shri A. Kalita, Advocate. : For the workman.

#### AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, New Delhi by a Notification L-22012/162/F-92-IR (C. II), dated 1-10-1992 made a reference to this Tribunal for adjudication of a dispute between the Management of F.C.I.; and their workman Shri Ram Charan Bezbaruah with copies to both the parties. On receipt of the reference notices were sent to both the parties to appear before this Tribunal and to file their written statement. The issue to be decided is as follows :

"Whether the action of the management of Food Corporation of India, Guwahati, Region in terminating the services of Shri Ram Charan Bezbaruah w.e.f April 1984 without following the provisions of Section 25 of I. D. Act, 1947 and not giving him any opportunity of re-employment as required under Section 25-H of the I. D. Act is justified ?

If not, to what relief the workman is entitled to ?"

The workman in his written statement contended that he worked as casual labour in the office of the District Manager, Ulubari, Guwahati-7 from September, 1981 to March 1984 regularly on payment of daily wages. On 11-9-1984 he found

that he was terminated from service. His repeated requests to reinstate him paid no dividend. He approached the Assistant Labour Commissioner for conciliation, but it also failed. Hence is the reference.

The Management in their written statement contended that the workman was engaged as casual labour in the office of the District Manager for cleaning, sweeping and water carrier work for 19 days in a month on daily wages basis. It has been alleged that the workman left the place of work in the early part of 1984 and never reported for work for long time; nor made any request to the management for re-employment. There arises no question of termination from service as he himself left the place of work. As the workman never worked for one year continuously the provision of Section 25-F and 25-H of the Act are not applicable to him. Hence the reference is liable to be dismissed.

The workman in his evidence deposed that he could not attend his duties with effect from 10-3-1984 to 9-6-1984 because of his serious ailment. He came to report on duty with a medical certificate from Doctor but was disallowed to report on duty on the plea of no vacancy. On the contrary the witness for the management deposed that he left the job voluntarily without any information. Exhibit 2 is the Medical Certificate issued by a Doctor. According to the Doctor the workman Ram Charan Bezbaruah was under his treatment for Infective Hepatitis from 10-3-1984 to 9-6-1984. His absence from duty is well justified and well established by the Doctor's certificate. No one could report on duty during the period of his ailment. As he was a daily wage worker he is not entitled to any wages for his absence; but he cannot be driven out from the service on the plea of leaving the job voluntarily when he has been serving for last 3 years.

The workman deposed that he worked continuously from 1981 to 1983 which was not denied by the Management. To prove that the workman worked for 19 days in a month the burden solely lies upon the Management. He was paid by the Management and his attendance were also recorded by the Management. These official records could have been produced to show that he worked for 19 days in a month and he was paid wages for 19 days. In the absence of this piece of material evidences the plea of the Management could not be accepted. Once it is established that a workman continuously worked for one year or 240 days in a year he cannot be terminated at the sweet will and pleasure of the Management Exhibit 1 proved his continuous service from September, 1981 to March, 1984.

Under the Industrial Dispute Act workmen means any person engaged in any Trade or any Industry to do any skilled, unskilled, manual or clerical work for hire or reward. He was engaged to do manual work. He was paid by the F.C.I. His works and attendance were supervised and controlled by the management. It proved that there existed a relationship of Employer and Employee between the Management and the Workman. As such he cannot be removed from service without following the provision of Section 25-F of the Act. The submission of the management that he is not entitled to the benefits of Section 25-F of the Act could not be accepted. Termination without service of one month's notice in writing indicating the reason of retrenchment and necessary compensation to him was clear violation of the provision of Section 25-F of the Act.

The plea of the Management that he never turned up to claim re-employment in F.C.I. holds no good when the workman laid a cogent evidence that he came to report on duty with a medical certificate issued by a Doctor after his ailment. Had the F.C.I. been sincere they could have employed him as soon as he reported to duty with medical certificate, but simply refused that there is no vacancy.

That there exists no vacancy holds no good by the contents of Exhibit 1 issued by the Chief Labour Inspector, F.C.I., District Office, Ulubari, Guwahati. It is mentioned in Exhibit 1 that his (workman) engagement was discontinued after the engagement of regular Messenger. As there were vacancies the Management engaged regular workman as Messenger to carry out the official works after his retrenchment. Such type of policy of recruitment be discontinued.

In the light of the above discussions it can be well said that the Management of F.C.I., Guwahati Region is not justified in terminating the service of Shri Ram Charan Bezborua with effect from April, 1984. The Management is hereby directed to reinstate him forthwith in the job he held with full back wages as are entitled by regular workers.

I give this AWARD on this 31st day of August, 1994 at Guwahati under my hand and seal.

J. C. KALITA, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1994

का.आ. 2794 —औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, असम के पंचपट की प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 14-9-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-22012/166/एफ/92 आईआर(सी-II)]

राजालाल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 16th September, 1994

S.O. 2794.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal Assam as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of F.C.I. and their workmen, which was received by the Central Government on the 14-9-1994.

[No. L-22012/66(E)/92-IR (C. II)]

RAJA LAL, Desk Officer.

#### ANNEXURE

IN THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, GUWAHATI, ASSAM

Reference No. 13(C) of 1992

#### PRESENT:

Shri J. C. Kalita,  
Presiding Officer,  
Industrial Tribunal, Guwahati.

In the matter of Industrial Dispute.

#### BETWEEN

The Management of Food Corporation of India,  
Ulubari, Guwahati.

#### AND

Their workman Shri Monohari Kalita

F.C.I., Tihu FSD, Nalbari.

#### APPEARANCES:

Shri Sishir Dutta, Advocate.—For the Management.

Shri G. N. Das, Advocate.—For the Workman.

#### AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour, New Delhi, by a Notification No. L-22012/166/F/92-IR (C. II) dated 9-10-1992 made a reference to this Tribunal for adjudication of a dispute between the Management of Food Corporation of India, and their workman Sri Monohari Kalita with copies to both the parties. On receipt of the reference notices were sent to both the parties to appear 2241 GI/94—18.

before this Tribunal and to file their written statement. The reference reads as follows:

"Whether the action of the management of Food Corporation of India, Guwahati Region in terminating the services of Sri Monohari Kalita w.e.f. February, 1985 without following the provisions of Section 25F of the I.D. Act and not giving him any opportunity of re-employment as required under Section 25F of the I.D. Act is justified?"

If, not to what relief the workman is entitled to?"

The workman in his written statement contended that he worked as casual worker in Tihu F.S.D. of F.C.I. on daily wages basis, but was suddenly asked to stop working from February 1985 and thereby terminated him from the service without giving him any opportunity or assigning any reason thereof. Though he has been constantly praying his reinstatement the management paid no heed, but subsequently gave employment to some other persons. Then he approached the Assistant Labour Commissioner, Guwahati who invited the management for conciliation but it failed. Termination from service without following the provisions of Section 25F and 25H of the Act is not justified and he is entitled to be reinstated with full back wages.

The Management in their written statement contended that the reference is not maintainable and this Tribunal has no jurisdiction to interfere. The workman was engaged on daily wages basis for 19 days in a month at Tihu F.S.D. for cleaning, Sweeping and Water Carrier Work in 1981. He was removed from casual service in 1985 when there was no need of further engagement. Management is not required to follow the provision of Section 25F and 25H of the Act as the workman never in continuous service for one year. No other persons are engaged after his retrenchment. As such he is not entitled to the relief claimed.

The witness for the Management deposed that no formal appointment letter is issued to any casual worker engaged on daily wages basis. This witness admitted that the workman worked from 1981 to 1985. The workman deposed that he worked for the whole month but was paid less. It means he was paid for the days he worked. According to management he was engaged for 19 days in a month, but no official record is produced to prove that the workman actually worked 19 days in a month. To prove this contention payment register and the attendance register ought to have been produced before this Tribunal to come to a conclusion that the workman never worked for 240 days continuously in a year. In the absence of the documentary evidence oral evidence of the Management witness could not be accepted.

Exhibit 1 says that the workman was engaged as casual worker during the period from November 1981 to February, 1985 without any mention therein that he was engaged for 19 days in a month. It further speaks that his reinstatement could not be considered as the handling and other depot operation are carried out through workers under "Workers Management Committees", but to this effect no evidence is adduced.

It is proved in evidence that he worked as a manual worker. The Act defines workman as follows: "Workman means any person employed in any Trade or any Industry to do any skilled or unskilled, manual or clerical work for hire or reward". His service was utilised on payment of daily wages and was under the supervision of the Management. All these go to show that there exists a relationship of employer and the employee between the Management and the workman. Once it is proved that he is a workman as defined in the Act he can be terminated only as per the provision of the Act.

Here it is proved that the workman worked for five years. As such he was entitled to one month's notice in writing indicating the reason for retrenchment and necessary compensation as laid down in Section 25F of the

it is not complied with. It can be well said that the retrenchment after continuous service for five years was illegal.

It has been explained that re-employment should not be given as the present system of engagement of worker is done under the workers management committee. This plea is not legally tenable once it has been proved that the workman served for five years continuously under the Control and Supervision of the Management but not under the Control of the workers Management Committee, was also paid by the management. Engagement of workers through "Workers Management Committee" in F.C.I. Depot clearly suggest that there is absolute necessity of workers in F.C.I. Depot. This retrenched workman who had served for five years cannot be deprived from re-employment as a regular worker. Workman deposed that one Nagen Seal was engaged as worker after his retrenchment and he is still in service. Management failed to give a satisfactory explanation on this point. In the light of the above it can be held that there is violation of the provisions of Section 25F and 25H of the Act; and the action of the management is not justified in terminating his service from regular employment.

In the result the workman is entitled to be reinstated forthwith against the post he held. Management is hereby directed to reinstate him forthwith with full back wages from the date of retrenchment.

I give this Award on this 30th August, 1994 at Guwahati under my hand and seal.

J. C. KALITA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1994

का.आ. 2795—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, जलगांव के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 2, बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19-9-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-40012/56/93-आई आर (डो यू)  
के.वी.बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 19th September, 1994

S.O. 2795.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Bombay as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Telecom District Manager, Jalgaon and their workmen, which was received by the Central Government on 19-9-94.

[No. L-40012/56/93-IR(DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

#### ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

PRESENT:

Shri S. B. Panse, Presiding Officer.

Application No. CGIT-2/34 of 1994

Employers in relation to the management of Telecom District Manager, Jalgaon.

AND

Their Workmen

#### APPEARANCES:

For the Employers—No Appearance.

For the Workmen—Mr. M. S. Chaudhari, Representative  
INDUSTRY : Telecommunications STATE : Maharashtra  
Bombay, dated 2nd September, 1994

#### AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, New Delhi by its letters No. L-40012/56/93-IR(DU) dated 25th July, 1994 had referred the Industrial dispute under section 10 of the Industrial Disputes Act for adjudication. It is in the following words :

"Whether the action of the management of Telecom. Distt. Manager, Jalgaon in not awarding temporary status to Shri Ramesh C. Hardekar, is proper, legal and justified ? If not, to what relief the workman concerned is entitled to ?"

2. After receipt of the reference the parties were given notices to appear before the Tribunal and put their submissions.

3. Today, the representative of the Applicant filed purshis (Exh. 2/W) that the Applicant is granted temporary status vide letter No. E-9/SDEC/SO dated 15-4-94 from the management of Telecom District, Sholapur. Therefore the instant case may please be treated as closed. On the basis of the above said Purshis I do not find that anything has to be adjudicated in the present matter, hence I pass the following order.

#### ORDER

1. The reference is disposed of for want of prosecution.

2. No order as to costs.

Dt. 2-9-94.

S. B. PANSE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1994

का.आ. 2796—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, पंजाब नेशनल बैंक के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19-9-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/185/90-आई.आर.बी. 2]

वी.के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 19th September, 1994

S.O. 2796.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Punjab National Bank and their workmen which was received by the Central Government on 19-9-94.

[No. L-12012/185/90-IR(B.II)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

## ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING  
OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL,  
NEW DELHI

I.D. No. 118/90

In the matter of dispute between:

The General Secretary,

Punjab National Bank Employees Union (Delhi),

W-8, Green Park, New Delhi-110016,

representing S. Shri Kamal Pathak, J. K. Saigal and  
Jagdish Puri

Versus

1. The Chairman & Managing Director,  
Punjab National Bank,  
Head Office, 7-Bhikaji Cama Place,  
New Delhi-110066.

2. The Regional Manager,  
South Delhi Region,  
Punjab National Bank,  
Competent House,  
F-14, Connaught Circus,  
New Delhi-1100 01.

## APPEARANCES:

Shri V. K. Gupta—for the workman.

Mrs. Renu Mishra—for the Management.

## AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-12012/185/B-IRVII dated 1-10-90 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of Punjab National Bank, New Delhi in stopping one increment with cumulative effect of S/Shri Kamal Pathak J. K. Saigal and Jagdish Puri was justified? If not to what relief the workmen are entitled?"

2. During the course of the proceedings parties arrived at a settlement and made statement that no dispute award be passed as the matter has since been settled. In view of this no dispute award is passed in this case leaving the parties to bear their own costs.

12th September, 1994.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this award may be forwarded to the Central Govt. for necessary action at their end.

12th September, 1994.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1994

का.श्रा. 2797—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19-9-94 को प्राप्त हुआ था।

[सं एल-12012/278/93-आई आर (बी-2)]

वी.के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 19th September, 1994

S.O. 2797.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Indian Overseas Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 19-9-94.

[No. L-12012/278/93-IR(B-II)]  
V. K. SHARMA, Desk Officer

## ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI, SHARMA, PRESIDING  
OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL,  
NEW DELHI

I.D. No. 27/94

In the matter of dispute between:

Shri Vijender Kumar through,

Mahasachiv,

National Bank Karamchari Sangathan,

B-202, Ashok Nagar, Mandawali Road,

Delhi-93.

Versus

Zonal Prabandhak,

Indian Overseas Bank,

Zonal Office, New Delhi.

M-13, Punj House Annexe,

Connaught Place, New Delhi-1100 01.

## APPEARANCES:

None—for the parties.

## AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-12012/278/93-IRB-2 dated 4-3-1994 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of Indian Overseas Bank, New Delhi in imposing the punishment of stoppage of one increment on Shri Vijender Kumar, Clerk vide their order dated 4-2-1989 is justified? If not, what relief, is the workman entitled to?"

2. No one appeared on behalf of the parties on the last date also no body had appeared and the workman had not filed even statement of claim inspite of opportunities having been so given. It appears that the workman is not interested in proceeding further with the dispute. No Dispute award is, therefore, given in this case leaving the parties to bear their own costs.

6th September, 1994.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this award may be forwarded to the Central Govt. for necessary action at their end.

6th September, 1994.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1994

का.श्रा. 2798—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यूनियन बैंक आफ इंडिया के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नं. 2, बम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 16-9-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/323/91-आई.आर. (बी.-2)]

वी.के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 19th September, 1994

S.O. 2798.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Bombay as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Union Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on 16-9-94.

[No. L-12012/323/91-IR(B.II)]  
V. K. SHARMA, Desk Officer

## ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL  
TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

## PRESENT :

Shri S. B. Panse, Presiding Officer

Reference No. CGIT-2/21 of 1992

Employers in relation to the Management of Union  
Bank of India.

## AND

Their Workmen

## APPEARANCES :

For the Employers.—Shri S. N. Verma, Representative.

For the Workmen.—Shri Dinesh Vengurlekar, Representative.

INDUSTRY : Banking STATE : Maharashtra.

Bombay, dated 2nd September, 1994

## AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, New Delhi by its letter No. L-12012/323/91-IR(B-2) dated 26th March, 1992 referred the Industrial Dispute under section 10 of the Industrial Disputes Act, to this Tribunal for adjudication. It is in the following terms :—

"Whether the action of the management of Union Bank of India in dismissing Shri Pradeep M. Joshi, Cashier-cum-Clerk from the services of the Bank is justified ? If not, to what relief the Workman entitled to ?"

2. After the receipt of the reference, the concerned Parties were served with the notices. They appeared before the Tribunal and submitted their claim.

3. The Workman contended that he joined the services of the Union Bank of India i.e. The management on 22nd March, 1977 at Parbhani Branch, District Parbhani. Thereafter he was transferred to Pandhala, District Kolhapur in August 1978. He was diligent. Thereafter on 25th August, 1983 he was served a Memorandum informing that he had committed gross misconducts.

4. On 18th February, 1984 he was informed that a departmental enquiry was fixed against him on 24th February, 1984 at 11 a.m. at Regional Office, Kolhapur. He was also informed that one Shri U. B. Rairikar was appointed as the Enquiry Officer in the matter. He was permitted to defend through a Representative.

5. The Workman contended that before issuing the Charge Sheet he was called in the Office and was asked to admit certain things which were recorded in the document dated August 18, 1982. The management relied upon those admissions in the charge. After issuance of the Charge Sheet the enquiry was started on 30th July, 1984 and was completed on the next day. The Enquiry Officer submitted his report on 17-9-1984. On 19-9-1984 he was issued with a Show Cause notice mentioning the proposed punishment of dismissal. Thereafter he was given a personal hearing on 11th October, 1984 but the submissions were not accepted and he was dismissed from the services on 25-10-1984. He filed a mercy petition in November 1984. But it was also rejected, informing him that he should have filed an appeal against that order within 45 days. Thereafter, again he made representations for allowing him to join the duty, but it failed.

6. The workman thereafter raised a demand and the conciliation proceedings commenced by a letter dated 9th April, 1991 issued by the Assistant Labour Commissioner. It ended in failure.

7. The workman contended that the charges which were levelled against him are vague. It is asserted that the Enquiry Officer relied upon the documents which were obtain-

ed from him using undue influence and pressure. The enquiry was in violation of the natural justice. It is averred that even if it is said that the enquiry is proper, the dismissal order is not just and proper looking to the charges. He averred that he is facing with mental troubles. Under such circumstance it is submitted that it may be held that the enquiry is not just and proper and he may be re-instated with the continuity in service and back wages.

8. The management opposed the claim by their written statement (Exh. M/3). It is asserted that the enquiry was just and proper. It is averred that there is no law in the enquiry and the punishment which was awarded to the workman is in conformity to the principles of natural justice, and the gravity of the offence which was committed by the Workman. It is denied that the workman so far as to certain charges levelled against him admitted them under undue influence and the enquiry officer relied upon the same.

9. My Learned Predecessor framed issues at Exh. 4. The issues and my findings thereon are as under :

## ISSUES

## FINDINGS

- Whether the inquiry held against the workman Shri P. M. Joshi was not held properly, & the rules of Natural Justice were not followed ? In the negative.
- Whether the action of the Management of Union Bank of India in dismissing Shri Pradeep M. Joshi, Cashier-cum-Clerk from the services of the Bank is justified ? In the affirmative
- If not, to what relief the workman Does not survive entitled ?
- What Award ? As per order below.

## REASONS

10. Shri Pradeep M. Joshi, the workman (Exh. W/9) affirmed that he joined the Union Bank of India, on the 22nd of March, 1977 and from August, 1978 he was at Panhala Dist. Kolhapur in their Branch. On 25th August 1983, he was charge-sheeted and a due enquiry was held against him and the punishment of dismissal was imposed upon him on 25-10-1984. After perusal of his evidence there is not a single word which can throw light on the allegation made by the workman in the statement of claim, that the enquiry was not just and proper. He had nowhere confirmed that the management sought his admissions on some charges using undue influence. It appears from his evidence that he is only on the point that a severe punishment was granted to him which should not be given. To substantiate this submission he lays reliance on the misdeeds committed by one Shri S. G. Kulkarni, Head Cashier-Cum-Clerk of Nate Branch, Dist. Ratnagiri. The record of Mr. Kulkarni is not before the Tribunal. He admitted that Kulkarni's case had no link with his case.

11. Mr. Balakrishna Rairikar (Exh. M/10) was the Enquiry Officer. He conducted the enquiry of the workman in respect of the charges levelled against him on 10-1-1984. He carried an enquiry on 30th and 31st of July, 1984 at Panhala and Kolhapur. The workman was represented by one Shri Sukhtankar, Asst. Secretary, Union Bank Employees' Federation, Maharashtra. After perusal of the charges which appear on the record I do not find that there is any ambiguity. The workman had full opportunity to defend his case and lead evidence. The Witnesses were duly cross-examined by him. After perusal of the enquiry papers nothing could be traced out, by which it can be said that the enquiry which was held against the workman was against the principles of natural justice.

12. Mr. Pairikr had affirmed that the Workman was never forced to admit any charge. He admitted some charges on his free will without any force or coercion. It can be further seen that at conclusion of the Enquiry, the workman gave a statement, admitting the acts of omissions and misconducts. The Enquiry Officer had also gone through the evidence on the record and had independently came to the conclusion that the workman is guilty of the charges levelled against him. I do not find any infirmity in respect of the enquiry which was held against the workman.



13. The findings which were recorded by the Enquiry Officer dated 17-9-84 were given to the workman. He was given personal hearing on 11-10-1984 before confirming the punishment of dismissal. The personal hearing was admittedly attended by the workman. He was heard there, but his submissions were rejected.

14. The workman in his affidavit and his representative at the time of the arguments submitted that looking to the nature of the charges levelled against him a harsh punishment is given to the workman. The charges against the workman were he has committed misappropriation of the Bank's Customers funds, manipulated the Bank's books of accounts and doing acts prejudicial to the interest of the Bank. The charge sheet further states that the workman was involved in fraudulent activities to the tune of Rs. 20,000 approx. It is tried to suggest that the workman has deposited all the amounts and there is no financial loss to the Bank. This submission is not sufficient to condone the fraudulent act committed by the workman.

15. In nut-shell, the modus operandi was that whenever a customer comes for depositing some money in the Bank the workman used to make an entry in his pass book, give the requisite portion of the pay-in-slip meant for the Customer after putting his initial and stamp in token of having received the amount. However, he would not make any entry in the books of accounts and thus pockets the amount, and if there was no sufficient balance in such accounts, he would make debit entries in the accounts of certain other Customers and then credit within the account of the customer, who had come to withdraw the money and then he will pay the money to such a customer. It means he was fraudulently keeping the Bank money with him, making false entries and some times not making entries which were required to be made. These all go to show that he is not a fit man to be in the Bank. The circumstances which are tried to bring on record that he is facing difficulty and there is nobody to look after his family members are the common grounds.

16. Again it was argued on behalf of the workman that one Mr. Kulkarni who had committed grievous mis-conduct is sympathetically looked by the Bank and as against the workman is not. By making this submission it is tried to suggest that there is discrimination. So far as the charges against Mr. Kulkarni and the enquiry proceedings are concerned, they are not before me. It is always seen that the facts of each case are different. Under such circumstances the management might have found it fit not to take any action or to take some action against Mr. Kulkarni which they find to be just. The action whatever may be taken against Mr. Kulkarni cannot be the precedent for another wrong doer.

17. For the above said reasons I record my findings on the points accordingly and pass the following order.

#### ORDER

1. The action of the management of Union Bank of India, for dismissing Shri Pradeep M. Joshi, Cashier-cum-Clerk from the services of the Bank is justified.
2. No order as to costs.

S. B. PANSE, Presiding Officer

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1994

का.आ. 2799.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसूचन में, केन्द्रीय सरकार केनरा बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19-9-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/403/91-आई.आर.बी.-2]  
बी.के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 19th September, 1994

S.O. 2799.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Canara Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 19-9-1994.

[No. L-12012/403/91-IR(B.II)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

#### ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA : PRESIDING OFFICER : CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL: NEW DELHI

I. D. No. 41/92

In the matter of dispute between :

Shri Sohan Lal,  
represented by the General Workers  
Union (Delhi),

A-97, Karampura, Shivaji Marg,  
New Delhi-110015.

Versus

M/s. Canara Bank,  
Through its Divisional General Manager,  
Staff Section (Workmen)  
D.D.A. Building, Nehru Place,  
New Delhi-110019.

#### APPEARANCES :

Workman in person with Shri U. C. Sharma.

Shri Jagat Arora for the management.

#### AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-12012/402/91-IRBII dated 20-4-92 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of Canara Bank in stopping one annual increment with cumulative effect of Shri Sohan Lal is justified? If not, what relief the workman is entitled to?"

2. The case was fixed today for the evidence of the management. Shri Ashok Kumar, Enquiry Officer of the Management appeared as a witness to support the enquiry proceedings. He was not cross-examined by the workman and the workman made statement that lenient view regarding punishment imposed upon him may be taken. Keeping in view the circumstances of this case I am of the opinion that the stoppage of one increment with cumulative effect is slightly harsh punishment and I therefore order that increment for first three years shall be stopped and from the fourth year he shall get increment, whichever in normal course is due to him. Parties shall bear their own costs.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this award may be forwarded to the Central Govt. for necessary action at their end.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer  
Central Govt. Industrial Tribunal, New Delhi  
6th September, 1994.

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1994

का.आ. 2800.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसूचन में, केन्द्रीय सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19-9-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-17012/31/93-आई.आर.बी.-2]  
बी.के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 19th September, 1994

S.O. 2800.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employees in relation to the management of I.I.C. of India and their workmen, which was received by the Central Government on 19-9-1994.

[No. L-17012/31/93-IR(B.II)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I.D. No. 65/94

In the matter of dispute between :  
Shri Dinesh Chander through  
Mahasachiv, Insurance Employees Congress (NZ)  
4th Khand, Jeewan Prakash, 25, K.G. Marg,  
New Delhi-110001.

VERSUS

Mandal Prabandhak,  
L.I.C. of India (N.Z.),  
Jeewan Bharti Building,  
Connaught Circus, New Delhi-110001.

APPEARANCES :

Shri K. K. Gupta for the management.  
None for the workman.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. 17012/31/93-BF IR, B-2 dated 26th May, 1994 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of I.I.C. of India, Northern Zone, New Delhi in not relaxing the upper age limit by one day in respect of Shri Dinesh Chander, peon for selection for appointment to the post of Apprentice Development Officer in I.I.C. is justified? If not, what relief is the said workman entitled to?"

2. The workman did not appear in this case even to file his statement of claim. It appears that he was not interested to pursue the case. A letter was received from the Insurance Employees Congress (NE) from the president that they do not want to pursue the case of the workman as he has since been promoted. The case may be treated as closed. In view of this letter and non-appearance of anyone on behalf of the management even to file statement of claim. No dispute award is passed in this case leaving the parties to bear their own costs.

1st September, 1994:

Central Govt. Industrial Tribunal, New Delhi

Further it is ordered that the requisite number of copies of this award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

1st September, 1994.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1994

का.आ. 2801.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि. के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19-9-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/280/90-आई आर बी-III/बी-II]  
वी. के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 20th September, 1994

S.O. 2801.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of American Express Bank Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 19-9-1994.

[No. L-12012/280/90-IR (B-III) /B-I]

V. K. SHARMA, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I. D. No. 7/91

In the matter of dispute between :

Shri H. K. Singh, as represented by American Express Employees Union, Hamilton House, Connaught Place, New Delhi-110001

VERSUS

The Management of American Express Bank Ltd., Hamilton House, Block A, Connaught Place, New Delhi-110001.

APPEARANCES :

S/Shri S. Sundram for the workman.  
Shri M. Dias for the Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-12012/280/IR(B-3) dated 29-1-1991 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of American Express Bank in discharging the service of Shri H. K. Singh, Special Teller w.e.f. 1-3-1990 is justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled to?"

2. During the course of the proceedings the parties filed joint application with the request that the matter has since been settled and no dispute award in terms of settlement may be given. Statement of the parties was recorded. In view of the joint application Ex. M-1 containing the terms of settlement alongwith the annexures a No dispute award is passed in this case. Party shall remain bound by the terms of the settlement and shall bear their own costs of this dispute

12th September, 1994.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

12th September, 1994.

BEFORE THE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NEW DELHI

REFERENCE : I. D. NO. 7 OF 1991

BETWEEN :

Mr. H. K. Singh as represented by American Express Employees Union, Hamilton House, Connaught Place New Delhi-110 001.

## AND

The Management of American Express Bank Ltd.,  
Hamilton House, Block A, Connaught Place, New  
Delhi-110 001.

## JOINT APPLICATION ON BEHALF OF THE PARTIES

The parties jointly submit as under :—

1. That an industrial dispute had been raised by the American Express Employees Union on behalf of Mr. H. K. Singh before the Labour Authorities, which dispute was subsequently referred for adjudication to this Hon'ble Tribunal.

2. That in the said dispute, the Union filed their Statement of Claim dated 12th February, 1991, which was duly replied to by the Bank vide their Written Statement, dated 15th April, 1991. Thereafter, the Union filed their Rejoinder dated 2nd July, 1991 and the case was fixed for recording of the evidence on behalf of the Management in the first instance; hence an Affidavit dated 31st March, 1992 of Mr. K. S. Balakrishnan was filed. In support of their claim the Union filed the Affidavits of Mr. S. Sundaram, General Secretary of the Union dated 14th May, 1991 and Mr. H. K. Singh, the Workman concerned dated 28th October, 1991. Thereafter Mr. K. S. Balakrishnan was duly cross-examined before this Hon'ble Tribunal on 13th August, 1992 and the case fixed for recording of cross-examination on behalf of the Union as also Mr. H. K. Singh the Workman concerned.

3. That, in the interim, the parties held negotiations to amicably resolve the dispute and in the circumstances on 9th June, 1994 the Workmen concerned Mr. H. K. Singh as also Mr. S. Sundaram, General Secretary of the American Express Employees Union agreed to withdraw the dispute (I. D. No. 7 of 1991) and to arrive at a fully and final settlement. A photocopy of the minutes of the meeting dated 9th June, 1994 duly signed by the parties is Annexure 'A'.

4. That the Workman has further received an amount of Rs. 93,277.36 as a one-time payment, photocopy of the receipt of which is Annexure 'B'. Photocopy of the receipt in respect of the Provident Fund amount received as on 1st March, 1990 amounting to Rs. 70,148/- is Annexure 'C'. Photocopy of the receipt towards gratuity amount of Rs. 52,621.14 is Annexure 'D'.

5. That in view of the aforesaid Settlement, no dispute whatsoever subsists between the parties, as the alleged dispute under reference has since been amicably resolved.

## PRAYER

It is, therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal be pleased to pass a 'No-dispute' Award in view of the satisfactory resolution of the industrial dispute and that appropriate Orders be communicated to the appropriate Government accordingly.

For and on behalf of the Workman.

Sd/-

S. SUNDRAM,  
GENERAL SECRETARY  
AMERICAN EXPRESS BANK  
EMPLOYEES UNION.

Place : New Delhi.

Dated : 8th August, 1994.

For and on behalf of the Management

Sd/-

K. S. BALAKRISHNAN, Director & Branch  
Operations Manager

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1994

का.आ. 2802 .—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मै, मैन्डल कोलफील्ड्स लिमि. की केदला अण्डरग्राउण्ड प्रोजेक्ट के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद

में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण (सं. I), धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19-9-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-20012/338/89-आईआर (कोल-I)]

वी.के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 20th September, 1994

S.O. 2802.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal. (No. I), Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Kedla Underground Project of M/s. C. C. L. and their workmen, which was received by the Central Government on 19-9-1994.

[No. I-20012/338/89-IR(Coal-I)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

## ANNEXURE

## BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d)(2-A) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 77 of 1990

## PARTIES :

Employers in relation to the management of Kedla Underground Project of M/s. C. C. Ltd.

## AND

Their Workmen.

## PRESENT :

Shri P. K. Sinha, Presiding Officer.

## APPEARANCES :

For the Employers : Shri R. S. Murthy, Advocate.

For the Workman : Shri D. Mukherjee, Secretary, Bihar Colliery Kamgar Union.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal

Dated, the 7th September, 1994

## AWARD

By Order No. L-20012/338/89-I.R. (Coal-I), dated 18-4-90 the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2-A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the action of the management of Kedla Underground Project of C. C. Ltd., P.O. Kedla, District Hazaribagh by not re-instating in service of Shri Mangru Manjhi w.e.f. 2-5-88 and not making payment of arrears of his wages alongwith other benefits provided by the management from time to time is legal and justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled?"

2. The concerned workman, Mangru Manjhi, was dismissed from service after the Inquiry Officer, in a domestic enquiry, held in his report that the charge of absenting from duty without authorisation and without information was established. Mangru Manjhi was employed as Timber Helper in Kedla Underground Project wherefrom he absented with effect from 9-3-87 without permission and without any satisfactory cause which action of the workman was a misconduct within the

meaning of order No. 17(i)(n) of the Model Standing Orders applicable to the aforesaid Project, as the allegation goes.

3. Admittedly the workman concerned was issued charge-sheet dated 21-8-87 but the workman, as alleged by the management, failed to submit any explanation. Thereafter a domestic enquiry was ordered, which was held and in which the workman concerned also participated. After completion of the enquiry the report dated 12-4-88 was submitted on consideration of which the workman was dismissed from service with effect from 2-5-88 by an order issued by the Project Officer/Agent dated 30-4-88/1-5-88.

4. The sponsoring Union in its written statement took the stand that the absence of the workman was known to the management and that the charge against the workman was not even proved in the enquiry. It also alleged that the workman was dismissed by a person who had no authority to do the same. It has also been alleged that the punishment inflicted was harsh.

5. The only ground for absence given in the written statement is that the workman had fallen ill.

6. In view of the objection of the sponsoring Union that the domestic enquiry was not fair and proper, that was taken up by the learned predecessor as preliminary issue. It will appear from order dated 24-6-92 that at the time of hearing of argument on the preliminary issue, the representative of the sponsoring Union, Sri D. Mukherjee conceded that the domestic enquiry was held fairly and properly. Similar was also found by the learned predecessor.

7. The points for consideration are, firstly, as to whether or not the management by its evidence in the domestic enquiry has proved the charge of misconduct against the concerned workman and, if so, whether the punishment awarded by the management to the workman was just and proper.

8. Under Clause 17(i)(n) of the Model Standing Orders, a continuous absence without permission and without satisfactory cause for more than ten days constitutes a misconduct on the part of the workman for which he can be punished including dismissal from service.

9. According to the charge the concerned workman had been absenting since 9-3-87 without permission. The charge-sheet is dated 21-8-87 which means that till that date the workman had continued absenting.

10. On behalf of the management, the statement of the management's representative was recorded by the Enquiry Officer who submitted that the workman was absent since 9-3-87 without information. He also submitted that the workman did not file any explanation to the chargesheet issued against him, nor did he join duty. He also placed the wage bill for the month of March, 1987 showing that the workman was present in that month 4 days only. He also produced Bonus Register showing that thereafter the workman had not worked for even a day.

11. The management's representative was cross-examined by the co-worker of the proceedee in which the management's representative denied that Mangru Manjhi had informed the Attendance Clerk about his illness. He was asked one more question, in which the co-worker had told him that he could give many example in which though the workman had filed leave application, that was found missing and the Attendance Clerk showed the workman to be absent because of which that workman had to file leave application again. This was a statement more than a question, but the management's representative denied though admitting that in one or two cases that had happened.

12. That the workman was absent since 9-3-87 is a fact admitted by the workman himself in his evidence. He has admitted that since he was ill, he was absenting from duty with effect from 9-3-87. The witness claimed that he had sent intimation by an application through his son. Thereafter this witness has given contradictory statement. Firstly he said that he did not know as to whom his son had given that application. In the same breath he said that he had given the application to the Attendance Clerk. He said that by the time of evidence he had submitted 3 to 4 applications.

About his illness he said that he was weak and had headache and also could not see. He also admitted that he never came to the doctor of the colliery, nor he could file any paper relating to the prescribing of medicines. He further said that he had not filed any certificate about his illness in the colliery. He also admitted that since his absence he never demanded work from the management because he was still ill. But he also said that if a work was given to him he was ready to work.

13. During the cross-examination he said that he did not get himself treated by a colliery doctor because he had no strength to go to that doctor whereas the private doctor treated him at his residence. In reply to another question he said that because of his illness he had filed duly filled up form for his retirement and if that is accepted, he was ready to retire from service.

14. Therefore, from the evidence it stands proved that the workman had remained continuously absent from his duty from 9-3-87, atleast till the date he had given his evidence which he had given on 31-3-88.

15. So for his explanation that he had submitted application about his illness is concerned, there is nothing on the record to show that any such application was filed. He said that he had sent application through his son, but also said that he did not know as to whom his son had handed over the application. He could have examined his son to prove that such an application was sent and to whom the application was handed over.

16. The workman had remained in attentive to his duty is clear from the fact that even after receiving the charge-sheet he did not file any explanation against the charge.

17. Therefore, from the materials on the record I have to hold that the absence was unauthorised.

18. The next point to consider is whether there was any satisfactory reason for his absence. The explanation is that the workman was ill. But the workman has filed no chit of paper to show that he had been all right from 9-3-87, and although. His explanation that he was so weak that he could not come to the colliery doctor can hardly be relied upon because he had participated in the domestic enquiry. In absence of any such paper it is difficult to accept his contention that he was ill.

19. Moreover in his evidence the witness has admitted that he was unable to see. But this must not have been the reason for his absence from 9-3-87 because except in an accident, one usually does not lose his eye-sight in a day. Therefore, if there was something wrong in his eye sight he could have got himself treated through colliery. In any case if his claim about his blindness was correct, the management cannot be asked to reinstate him.

20. In such case the proper course was to file an application for his retirement on medical ground, which the workman has accepted that he has done.

21. Sri D. Mukherjee, appearing for the workman has placed before me an alternative argument that justice would be done if the management was asked to accept his application for retirement on medical ground, and to appoint one of his dependant, which is the existing procedure.

22. I do not know as to what has happened to that application if that was filed. But I hope that if the same was filed, and if no decision has been taken on that, the management would consider that sympathetically and do the needful in accordance with the procedure and rules, including the employment of a dependent. But I am afraid that this Tribunal cannot give any such direction since that would be beyond the scope of the present reference.

23. In view of the aforesaid facts, I hold that it has been proved that the workman had absented himself for months altogether, without authorisation and without sufficient reason. In view of this finding I must hold that the action of the management was justified.

24. In so far the reference about payment of arrears of wages alongwith other benefits is concerned, the workman has been found guilty of the misconduct. The workman also admitted that since 9-3-87 he did not come to work on any day because he was medically and physically unfit to do so. In view of this there is no scope of directing the management to pay him back wages and other benefits.

25. Therefore, following is the award—

The action of the management of Kedla Underground Project in not re-instating Mangru Manjhi in service with effect from 2-5-88 and not making payment of arrears of wages alongwith other benefits (with effect from 9-3-87) was justified. The workman is entitled to no relief.

Under the circumstances of the case, there will be no order as to the costs.

P. K. SINHA, Presiding Officer  
नई दिल्ली, 20 सितम्बर 1994

का.आ. 2803 — औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसूचन में, केन्द्रीय सरकार, मै. भारत कोकिंग कोल लिमि. का मूनीडीह प्रोजेक्ट के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (सं. 1), धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19-9-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एन-20012/265/91-आई आर (कोल-1)  
बी.के. शर्मा, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 20th September, 1994

S.O. 2803.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal (No. I), Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Moonidih Project of M/s. B.C.C. and their workmen, which was received by the Central Government on 19-9-1994.

[No. L-20012/265/91-IR (Coal-I)]  
V. K. SHARMA, Desk Officer

#### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, DHANBAD

In the matter of a reference under Section 10(1)(d) (2-A) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 50 of 1992

#### PARTIES :

Employers in relation to the management of Moonidih Project of M/s. B.C.C. Ltd.

#### AND

Their Workmen.

#### PRESENT :

Shri P. K. Sinha, Presiding Officer.

#### APPEARANCES :

For the Employers—Shri B. Joshi, Advocate.

For the Workmen—Shri S. Bose, Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh.

STATE : Bihar

INDUSTRY : Coal

Dated, the 5th September, 1994

2241 GI/94—19.

#### AWARD

By Order No. L-20012/265/91-IR (Coal-I) dated, the 22nd July, 1992, the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of sub-section (2-A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

“Whether the action of the management of Moonidih Project of M/s. B.C.C. Ltd., PO Moonidih, Dist. Dhanbad in not paying the wages for the forced idle period to Shri R. S. Tiwari, Grade-I Clerk from 29-11-88 to 18-1-90 is justified? If not, to what relief the workman is entitled?”

2. The dispute between the parties lies in a narrow compass. It will so appear from the materials on the record including the written statement filed by the parties, that the concerned workman, R. S. Tiwari, a Grade-I clerk in the Moonidih Project had filed declaration (Ext. M-3 in the domestic enquiry) of his family members for availing L.T.C. on 1-2-1984 showing Sheojee Tiwari and Birendra Tiwari, 17 years and 16 years old respectively, as his brothers, residing with him, besides his wife, mother and one son. Then he claimed L.T.C. for travelling upto Agra submitting a bill of Rs. 2052 which was reduced by the management to Rs. 1584, claimed to have been done in accordance with the rule (Vide Ext. M-4 of the domestic enquiry). Later the workman was chargesheeted that his two brothers neither depended upon his earning nor were minors, therefore, the workman had cheated the company and put it in the loss to the tune of Rs. 1584. It was also claimed that he had taken only two days' earned leave whereas under rule he had to take 7 days' earned leave. A domestic enquiry was held. The plea of the workman was that at that time 7 days' leave rule was not in force and he denied the allegation relating to his brothers. The Enquiry Officer found the charges to have been proved and the workman consequently, was ordered to be dismissed from service vide Office Order dated 28-11-88 (Ext. M-8).

3. Back ground has been discussed in order to appreciate the present reference.

4. It will appear that thereafter the sponsoring Union raised the matter against the order of dismissal with the management. Thereafter the matter was settled between the management and the sponsoring Union and the document of settlement dated 16/17-1-90 was signed. Following is the settlement (Ext. M-12) :

“After enquiry into the alleged misconduct, Shri R. S. Tiwari, Clerk Gr. I Moonidih Project was dismissed vide office order No. MND/PO/DA (MR)/88/1732 dated 28-11-1988. The matter was taken up through an appeal and negotiations at different levels/times. After a series of negotiations the matter was settled on the following terms and conditions :—

#### TERMS OF SETTLEMENT

1. Shri Tiwari will be re-instated in service to the post where from his services were terminated. However, the period from the date of his idleness to the resumption of his duty will be treated as continuous services for the purpose of gratuity.
2. On resumption Shri R. S. Tiwari will be posted at Putkee Balihari Area.
3. Shri R. S. Tiwari will vacate the Quarters under his possession immediately on getting an accommodation at Putkee Balihari Area.

This solve the dispute in full.”

It will appear that on behalf of the Union Sri G. D. Pandey, Vice-President of R.C.M.S. had signed the document of Settlement. It will further appear from Ext. W-5 dated 11/15-3-90 issued to the Director (Personnel), Bharat Coking Coal Ltd. by the same Sri G. D. Pandey on behalf of the Union relating to a representation filed by the concerned workman that it was alleged that the action of the management in dismissing the workman was illegal which was done because of the trade union activities of the workman. For such dismissal

the workman had remained idle for one year before he was allowed to resume his duty. It was demanded that the management should pay to the workman wages for that period.

5. It appears that in view of the settlement the management did not agree to it and, ultimately, the present dispute was raised relating to payment to the concerned workman the wages for the idle period, i.e. from 29-11-88 to 18-1-90.

6. Both sides had filed their documents, which were marked exhibits with their consent. On the documents having been so marked as exhibits, both the parties submitted that they would not adduce evidence and would argue the case on the basis of documents. It is on this premises that the arguments of both the sides were heard. Shri B. Joshi, learned Advocate appearing for the management argued with force that the management was bound to implement only the terms of settlement reached between the management and the sponsoring Union. His argument was that there was no agreement to pay the workman wages for the idle period, the only concession that was given to the workman was that the period of idleness would be treated as continuous service for the purpose of gratuity alone. He also argued that the parties had agreed that the settlement had solved the dispute in full. Sri Joshi submitted that in view of this agreement which was accepted by the sponsoring Union and on which document Sri R. S. Tiwari had also signed as witness, it did not lie in the mouth of the sponsoring Union to claim full wages for the period of idleness also.

7. On the other hand, Sri S. Bose appearing for the sponsoring Union argued that this settlement was silent on the point of payment of wages for the period of idleness which was to be decided later. He argued that the management had agreed to retrace its steps and to re-instate the workman in service when it was made to realise by the sponsoring Union that its action was so patently illegal that it could not stand a judicial scrutiny. It was for this reason that within two months of the dismissal of the workman—when the matter was taken up with the management the management readily agreed to reinstate the workman. He also argued that in other case of such settlement when it was agreed with the workman who was punished with dismissal that he would not be paid back wages on his reinstatement, that condition was expressly incorporated in the deed of settlement. For example Sri Bose pointed out to Ext. W-3 in which also a settlement was reached between two parties relating to reinstatement of one Jhari Bouri, a workman in his original job. In this settlement it was clearly mentioned that the workman was to be reinstated without any back wages but with continuity of service. Sri Bose submitted that the terms of settlement do not say that the period of idleness was to be treated as continuous service for the purpose of gratuity alone. According to him, the terms of settlement does not even speak about any sort of punishment to the workman for the alleged misconduct or about reduction of punishment, hence the management cannot argue that his wages for the idle period was to be withheld as reduced punishment to the workman. Moreover it was argued that the Standing Orders do not provide for any such penalty for any alleged misconduct.

8. Sri Bose also pointed out that in their written statement they have mentioned in paragraphs 7 and 8 that while signing memorandum of settlement the issues of payment of wages including bonus, quarterly bonus and other benefits for the idle period were raised but it was agreed that the issue would be mutually settled and for this reason these issues were not included in the settlement.

9. The management in its rejoinder to the written statement of the sponsoring Union has admitted this much that at the time of entering into settlement the sponsoring Union had demanded payment of wages, bonus and other benefits for the idle period, but the management did not concede to the demand of the Union.

10. A question would naturally arise if such demands were made at the time of settlement and if the management did not agree to that and if even after refusal of the management to accede to such demands the sponsoring Union yet agreed to the settlement, then there was no reason as to why that was not clearly incorporated in the terms of settlement

like it was done in Ext. W-3. This settlement does not even simply states that the aforesaid period would be treated as continuous service "only" for the purpose of gratuity. This simply states that the aforesaid period would be treated as continuous service for the purpose of gratuity. Because of such vagueness in the term of settlement it cannot be said for sure that any decision about the back wages and other benefits was arrived at during those talks, as claimed by the management in its written statement because, had that been so it was natural to incorporate agreement about payment or non-payment of wages in the term of settlement itself, instead of maintaining silence over this issue.

11. On behalf of the management I have been pointed out that as per the terms of settlement, three conditions incorporated therein solved the dispute in full which expression was used at the end of this settlement.

12. But use of the expression—"This solve the dispute in full"—will hardly mean that the dispute on any point not incorporated in the terms of settlement would be taken to have been resolved in favour of the management. As a matter of fact the terms of settlement mainly deal with the reinstatement of the workman and treatment of the period of idleness as continuous service for the purpose of gratuity. If the aforesaid contention of the management is accepted then this would give rise to many disputes. For example, there is no agreement about seniority of the workman on his reinstatement. Then can the management argue that the workman had lost his seniority because of disruption of his service as his service was treated continuous only for the purpose of gratuity? Similarly other dispute may be raised like availing of L.T.C. etc.

13. The short recital of the case in Ext. M-12 states about dismissal of the workman and goes on to say that the matter was taken up through an appeal and negotiations were held in which the matter was settled. Therefore, it has been argued that the main point disposed of by this settlement was regarding lifting of the order of dismissal and reinstatement of the workman and this was the dispute which was resolved in full.

14. In view of the circumstances discussed above I find that the sponsoring Union was entitled to raise dispute regarding back wages and other benefits during the period of idleness.

15. Now the question to be decided is whether the workman is entitled to back wages and other benefits.

16. I have already stated that the term of settlement do not say specifically that there was any agreement that the workman deserved punishment for his alleged misconduct and that the punishment was being reduced. The settlement would show that the management had found it fit to reinstate the workman back in service.

17. Sri Bose has argued that the management did so because it was convinced that punishment had wrongly been awarded and that the workman had committed no misconduct. Similar point has been taken in their written statement also.

18. The management on its own had filed the documents of domestic enquiry on the alleged misconduct of the workman. Those documents with consent of both the sides have also been marked exhibits. Though the decision in pursuant to that domestic enquiry is not the subject matter of this reference and this Tribunal is not supposed to give a verdict on the justification or otherwise of awarding punishment to the concerned workman after holding him guilty of the charge of misconduct, but I have looked into those documents for the limited purpose of ascertaining as to whether there can be any substance in the aforesaid assertion of the sponsoring Union. I am looking to the documents of the domestic enquiry for the aforesaid limited purpose because to that extent the domestic enquiry has a bearing on a just conclusion to be arrived at in the present reference.

19. In so far as the charge of availing of only two days leave for availing L.T.C. is concerned the concerned workman had contended that at the time he availed of L.T.C.,

a workman could take less than seven days of leave and that many other workmen were allowed L.T.C. on that premises. Some evidence is on the record but I will refrain from commenting upon those evidence for the reason that evidently after making it clear in his claim that the workman had not availed of seven days of leave, the management had allowed him payment on account of L.T.C. and actually had made that payment. If the claim was against rules, all that was needed to be done was to reject the claim.

20. In so far as the second charge is concerned that the workman had claimed L.T.C. on behalf of his two younger brothers who were neither dependent upon him nor minors, I find that no evidence was led that at that time those two brothers were not dependent upon the workman. But the workman in his evidence has attempted to support his case on this point. Whether or not the workman succeeded in proving that is another matter but so far evidence is concerned it stands as above.

21. It will appear that in the domestic enquiry the management representative was the only witness on behalf of the management who not only revealed the charges but also proved some documents including an affidavit and application filed on behalf of Sheojee Tiwary in which he had claimed that his date of birth was 15-1-1964. Admittedly, a dependent minor brother came within the definition of 'family' as per E.L. M-1 and M-6. But Ext. M-4 would show that though he had claimed L.T.C. for 50%, he was allowed payment for 40% only though it is not clear in this exhibit as to who was excluded. From the statement of the management's representative it would appear that the management had stressed about Sheojee Tiwary that he was not a minor. If it is admitted that Sheojee Tiwary was not a minor then the concerned workman was not entitled to take L.T.C. for him. But evidently the concerned workman was paid L.T.C. for four persons only, and one person out of the family members who had taken that trip was excluded by the management from the payment. So evidently for one person the concerned workman was not paid any L.T.C.

22. I again make it clear that I am not expressing any opinion as to whether or not the management has conclusively proved its charge against the concerned workman, but in view of certain facts observed by me in the documents of the domestic enquiry it cannot be said that the claim of the sponsoring Union in this regard was without any force.

23. I also find substance in the line of argument that the management would not be supposed to have reduced the punishment by withholding wages for the idle period because there is no such punishment provided in the Standing Orders. A copy of Standing Order has been brought by the management which is Ext. M-9. Order No. 17 deals disciplinary action and penalties. This runs as follows :

"(i) A workman may be suspended or fined or his increment may be stopped or he may be demoted or dismissed without notice if he is found to be guilty of misconduct ....."

Withholding of pay and other benefits which may be reduced in terms of money cannot be termed as stoppage of increment. If the management wanted to impose fine by reducing the sentence, it was bound to mention the specific amount of fine in the document of settlement. This also suggests that the term of settlement did not amount to the imposing of a lesser punishment.

24. If the management has not proved that the punishment of dismissal was reduced to the withholding of wages for the idle period, then the workman should be held entitled to wages for the period of idleness.

25. The sponsoring Union in this regard has relied upon a decision of Hon'ble Supreme Court reported in 1994 Lab. I.C. 699 (Between Suresh Sakharam Chaugule and others Vs. M/s. Parel Cotton Press Factory Pvt. Ltd.).

26. In the case connected with the aforesaid decision the appellants were working as 'Labadies' in the factory of the respondent who were stopped from working with effect

from 18-10-75 and, subsequently, were dismissed from service by order dated 9-1-76. Since a reference about demands of the Labadies was pending and since approval about dismissal was not sought by the management, a complaint was filed before the Tribunal wherein the dismissal order was challenged. The management made a statement in the Tribunal that it had withdrawn the dismissal order. The Tribunal held in favour of the appellants.

27. Then the appellants filed an application under Section 33-C (i) of the Industrial Disputes Act, 1947 for wages and bonus from 18-10-75 to 28-11-79, which was dismissed by the Labour Court on the ground that there was no specific order by the management reinstating the appellants into service.

28. Their Lordships of Hon'ble Supreme Court held that since the order of dismissal was withdrawn by the management by making a statement before the Industrial Tribunal on 10-5-76, as consequence thereto the appellants would be deemed to be taken back in service and entitled to all the back wages from the date when they were stopped from working in the factory.

29. Shri Bose has argued that as per ratio of this decision if a dismissal was withdrawn and the workman was taken back into service, the workman would be entitled to all the back wages from the date when he was stopped from working.

30. The only difference from the present reference is that in this reference there is a written agreement and it is the terms of this written settlement which have to be interpreted to decide the issue. But this decision will help to the extent that if a workman, after dismissal, was reinstated into service by withdrawing of order of dismissal and if there was no express agreement about payment of wages for that interim period, the workman would be deemed to be entitled to back wages.

31. In this regard another decision reported in 1991 (1) LLJ-188 (Between Sudhakar Babu Rao Bodke and State of Maharashtra and others), of the Hon'ble High Court at Bombay may be seen. This is a case relating to a Sub Inspector in the Prohibited and Exercise Department of Government of Maharashtra who was ultimately terminated from service since he could not pass the departmental examination. On his representation he was reinstated into the service making it clear that he would not be allowed to count his past service for the purpose of seniority or for the purpose of fixation of pay and pension, rather for all practical purpose to be treated as fresh recruit. His Lordship observed that reinstatement involved putting a particular person back, in law and in fact, to the same position as he had occupied earlier before his services were terminated by the employer because to reinstate a man means to place him in the position from which he was dismissed so as to restore status quo ante the dismissal. Though in that the matter of payment of wages during the period of termination was not raked up, yet the principle was enunciated that reinstatement restored that status-quo-ante the dismissal.

32. The matter of payment of wages was considered in another case decided by the Hon'ble High Court at Patna. The principle for reinstatement was decided in this decision reported in 1969 (1)-LLJ-145 (Between Bihar Talkies Jharla and Industrial Tribunal and another). In the aforesaid case the Respondent Nos. 5 and 6, who were employed in the aforesaid Cinema Hall were dismissed from service on 14-6-60. The employees filed two applications under Section 26 of the Bihar Shops and Establishment Act praying therein to reinstate them with full back wages as well reasonable compensation. The learned Presiding Officer of the Labour Court allowed the application in part so much so that the employer was ordered to reinstate the employee and to pay each of them two months pay by way of compensation. No specific order was passed about the prayer of arrears of wages. Then the employees filed application under Section 28 of the aforesaid Act which was allowed. That order was upheld by the Hon'ble Court in the aforesaid decision. It was also held that the order of the Labour Court cannot be interpreted to mean that the employees concerned were not replaced in the position from which they were dismissed, so as to restore the status-quo-ante the dismissal. Their Lordships also held that simply because the Presiding Officer of the

Labour Court had not specifically granted arrears of wages claimed by the employees they were debarred from making the claim under Section 28 of the Act.

33. No doubt, that case related to provisions of Bihar Shops and Establishments Act, yet the principle upheld therein will apply in this case also. In that the employees had made specific prayer for back wages, but the order of the learned Labour Court was silent on that prayer. Since with reinstatement, the status quo ante was restored, the employees were held to be entitled to claim afresh the back wages.

34. In the instant case also the management has admitted that the demand relating to back wages etc. were raised but that was not conceded by the management. But that demand has not specifically been denied in the terms of settlement. Therefore, I am of the opinion that in view of the decisions aforesaid as also in view of the facts of this particular reference discussed in this order, the reference should be ordered in favour of the sponsoring Union.

35. In view of the aforesaid I find that the concerned workman is entitled to the payment of wages for the idle period, which has been described in the reference as the "forced idle period".

36. Following is, therefore, the award—

The action of the management of Moonjidi Project of M/s. B.C.C. Ltd. in not paying the wages for the forced idle period to R. S. Tiwari from 29.11.88 to 18.1.90 is not justified. The management is directed to pay the workman back wages for the aforesaid period within three months of this award becoming enforceable failing which the amount would be payable with interest at the rate of 12% per annum over that amount, thereafter.

Under the circumstances of the case there will be no order as to the cost.

P. K. SINHA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 20 सितम्बर 1994

का.आ. 2804. —औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय स्टेट बैंक आगरा के प्रबन्धन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19-9-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/69/87-डीII(ए)बी. I]

वी.के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 20th September, 1994

S.O. 2804.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India, Agra and their workmen, which was received by the Central Government on the 19-9-1994.

[No. L-12012/69/87-D.II(A)]B.I.]

V. K. SHARMA, Desk Officer

# ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I. D. No. 64/88

In the matter of dispute between :  
Shri Ashok Kumar Aggarwal through  
The Regional Secretary,

State Bank of India Employees Association,  
24, Laxmi Market, 2nd Floor, Belanganj,  
Agra.

Versus

Regional Manager,  
State Bank of India,  
Regional Officer,  
Agra.

## APPEARANCES:

Workman in person.—Shri A. K. Aggarwal with Shri Dev Shastri for the Management.

## AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-12012/69/87-D.II(A) dated nil has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of State Bank of India in withdrawing the Special Teller allowance from Sri Ashok Kumar Aggarwal w.e.f. 1-3-1986 is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The case was fixed for arguments on 6-9-1994 when both the parties made statement that the dispute has since been settled and no dispute award may be given in this case. In view of this statement no dispute award is given leaving the parties to bear their own costs.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 20 सितम्बर 1994

का.आ. 2805 —औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सेंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के प्रबन्धन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-09-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-42011/5/92-2 आई आर (विविध)]

बी एम डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 20th September, 1994

S.O. 2805.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Ware Housing Corporation and their workmen, which was received by the Central Government on 20-09-1994.

[No. L-42011/5/92-IR (MISC)]

B. M. DAVID, Desk Officer



## ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING  
OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL,  
NEW DELHI

I. D. No. 61/93

In the matter of dispute between :

Shri Tara Chand and others through  
The General Secretary, C.W.C. Worker's Union,  
309, 3rd Floor, 92, Deepali Nehru Place, New Delhi-19.

Versus

The Manager (Personnel),  
C.W.C. 4/1, Siri Fort Industrial Area,  
Hauz Khas, New Delhi-16.

## APPEARANCES :

Shri Girish Chander, Virender Kumar,  
Shri Ram Chander, Shri Raj Kumar and  
Shri Leela Dhar in person.  
Shri Kul Bhushan with Shri J.P. Yadav for the Manage-  
ment.

## AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour  
vide its Order No. L-42011/5/92-IR (Misc.) dated 23-8-93  
has referred the following industrial dispute to this Tribunal  
for adjudication:

"Whether the action of the management of CWC in  
not giving the equal pay for equal work to S/Shri  
Tara Chand, Narender Kumar, Girish Chand, Leela  
Dhar, Raj Kumar, Ram Chander, Rajram and Ram  
Kishore working as Farash, Farash, Helper, Helper,  
Sweeper, Sweeper, Sweeper, Sweeper, respecti-  
vely working since Nov. 1990 is justified? If not,  
to what relief the workmen concerned are entitled?"

2. During the course of the proceedings of this case the  
workman filed an application that they do not want to con-  
test the application and wanted to withdraw the case and  
close the dispute. Statement to his effect was recorded. In  
view of the statement of the parties no dispute award is passed  
leaving the parties to bear their own costs of this dispute.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

12th September, 1994.

Further it is ordered that the requisite number of copies  
of this award may be forwarded to the Central Govt. for  
necessary action at their end.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1994

का.या. 2806.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947  
(1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय  
सरकार कलावती सरन चिल्ड्रेन हॉस्पिटल, नई दिल्ली के  
प्रबन्धन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच,  
अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार  
औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती  
है, जो केन्द्रीय सरकार की 19-9-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-42011/5/92-आई.आर. (डी.य.)]

के.बी.बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 20th September, 1994

S.O. 2806.—In pursuance of Section 17 of the Industrial  
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government  
hereby publishes the award of the Central Government In-  
dustrial Tribunal, New Delhi, as shown in the Annexure, in  
the industrial dispute between the employers in relation to  
the management of Kalawati Saran Children Hospital, New  
Delhi and their workmen, which was received by the Central  
Government on 19-9-94

[No. L-42011/5/92-IR(DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

## ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESIDING  
OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL,  
NEW DELHI

I.D. No. 53/93

In the matter of dispute between:

Secretary,  
Kalawati Hospital Workers Union,  
11/59 Panchsatan Road House No. 1,  
New Delhi-110001.

Versus

Medical Superintendent  
Kalawati Saran Children Hospital,  
Bangla Sahib Marg, New Delhi-110001.

## APPEARANCES :

None—for the parties.

## AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide  
its Order No. L-42011/5/92-IR (D.U.) dated 29-7-93 has  
referred the following industrial dispute to this Tribunal for  
adjudication :

"Whether the Management of Kalawati Saran Children's  
Hospital is justified in refusing—

- (1) to make payment of difference in the rates of  
cloth for the warm uniforms of its Class IV  
staff issued in Dec., 1991;
- (2) payment of extra care allowance to its class IV  
staff working in ICU/NN Wards/Totnus as is being  
paid to the doctors working in these units/wards.
- (3) filling up of posts lying vacant since long;
- (4) provision of separate and suitable common and  
recreation rooms for the male and female employees.
- (5) regularisation of services of daily rated and ad-  
hoc employees;
- (6) next higher scale for the employees lying stagnant.
- (7) regular medical check-up to the employees ;
- (8) provision of separate quota of quarters for its em-  
ployees ;
- (9) giving relaxation to the SC & ST candidates for  
promotion as UDC ;
- (10) abolition of the minimum qualification of diploma  
in electric Trade and radiography for appointment  
as Autoclave Assts. and Room Assistants, respec-  
tively ;
- (11) non-inclusion of risk allowance in respect of  
Group C & D employees ;
- (12) provision of refresher/training courses ; and
- (13) grant of at least one promotion in a service of  
eight years ?

If not, what relief the concerned workmen are entitled  
to?"

2. None appeared on behalf of the parties and the case was  
called many times. Workman did not appear even for his  
exparte evidence. In view of no evidence on record. No dis-  
pute award is given in this case leaving the parties to bear  
their own costs.

Dated : 1st September, 1994.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

क.आ. 2807.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मै. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की गधुर कोलियरी के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (सं. I), धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-9-94 को प्राप्त हुआ था।

संख्या-एल-20012/105/83-डी.-3(ए)/आईआर  
(कोल-I)]

वी.के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 22nd September, 1994

S.O. 2807.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal (No. I), Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Godhur Colliery of M/s. BCCL and their workmen, which was received by the Central Government on 20-9-94.

[No. L-20012/105/83-D.III(A)/IR (Coal-I)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

#### ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. I, DHANBAD

In the matter of a reference under section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 16 of 1988

#### PARTIES :

Employers in relation to the management of Godhur Colliery of M/s. B.C.C. Ltd.

AND

Their Workmen

#### PRESENT :

Shri P. K. Sinha, Presiding Officer.

#### APPEARANCES :

For the Employers : Shri B. Joshi, Advocate.

For the Workmen : Shri S. Bose, Secretary.

Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dated, the 13th September, 1994

#### AWARD

By Order No. L-20012/105/83-D.III (A), dated, the 10th August, 1983, the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the action of the management of Godhur Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, in not designating Shri B. K. Pathak as Bhatta Supervisor in Technical and Supervisory Grade-B is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?"

2. This reference case was fixed for hearing arguments on 5-9-1994. Shri S. Bose, Secretary of the sponsoring Union, filed an application on 5-9-1994 stating therein that the concerned workman was declared medically unfit and, in his place, his dependant has been employed by the management. For this reason the sponsoring Union was not interested to proceed with the case.

3. Under the circumstances, I am constrained to render a 'no dispute' award.

4. Therefore a 'no dispute' award is rendered in the present case.

P. K. SINHA, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

क.आ. 2808.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इंडियन बैंक के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण मद्रास के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22-9-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-12012/326/86 डी. 2(ए)/आई.आर.  
(बी. 2)]

वी.के. शर्मा, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 22nd September, 1994

2808.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Madras as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Indian Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 22-9-1994.

[No. L-12012/326/86-D.II(A)/IR (B. II)]

V. K. SHARMA, Desk Officer.

#### ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, TAMIL NADU, MADRAS

Thursday, the 5th day of May, 1994

#### PRESENT :

Thiru K. Sampath Kumaran, B.A. B.L., Industrial Tribunal.

Industrial Dispute No. 57/87

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, between the Workman and the Management of Indian Bank, Rasi-puram).

#### BETWEEN

The workman represented by

The General Secretary,  
Indian Bank Employees' Union,  
25, Second Line Beach,  
Madras-600001.

#### AND

The Assistant General Manager,  
Indian Bank,  
31, Rajaji Salai,  
Madras-600001.

## REFERENCE :

Order No. L-12012/326/86-D.II(A), dated 11-5-1987, Ministry of Labour, Govt. of India, New Delhi.

This dispute coming on for final hearing on Thursday, the 21st day of October, 1993 upon perusing the reference, Claim and Counter Statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiru N. G. R. Prasad for Tvl. Tow and Reddy, Advocates appearing for the Workman and of Thiru R. Arumugham, for Tvl. Aiyar & Dolia, Advocates appearing for the Management and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following :—

## AWARD

This reference has been made for the adjudication of the following issue :

“Whether the action of the management of Indian Bank in relation to their Rasipuram Branch in dismissing Shri T. M. Periaswamy, Sub-staff from service with effect from 3-9-1985 is justified? If not, to what relief the workman concerned is entitled?”

2. The Petitioner filed the following Claim Statement.—T. M. Periaswamy, was working as a sub-staff in Rasipuram Indian Bank, Coimbatore. By a letter dated 29-9-1984 of the Zonal Manager, Indian Bank he was charge sheeted alleging (a) that on 18-2-1984, he had presented to the Manager of the Bank a withdrawal slip for Rs. 4,000 on S.B. Account No. 166206 of Sri P. Kuppan for getting his order thereon to pass it without pass book stating that P. Kuppan was well known to him and was standing at the counter but had not brought the pass book. P. Kuppan allegedly denied having visited the branch for the withdrawal of money on 18-2-1984; (b) that on 18-2-1984 he had issued the token No. 285 against the withdrawal slip for Rs. 4,000 to P. Kuppan who was said to be standing at the S.B. Account counter which was not his duty at all; (c) that on 18-2-1984 when Mr. S. Jayakumar S.B. Passing Officer called Sri Kuppan by name while passing the withdrawal slip as it was without pass book, he had intervened and informed him that Mr. Kuppan was sitting in the Manager's room.

3. This according to the respondent indicated commission of gross misconduct as per 19.5 (d) and (j) and minor misconduct as per 19.7 (d) of the Bipartite Settlement dated 19-10-1966. After enquiry, the disciplinary authority informed the workman by letter dated 3-9-1985 that the Enquiry Officer had found him guilty of the charges and that he proposed to inflict the punishment of dismissal without notice in terms of Para 521(5)(a) of Sastry Award. The workman preferred an appeal dated 17-10-1985 to the General Manager who by letter dated 18-12-85 informed the workman that he was satisfied that the punishment of dismissal was just and proper and confirmed the punishment.

4. The dismissal order passed against him is illegal, unjust and is liable to be set aside. The enquiry is vitiated by bias. The observation of the enquiry officer

in his report since the worker did not raise any objections regarding leading questions, they were allowed shows that he had not performed his duty as an un-biased officer. The finding is not supported by evidence on record and is therefore, perverse. The Complaint of Kuppan (ME 4) was not put to Kuppan at the enquiry. He said nothing about having given such a detailed complaint. Therefore, no reliance should have been placed by the Enquiry Officer or the authorities on that document. MW1, Manager of the branch said that he did not know whether Kuppan was present on 18-2-1984 or not. The register for payment of withdrawal slips not accompanied by pass book was not produced, which alone would have clinchingly proved that the withdrawal slip was produced without the pass book. There was no charge that Periaswamy misappropriated Rs. 4,000. In the absence of such charge, the allegations that he misrepresented to have the withdrawal slip encashed cannot stand to reason. For the first time, without any evidence in that regard, the Disciplinary Authority in letter dated 29-7-1985 proposing the punishment says that Periaswamy committed the misconduct only to benefit himself. The cashier of the bank, who would have been a crucial witness in such a case of disbursement of cash on wrongful representation, was not examined. The Disciplinary Authority in proposing the punishment of dismissal has been influenced by the above said non-acceptable charge and hence the punishment is unjustified.

5. Para 521(10) (c) of the Sastry Award has laid down that in awarding the punishment by way of disciplinary action, the authority concerned shall take into account the gravity of the misconduct, previous record if any, and aggravating and extenuating circumstances. The authorities had not considered these facts in the case in imposing extreme punishment. The workman has had an unblemished record of service. The punishment given is shockingly disproportionate to the gravity of the offence alleged. The Enquiry Proceeding was vitiated by legal infirmities. The Branch Manager also carried prejudice against the said workman as he belongs to union which is not in the good books of the Management. An award may be passed holding the dismissal of T. M. Periaswamy as unjustified, and illegal directing the respondent to reinstate, with full back wages, continuity of service and other attendant benefits.

6. The Respondent filed the following Counter.—The Manager of the Rasipuram Branch received a complaint dated 3-4-84 from Kuppan, as S. B. Account Holder of that branch. He had stated therein that withdrawal of Rs. 4000 purported to have been made on 18-2-84 by him was wrong and that he had not withdrawn any amount on that day. He further stated that on that day he had been to Sendhamangalam from where he returned at 3.00 p.m. that on no occasion he withdrew from his account without his pass book. The Manager of the Rasipuram branch on receipt of the complaint from Kuppan forwarded the same to the Zonal Manager, Coimbatore. On the basis of the preliminary enquiry, show cause notice was issued to T. M. Periaswamy on 14-7-84. When the said Show Cause Notice was received by him on 16-7-84, T. M. Periaswamy remitted Rs. 4,000 into the S. B. Account of Shri

Kuppan, but he did not reply to the Show Cause Notice. Therefore, charges were framed against him. In the departmental enquiry, the employee fully participated and was defended by a defence counsel. The Enquiry Officer, based on the oral and documentary evidence, concluded that the charges were proved. The Disciplinary Authority concurred with his findings and found him guilty of the misconduct, under 19.5 (d) and (j) and 19.7(d) of the Bipartite Settlement dated 19-10-1966. The Disciplinary Authority by the letter dated 29-7-85, proposed the punishment of dismissal for gross misconduct and for minor misconduct. The Disciplinary Authority found that the employee had committed gross misconduct and awarded the punishment of dismissal from service by the letter dated 3-9-85. The union on behalf of the employee requested for a personal hearing and the same was granted on 18-11-85 and 23-11-85 by Appellate Authority. The Appellate Authority after considering all the points, raised, dismissed the appeal by its order dated 18-12-85. MW1, the branch manager had deposed about the request of Periaswamy on 18-2-84 initial the S. B. Pay Order as it was not accompanied by the pass book. He also stated that Periaswamy stated he knew Kuppan and he was at the Counter and pay order may be passed. Therefore, only on the representation of T. M. Periaswamy, MW1 initialled the S. B. Pay Order. MW6, Jayakumar deposed that when he called Kuppan's name to pass the pay order without production of the pass book, Periaswamy intervened that Kuppan was sitting in the Manager's room. So, it is on this information, Jayakumar passed the withdrawal slip. It was established that Kuppan was not in station on 18-2-84 till 3.00 p.m. and had not withdrawn Rs. 4,000 on that day. Kuppan has also deposed about it. The second charge regarding the issue of token is not denied. There is no substance that the enquiry is vitiated by bias. The reliance placed on Ex. M.3 the complaint letter is justified. The findings are not perverse. Only when the withdrawal slip is not accompanied by the pass book, the orders of Manager is necessary to pass such withdrawal slips. The employee was charge sheeted for wilful damage or attempt to cause damage to the property of the bank or any of its customers, and doing an act prejudicial to the interest of the bank or gross negligence or likely to involve bank in serious loss. The Disciplinary Authority in his order dated 18-12-85, noted the fact that the charge sheeted employee remitted Rs. 4000 on 16-7-84 when he received Show Cause Notice, and this goes to show that the charge sheeted employee paid the amount as he felt guilty. The reading of the charge shows that the charge sheeted employee had benefitted himself. The Banking industry is one where the staff members have to handle public money. Under such circumstances, the staff members have to maintain integrity & honesty. The business of the bank depends upon the trust and confidence reposed by the public in the bank. When a Staff member involves in the fraudulent activity or embezzlement of money belonging to the customer, reputation of the bank would be tarnished. Public would lose confidence in the bank. Therefore, the punishment does not warrant any interference. The Enquiry Officer had taken into account all the materials on record, and the enquiry was fair and proper. In the event of this Tribunal coming to the conclusion that the enquiry is not fair and proper an

opportunity may be given to the respondent to prove the charges against T. M. Periaswamy by letting in additional/fresh evidence. The allegation that the Branch Manager also carried prejudice against the charge sheeted employee as he belonged to the petitioner-union is false. The claim may be dismissed.

7. The issues that arise for consideration in this Industrial dispute are :

1. Whether the enquiry against the employee T. M. Periaswamy was fair and just ?
2. Whether the charges against the said employee Periaswamy have been proved ?
3. Whether the punishment imposed upon the employee is disproportionate ?

8. Issues 1 to 3.—The employee concerned in this Industrial Dispute Shri T. M. Periaswamy was working as Sub-staff in the respondent—bank's branch at Rasipuram. The charge against him is that on 18-2-1984, he took a withdrawal slip for Rs. 4,000 on the Savings Bank A/c. of Shri Kuppan to the Branch Manager (MW1 before the Enquiry Officer) and requested him to pass it stating that the account holder Kuppan is standing out at the counter and is very well known to him but had not brought the pass book, whereas Kuppan denied that he came to the bank, on that day to withdraw any amount. The next charge is that the employee T. M. Periaswamy issued token 285 against this withdrawal slip for encashment, which was not at all his duty. The 3rd charge against the employee is that on 18-2-1984 when the Saving Bank Passing Officer Shri S. Jayakumar called Shri Kuppan by name while passing the withdrawal slip, since it is not accompanied by the pass book, the delinquent employee T. M. Periaswamy intervened and informed Jayakumar that Kuppan was sitting inside Manager's room, which is not true. According to the respondent-management the employee made misrepresentations leading to wilful damage or attempt to cause damage to the property of the bank or its customers, and had done acts prejudicial to the interest of the bank likely to involve the bank in serious loss. He is alleged to have acted in breach of the rules of business. The workman is alleged to have committed misconducts as per Para 19(5)(d), 19(5)(i) and 19(7)(d) of Bipartite Settlement dated 19-10-1966. Though the Show Cause Notice was issued to the workman on 14-7-1984 (Ex. M. 5) he did not send any reply. Then the charge sheet dated 29-9-1984 under Ex. M.6 was issued to him for which also no explanation was given by the workman. But, in the enquiry, the employee took part and was defended by a defence representative. The Enquiry Officer gave his finding Ex. M.8 dated 16-4-1985, finding him guilty of all the charges. To the second show cause notice dated 29-7-1985 (Ex. M.9), the defence representative has given a reply Ex. M.10 dated 17-8-1985. The Disciplinary Authority dismissed him from service under Ex. M.11 dated 3-9-1985. The appeal preferred by the employee under Ex. M.12 was also rejected under Ex. M.13.

9. I will first deal with the question whether the charges against the employee have been proved. MW1 who was the branch manager of the concerned

branch at the relevant time deposed in his evidence that on 3-4-1984 Kuppan alongwith C. Krishnan met him and informed him that a sum of Rs. 4,000 has been debited wrongly in his S.B. Account and that he found it out only after he remitted Rs. 2,980 on 24-3-1984. He also stated that Kuppan informed him since could not read and write, he (Kuppan) had shown the pass book to his son, and then only came to know about this withdrawal of Rs. 4,000 MW1 also stated that Kuppan told him that he did not come to bank on 18-2-1984 and wanted the bank to reimburse the sum of Rs. 4,000. MW1 also stated that Kuppan gave the complaint with regard to this matter, which is now marked as Ex. M.2 and which was marked as Ex. M.E.3 in the domestic enquiry. MW1 further stated that on 18-2-1984, the employee Periaswamy brought the pay order (Ex. M.1) and requested him to initial the pay order as it was not accompanied by the pass book, that when he (MW1) asked him whether he knew the party, Periaswamy replied that the party was at the counter and as he knew him very well, the pay order may be passed. MW1 stated that accordingly he endorsed the word "PASS", initialled it, and asked him to get it passed for payment by Jayakumar after verifying the signature with the specimen. Of course, he stated that he did not know whether Kuppan had come on that day. He also stated that it is Periaswamy who issued the token and has also made the entry regarding the same. It was through the Branch Manager (MW1) that the complaint given by Kuppan was marked as Ex. M.E.3. In cross-examination, the evidence of MW1, the Branch Manager on this aspect was not at all questioned by the employee. The question that was asked of the branch manager (MW1) was as to whether no prejudice will be caused to the bank by the sub-staff issuing the token. He had not even suggested that he did not take the pay order to the Manager, or that he did not request the Branch Manager to pass it or that he did not say that he knew Kuppan and that he was standing at the counter. Therefore, it is clear that the evidence of MW1 with regard to the first charges stands uncontroverted, and there is no reason to reject the same. Although, it is stated that Branch Manager was also biased against Periaswamy, there was no suggestion to that effect also to the Branch Manager (MW1). There is also no proof at all for the same. So far, as the second charge is concerned, as pointed out already, here again the evidence of MW1 stands uncontroverted and has to be accepted.

10. The 3rd charge is that on 18-2-1984 when Jayakumar, the Savings Bank Passing Officer called Kuppan by name while passing the pay order, the employee Periaswamy intervened and stated that Kuppan was sitting in the Manager's room and that the said statement is not true. We have the evidence of Jayakumar who was examined as MW6 before the Enquiry Officer. Jayakumar stated in his evidence that it was he who passed this pay order (Ex. M. 1), that he called Kuppan by name, that Periaswamy informed that Kuppan was in Manager's room and pointed out the pass instructions made on the top of the pay order by the Manager. Jayakumar stated that he passed the above instrument presuming that Kuppan was in the Manager's room. Jayakumar had also sent a letter to Zonal Manager of the respondent-Bank on 2241 GI/94—20

12-4-84 under the original of Ex. M. 4 wherein also he has mentioned about these facts. No question was put to him by the employee in cross-examination. Therefore, this evidence of Jayakumar (MW6 before the Enquiry Officer) also stands uncontroverted and has to be accepted. Kuppan himself was examined as MW4 before the Enquiry Officer. He stated that on 18-2-84, he was not in station and had gone to Sendhamangalam, that he cameback only at 3.00 p.m. on that day, that it was a saturday, that he had not given any cheque to anybody, and that he had never withdrawn any money except himself coming in person, and without the pass book. He also stated that he met the Manager and also had given a written complaint. He was also not cross-examined by the defence. No question whatsoever was put to him. Of course, it is contended on behalf of the workman that Kuppan had not mentioned anything about the complaint Ex. M. 2 dated 3-4-84, and therefore, no reliance can be placed upon this complaint at all. It was also contended that the enquiry officer was not right in relying upon it. But the Branch Manager, MW1 to whom this complaint was given by Kuppan had spoken to the fact that this complaint was given by Kuppan so it was introduced in evidence before the Enquiry Officer as an exhibit. No question was put with regard to the same to MW1 stating that this complaint was not given by Kuppan. When Kuppan was examined before the Enquiry Officer as MW4 he stated that he had given a written complaint to Manager. Of course, he was not specifically asked to identify his complaint. But, it does not mean that he had not given complaint. No question was also put to him with regard to the complaint and no suggestion was made to him that he had not given such complaint. Therefore, this contention that this complaint ought not to have been relied upon by the Enquiry Officer cannot at all be accepted. MW5 Periaswamy, the son of Kuppan stated that on 27-3-84 he came to the bank, that the Branch Manager was on leave, and that he complained to the incharge Manager about this fraudulent withdrawal of Rs. 4,000.

11. So, we find that the evidence of the above witness on material points has not even been questioned in cross-examination by the defence; and without doing so, the contention of the employee that the evidence of these witnesses should have been corroborated as to the facts stated by them cannot at all be accepted.

12. The learned counsel for the petitioner contended that the fact that the pay order Ex. M. 1 was passed without any question shows that it must have been accompanied by the pass book, and that the 'Register for payment of Pay Orders which are not accompanied by pass book' has also not been produced by the bank, and if that register had been produced, it would have easily proved that this Pay order for Rs. 4,000 was or was not accompanied by the pass book. The petitioner wants to make it appear that there was no necessity at all for the workman to make such representations either to the Manager or the Passing Officer. Because, the evidence on the side of the Management shows that the Branch Manager has to pass only those pay orders which are not accompanied by pass book, and otherwise it was not necessary for him to pass the pay

orders. That is why the petitioner contends that the pay order was accompanied by the pass book. But no such suggestion was made either to the Passing Officer (Jayakumar) (MW6) or the Branch Manager (MW1). So, this contention cannot be accepted. The contention that the 'register for the payment of pay orders not accompanied by pass book' has not been produced also cannot be availed of by the petitioner, because, the petitioner did not make a request for production of such a document and therefore, it is not necessary for the respondent-bank to produce it, especially in view of the fact that the petitioner had not questioned the evidence on the side of the Management that this pay order did not accompany the pass book. Therefore, this contention of the petitioner cannot also be accepted. Of course, the Enquiry Officer has observed that the defence has not made any attempt to prove that the pay order was accompanied with the pass book. The petitioner contends that it is for the Management to prove that the pay order was not accompanied the pass book, and this observation of the Enquiry Officer shows is bias. Such a contention cannot be accepted. I have already pointed out that MW1 stated in his evidence that the employee Periaswamy requested him to initial the pay order as it was not accompanied by the pass book. This aspect of the evidence was not questioned by the employee in cross-examination. Jayakumar (MW6 before the Enquiry Officer) stated in his evidence that the pass book did not accompany the Pay Order. His evidence in this respect was also not questioned by the workman. Therefore, in the face of the evidence of these 2 persons, the Enquiry Officer must have observed that the petitioner had not proved the contrary. Therefore, it cannot be stated that he was prejudiced.

13. It was contended on behalf of the petitioner that the cashier who had made the payment for the pay order Ex. M. 1 was not examined to prove that, and if he had been examined, it would have been established as to who received the payment. But, the charge against the workman—periaswamy is not that he received the Money under Ex. M. 1 and misappropriated it. The charge against him is that he made misrepresentations and had the pay order passed by the Manager and the Passing Officer Jayakumar, and that he had also issued a token for the payment, which was not his duty at all. If these charges are proved and if Kuppan had not come to receive the amount, then the result will be that it is workman T. M. Periaswamy who was benefitted by this misconduct and withdrawal of the amount. So, when the charge is not that the workman Periaswamy misappropriated the amount, it is not necessary to examine the cashier to prove that the payment was to the employee Periaswamy. The misrepresentations themselves are sufficient to constitute the misconduct and such misrepresentations are acts which are prejudicial to the interest of the bank and are likely to involve the bank in loss. In fact had not the sum of Rs. 4,000 been remitted by the workman into the account of Kuppan after the Show cause notice, as is evident from Ex. M. 14, the bank would have sustained the loss. Therefore, this contention of the petitioner cannot be accepted. One another fact which also goes to prove the case of the respondent is that the workman—Periaswamy had remitted the sum of

Rs. 4,000 into the account of Kuppan. There was no necessity for him to do so, if he is not in anyway concerned with it. But, the learned counsel for the petitioner contends that the mere fact that the amount was remitted into the account of Kuppan will not indicate that the workman is guilty of misconduct. The petitioner relied upon the decision in *ALLAHABAD BANK Vs. P. K. MUKHERJI & OTHERS* (1993 1-LLJ p. 390). But we find that mere remittance of this amount by workman into the account of Kuppan is not the only point which is urged to prove that he had committed the misconduct. As pointed out already, the workman had not given any explanation to the Show Cause Notice and to the charge memo. There is also the uncontroverted evidence of the witnesses examined on the side of the Management on material particulars. The workman himself did not come into the box to deny the charges. If we take these circumstances pointed out already alongwith fact that he had remitted the sum of Rs. 4,000 into the account of Kuppan, it will be clear that the workman Periaswamy had committed the misconduct as alleged. Therefore, taking into consideration all these facts, I find that the charges against the workman Periaswamy have been proved.

14. The next question is whether the enquiry was just and fair. The learned counsel for the petitioner pointed out that certain leading questions were put to the witnesses and therefore the enquiry is vitiated. But in the decision in *HINDUSTAN LEVER LTD. Vs. PRESIDING OFFICER LABOUR COURT* (1970 2-MLJ p 473) it was held that the Enquiry Officer may put questions to witness which may be in the nature of cross-examination but some of the questions may appear to be leading ones, and that these matters by themselves do not directly conclude the issue whether the principles of natural justice have been violated. Therefore, we have to find whether the workman has been prejudiced by these questions. A question was put to MW2 as follows:

Q: Did Mr. Kuppan represent to you at any time during your tenure of the Office about his non-appearance in the branch on 18-2-84 and of withdrawing Rs. 4,000 in his account?

Witness answered as "Yes, he re-presented".

Ofcourse, the question suggests that he did not appear on 18-2-84. Another question asked to this witness was as follows:

Q: Did he attribute any reasons for non-appearance?

The reply given was "No reasons".

The following question was put to MW 5.

#### Matter in Regional Language

Ofcourse this question is also in the leading form. But, from the lengthy answer given by the witness, it can be seen that it is not as if only by putting such leading question, the witness is able to give the answer. He had mentioned in detail as to what happened on

27-3-84. These questions and answers do not relate to the incidents which formed the basis for the charge i.e. the incidents that happened on 18-2-84, but only certain things happened later and as to the conduct of the parties subsequent to the incident. Therefore, I find that these leading questions have not prejudiced the workman. Further, I have already pointed out that when MWs 1, 4 and 6 viz., Branch Manager, Kuppan and Jayakumar deposed about the specific acts of misrepresentations and about the fact that Kuppan did not come to the bank on 18-2-84, no questions at all were put to them denying it. Therefore, I find that the contention of the workmen that in view of the leading questions, the enquiry is vitiated cannot be accepted.

15. One other point raised by the petitioner is that in the second show cause notice Ex. M. 9, dated 29-7-85, the Disciplinary Authority has stated that the delinquent had indulged in these conducts only to benefit himself with the sum of Rs. 4,000, he considers that the appropriate punishment for gross misconduct will be dismissal from service and so this certainly shows that the workman has been punished for some thing with which he has not been charged, and that he has not been punished for the misconduct for which he was tried. The relevant portion in Ex. M. 9 is as follows :

"As the above are reprehensible conduct and you indulged in these conducts only to benefit yourself with the sum of Rs. 4,000, I consider that the appropriate punishment for gross misconduct will have to be dismissal without notice as per Para 19.6.(a) of the Bipartite Settlement dated 19-10-1966. In respect of the offence committed by you under minor misconduct as per 19.7(d) I impose the punishment of censure as per 19.8(a) of the Bipartite Settlement."

16. The learned counsel for the petitioner also relied upon the decision in Allahabad Bank Vs. P. K. Mukherji and Others (1933 I-LLJ P 390) in this connection and contended that the Disciplinary Authority has not applied its mind but has passed the order of dismissal on extraneous and irrelevant grounds. But, I find that the Disciplinary Authority has in the preceding portions of the portion extracted above has also stated in Ex. M. 9 that the workman concerned is guilty of the gross misconduct by the misleading presentation of the pay order and causing wilful damage to the property of the customer, and by misrepresentation to Jayakumar (Passing Officer) when he called Kuppan by name saying that Kuppan was in the Manager's room, and that he had acted in a manner prejudicial to the interests of the bank. He has also stated that he had committed minor misconduct of issuing the token which was not his duty at all. It is only after saying so, that the Disciplinary Authority had stated that he has indulged in this reprehensible conduct only to benefit himself with the sum of Rs. 4,000. As pointed out already when Kuppan had not received the amount, naturally it would follow that the employee Periaswamy is benefitted by this withdrawal. But, there was no charge that he misappropriated the money and therefore, the observation of

the Disciplinary Authority that as the delinquent had indulged in this conduct only to benefit himself with the sum of Rs. 4,000 he considers the appropriate punishment to be dismissal cannot be proper. But, at the same time, it cannot be stated that the delinquent was punished for the misappropriation of Rs. 4,000. I have already pointed out that the Disciplinary Authority found him guilty of all the charges and only observed that the delinquent indulged in these misconducts to benefit him. Therefore, it cannot be stated that the delinquent was punished for a misconduct with which he was not charged, and that he was not punished for a misconduct for which he was tried. The Disciplinary Authority had made this observation only while proposing the punishment. Therefore, it cannot be stated that the enquiry is vitiated. This Court certainly is entitled to consider whether the punishment of dismissal imposed is justified even disregarding these observations of the Disciplinary Authority in as much as the charges against the delinquent have been proved. The charges that he misrepresented to the Manager that he knew Kuppan and that Kuppan was waiting at the Counter, and got the pay order passed without the pass book, and that he misrepresented to the Passing Officer, Jayakumar that Kuppan was sitting in the Manager's room are serious. As pointed out already, these acts cause damage to the property of the customer and also are against the interests of the bank. Therefore, when the delinquent had indulged in such misconducts and when the constituent of the bank had come and reported about the improper debit of Rs. 4,000, it is clear that the confidence of the constituent in the respondent-bank will be shaken and will be at stake, apart from exposing the bank to the risk of financial loss. Therefore, even if the charges that are proved against the delinquent, the punishment of dismissal is justified and it cannot be stated that this in any way vitiates the enquiry as such.

17. One other contention that was put forward by the petitioner is that the delinquent was not given a personal hearing. But, I find that the Second Show Cause Notice Ex. M. 9 specifically mentions that if he requires a personal hearing regarding the nature of the proposed punishment, he may write to the Disciplinary Authority so that a convenient date and time could be fixed. In his reply, Ex. M. 10, the defence representative has not asked for a personal hearing. There is also no other evidence to show that the delinquent asked for a personal hearing. Therefore, this contention of the petitioner also cannot be accepted.

18. The next contention of the petitioner is that the past record of the delinquent was not taken into consideration while imposing the punishment. As per the petitioner Clauses 19.10 and 12(C) of the Bipartite Settlement, the respondent bank is bound to consider the past record before imposing the punishment. But, the petitioner has not been able to show that there are extenuating circumstances that could be ascertained from his record of past service. As the learned counsel for the respondent rightly contended, if the charges are trivial, and if the delinquent has to be punished, the record of his past conduct will be of use in deciding as to what could be the punishment. But, when the delinquent had



indulged in gross misconduct which will certainly affect the very confidence of the constituents of the bank, and which will adversely affect the interests of the bank, the record of his past conduct will have no influence over the punishment to be imposed. The learned counsel for the respondent relied upon the decision in *A. S. Kasinathan Vs. M. D. L. B.* (1983 II-LLJ p 374). The workman concerned in the dispute in the case was dismissed for having incited workers to go on an illegal strike. While, considering the question whether the order of dismissal passed against the workman is vitiated for the reason that the past record of service had not been taken into consideration, the Hon'ble High Court of Madras held that 'where a worker is guilty of a serious offence inviting dismissal, very little will turn upon the previous record of the worker, and that the fact that a person had a previous good record could hardly weigh with the Management when it finds that the worker by inciting illegal strike was paralyzing the working of the industry and in such an instance, the Management proceeded to dismiss the person, the non-consideration of the previous record would not vitiate the final order. In the decision in 1983 II-LLJ p 364, referred to above, the decision in *Solar Works Vs. Their Workmen* (1968 I-LLJ p 765) was relied upon, wherein it was held as follows :

"Where the misconduct per se was sufficient to justify the dismissal because of its serious nature, there is no scope at all for entertaining any apprehension that the Management failed to give weight to the Provision of Standing Order 16(d) regarding past good conduct of the workers in fixing the quantum of punishment or that if it had done so, a different result would have followed".

19. Therefore, in these circumstances, I find that when the misconduct indulged in by the delinquent-employee is serious, the punishment of dismissal imposed upon him is justified and whatever be his record of past conduct, it will be of no avail to the workman.

20. Therefore, taking into consideration all these circumstances, I find that the dismissal of Shri T. M. Periaswamy, Sub-Staff from service is justified and that he is not entitled to any relief.

21. In the result, I hold that the dismissal of Shri T. M. Periaswamy, Sub-Staff from service with effect from 3-9-85 is justified, and that he is not entitled to any relief. Award is passed accordingly. No costs.

Dated, this the 5th day of May, 1994.

K. SAMPATH KUMARAN, Industrial Tribunal  
WITNESSES EXAMINED

For both sides : None

DOCUMENTS MARKED

For Workman :

Ex. W-1|29-7-85 : Second Show Cause Notice issued to Thiru T. M. Periaswamy (Xerox copy).

Ex. W-2|13-1-86 : Letter from the Petitioner-Union to the Regional Labour Commissioner (Central), Madras-6 (Xerox copy).

Ex. W-3|11-4-86 : Letter from the Management to the Conciliation Officer (Xerox copy).

Ex. W-4|7-8-86 : Conciliation Failure Report (Xerox copy).

Ex. W-5|11-5-87 : Order of reference (Xerox copy).

For Management :

Ex. M. 18-2-84 : Withdrawal slip for Rs. 4,000.

Ex. M. 2|3-4-84 : Letter from Thiru P. Kuppan to the Management Bank (Xerox copy).

Ex. M. 3|7-4-84 : Letter from the Manager, Indian Bank, Rasipuram to Zonal Manager, Coimbatore with regard to complaint preferred by Thiru P. Kuppan (Xerox copy).

Ex. M. 4|12-4-84 : Letter from S. Jayakumar, the Officer, Indian Bank, Rasipuram to the Zonal Manager, Coimbatore (Xerox copy).

Ex. M. 5|14-7-84 : Show Cause Notice issued to Thiru T. M. Periaswamy (Xerox copy).

Ex. M. 6|29-9-84 : Charge sheet issued to Thiru T. M. Periaswamy (Xerox copy).

Ex. M. 7 : Proceedings of the Enquiry Officer (Xerox copy).

Ex. M. 8|16-4-85 : Findings of the Enquiry Officer (Xerox copy).

Ex. M. 9|29-7-85 : Second Show Cause Notice issued to Thiru T. M. Periaswamy (Xerox copy).

Ex. M. 10|17-8-85 : Reply by Thiru E. Arunachalam, Defence Representative, to the Show Cause Notice (Xerox copy).

Ex. M. 11|3-9-85 : Dismissal order (Xerox copy).

Ex. M. 12|17-10-85 : Appeal preferred against his dismissal order (Xerox copy).

Ex. M. 13|18-12-85 : Order rejecting the appeal (Xerox copy).

Ex. M. 14|16-7-84 : Letter from the Management-Bank informing about the remittance of Rs. 4,000 by Thiru T. M. Periaswamy (Xerox copy).

K. SAMPATH KUMARAN, Industrial Tribunal

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

का.आ. 2809.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, मै. भारत कोकिंग कोल लिमि. के भासगोरा क्षेत्र की सिमलाबहल कालियरी के प्रबन्धन के संबंध में निर्यातकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (सं. I), धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-9-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एन-20012/49/90-आई आर (कोल-I)]  
वी.के. शर्मा, डेस्क अधिकारी



New Delhi, the 22nd November, 1994

S.O. 2809.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal. (No. 1), Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Simlabahal Colliery under Bhalgora Area of M/s. BCCL and their workmen, which was received by the Central Government on 21-9-94.

[No. L-20012/49.90-IR(Coal-I)]

V. K. SHARMA, Desk Officer

#### ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT DHANBAD

#### PRESENT :

— Shri P. K. Sinha, Presiding Officer.

In the matter of an industrial dispute under Section 10 (1)(d) of the I.D. Act, 1947.

Reference No. 211 of 1990

#### PARTIES :

Employers in relation to the management of Simlabahal Colliery under Bhalgora Area of M/s. B.C.C.L. ;

AND

Their workmen.

#### APPEARANCES :

On behalf of the workmen : Shri S. P. Singh, General Secretary, Khan Mazdoor Congress.

On behalf of the employers : Shri S. N. Sinha, Advocate.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dated, Dhanbad, the 14th Sept. '94.

#### AWARD

The Govt. of India, in the Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-20012/49/90-IR. (Coal-I), dated the 17th September, 1990.

#### THE SCHEDULE

“Whether the action of the management of Simlabahal Colliery under Bhalgora Area of M/s. BCCL in punishing Shri Bhola Singha, Winding Engine Operator vide letter No. SPC/BCCL/PD/89/93 dated 5/6-1-89 is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?”

The sum total of the allegations against the workman Bhola Singh, the Winding Engine Operator at Simlabahal Colliery is that on 10-12-88 when the

concerned workman was on duty in the second shift starting from 4 P.M., due to his negligence at about 10.30 P.M. there was over winding, damaging the brake of the Winding Engine, its cable and its cage and also resulting in loss of production in the second shift as also on the following third shift.

3. The simple defence of the workman, as coming out from his explanation to the chargesheet as well from the W.S. filed on behalf of the sponsoring union, is that over winding was not caused by any negligence on the part of the workman but on account of mechanical failure. According to the W.S., over winding takes place for two reasons, viz., failure of brake and supply of bad engine oil. It has also been averred that there was clear instruction from the Mines Deptt. to use automatic brake which instruction was overlooked by the management as a result of which the Operator of the Winding engine was forced to manage the work through the hand brake, hence he cannot be held responsible for over winding. It was also alleged that besides this, there was ill maintenance of brake and bad quality of engine oil was supplied.

4. In his explanation to the chargesheet (Ext. W-2 = Ext. M-2) the workman had maintained that the overwinding was the result of mechanical failure of the devices which did not work properly on account of the defect that had developed. He also submitted that he already had reported that vacuum brake was not working properly. The system of automatic stoppage of steam also did not work, nor vacuum brake worked at the moment of the overwinding. According to him, oil supplied for the machine was of light quality which the workman had shown to the Agent. The quality of oil also caused the failure of the system.

5. His explanation was not found satisfactory and a domestic enquiry was held in which the Enquiry Officer, in course of his report, found the proceedee guilty only to some extent and opined that the occurrence did not take place entirely because of the carelessness of the workman. He also found that on the date the occurrence had taken place Shri Bhola Singh had gone to the management with complaint relating to the Engine. The Enquiry Officer found that only fault of Bhola Singh was that if there was any defect in the engine, he should have stopped working.

6. It appears that this report and the materials on the record were considered by the management which, by its letter dt. 5/6-1-89 (Ext. M-3) addressed to Shri Bhola Singh informed him that the charges had been established beyond doubt which warranted his dismissal, but since the workman had begged apology and had assured not to commit such offence in future, the management punished him by reverting him back to Cat. III wages with the initial basic and to other work than the work of Winding Engine Operator. By way of punishment the management also confirmed the period of his suspension as punishment hence denied him wages for the period from 12-12-88 to 22-12-88.

7. The complaint of the sponsoring union is not only that the offence was not proved in the domestic enquiry but even if proved, the workman was punished heavily on three counts, viz., reduction in rank, reduction

tion in wages, and the period of suspension being also treated as punishment.

8. The points for consideration in this reference are firstly, as to whether or not the management by its evidence had proved its charges against the workman and, if so, whether the punishment imposed by the management was just and proper.

9. From perusal of the record, including the W.S. of the management it will appear that, subsequently, by office order dt. 22/25-6-90 (Ext. M-4) the management had reviewed the question of demotion of the workman and ordered that the workman be against put in Cat. IV with effect from 12-6-90 on the same pay he was getting earlier, with the date of his increment remaining the same.

10. From the record, exts, and the W.S. it will appear that the workman on being demoted vide Ext. W-3=M-3 had filed a protest petition against the punishment imposed (Ext. W-4) again claiming that the occurrence had taken place because of the mechanical failure. From Ext. W-6 it will appear that the workman submitted second protest petition dt. 13-1-89 against the punishment imposed upon him and informing the management his inability to accept the punishment, also informing that he was left with no other way but to raise an industrial dispute. The materials on record would also show, about which there is no dispute, that the workman did not join on his demoted post in the beginning, but he joined on that demoted post on 3-5-89. As already stated, with effect from 12-6-90 the workman was restored to his original Cat. IV.

11. Now coming to the domestic enquiry, the charges against the workman were two fold. First was that because of his carelessness, overwinding occurred for which the brake of winding engine, cage etc. were damaged. The second charge was that because of this overwinding the production of the company suffered in the second shift as well in the third shift. Admittedly, the workman was on duty in the second shift and charge on this point means that the production in the second shift had suffered with effect from 10.30 P.M. when the overwinding occurred.

12. The point now is to see as to whether or not the management by its evidence has proved that those things occurred because of the carelessness of the workman.

13. From the record it will appear that on behalf of the management only the management's representative, Shri S. D. Singh, an Officer of the company, gave his statement. From the record of enquiry it will appear that the management's representative was asked to present his side of the case in which he alleged that overwinding had occurred at about 10. 30 P. M. on that day though in the first shift there was no complain in the Winder. He submitted that Shri Bhola Singh was on duty since 4 P.M. and had there been any defect in the engine, Bhola Singh would have informed the management. He also submitted that after taking over charge, Bhola

Singh did not complain about any defect in the engine and he continued working on the cage till 10. 30 P. M. during which period he brought on the surface the load (of coat) and also brought on the surface the workman of the first shift as well sent underground the workmen of the second shift. It was his argument that if there was any defect in the winder then the workman should have informed, and stopped working.

14. In course of cross-examination Bhola Singh gave his statement claiming that on that very day at about 8 P. M. he had complained to the Agent that the oil supplied for the engine was thin which could cause damage. According to him, the Agent told him to remain on the next day. The enquiry officer has not noted the reaction of the management's representative on the aforesaid assertion of the workman.

15. It appears that thereafter the management did not adduce any more evidence and Bhola Singh was asked to place his case who struck to what he had said earlier. On question by the management's representative Bhola Singh said that the defective oil was being supplied since long but on his various complaints good quality oil in the quantity of 10 to 15 Litres was supplied by purchasing the same from the market which could be seen in the register of the Godown incharge. In cross-examination this witness said as to what were the duties of the winding engine operator. The workman also said that the signal system was not present in the case he operated. The management representative said that the signal system had gone out of order because of carelessness of the workman which was not repaired till the date of evidence, which was recorded on 27-12-88. But the workman disputed this assertion stating that the signal system was out of order since long. In reply to another question the workman said that after taking charge on that day he had checked the engine, and had started it after finding the same to be alright.

16. At the end, the enquiry officer noted that after argument by both the sides Bhola Singh said if any mistake was committed by him on that day, he apologised for that and promised not to be careless in future.

17. It is this statement of the workman which has been pounced upon by the learned counsel for the management who submitted in course of argument that this was an admission on the charges against the workman, therefore, the management had nothing more to prove.

18. But this argument is apparently misconceived. The workman appears to have qualified his apology with the percent "if" any mistake was committed by him on that day. Therefore, the apology was subject to the condition that any mistake was established to have been committed by the workman. Such conditional apologies are not uncommon coming from a worker who at stage did not know as to what the Enquiry Officer would find proved.

19. That brings us back to the question as to whether or not by its evidence the management had proved its charges.

20. Evidently, the management had miserably failed to prove any of the charges. The management's representative did not say that he was himself present at the time of the accident or that he was a technical hand to understand the complexity of the charge. From this record it will appear that the management's representative was a Personnel Officer.

21. Even then in his statement the management's representative did not say that there was any loss of production because of the overwinding or that the overwinding was proved to have been caused by the negligence of the workman and that it was not a result of mechanical failure. There is no categorical statement on this score even by the management's representative who hardly was qualified to be a competent witness to prove the charges. He did not say even a word about the damage caused to the brake of the engine or to any of the articles mentioned in the chargesheet. From his evidence it will appear that he had tried to prove the charges with the help of argument and conjectures.

22. There is nothing on the record to show that overwinding incident was caused on account of any negligence on the part of the concerned workman. Simply because the incident was caused while the workman was on duty, would not prove ipso facto that it was the carelessness of the workman which caused the incident. Evidently the Engine had performed perfectly for about 6.30 hours in the second shift without any accident. The workman has claimed during cross-examination that before starting the engine he had checked the same. Therefore, if everything was alright when the workman had started working and something occurred out of the way during the period of his duty, it had to be proved by cogent evidence that what had happened was the result of the carelessness of the workman.

23. Therefore, I don't find that there is any evidence on the record to prove the carelessness on the part of the workman. In such circumstances, if any damage was caused of the machine or there was any loss of production the workman could not be held responsible for that. But as already seen, the management did not think it fit to adduce any evidence showing any of the alleged damage or the alleged loss in production.

24. Under such circumstances, if any punishment was awarded to the workman by the management, that cannot be sustained. Therefore, I hold that the punishment of demotion or the punishment of suspension for 10 days was unjust and improper.

25. Shri Sinha, the learned counsel for the management had pointed out that for quite sometime after the punishment the workman had not joined on the demoted post, i.e., upto 2-5-89. He argued that therefore the workman cannot claim the relief of wages that period.

26. I do not agree with this argument. Since nothing was proved in the domestic enquiry against the concerned workman, the punishment of demo-

tion was illegal and an illegal order of the management cannot force a workman to forsake something to which he was legally entitled. Since demotion was not legal, his refusal to join on that post had legal sanctity. It has not been proved that prior to his joining on his demoted post on 3-5-89 he was offered by the management to provide him work in Cat. IV post. In this view of the matter the workman would be entitled to the wages which he was getting and to which he would have been entitled to had he not been suspended and, subsequently demoted.

27. Following, therefore, is the Award :—

"The action of the management of Simlabahal Colliery under Bhalgora Area of M/s. BCCL in punishing Shri Bhola Singh, Winding Engine Operator vide letter No. SBC/BCCL/PD/89/93 dated 5/6-1-89 was not justified. The workman was entitled to continue on Cat. IV post although the period he was not allowed to continue by the management because of his suspension and subsequent demotion."

The result is that the management is directed to pay him wages of Cat. IV which the workman was getting and to which he otherwise would have been entitled had he not been suspended and subsequently demoted to Cat. III post. While computing this amount, if any amount by way of wages and by way of other benefits have been paid to the workman for the aforesaid period, that amount would be adjusted.

28. Under the circumstances, there would be no order as to the costs.

P. K. SINHA, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

का.प्रा. 2810.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस.डी.ओ. टेलीकॉम, करीमनगर के प्रबन्धनत्व के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-9-94 को प्राप्त हुआ था।

संख्या एल-40012/233/91-आईआर (डीवी)

के.वी. बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 22nd September, 1994

S.O. 2810.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of S.D.O. Telecom, Karimnagar and their workmen, which was received by the Central Government on 21-9-94

[L-40012/233/91-IR(DV)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

## ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT  
HYDERABAD

## PRESENT :—

Sri Y. Venkatachalam, M.A..B.L., Industrial  
Tribunal-I.

Dated : 12th day of September, 1994

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 6 OF 1994

## BETWEEN :

Sri B. Venugopal S/o Rangachary,  
Mandal, Manakondur (V) (C/o  
Venkateswara Temple, Manakondur,  
Dist. Karimnagar-505 469 ... PETITIONER

## AND

The Sub-Divisional Officer,  
Telecom, Karimnagar 505 001. ...

## RESPONDENT

## APPEARANCES :—

M/s. C. Suryanarayana & P. Bhaskar, Advocates  
for the Petitioner.

Sri P. Damodar Reddy, Advocate for the Res-  
pondent.

## AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. L-40012/233/91-IR(DU), dt. 20-1-1993 referred the following dispute under Section 10(1)(d)(2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the Management of S.D.O., Telecom, Karimnagar and their workmen to this Tribunal for adjudication :

"Whether the management of Sub-Divisional Officer, Telecom, Karimnagar is justified in terminating the services of Sri B. Venugopal, Ex-Casual Mazdoor? If not, what relief he is entitled to?"

This reference is registered as Industrial Dispute No. 6 of 1993 and notices were issued to both the parties.

2. The brief facts of the claim statement filed by the Petitioner read as follows:—The Petitioner submits that he is a physically handicapped person as he is totally blind in the left eye. Three per cent of the vacancies of posts are reserved for physically handicapped persons. The petitioner was initially recruited in March 1985 as a Ticket Boy on casual basis. Later, he was sponsored by the Employment Exchange, Karimnagar. He was engaged as Ticket Boy during 1-4-1985 to 31-5-1985 and later as a Casual Mazdoor to assist the Technician in the Telephone Exchange till the end of June, 1986. Thus he was engaged continuously for a total of 365 days, from 1-4-1985 to 30-6-1986. During the period of one year preceding 30-6-86 he was put in a total of 259 days of continuous service. Thereafter the petitioner fell sick due to abdominal TB and could not attend to his duties as he was under treatment of Dr. K. Shivaji Civil Surgeon Specialist, District Headquar-

ters, Hospital, Karimnagar and was advised complete rest. He was under treatment from 1-8-1986 to 21-3-1988 and submitted fitness certificate on 22-3-1988 to the Sub-Divisional Officer Phones, Karimnagar with a request to take him back to duty by condoning his absence due to ill-health. Instead, he was taken back to work w.e.f. 5-6-1988 in the jurisdiction of the Respondent-employer. After he was taken back to duty w.e.f. 5-6-1988 the Petitioner was employed till 19-10-1988. But his services were abruptly terminated from 20-10-1988 by the Respondent on the untenable grounds that he was recruited after 30-3-1985 and that there was a break in his service during 1-8-1986 to 21-3-1988 even though the petitioner was recruited long before 7-5-1985 the date on which the DG P&T New Delhi circulated orders of Department of Personnel and AR imposing ban on fresh recruitment of Casual workers. He was neither given notice nor paid notice period wages in lieu of notice before his service was terminated. Thus the mandatory provisions of the ID Act has been violated and hence the termination of the petitioners service is retrenchment which is illegal, null and void. Moreover the DG's orders dt. 1-10-84 have also not followed. The Respondent's action in taking back the petitioner to duty after he submitted the fitness certificate establishes that the break in service was condoned. Alternatively, it must be deemed to have been condoned. Moreover the petitioner's absence was after due intimation to the Department about his sickness and the intimation was given immediately after he fell sick but not belatedly. In view of the above circumstance the petitioner prays that this Hon'ble Tribunal may be pleased to declare that his termination is retrenchment and it is illegal and to declare that he is entitled to reinstatement in service with full back wages and continuity of service and for all other benefits which are incidental and consequential to the reinstatement viz., absorption in the Department as Regular Mazdoor or Group 'D' employee according to the petitioner's turn in the seniority list, grant of increments and resultant increases in pay etc. and pending the same for conferment of temporary status. The petitioner prays that this Hon'ble Tribunal may pass Award accordingly.

3. The Respondent has not filed their counter.

4. The point for adjudication is whether the Respondent is justified in terminating the services of Sri B. Venugopal, Ex-Casual mazdoor?

5. No oral or documentary evidence have been adduced by both the parties.

6. The case of the Petitioner workman is that he is a physically handicapped person as he is totally blind in the left eye, the petitioner was initially recruited in March 1985 as a Ticket Boy on casual basis, later he was sponsored by the Employment Exchange, Karimnagar, that he was engaged as Ticket Boy during 1-4-1985 to 31-5-1985 and later as a Casual Mazdoor to assist the Technician in the Telephone Exchange till the end of June 1986, thus he was engaged continuously for a total of 365 days from 1-4-1985 to 30-6-1986, that during the period of one year preceding 30-6-1986 he has put in a

total of 259 days of continuous service, that thereafter the petitioner fell sick due to abdominal TB and could not attend to his duties as he was under treatment of Dr. K. Shivaji, Civil Surgeon Specialist, District Headquarters, Hospital, Karimnagar and was advised complete rest. After he was taken back to duty w.e.f. 5-6-1988 the petitioner was employed till 19-10-1988 but his services were abruptly terminated from 20-10-1988 by the Respondent on the untenable grounds that he was recruited after 30-3-1985 and that there was a break in his service during 1-8-1986 to 21-3-1988, even though the petitioner was recruited long before 7-5-1985 the date on which the DG, P&T New Delhi circulated orders of Department of Personnel & AR imposing ban on fresh recruitment of casual workers. The Petitioner-workman has submitted his written arguments along with some documents in support of its case. A perusal of a document from S.D.O. Telecom, Karimnagar vide letter No. ID/91-92/5, dt. 12-10-1991 wherein the following facts were mentioned as follow :

1. The applicant i.e. the petitioner did not work in Telecom Sub-Division, Karimnagar from 1-4-1985 to 31-5-1985 and from 1-6-1985 to 4-6-1986. That the applicant did not submit any medical certificate to SDO Telecom Karimnagar. That the applicant was taken to work from 5-6-1988 to 19-10-1988 for maintenance work at Mankondun and Gangipalli Exchange and was removed after the work is over. He worked for a period of 126 days. As the engagement is purely of casual nature the applicant has been removed after the cessation of work. As the applicant is not a regular employee, the question of termination of service or of notice does not arise. That no representation letter of the applicant is available in this office. The applicant cannot be taken back to work. So from the above fact it is clear that the Petitioner workman did worked for 126 days only as he was purely engaged on casual nature and he was not a regular employee. It is also pertinent to note that when he was under treatment from 1-8-1986 to 21-3-1988, the petitioner did not submit any medical certificate to S.D.O. Telecom, Karimnagar to substantiate his sickness. So from the above facts and circumstances it is clear that the petitioner workman did not put in 240 days continuous service and that he was engaged only on casual basis and that he is not liable to be reinstated into service and that his termination is not retrenchment and also he is not liable to be absorbed in the Department as Regular Mazdoor or Group 'D' employee.

7. In the result, the Management of Sub-Divisional Officer, Telecom, Karimnagar is justified in terminating the service of Sri B. Venugopal, Ex-Casual Mazdoor and he is not entitled to any relief.

Award passed accordingly.

2241 GI/94—21.

Typed to my dictation, given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 12th day of September, 1994.

Y. VENKATACHALAM, Industrial Tribunal-I

Appendix of Evidence.

NIL

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

को.आ. 2811.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार टेलीकॉम के प्रबन्धन के संबद्ध नियोक्तों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचपट्टे को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-9-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-40012/264/91—आई.आर. (डी.यू.)]

के.बी.बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 22nd September, 1994

S.O. 2811.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Telecom, Nagarkurnool and their workmen, which was received by the Central Government on 21-9-94.

[No. L-40012/264/91-IR (DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer.

# ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT HYDERABAD

PRESENT :

Shri Y. Venkatachalam, M.A., B.L., Industrial Tribunal-I.

Dated : 14th day of September, 1994

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 9 OF 1993.

BETWEEN :

Shri V. Krishnayya, S/o. Shri V. Chinna Ramulu, Tharikal P. O. Kalwakurty-509 324 Mahaboob Nagar Distt.

..PETITIONER

AND

1. The Sub-Divisional Officer, Telecom, Nagarkurnool-509 209 Mahaboob Nagar, Distt.

2. The District Engineer, Telecom, Nagarkurnool-509050 (A.P.) Mahaboob Nagar.

RESPONDENTS

## APPEARANCES :—

M/s. C. Suryanarayana and P. Bhaskar, Advocates for the Petitioner.

Shri P. Damodar Reddy, Advocate for Respondents.

## AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. L-40012/264/91-IR (DU), dated 20-1-1993 referred the following dispute under Section 10 (1) (d) (2-A) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the Management of Telecom, Nagarkurnool and their workmen to this Tribunal for adjudication :

“Whether the action of the management of Sub-Divisional Officer, Telecom, Nagarkurnool is justified in terminating the services of Shri V. Krishnayya w.e.f. 1-11-1989 ? if not, what relief the workman concerned is entitled to ?”

This reference was registered as Industrial Dispute No. 9 of 1993 and notice were issued to both the parties.

2. The brief acts of the claims statement filed by the petitioner workman read as follows :—The Petitioner herein submits that the 1st Respondent initially recruited and employed him as a Casual Mazdoor w.e.f. 1-12-1988. Except in the month of July, 1989 he was continuously till the end of October, 1989. In the month of July, 1989 he was not employed due to cessation of work but not for any reason attributable to the petitioner. During the period between 1-2-1988 and 1-10-1989 he was engaged for a total period of 295 days. But w.e.f. 1-11-1989 the petitioner's services were abruptly terminated by verbal orders of the 1st respondent the ground that he was recruited after 30-3-1985 the date on which the D.G., P & T issued orders prohibiting fresh recruitment of casual mazdoors. In this connection the petitioner submits that the order dt. 30-3-85 as such did not envisage termination of casual mazdoors, but only envisages redeployment of casual mazdoors on other works including those in other neighbouring units. The petitioner therefore, submits that termination of his service is retrenchment which is illegal, null and void and that he is entitled to re-instatement in service atleast against a reserved point as he belongs to a Scheduled Castes, with full back wages, continuity of service and protection of his seniority for all purposes including his absorption in regular establishment according to his turn in the seniority list of casual mazdoors of Mahboobnagar Telecom District and against a reserved point besides being entitled to conferment of temporary status. The petitioner prays that this Hon'ble Tribunal may be pleased to pass the Award accordingly.

3. The brief facts of the counter filed by the Respondent read as follows.—Without prejudice to the contentions it is submitted that the petitioner was engaged for casual works on casual basis, during the period December, 1988 to October, 1989, the petitioner was not recruited by the Department for regular

employment. The petitioner has not worked continuously as alleged by him. That the petitioner was taken on work on casual basis whenever there was work and disengaged when the work was not available. It is therefore submitted that the question of termination of his services etc. does not arise. The petitioner was taken on work temporarily to meet casual nature of work. At no time the services of the petitioner were terminated and as such the question of providing re-employment does not arise. During the period the petitioner was paid on the basis of daily wages prevailing at the time. He was paid the wages for the actual working days and nothing is payable now to him from the respondent department. The petitioner was not recruited or appointed under any statutory rules of the department, the question of granting of temporary status does not arise. The claim of the petitioner is not substantiated in the eye of law. There are no merits in the claim of the petitioner. He is not entitled to the benefits of re-instatement into service, payment of back wages, continuity of service, seniority and other attendant benefits, as per law or on the facts of this case. It is therefore prayed that the Hon'ble Court may be pleased to pass an award holding that the claim of the petitioner is neither legal or valid, and consequently grant no relief to him.

4. The point for adjudication is whether the action of the Respondent is justified in terminating the services of Sri V. Krishnayya w.e.f. 1-11-1989 ?

5. W.W1 was examined on behalf of the Petitioner workman and marked Exs. W1 to W6. No oral or documentary evidence, has been let in by the Respondent.

6. W.W1 is V. Krishnaiah. In brief he deposed that he was initially engaged under S.D.O. Telecom, Nagarkurnool. He was engaged by the Respondent from 1-12-1988 to October, 1989 for a period of 295 days. He was disengaged by the Respondent without assigning any reasons. He was engaged by the Respondent as casual labour. At the time of termination he was not served with any notice. Ex. W1 is the representation made to the Regional Labour Commissioner. Ex. W2 is the xerox copy of working days particulars. Ex. W6 is the xerox copy of para-wise remarks of representation made by the R.L.C.

7. In this case the allegation of the Petitioner workman is that the first Respondent initially recruited and employed him as a casual Mazdoor w.e.f. 1-12-1988 except July 1989 he was continuously employed till October, 1989, that during the period between 1-2-1988 and 1-10-1989 he was engaged for a total of 295 days, that he was terminated by verbal orders on 1-11-1989 on the plea that he was recruited after 30-3-1985 the date on which the D.G., P & T issued orders prohibiting fresh recruitment of casual mazdoors.

8. The contention of the Respondent on the other hand is that the petitioner was engaged for casual workers on casual basis, during the period December 1988 to October, 1989 that the petitioner was not recruited by the Department for regular employment and he did not worked continuously, that whenever there was work he was taken on casual basis and disengaged when the work was not available, thus the question

of termination of his services etc. does not arise, that the petitioner was not recruited or appointed under any statutory rules of the Department and the question of granting of temporary status does not arise.

9. From a perusal of material available on record it is seen that the Petitioner-workman was engaged for casual works on casual basis and he was not recruited by the Department for regular employment. It is seen that whenever the work is available, casual labours are engaged for casual work. Thus I see that there is no termination of services as the work done by the petitioner is of a casual nature. It is pertinent to note that the petitioner was paid on the basis of daily wages and he was paid the wages for the actual working days. There is no documentary evidence to show that the Petitioner was recruited or appointed under any statutory rules of the Department, thus the question of granting of temporary status does not arise. Hence I find that the claim of the petitioner is not sustainable in the eye of law and I find that there are not merits in the claim of the Petitioner and he is not entitled to the benefits of reinstatement into service, payment of back wages, continuity of service etc. Therefore I find that the Respondent was justified in terminating the services of the petitioner workman w.e.f. 1-11-1989.

10. In the result, the action of the Management of Sub-Divisional Officer, Telecom, Nagarkurnool is justified in terminating the services of Sri V. Krishnayya w.e.f. 1-11-1989 and he is not entitled to any relief.

Award passed accordingly.

Typed to my dictation, given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 14<sup>th</sup> day of September, 1994.

Y. VENKATACHALAM, Industrial Tribunal-I

#### Appendix of Evidence :

Witnesses Examined  
for Workmen :

W.W1 V. Krishnaiah

Witnesses Examined  
for Management :

NIL

Documents marked on behalf of Workman :

Ex. W1 Xerox copy of the representation is given to the Regional Labour Commissioner.

Ex. W2 Xerox copy of statement showing the No. of days worked in Respondent-Management.

Ex. W3 Xerox copy of Minutes of the Meeting dt. 15-11-91 between the both parties.

Ex. W4 Xerox copy of Caste Certificate issued by M.R.O. Kalwakurti.

Ex. W5 Xerox copy of Failure Report of Conciliation.

Ex. W6 Xerox copy of parawise remarks submitted by Respondent before the Conciliation Officer.

Documents marked on behalf of Management :

NIL

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

का.प्र. 2812—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार माइक्रोवेव मटेनेन्स, डलहाउस के प्रबन्धन के संबंध निथोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निम्नित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, चंडीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-9-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-40012/183/90—आई.आर. (डी.यू.)]

के.वी.बी. उन्नी, ईस्क अधिकारी

New Delhi, the 22nd September, 1994

S.O. 2812.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Microwave Maintenance, Dalhousie and their workmen, which was received by the Central Government on 20-9-94

[No. L-40012/183/90-IR(DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

#### ANNEXURE

BEFORE SHRI M. S. SULLAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, CHANDIGARH

Case No. I, D. 75/91

Madan Lal Vs. Microwave Maintenance Dalhousie  
For the workman—Shri Veneet Khanna.

For the management—Shri Madan Mohan.

#### AWARD

In the wake of industrial dispute raised by the workman the appropriate government (Central Govt.) vide letter No. L-40012/183/90. IR( D. U.). D2(B) dated 14<sup>th</sup> June 1991 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

“Whether the action of Asstt. Engineer, Microwave Maintenance Dalhousie in terminating the services of Shri Madan Lal son of Shri Bansi Lal w.e.f. 30-11-1987 is justified? If not, what relief he is entitled to?”

2. The brief facts relevant for the disposal of present reference are that Madan Lal workman was appointed as daily wage mazdoor in Microwave Station, Dalhousie on 12<sup>th</sup> March 1987, vide appointment letter dated 11-3-1987. According to the workman, he worked with the respondent from 12-3-1987 to 30-11-1987 when his services were dispensed with, without assigning any reason. The workman preferred the claim to the Asstt. Labour Commissioner (C) Chandigarh, but the respondent has not taken him in service. In all, it has been alleged by the workman that he has completed 240 days of service but his services were terminated without any notice and



without assigning any reason. On the footing of aforesaid grounds, the workman claimed reinstatement in service w.e.f. 12-3-1987, with continuity in service, full backwages and other service benefits.

3. The respondent management contested the claim of the workman and filed written statement inter alia pleading certain preliminary objections of limitation etc. According to the management, the workman was engaged as daily wage mazdoor at the rate of Rs. 13 per day, which was renewed on day to day basis. As the contract came to an end on 30-11-1987, and it was not renewed, the claim of the workman is not maintainable in view of the provisions of Section 200(bb) of the Industrial Disputes Act (hereinafter referred to be the Act). It was alleged by the management, that as persons senior to him had become available for re-employment and they had a statutory right in preference to the applicant U/S 25-H of the Act, the workman had no right to maintain the claim. Even, there was no post or contingent for filling the post of casual workers after 30-11-1987.

4. The case set up by the management is that according to the policy contained in letter A-2/ Vol. IV dated 2-6-1987 of re-employing the already retrenched workers, the replacement was to take effect by 30-6-1987. The petitioner was to be retrenched w.e.f. 30-6-1987 when he had not completed 240 days of service. He continued as daily wage mazdoor as fortuitous arrangement. It will not be out of place to mention here that the management had stoutly denied other allegations of the workman and alleged that the petitioner was engaged as daily wage mazdoor for specified period vide appointment letter dated 11-3-1987, Ex. M1, and his services were dispensed with after the contract came to an end. That being so, the management prayed for the dismissal of the claim of the workman.

5. Controverting the allegations of the written statement and reiterating the stand taken in the statement of claim, the workman filed the replication.

6. The workman, in order to substantiate his claim, appeared as his own witness, as WW1, who has tendered his affidavit, Ex. W1. The management got proved from the workman, Ex. M1, the appointment letter and Ex. M2, the demand notice. The management in order to rebut the evidence, produced on record by the workman, examined Bal Mukund, Asstt. Engineer, Microwave Maintenance, Dalhousie, as MW1, who has tendered his affidavit, Ex. M3 and documents Ex. M4, policy letter dated 2-6-1987, Ex. M5, the certificate and Ex. M6, letter from Divisional Engineer, Telegraphs, Microwave Maintenance, Jalandhar with a copy to Bishan Dass.

7. Having heard the representative of the parties, having gone through the evidence on record with their help and after bestowal of thoughts on the entire matter, to my mind, the reference petition deserves dismissal. As mentioned above, the case set up by the workman is that he has completed 240 days of his service, but the management has terminated his services without assigning any reason. In his affidavit Ex. W1, while reiterating his stand, the workman pleaded that neither any notice nor retrenchment compensation was given or offered to him. In cross-

examination, he has admitted that his initial appointment was for three months vide appointment letter Ex. M1. No extension letter was given to him. He does labour work and earns Rs. 700.80 per month. On the other hand, the case set up by the management was that workman was engaged as daily wage mazdoor at the rate of Rs. 13 per day, which was renewed on day to day basis. The contract came to an end on 30-11-1987 and was not renewed. So claim of the workman was not maintainable in view of Section 200(bb) of the Act. It is also so stated by the management in its affidavit, Ex. M-3. Now the short and significant question though important arises for determination in this case is whether the workman is a retrenchee and is entitled for the benefits of Chapter A of the Act. The retrenchment has been defined U/S 2(oo) which postulates that retrenchment means, the termination by the employer of the service of a workman for any reason whatsoever, otherwise than, as a punishment inflicted by way of disciplinary action, but does not include the termination of service of a workman as a result of the non-renewal of the contract of employment between the employer and the workman concerned on its expiry or of such contract, being terminated under a stipulation in that behalf contained therein. At this stage, it would be expedient to reproduce the contents of the appointment letter Ex. M-1, for better appreciation :—

“Assistant Engineer  
Microwave (Mtce)  
Dalhousie-176304

To

Shri Madan Lal  
son of Shri Bansilal,  
Village Kathlog  
Dalhousie

No. MW-DLU/A-3/86-87/71, dated at Dalhousie, 11-3-1987.

Sub : Selection for daily mazdoor.

This office has selected you as daily wage mazdoor @Rs. 13/- per day up to the period of three months and may or may not be extended further. You are required to come on work within seven days on the receipt of this letter, otherwise, your selection will be cancelled.

Sd./-  
Assistant Engineer  
Microwave (Mtce).  
Dalhousie-176304.

The bare perusal of the appointment letter, Ex. M-1, would go to show that the workman was selected as daily wage mazdoor @ Rs. 13/- per day up to the period of three months and may or may not be extended further. Thus it would be seen that workman was selected as daily wage mazdoor for the fixed period of three months with a clear stipulation that the said period may or may not be extended further. It stands proved on the record from the affidavit of the management, Ex. M-3, and even the cross-examination of the workman, as WW-1, that his initial appointment was for three months vide letter, Ex. M-1. The period of service of the workman was not renewed and the contract came to an end on 30-11-1987. So his services were dispensed with.



8. The sole contention of the representative, that since the workman had completed 240 days of service, so he is entitled for the benefits U/S 25-F and 25-H of the Act, to my mind, is devoid of merits, because the workman is entitled to statutory benefits of Section 25-F and 25-H only if he is a retrenchee. Taking the risk of repetition, as mentioned above, the appointment of the workman was purely contractual for a specified period vide Ex. M-1, so he is excluded from the definition of retrenchee, as contained in Section 200(bb) of the Act. It is now well settled that if the appointment of a workman is purely adhoc and contractual for a limited period, the right to remain in the post come to an end after expiry of contractual period. Reliance in this regard can be placed to judgements Director, Institute of Management Development U. P. Vs. Smt. Pushpa Srivastava reported in J. T. 1992 (4) S. C. page 489, Surinder Kumar Gyani Vs. State of Rajasthan and another reported in 1993 Supreme Court Cases (L&S) page 24 & Madhyamik Siksha Parishad U. P. Vs. Anil Kumar Mishra and others 1994 Lab. I. C. page 1197.

9. Thus seen from any angle, if the material on record is put together and is perused in relation to the law laid down by the Hon'ble Supreme Court, mentioned above, the conclusion is unescapable that the appointment of the workman was purely temporary and on daily wage basis of Rs. 13/- per day, for a fixed period with a clear stipulation that it may or may not be extended further. He is excluded from the definition of retrenchee as contemplated U/S 200(bb) of the Act, and is not entitled to any benefits claimed by him. Consequently, the action of the respondent management in terminating the services of the workman is justified. The reference is answered accordingly against the workman. Award be submitted to the appropriate Government in accordance with law.

Chandigarh.

Dated : 2-9-1994.

M. S. SULLAR, Presiding Officer.

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1994

का.आ. 2813.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसूचन में, केन्द्रीय सरकार एस.डी.ओ. टीलीकाम, मेडक के प्रबंधन के संयुक्त नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 21-9-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-40012/273/91-आई.आर. (डी.यू.)]

के.वी.बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 22nd September, 1994

S.O. 2813.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Hyderabad as shown in the

Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of SDO Telecom, Medak and their workmen, which was received by the Central Government on 21-9-94.

[No. L-40012/273/91-IR(DU)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL AT HYDERABAD

PRESENT :

Sri Y. Venkatachalam, M.A., B.L.,  
Industrial Tribunal-I.

Dated 12th day of September, 1994

INDUSTRIAL DISPUTE NO. 10 OF 1993

BETWEEN

Sri Syed Anwar,  
S/o Syed Ahmed,  
Casual Telecom Mazdoor,  
3-2-55/1 Arab Galli,  
Medak-502 110.

... PETITIONER

AND

The Sub-Divisional Officer,  
Telecom, Medak-502 110.

... RESPONDENT

APPEARANCES :

M/s. C. Suryanarayana and P. Bhaskar,  
Advocates for the Petitioner.

Sri P. Damodar Reddy,  
Advocate for the Respondent.

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. L-40012/273/91-IR(DU), dt. 17-1-1993 referred the following dispute under Section 10(1)(d) (2A) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the management of SDO Telecom, Medak and their workman to this Tribunal for adjudication :—

“Whether the action of management of Sub-Divisional Officer, Telecom, Medak is justified in terminating the services of Sri Syed Anwar w.e.f. 1-7-1989? If not, what relief the workman concerned is entitled to?”

The reference is registered as Industrial Dispute No. 10 of 1993 and notices were issued to both the parties.

2. The brief facts of the claim statement filed by the Petitioner-Workman read as follows—The Petitioner herein submits that he was initially recruited and employed by the Respondent w.e.f. 5-7-1988. He was employed continuously till the end of June, 1989 except in the months of December, 1988 and April, 1989. Thus he was employed for a total of 268 days during the one year period from July, 1988 to June 1989. During the aforesaid period his name was included in the M/Rs up to the end of October 1988 but later removed from the M/Rs. without notice to the petitioner and thereafter he was employed on various works and paid his wages on ACG-17 receipts. The Respondent retrenched the petitioner from service

w.e.f. 1-7-1989 on the sole ground that he was recruited after 30-3-1985, the date on which the DG P&T issued orders prohibiting fresh recruitment and engagement of casual mazdoors. He was neither given notice nor paid notice period wages in lieu of the notice. Thus the retrenchment of the petitioner was in gross violation of Section 25-F of the I.D. Act as well as Subsequent orders of the Department vitiated ab initio, illegal, null and void. In this connection the petitioner submits that the DG's order dt. 30-3-85 as such does not envisage retrenchment of casual mazdoors but envisages their redeployment in other works of casual nature. The Supreme Court also directed the Respondents therein to prepare a scheme on rational basis to absorb the casual mazdoors with one year service i.e. for those who have worked at least for 240 days in a year. The petitioner submits that he was not paid full wages in accordance with the Supreme Court's decision in AIR 1987 SC 2342 as well as the Subsequent orders of the Department of Telecom. Further, the petitioner is also entitled to the benefit of the order dt. 7-11-1989 of the Director-General, Telecom according to which a casual mazdoor who has rendered 240 days service in a year has to be granted temporary status pending his absorption in the Department. In view of the above circumstances the petitioner prays that this Hon'ble Tribunal may be pleased to declare that his retrenchment is illegal, null and void and to pass an Award Directing his reinstatement with full back wages and continuity of service with all incidental and consequential benefits besides directing payment of the difference of wages together with interest thereon at Bank rates for the period he worked after deducting the wages he was actually paid.

3. The Respondent has not filed their counter.

4. The point for adjudication is whether the action of the Respondent is justified in terminating the services of Sri Syed Anwar w.e.f. 1-7-1989?

5. W.W1 was examined on behalf of the Petitioner and marked Exs. W1 to W4. No oral or documentary evidence has been adduced by the Respondent.

6. W.W1 is Syed Anwar. He deposed that he was engaged by the Respondent from 5-7-1988 to 30-4-1989. At the time of engagement the Respondent used to pay a daily wage of Rs. 14.00 while the actual wage was Rs. 36.00 per day. Ex. W1 is his working days particulars issued by S.P.O. Telecom, Medak. Now I am unemployed. He is staying with his parents-in law. He requests that he may be reinstated with all attendant benefits. He was engaged by the Respondent for a total period of 268 days. Ex. W2 is the Complaint made to the Regional Labour Commissioner (Central), Ex. W3 is the copy of minutes dt. 25-11-1991. Ex. W4 is the copy of failure report dt. 24-12-1991.

7. The case of the Petitioner workman is that he was initially recruited and employed by the Respondent w.e.f. 5-7-1988, that he was employed continuously till the end of June, 1989 except in the months of December, 1988 and April, 1989, that he was employed for a total period of 268 days during the one year period from July, 1988 to June, 1989, that the Respondent retrenched the Petitioner from service

w.e.f. 1-7-1989 on the sole ground that he was recruited after 30-3-1985 the date on which the DG, P&T issued orders prohibiting fresh recruitment and engagement of casual mazdoors. To substantiate the case of the petitioner workman, he filed documents Exs. W1 to W4. Ex. W1 is Memo No. E-25[MDK] 91-92, dt. 23-11-1991. It indicates that the Petitioner-workman worked for 118 days during the period from July 1988 to October, 1988 and then November 1988, June 1989, September 1989 and June 1989 the workmen worked for 150 days. The two spells of working clearly shows that the person was engaged on casual basis. It is seen that the workmen was engaged on casual basis and he was not employed on regular basis as such the retrenchment does not arise. From Ex. W3 it is seen that the Management representative stated that the Petitioner-workman was engaged w.e.f. 5-7-1988 and continued upto 31-10-1988 on Muster Rolls, that subsequently from 1-11-1988 to 30-6-1989 on ACE-17, that he was engaged purely casual basis and he was disengaged after allotted work was over that as he was engaged after 30-3-1985 as per the DG's order, he was not engaged on regular basis retrenchment of his service does not arise. So as seen from the above two exhibits it is clearly seen that the petitioner workman has not put in 240 days continuously in a calendar year, there was disengagement of his service as casual labour and the petitioner workman has not shown or produced any documents to substantiate his case. Hence I find that the petitioner-workman is not entitled to be reinstated into service and that the termination of the services of the workman is justified.

8. In the result, the action of the Management of Sub-Divisional Officer, Telecom, Medak is justified in terminating the services of Sri Syed Anwar w.e.f. 1-7-1989 and he is not entitled to any relief.

Award passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 12th day of September, 1994.

Y. VENKATACHALAM, Industrial Tribunal-I

#### APPENDIX OF EVIDENCE

Witnesses Examined on behalf of Workman:	Witnesses Examined on behalf of Management:
---	--

W.W1 Syed Anwar

NIL

Documents marked on behalf of Workman :	
---	--

Ex. W1/23-11-91.—Statement showing the working days particulars.

Ex. W2/21-7-91.—Copy of representation of the workman for conciliation.

Ex. W3.—Copy of Minutes of Conciliation Proceedings.

Ex. W4/24-12-91.—Copy of Failure Report by the Conciliation Officer.

Documents marked on behalf of Respondent :

NIL

नई दिल्ली, सितम्बर 1994

का.आ. 2814—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पोस्टल डिपार्टमेंट, वीरुधनगर के प्रबन्धन के संबंध में निम्नलिखित और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, मद्रास, के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-9-94 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-40012/253/91-आई.आर. (डी.यू.)]  
के.वी.बी. उन्नी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 23rd September, 1994

S.O. 2814.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Madras as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Postal Department Virudhunagar and their workmen, which was received by the Central Government on 23-9-94.

[No. L-40012/253/91-IR(DU)]  
K. V. B. UNNY, Desk Officer

## ANNEXURE

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL,  
TAMIL NADU, MADRAS

Monday, the 9th day of May, 1994

## PRESENT :

Thiru K. Sampath Kumaran, B.A. B.L.,  
Industrial Tribunal.

## INDUSTRIAL DISPUTE NO. 82/1992

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the Workman and the Management of Postal Department (Superintendent of Post Offices, Virudhunagar).

## BETWEEN

Shri S. Mahalakshmi,  
Sinnakannanpatvi,  
Sivakashi—Virudhunagar Dt.,  
Tamil Nadu-626123.

## AND

The Superintendent of Post Offices,  
Virudhunagar Division,  
Virudhunagar-626 001.

## REFERENCE :

Order No. L-40012/254/91-IR(DU), dated  
25-9-92, Ministry of Labour, Government  
of India, New Delhi.

This dispute coming on for final hearing on Thursday, the 3rd day of March, 1994 upon perusing the

reference, claim and counter statement and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Miss S. Jothivani, Advocate appearing for the workman and of Smt. C. K. Vishnupriya, Central Government Pleader appearing for the Management and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following.

## AWARD

This is a reference made for the adjudication of the following dispute :

“Whether the action of the Postal Department (Superintendent of Post Offices, Virudhunagar) in terminating the services of Miss S. Mahalakshmi, Extra Post Master is justified? If not what relief the workman concerned is entitled to?”

2. The Claimant filed the following Claim Statement.—The petitioner served the Respondent-Department in various spells from 4-9-87 to 12-11-89 as acting extra Departmental Branch Post Master. The Petitioner was appointed on a provisional basis by the memo No. 5/115 dated 17-10-1989 by the Senior Superintendent of Post Offices Virudhunagar from 12-11-1989 and a formal order to that effect was passed under memo B. 5/102 dated 4-6-90 according to which the appointment was in the nature of a contract liable to be terminated by notice in writing. The petitioner was discharged from service on 26-7-90, 425 days and has served for more than 260 days continuously without break from 12-11-89 to 26-7-90. The petitioner was discharged from service on 26-7-90 but, no formal order of termination was passed. No notice as envisaged by the Industrial Disputes Act was served before discharging him from service. The petitioner raised an Industrial dispute under Sec. 2(A) before the Labour Authority for which the respondent filed a counter alleging that the post of Extra Departmental branch post master fell vacant consequent upon the superannuation of the regular holder of the post on 12-11-89, that the employment exchange was addressed for nomination of candidates for that post, that the Employment Officer sponsored 7 candidates, and all the nominees were asked to submit their applications, that only two applications were received, and so, a local notification was issued. The petitioner who had applied in response to the local notification was selected and appointed as Branch Post Master Sinnakarman Patti Branch Office on 12-11-89. But, the selection was set aside on some technical and on administrative grounds by the Director of Postal Services. Accordingly the petitioner was discharged from service. The termination was not for any misconduct on the part of the petitioner. Once the selection was nullified by the Controlling Authority, the respondent had no option except to discharge the petitioner from the post. The Sub-Divisional Inspector Sivakasi while discharging the petitioner from service on 26-7-90 explained to her the reasons for the termination.

3. The action of the respondent in discharging the petitioner from service on 26-7-90, without any notice is illegal. The non-compliance with the provisions of Section 25-F of the Industrial Disputes Act renders

the termination void. The termination is the result of non-application of mind and favourism, amounting to unfair labour practice, and is contrary to principles of natural justice.

4. Therefore, an award may be passed holding that the non-employment of the petitioner from 26-7-90 is illegal and direct reinstatement of the petitioner into service with all attendant benefits.

5. The respondent filed the following Counter.—S. Srinivasan, Extra Department Branch Post Master attained the age of Superannuation on 12-11-89. The District Employment Office which was addressed, sent a list of names, and the nominees were asked to send the applications. A local notification calling for applications was issued. The petitioner who had applied in response to the local notification was selected and appointed as Extra Departmental Post Officer, Chinna Kaman patti Branch Post Office on 12-11-89. On a complaint by one of the nominees of the Employment Exchange the Director of Postal Services observed as follows : Set aside the selection of the petitioner and order to start the recruitment process once again.

1. Issue of local notification is unnecessary and one of the two candidates who had applied out of 7 sponsored by the Employment Exchange should have been selected.
2. If the criterion of selecting the present incumbent was on the basis of income the person who was originally sponsored by the employment exchange had also produced an income certificate?
3. How a person already employed in a match factory could be selected?
4. The recruitment was not done as per standing instructions.

The petitioner was discharged on 26-7-90. Again the District Employment Officer was addressed to sponsor candidates for the post. A list of 20 persons was received and a more suitable candidate was selected and appointed Extra Departmental Post Officer Chinna Kaman Patti Branch Post Office and he is still continuing in the post. As the selection of the petitioner is declared irregular and set aside the petitioner was discharged. The termination of her service was not for any misconduct, but, it is the result of the execution of the order of the reviewing authority, setting her selection at naught. There was no alternative for the respondent except to obey to give effect to that order of the reviewing authority. The Sub Divisional Inspector, Sivakasi while discharging the petitioner from service on 26-7-90 explained to her the reasons for termination and handed over a copy of the charge report to her. A formal order of termination was subsequently issued by the Superintendent of Post Offices under memo B-5/162 dt. 28-1-91. Rule-6 of Post and Telegraphs Extra Departmental Agents (Conduct and Service) Rules 1964 speaks about the termination of service. The services of an employee who has not already rendered more than 3 years of continuous service from the date of appointment shall be liable for termination by the appointing authority at any time without notice. So, here is no violation of any rule. Therefore, the petition may be dismissed.

6. The issues that arises for consideration in this Industrial Dispute are :

1. Whether the petitioner had served under the respondent for more than 260 days continuously without break from 12-11-1989 to 26-7-90 and whether the termination of her services is illegal?
2. Whether the appointment of petitioner as Extra Departmental Post Master under the order dated 4-6-90 can be cancelled without issuing a notice to the petitioner and without affording an opportunity to her to defend the action for terminating the services?
3. Whether the termination of her services under Rule-6 of the Post and Telegraphs Extra Departmental Agents (Conduct and Service) Rules 1964 is valid?
4. Whether the petitioner is entitled to be re-instated into service?

7. Issues 1 to 4.—Certain names were sponsored by the Employment Exchange at the request of the respondent for appointment to the post of Extra Departmental Post Master. Under Ex. W-2 a formal order appointing the petitioner as Extra Departmental Branch Post Master at Chinna Kamanpatti on 4-6-90 was issued, though actually she was appointed on 13-11-89 itself. Even according to the respondent the Employment Exchange sponsored 7 persons and all of them were asked to send their applications and that in response applications were received from only two of the nominees. The respondent contends that since there were only 2 applications. A local notification calling for applications was issued on 24-8-89. The respondent also contends that the petitioner also applied in response to the local notifications, was selected and appointed as Extra Departmental Post Master on 13-11-89. She was suddenly discharged from service on 26-7-90. Therefore, there is no question that the petitioner was appointed to this post on 13-11-89 and worked till 26-7-1990 continuously. According to the petitioner she has worked for 260 days continuously without break, but was dismissed service without notice and without disclosing her the reasons for such discharge, and without asking her to put forward her case with regard to the same. The respondent contends that one of the nominees had given a complaint against the selection of the petitioner and the Director of Postal Services observed that the local notification ought not to have issued, that one of the two candidates (out of the seven) sponsored by the Employment exchange who had applied should have been appointed. that the person sponsored by the Employment Exchange had also produced income certificate that the person already employed in a match factory should not have been selected, and that the recruitment was not done as per the Standing instructions on the subject and therefore, set aside the selection of the petitioner. The respondent contends that fresh recruitment was also ordered and a more suitable person has been appointed in the place of the petitioner after discharging her from service on 26-7-90. It is admitted by the respondent that the petitioner was not discharged from service for any misconduct, but, only in execution of

the order of the Superior namely, the Director of Postal Services.

I have already pointed out that there is no question that the petitioner had served for more than 250 days from 12-11-1989. The petitioner even contends that even prior to 12-11-89 she was working between 6-9-87 to 12-11-89 also. The petitioner in her evidence also stated that she had worked from 6-9-87 to 12-11-89 in a leave vacancy and from 13-11-89 as a permanent Branch Post Master. Of course, this was disputed by the Respondent. Whatever it is there is no question that she was working from 12-11-89 to 26-7-90. She also stated that no reason was given to her for her removal from service on 26-7-90, that no notice that she will be removed from service was given to her, and that she was not paid one month's wages in lieu of notice. The suggestion put to her by the respondent was that she worked temporarily during 13-11-89 to 26-7-90 and after the expiry of the period she was relieved, but she denied this suggestion. But it is not disputed that no notice was given to her about the intention of the respondent to discharge her from service. According to the respondent she was discharged from service on administrative grounds and as her selection was set aside. Even if that be so, before discharging the petitioner from services the respondent should have put her on notice about their intention to discharge by giving her the reasons and asking her to defend the action. Even a notice that they are going to discharge her from service was not issued by the respondent. But a relieving order was issued to her on 28-1-91 stating that she was relieved from the post. Even there it is not stated that she was discharged from service. As pointed out already while she was discharged from service, on 26-7-90, this relieving memo, (Exhibit W-4) was given long thereafter, that is, on 28-1-91. It is not as if she was not appointed for a particular period, and that after the expiry of that period, her services were put an end to. The appointment order Ex. W-2 does not specify that she was appointed for a particular period. Therefore, the suggestion to WW1 made by the respondent that after the expiry of the period she was relieved from the post cannot be accepted. The selection of the petitioner cannot be set aside without an opportunity to the petitioner to represent her case. The allegation is that she was discharged from service, that the services of an employee who had not rendered more than 3 years of continuous service can be terminated by the appointing authority at any time without notice in view of Rule-6 of the post and Telegraph Extra Departmental Agents (Conduct & Service Rules) 1964. First of all the relieving order Ex. W-4 does not purport to be one issued under the said rule. Even if it is considered to be a termination under the said rule, the respondent is not entitled to terminate the services of the petitioner for some alleged irregularity which had taken place prior to the appointment, and on that ground the services of the petitioner cannot be put to an end. The learned counsel for the petitioner relied upon the decision of the Central Administrative Tribunal (Ernakulam) in R. Ralathi Vs. S.D.I. of Post Offices, Haripad & others (1991(1) CAT Page 105, in support of her contention. That decision also relates to termination of an Extra Departmental Branch Post

Master on Administrative ground as some irregularities in the selection proceeding were revealed. But no, opportunity to be heard was given to the concerned employee. It was held that Rule-6 of the Extra Departmental Agents (Conduct & Service) Rules 1964 cannot be invoked for terminating the services on some grounds that had arisen before or in regard to the appointment. It was held that the termination order terminating the services without giving an opportunity to show cause is illegal, void, being violative of natural justice. In that case also after termination of the services of the concerned employee a second interview was conducted and another person was appointed. It was held that when the termination of the services is set at naught the second interview and the selection automatically goes. Therefore, taking into consideration all these factors I find that the petitioner had served under the respondent for more than 250 days continuously without break from 13-11-89 to 26-7-90. That the appointment of the petitioner as Extra Departmental Post Master cannot be cancelled without issuing a notice to the petitioner and without affording an opportunity to put forward her case, that the termination of her services even if it had been made under the Rules of Post & Telegraph Extra Departmental Agents (Conduct & Service Rules) 1964, the same is not valid as it purports to have been made for some irregularity in what happened prior to her selection and appointment. Therefore, I find that the termination of the services of the petitioner is not justified but is illegal and against the principles of natural justice, and has to be set aside. I also find that the petitioner is entitled to reinstatement into service with backwages.

In the result, I find that the action of the Postal Department (Superintendent of Post Offices), Virudhunagar in terminating the services of the petitioner—S. Mahalakshmi, Extra Departmental Post Master is not justified and the same is set aside. The petitioner is directed to be reinstated with continuity of service with full back wages. An award is passed accordingly. No costs.

Dated, this the 9th day of May, 1994.

THIRU K. SAMPATH KUMARAN, Industrial Tribunal

#### WITNESSES EXAMINED

FOR WORKMAN:

W.W. 1.—Kumari S. Mahalakshmi.

FOR MANAGEMENT: None.

#### DOCUMENTS MARKED

Ex. W-1/22-9-89.—Letter from Respondent/Management to Petitioner—workman Kumari S. Mahalakshmi to appear with documents. (Xerox copy).

Ex. W-2/4-6-90.—Appointment order issued to Petitioner—worker as Extra Departmental Branch Post Master (Xerox copy).

Ex. W-3/12-11-89.—Charge taking report (Xerox copy).

Ex. W-4/28-1-91.—Order of relieving the petitioner—worker (Xerox copy).

Ex. W-5/15-2-91.—Petition u/s. 2-A of the I.D. Act, 1947 filed by petitioner—worker before the Conciliation Officer (Central Labour Commissioner's Office), Madras-6 (Xerox copy).

Ex. W-6/12-6-91.—Counter Statement filed by the Respondent|Management filed before the Conciliation Officer (Central Labour Commissioner's Office) Madras-6 (Xerox copy).

Ex. W-7/3-9-91.—Rejoinder filed by the petitioner—worker before the Conciliation Officer, Madras-6 (Xerox copy).

Ex. W-8/27-9-91.—Reply (to the rejoinder) filed by Respondent|Management before the Conciliation Officer, Madras-6 (Xerox copy).

Ex. W-9/1-10-91.—Conciliation Failure Report (Xerox copy).

FOR MANAGEMENT : Nil.